दैनिक इबादत सम्पादकीय

लोकसभा चुनाव, परिणाम आज

भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार और मतदान सात चरणों में 44 दिनों में संपन्न हुआ। यह अभी तक की सबसे लंबी अवधि का चुनाव साबित हुआ है। 1996 के लोकसभा चुनाव 11 दिन में संपन्न हुए थे। 1998 का लोकसभा चुनाव 20 दिन में संपन्न हुआ था। 2000 में लोकसभा के चुनाव 21 दिन में संपन्न हुए। 2004 का लोकसभा चुनाव भी 21 दिन में संपन्न हुआ था। उसके बाद से लगातार चुनाव की समयावधि बढ़ती गई है। 2009 में 28 दिन, 2014 में 36 दिन और 2019 में 39 दिन में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनाव की अवधि 44 दिन रही, जो अभी तक का सबसे ज्यादा दिनों का रिकॉर्ड है। 1996 से लेकर 2024 के बीच का काल देश में संचार क्रांति के रुप में जाना जाता है। इस दौरान गांव-गांव तक फोन और इंटरनेट का विस्तार हो गया। परिवहन यातायात के साधन सुलभ हुए। खूब अच्छी सड़कें बनीं। हर गांव से पहुंच मार्ग मुख्य सड़क तक मिल गया। चुनाव ईवीएम मशीन से होने लगे। हवाई जहाज चलने लगे। चांद पर हमने अपना चंद्रयान भी उतार दिया। इसके बाद भी आम चुनाव की अवधि बढ़ती चली गई। तमाम व्यवस्थाओं के बीच चुनाव हुए, इसके बाद भी 2024 का लोकसभा चुनाव की अवधि कम होने के स्थान पर और बढ़ती चली गई, यह हैरान करने वाली बात है। सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। सात चरण में मतदान होने से हर चरण में चुनाव प्रचार करने की अवधि अलग-अलग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बिरले उम्मीदवार और पार्टी के स्टार चुनाव प्रचारक रहे हैं जो प्रत्येक चरण से लेकर अंतिम चरण तक जहां-जहां चुनाव होने तक 44 दिन लगातार प्रचार करते रहे। कोई भी राज्य हो, कोई भी चरण हो, प्रधानमंत्री 24 घंटे हर समय मतदाताओं के सामने चुनाव प्रचार के लिए बने रहे। इस लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनसभा और रैलियां करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में 188 रेलियों को संबोधित किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के सातों चरणों में इनका चुनाव प्रचार सतत चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सरकारी सुरक्षा में रहते हुए चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव प्रचार में मीडिया के सभी राष्ट्रीय चैनल लगातार दोनों का प्रसारण करते रहे। भले ही प्रत्येक चरण के मतदान के दौरान चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत चुनाव प्रचार में रोक लग गई हो, मतदान के दिन किसी तरीके का प्रचार नहीं किया जा सकता हो, लेकिन वहां पर भी टेलीविजन के माध्यम से लगातार प्रचार-प्रसार होता रहा। 44 दिन की लंबी समयावधि चुनाव आयोग ने शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सात चरणों में चुनाव संपन्न कराने का काम किया है। बहरहाल इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी लंबी अवधि के लिए इतिहास में जरुर दर्ज किया जाएगा।

इस बार भी जीत गई जनता, हार गई जातिवादी मानसिकता

– पंकज कुमार मिश्रा

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का मिडिया, अदालतों और संसद के साथ साथ जनता के प्रति भी सीधी जवाबदेही होती है जोकि लोकनीति के रूप में अति आवश्यक है। इस धारणा को सकारात्मक बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संवैधानिक संस्थाओं को चाहिए वह बिना किसी दवाब के विपक्ष और नागरिक संगठनों के सवालों का समुचित जवाब दे ताकि नकारात्मक अवधारणाएं पनपने ही ना पाएं। एक स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष, जागरूक नागरिक संगठन, जवाबदेह संस्थान और स्वतंत्र व निष्पक्ष मीडिया होना बेहद जरूरी होता है वर्ना सरकार और सत्ता के निरंकुश होने में समय नहीं लगता है। यहां लोहिया जी का एक कथन याद आता है कि 'अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जायेगी' बेहतर होगा कि सड़क, चौराहों, चायखानों, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर उठ रही आवाज़ों को दबाया न जाए बल्कि उनके संतोषजनक उत्तर देकर ध्रुव राठी जैसे विदेशी वामपंथीयों की बोलती बंद की जाए। चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन खोई साख का लौटना बहुत कठिन होता है। चुनाव आयोग अपने आप में एक बेहद ताकतवर और अधिकार प्राप्त संस्था है। उसका न सिर्फ निष्पक्ष होना बल्कि दिखना भी बेहद जरूरी है। लेकिन जिस तरह से इन चुनावों में इस शीर्ष संस्था ने रवैया अपनाया है उसकी प्रशंसा की जा सकती है। चाहे वह हेट स्पीच पर की गई शिकायतों पर संज्ञान हो या फिर बंगाल में खुलेआम धर्म और जाति आधारित प्रचार और वोट की अपील। सत्ता पक्ष द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने में भी चुनाव आयोग कामयाब दिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों ने तो आदर्श आचार संहिता की इज्जत बचाये रखी। ओपिनियन पोल दिखाने की पाबंदी के बावजूद विपक्ष पोषित युटुबर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव विश्लेषण की आड़ में मतदाताओं को प्रभावित करने का खेल जारी रखें रहें। इधर एक चरण की वोटिंग होती थी उधर दूसरे चरण का प्रचार चलता था और युटुब पर सजीव प्रसारण होता रहा। सोशल मीडिया तो बिल्कुल बेकाबू रहा। माहौल जानने की आड़ में लाइव पोल, ऑपिनियन पोल, एक्जिट पोल आदि सभी चलते रहे। कभी सरकारी गाड़ी से खाली ईवीएम बरामद होने की शिकायत को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने अपना रोना शुरू किया तो कभी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने की शिकायत कभी पैसा बांटने की शिकायत, कभी जान बूझ कर पर्चा खारिज करने की शिकायत। चुनाव आयोग ने या तो शिकायतों को खारिज किया या फिर कठोर कार्रवाई करने, स्पष्टीकरण और स्थानान्तरण जैसी कार्रवाई करके अपने कर्तव्य की पूर्ति की। लोकतंत्र में जनता का विश्वास चुनावों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि न्याय होना ही जरूरी नहीं होता है, न्याय दिखना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह लोकतंत्र ने निष्पक्षता और शुचिता होना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसका दिखना भी जरूरी होता है। हर बार की तरह एक बार फिर से चुनाव खत्म होते ही ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने लगेंगे। जाहिर है ये सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इनमें टेंपरिंग, वोट प्रतिशत, पेपर ट्रेल से मिलान और पोस्टल बैलेट की गिनती पर आशंकाएं शामिल हैं जो निराधार होती है। विपक्ष के इन सवालों को सत्ता पक्ष और मीडिया का एक धड़ा यह कह कर खारिज कर देता है कि विपक्ष हार की हताशा और कुंठा का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ कर अपनी खीज मिटाता है। ईवीएम का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा लेकिन शीर्ष अदालत ने वहां इन आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर संदेह करना सही नहीं है। इसलिए हमारे अनुसार सार्थक आलोचना की आवश्यकता है, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो। लोकतंत्र का अर्थ सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट की गिनती में मशीन की मदद लेने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन क्या इससे सरकार और दूसरी संविधानिक संस्थाओं पर उठ रही उंगलियां शांत हो गईं ? जनतंत्र में धारणा बहुत मायने रखती है। विपक्ष द्वारा बार बार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के कार्यकाल को याद कर मिसाल दी जाती है। आखिर चुनाव आयोग विपक्ष के बीच अब अपनी विश्वसनीयता को लेकर क्यों नहीं गंभीर दिखता है। क्या लोकतंत्र में उसकी जवाबदेही सिर्फ संसद और न्यायालय तक ही है जनता के विश्वास को जीतने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करने चाहिए थे ? क्यों नहीं उसने ऐसा कुछ किया जिससे विपक्ष को लगता कि वह निष्पक्ष है और सत्ता सरकार के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। आज जो ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के एक हिस्से में धारणा है वह कल को बलवती होकर जनता के व्यापक हिस्से को प्रभावित कर सकती है जोकि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए विपक्ष समेत सभी यूट्यूब संस्थाओं को समय रहते चेत जाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का निष्पक्ष होना और दिखना दोनों महत्वपूर्ण है।

(राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार जौनपुर, यूपी)

आखिर सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों का कौन है जिम्मेदार ?

कहीं-कहीं सड़क निर्माण तकनीकी में चूक भी हादसों की वजह बनने की खबरें आई हैं। वहीं बड़ी संख्या में हादसों की वजह अनियंत्रित रफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन तथा शराब पीकर वाहन चलाना रहा है। यदि दुर्घटनाओं के कारणों में विस्तार से जाएं तो वाहन चलाने के अनुभव के बिना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना व ट्रक चालकों की आंखों की नियमित जांच न होना भी सामने आता है।

– मनोज कुमार अग्रवाल

गर्मी की छुट्टियां होते ही देश में पहाड़ी राज्यों की ओर मैदानी क्षेत्रों के निवासियों की पिकनिक व धार्मिक टूर का सिलसिला शुरू हो जाता है। अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार पहाड़ी क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे वह धार्मिक तीर्थयात्रा व पर्यटन दोनों काम एक साथ करने का विचार रखते हैं लेकिन इन दिनों रोजाना धार्मिक यात्रा के दौरान सड़क हादसे और उनमें जनहानि के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में जम्मू के अखनूर में हुए सड़क हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 69 लोग घायल हो गए। यह यात्री यूपी के हाथरस से जम्मू संभाग के जिला रियासी के शिवखोड़ी धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि डोडा में पिछले साल हुए हादसे के बाद यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना15 नवंबर 2023 डोडा के अस्सर इलाके में यात्रियों से भरी एक बस सड़क से फिसल कर 300 फुट गहरी खाई में गिर गई थी। इसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी और 19 घायल हो गए थे। इसी साल 29 मार्च को रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) के फिसल कर खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इनमें से भी प्रत्येक 5 में से 1 मौत भारत में होने के कारण भारत को सड़क दुर्घटनाओं की राजधानी भी कहा जाने लगा है जिनमें परिवारों के परिवार तबाह हो रहे हैं। हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की बानगी देखिए 18 मई को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में केदारनाथ से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार मवेशियों से टकराने से बचाने की कोशिश में पलट जाने से उसमें सवार 2 महिलाओं की मौत व 11 अन्य घायल हो गए। 23 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर से चारधाम यात्रा के लिए आए तीर्थ यात्रियों की बस समराला के निकट एक ट्राले से टकरा जाने से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 24 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं की मिनी बस दिल्ली-जम्मू हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। 24 मई को ही कर्नाटक के श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या आ रही एक मिनी बस के अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर एक ट्रक से टकरा जाने के कारण तीन श्रद्धालुओं की मौत और 14 घायल हो गए। 25 मई को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक कार के सड़क से फिसल जाने से पंजाब के 4 पर्यटकों की मौत तथा 3 घायल हो गए। 26 मई रात को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राजसर में एक सड़क दुर्घटना में एक कार और ट्रक की टक्कर में एक दम्पति और उनकी 7 वर्ष की बेटी के अलावा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।26 मई को ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सीतापुर से उत्तराखंड में मां पूर्णागिरि के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर तेज गति से आ रहा डम्पर पलट जाने से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 26 मई को ही हिसार के सैक्टर 27-28 मोड़ के निकट ट्रक से बचने के प्रयास में लड़की का रिश्ता करने आए परिवार की कार पलट जाने सेकार सवार दम्पति और 2 भाइयों सहित 5 लोगों की जान चली गई। 28 मई को ही अलमोड़ा में एक सड़क दुर्घटना में रुड़की के एक परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। 29 मई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे कर्ण भूषण सिंह के काफिले की एक गाड़ी ने 2 बाईक सवारों को रौंद दिया जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई जबकि सड़क के किनारे बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।29 मई को ही महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक कार के नहर में गिर जाने से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई।29 मई को ही फिरोजपुर के कस्बा मक्खू में सड़क पार करते समय एक दुकानदार को एक बस ने टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 29 मई को ही दिल्ली में तेज रफ्तार बाईक गीता कालोनी फ्लाईओवर से लगभग 25 फुट नीचे गिर जाने से दो युवकों की मौत हो गई। अब 30 मई को जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकी चौरा कालीधार मार्ग पर एक हृदय विदारक दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के हाथरस से शिवखोड़ी जा रही तीर्थयात्रियों की स्लीपर बस ड्राईवर द्वारा तीखे मोड़ पर संतुलन न रख पाने के कारण 5-6 पलटियां खाकर 200 फुट की गहरी खाई में गिर जाने से 22 तीर्थ यात्रियों की मौत और 64 तीर्थ यात्री घायल हो गए। निश्चय ही यह दुर्घटनाएं अत्यंत दुखद हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से मरने वालों के परिवारों पर अचानक वज्रपात हो जाता है, इनके चलते अनाथ, विधवा और यतीम हो जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बूढ़े माता-पिता का जीवन भी नरक बन जाता है। अत: इनसे बचाव के लिए वाहन चालकों को प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निस्संदेह, ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के मूल में मानवीय लापरवाही ही होती है। यह विचारणीय तथ्य है कि मैदानी इलाकों से पर्वतीय मार्गो पर बस या अन्य वाहन ले जाने वाले चालकों को क्या पहाड़ी रास्तों पर बस चलाने का पर्याप्त अनुभव होता है? जो तीखे मोड़ पर वाहन को नियंत्रित कर सकें दरअसल, जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पहाड़ी इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं में मानवीय क्षति ज्यादा होती है।

वजह साफ है कि गहरी खाई बचने के मौके कम ही देती हैं। यह विडंबना है कि बड़े हादसों के बाद शासन-प्रशासन की तरफ से मुआवजे व संवेदना का सिलसिला तो चलता है लेकिन हादसों के कारणों की तह तक नहीं जाया जाता। यदि हादसों के कारणों की वास्तविक वजह सार्वजनिक विमर्श में आए तो उससे सबक लेकर सैकड़ों लोगों की जान बचायी जा सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं करीब साढ़े चार लाख लोग इन दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। इनमें कई लोग तो जीवन भर के विकलांगता का शिकार हो जाते हैं।

आपको बता दें कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में नीति-नियंताओं की तरफ से बेमौत मरते लोगों का जीवन बचाने की ईमानदार पहल नहीं होती। हाल के वर्षों में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गो का विस्तार हुआ। सड़कें चौड़ी और सुविधाजनक हुई। लेकिन रफ्तार का बढ़ना जानलेवा साबित हो रहा है। कहीं-कहीं सड़क निर्माण तकनीकी में चूक भी हादसों की वजह बनने की खबरें आई हैं। वहीं बड़ी संख्या में हादसों की वजह अनियंत्रित रफ्तार, यातायात नियमों का उल्लंघन तथा शराब पीकर वाहन चलाना रहा है। यदि दुर्घटनाओं के कारणों में विस्तार से जाएं तो वाहन चलाने के अनुभव के बिना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना व ट्रक चालकों की आंखों की नियमित जांच न होना भी सामने आता है। दरअसल, वाहनों की फिटनेस, सार्वजनिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच तथा निर्धारित समय तक ही वाहन चलाने की अवधि भी तय की जानी चाहिए। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि चालक की नींद पूरी न होने और उसे पर्याप्त आराम न मिलने से हादसा हुआ चिंता की बात यह भी है कि लोग रात में सफर करना सुविधाजनक मानने लगे हैं। जबकि रात को वाहन चलाना कई मायनों में असुरक्षित होता है और किसी हादसे के बाद पर्याप्त सहायता व उपचार न मिलना जानलेवा साबित हो सकता है। इन दुर्घटनाओं का दुखद पहलू यह है कि मरने वाले में अधिकांश युवा व परिवार के कमाने वाले सदस्य होते हैं। हादसे के बाद पूरा परिवार गरीबी के दलदल में चला जाता है। यह राष्ट्र की बड़ी आर्थिक क्षति होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि यदि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओ में मरने वाले लोगों की संख्या रोकी जा सके तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीन फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। नीति-नियंताओं को इस बात पर भी विचार करना होगा कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में वाहन कम होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में क्यों होती हैं? दुर्घटनाओं के कारणों में सड़कों की खस्ता हालत, खुले मैनहोल, यातायात नियमों का उल्लंघन, शराब पीकर या अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाना, लगातार अधिक समय के लिए बिना रुके या बिना पूरी नींद लिए वाहन चलाना शामिल है। अत: इन्हें रोकने के लिए कुछ अवधि के बाद ड्राईवर को आराम दिलाना, उसका मुंह आदि धुलवाना और लम्बा सफर होने पर एक अतिरिक्त ड्राईवर साथ लेकर चलना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

युद्ध की विभीषिका से बच्चों को बचाएं

– बाल मुकुन्द ओझा

यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को, बल्कि उनके भावात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। दुनिया के आधे से अधिक बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया हैं और इस तादाद के 64 प्रतिशत बच्चे दक्षिण एशिया में हैं। सभी बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक है और लाखों बच्चों के लिए यह कठोर वास्तविकता है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है।

यह दिवस सयुंक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं जीवन-सुरक्षा से जुड़े प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सयुंक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरूआत 19 अगस्त 1982 को हुई थी। सैन्य मुठभेड़ में बच्चों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है। इस युद्ध में बच्चे भी झुलस रहे है। हम दिवस जरूर मनाएं मगर जब वास्तविक विपदा आएं तो उसका भी मिलजुलकर सामना करें। यूक्रेन युद्ध की बात करें तो हम पाएंगे की बच्चे कभी युद्ध नहीं छेड़ते, लेकिन जब कभी युद्ध होता, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस युद्ध के दौरान लाखों बच्चों को असीम पीड़ा झेलनी पड़ी है। शिक्षा से वंचित होने के साथ सैंकड़ों बच्चों ने न केवल अपने परिजनों को खो दिया अपितु बहुत से बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज सबसे ज्यादा जरुरत इस बात की है कि हम युद्ध की विभीषिका से बच्चों को बचाएं। तभी ऐसे दिवसों की सार्थकता सिद्ध होंगी। बच्चों के कुपोषण, अनाथ बच्चों के संरक्षण, बालश्रम, गरीबी और भुखमरी, बाल विवाह तथा बच्चों की शिक्षा सहित अनेक स्तरों पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के दिवस वैश्विक स्तर पर मनाये जाते है। इसी कड़ी में दुनिया भर में हर साल 4 जून हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर बच्चों की पीड़ा और दर्द से आम आवाम को सतर्क और जागरूक किया जाता है। सही बात तो यह है ये सभी दिवस रश्मि होते जा रहे है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र और उससे जुडी संस्थाएं इन दिवसों का आयोजन कर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। चाहे औपचारिकता ही पूरी हो मगर एक दिन विश्व का ध्यान निहित उद्देश्यों की और आकर्षित जरूर किया जाता है। इस दौरान कोरोना ने हजारों बच्चों को अकाल मौत के मुंह में धकेल दिया।

भारत में चार करोड़ बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार होकर अपने घरों से पलायन कर फुटपाथ या सड़क पर रहने को मजबूर हैं। .घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर यह मासूम अपने घरों को छोड़ देते हैं और फिर इनकी जिंदगी नरक से कम नहीं होती है। घरेलू हिंसा के शिकार हजारों बच्चे घर छोड़ने के बाद पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाना, खेतों में काम करना , कोयले की खानों में, पत्थर खदानों, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग तथा होटलों व ढाबों में झूठे बर्तन धोना आदि सभी काम मालिक की मर्जी के अनुसार करने होते हैं। भारत के एडवोकेसी ग्रुप नो वॉयलेंस इन चाइल्डहुड की एक स्टडी के अनुसार दुनिया के चार में तीन बच्चे किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हैं। स्टडी अनुसार दुनिया के तकरीबन 1.7 अरब बच्चे मानसिक या शारीरिक हिंसा का शिकार हैं। 13-15 साल की आयु वर्ग के तकरीबन 13.8 करोड़ बच्चे दादागिरी, गुंडागर्दी के शिकार बनते हैं तो वहीं 12.3 करोड़ बच्चे स्कूलों में होनेवाली लड़ाइयों में हिंसा का शिकार होते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कागजी कार्यवाही और भाषणबाजी से ऊपर उठकर धरातल पर आकर यथार्थ में बच्चों पर अत्याचार और हिंसा को सख्ती से रोके और उनके अधिकारों को संरक्षित कर विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाएं ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कविता: प्रतिद्वंदी

अच्छा चलो कल से हम
नहीं रहेंगे, तुम्हारे प्रतिद्वंदी,
क्यों ना हम भी कर लें
इसी बात पे रजामंदी
बेवजह दिखाता नहीं
कोई आजकल किसी
से भी हमदर्दी
एक अरसे से वैसे भी
हम यही बात सुना करते हैं।
सदा से ही चला करती है
मानवता के द्वार पर मंदी
फिर क्यों उलझे हम
बेवजह एक दूजे से
इस बात पर की
कौन बाहर का है
और कौन घर का
बस विचार तुम्हारे
हमारे बेमेल है ।
सब सिद्धांतों का ही
तो खेल है।
अच्छा चलो कल से हम
नहीं रहेंगे तुम्हारे प्रतिद्वंदी।

डॉ. कांता मीना
(शिक्षाविद् एवं साहित्यकार)

'मोदी की गारंटी' विभिन्न क्षेत्रों, नागरिकों और योजनाओं में किए गए वादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। 'मोदी की गारंटी' का अर्थ ही है लोगों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। 'मोदी की गारंटी' का अर्थ है विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत। यह युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और दशकों से उपेक्षित सभी हाशिए पर रहने वालों और कमजोर वर्गों के लिए एक गारंटी है।

कैसे नरेन्द्र मोदी ने जीता जनता का विश्वास

– आर.के. सिन्हा

लोकसभा चुनाव के कल 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले एक्जिट पोल के अनुमान तो आ गए हैं। वे कमोबेश वैसे ही हैं जैसा कि मैंने अपने कई पूर्व के लेखों में लिखा है। उन्होंने बहुत साफ संकेत दे दिया है कि देश में तीसरी बार नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। एक्जिट पोल के अनुमानों से साफ है कि नरेन्द्र मोदी आज देश के एकछत्र नेता बन चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का इतना अभूतपूर्व विश्वास कैसे मिलने लगा है? अगर आप इस सवाल का उत्तर तलाशेंगें तो आपको पता चलेगा कि एक वे अपने वादों को सही ढंग से समय सीमा के अन्दर ही पूरा करते हैं। 'मोदी की गारंटी' विभिन्न क्षेत्रों, नागरिकों और योजनाओं में किए गए वादों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। 'मोदी की गारंटी' का अर्थ ही है लोगों के कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। 'मोदी की गारंटी' का अर्थ है विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत। यह युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और दशकों से उपेक्षित सभी हाशिए पर रहने वालों और कमजोर वर्गों के लिए एक गारंटी है।

कल्याण की गारंटी

सबसे बुनियादी जरूरतों से शुरुआत करते हुए, मोदी सरकार द्वारा आज सबसे गरीब लोगों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों से लैस किया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करते हुए, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। इस गारंटी से यह सुनिश्चित होता है कि भारत वर्ष में कोई भी भूखा न सोए। प्रत्येक व्यक्ति को एक छत प्रदान करने के उद्देश्य से, मोदी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' की गारंटी देती है। आज, इस योजना के तहत चार करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। गाँवों का 100% विद्युतीकरण भी इस वादे का हिस्सा है। आज जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुँच रहा है, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन की गारंटी देता है।

सब हों स्वस्थ

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो लगभग 12 करोड़ कमजोर परिवारों से संबंधित लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। योजना एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि चिकित्सा आपात स्थिति गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए कर्ज के चक्र में न बदल जाए। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं। इसलिए गरीबों को लाभ हो रहा है, वे उनसे जुड़ रहे हैं।

अन्नदाताओं को सशक्त बनाना

प्रधानमंत्री मोदी की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है, जो 2024-25 में 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो 2014-15 के बाद से उल्लेखनीय 300% की वृद्धि है। पीएम-किसान योजना से 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ हुआ है, जिन्हें सहायता के रूप में 2.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार किसानों को उद्यमी बनने में भी सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है क्योंकि 7,000 जीवंत कृषि और संबद्ध स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं।

नारी शक्ति के बढ़ते कदम

अभी तक मिलने वाली खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को देश की महिलाओं ने भरपूर वोट दिए। मोदी सरकार औरतों को पूरे लगन और संकल्प पूर्वक स्वावलंबी बना रही है। सरकार की जन धन योजना जैसी पहल से 28 करोड़ महिलाओं को पहली बार बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त हुई है, जबकि लगभग 31 करोड़ मुद्रा ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। तीन तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। इसके अलावा, पीएम उज्ज्वला योजना जैसी पहलों की सफलता, दस करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके, महिलाओं को सशक्त बनाया है, जो सरकार की महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक समावेशी और लिंग संवेदनशील समाज बनाने में योगदान किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ी छलांग है। भारत के युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके सशक्तिकरण की गारंटी दी है। जैसे ही भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर रहा है, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ, पीएम मुद्रा योजना ने 8 करोड़ पहली बार युवा उद्यमियों को ऋण प्रदान की है।

प्रेरित करती भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक यात्रा उल्लेखनीय रही है। भारत अब विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2014 से 2023 तक एफडीआई में रिकॉर्ड 596 बिलियन डॉलर आकर्षित कर रहा है। प्रति माह औसतन 1.72 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर राजस्व, और एमएसएमई क्षेत्र का विकास, जिसमें 15 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं, भारत के आर्थिक पुनरुत्थान को उजागर करता है।

अनुच्छेद 370 का अंत

मोदी सरकार ने संविधान की धारा 370 को हटाकर सारे देश का सम्मान पाया है। यह एक इस तरह का कानून था जिसने कश्मीर के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया था। 1994 और 2004 के बीच, 40 हजार से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुईं, लेकिन मोदी सरकार के नौ वर्षों में, इन घटनाओं में भारी गिरावट आई, केवल 2,197 घटनाएं हुईं। इसी तरह, नागरिकों की मौतों की संख्या में 72% की कमी आई, और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 59% की कमी आई। कोविड काल को कौन भूल सकता है? उस कठिन दौर में प्रधानमंत्री मोदी दिन-रात देश की जनता के साथ खड़े थे। यदि उस समय मोदी सरकार बेबस जनता के साथ हर तरह से सहयोग न कर रही होती तो हालात और खराब हो जाते।

न जाने कितने लाख भारतीय नागरिकों की मौतें होतीं

कोरोना को शिकस्त तो मिलनी ही थी और अंत में कोरोना हारा। भारत गर्व कर सकता है कि उसने नरेन्द्र मोदी की सरपरस्ती में सबसे आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी। भारत ने कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए दो तरह के टीके भी ईजाद कर लिये थे। निश्चित रूप से कोरोना पर विजय पाने की दिशा में भारत ने दुनिया को संजीवनी बूटी दी। भारत के वैज्ञानिक विश्व भर के लिए एक मिसाल बने। हमारे देश में बनी वैक्सीन दुनिया के कई देशों गई। इसके चलते दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के प्रयास की सराहना करते रहे। कोरोना की सफल वैक्सीन ईजाद करके भारत ने सिद्ध कर दिया है कि मानव जाति की सेवा के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध है। कहना न होगा कि इन तमाम कारणों के चलते नरेन्द्र मोदी को लेकर देश में विश्वास का भाव बढ़ता ही जा रहा है जो 'चार सौ पार' के नारे को वास्तविकता में बदलने जा रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

मजबूरियां इंसान से क्या-क्या नहीं कराती!

मजबूरियां इंसान से चाहे जो करा ले, कम ही होता है। मजबूरियों के बस में इंसान क्या कुछ नहीं झेलता बद से बदतर स्थिति भोगता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की मजबूरियां आती जाती रहती हैं। उन मजबूरियों से अपने आप को डटकर मुकाबला करते हुए, उसके समाधान की दिशा में प्रयास करते हुए, उसे मजबूरी ना रहने दें और जीवन को सफल बनाने के लिए अपने कर्तव्यनिष्ठ सद्गुण से आगे बढ़े, क्योंकि जीवन में आफत बनकर आती मजबूरियों का धैर्य से सामना करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यह तो जानी-मानी सी बात है। मजबूरियों के बस में आदमी परेशान रहता है और उन परेशानियों से निजात पाने के लिए धैर्य के साथ लगना पड़ता है।तभी समस्याओं का मजबूरियों का निदान दिखता है।आदमी का जीवन मजबूरियों से बंधा है, आदमी मजबूरी के बस में होकर क्या से क्या न करता रहता है। परेशानियों का सबब मजबूरियां ही बनती है और इस मजबूरी के चलते लोगों को हजार कर्म करने पड़ते हैं। बावजूद इसके मजबूरियां दामन थामे रहती है। इस आधुनिक काल में लोग जिंसों और मिहनत की कीमत नहीं लेते, मजबूरियों की कीमत लगाते हैं। जरूरत के हिसाब से मौके का फायदा उठाते, दाम लगता है आज। जिस चीज का दाम दस रुपये होते हैं, मजबूरी में उसके दाम ऊंचा यानी दस का सौ रुपये हुआ बताया जा सकता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूर हैं, मजबूरियां इस कदर सितम ढाने लगी है कि लोग अब वेउवहार भूल चुके हैं।पैसे पर हर चीज चल रही है, जान हो या फिर जिंदगी सब कुछ पैसे पर टीक गया है। पैसा के चलते लोग क्या से क्या करने लग गए हैं।ईमानदारी को ताक पर रखकसर सिर्फ पैसा कमाने की चाहत रखने वाले लोग दुनिया में भर गये है। दुनिया पैसे पर ही चलती है, यह तो सभी जानते हैं।यह सब की बात है, आप हो या हम। पर जो कोई ईमानदार होता है, उसे यह सब सालता है, लगता है कि यह सब क्या हो रहा है, यह सब आज के आधुनिक जुग में जो बदलाव आया है, उसी का नतीजा दिखता है, जो नई पीढी आई है, वह बदलाव के साथ चल रही है। बदलाव भी ऐसा कि सब कुछ भुला कर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना। फिर उस पैसे को जिसी तिस तरह खर्च कर देना, यानी शानो शौकत में अपनी सुख-सुविधाओं में लगा देना। कमाना और खर्च कर सुख से जीने की चाहत रखना। हर तरह की जरूरतें पूरी हो।शानो शौकत बनी रहे, आज के लोगों का खास शगल बन गया है। विशेष कर युवाओं को इसका लत सा लग गया है और इसी को लत को लक्ष्य बना कर लोग जीना चाहते हैं, जी रहे हैं। इसी लक्ष्य के पीछे सभी भाग रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में चाहे जो कुछ भी करना पड़े, किसी का भी मन मान मयार्दा खत्म करना पड़े, वह तुरंत खत्म कर देते हैं। दोस्ती रिश्तेदारी समाज, परिवार सब इसी के पीछे लगे हैं, पैसा है तो सब कुछ है, वर्ना कुछ भी नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं । लोग पैसे की चाहत में किसी की भी जान लेना आसान बात समझते हैं। जीवन दे नहीं सकते, लेकिन पैसे के लिए जीवन ले सकते हैं। तो बात कर रहा था कि मजबूरियां अगर आपके सामने हैं, तो मजबूर होकर आपको वह सब कुछ करना ही पड़ेगो जो, आपकी मजबूरी का निदान है और यह मजबूरी सिर्फ खत्म हो सकती है, तो वह पैसे से ही खत्म हो सकती है।अब सवाल उठता है कि लोगों की मजबूरियों को जिस कदर भंजाया जा रहा है, वह कितना उचीत है? उसे रोकने वाला कौन है! कोई तो दिखता नहीं? सब्जी खरीदने जाइए वहां भी दस का सौ लेना दुकानदार चाहता है और आपकी मजबूरी है कि खरीदनी ही है, तो फिर खरीदिए! क्योंकि हर कोई आपसे आपके मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहता है और जब जमात के जमात लोग एक ही मकसद पाल रखे हो, तो फिर आपकी मजबूरी के किसी को क्या लेना देना।आपकी मजबूरी से आप को निजात दिलाने वाला कौन हो सकता है, हर जगह चाहे वह काम करने वाला मजदूर हो, रिक्शा ठेला चलाने बाला, ड्राइवर जो चार चक्का चलाता, सभी का अपना अपना हिसाब हो गया है। काम कम करना है और अधूरा कर पैसे की? मांग यह आदत में सुमार हो गया है। यह पूरी तरह से तो पैसे पर निर्भर हो गया है। लोग कहते हैं की दूध में जितना चीनी डालोगे, उतना ही मिठ होगा। मजबूरियां वेहिसाब हैं, डॉक्टर चिकित्सा किल्नीक, स्कूल शिक्षा का केंद्र यानी, यानी हर जगह, मजबूर अगर आप है, आपकी चाहत है, यही चीज खरीदनी है, यही नाम लिखना है, यही इलाज कराना है, तो फिर अगला जो है, वह आपको अपने हिसाब से चलाएगा हजार का दस हजार भी ले सकता है।अब इस महंगाई के जमाने में, सभी लोग महंगाई का रोना रोते है। सभी कहते हैं कि जमाना बदल गया, सभी मानते हैं कि सब ऊपर वाले का किया कराया है। अपनी जवाबदेही, अपनो का सम्मान, इमानदारी, सब कुछ ताक पर रख दिया गया है।वह जमाना आ गया है, जब लोग अपने अपने हिसाब से व्यवहार भी करने लगे हैं। हर जगह पैसे का बोलबाला हो गया है। हर कोई पैसे बटोरने में लगा है, अगले के पास कितनी मजबूरी है, इसकी कोई गिनती नहीं करता, अपने पैसे गिनने में ही लगा रहता है।आज ईमानदारी, सच्चाई, सज्जनता, सब कुछ भटका सटका चला जा रहा है। मिटता चला जा रहा है। ? मजबूरियों का जाल इस कदर लोगों को अपने में समेट कर चल रहा है कि लगता है, यह जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए ही बना है, पैसे पर ही मजबूरियों का निदान होना है। पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, पर पैसे के लिए आदमियता को भूल जाए, यह तो जरूरी नहीं दिखता? आदमीयता, ईमानदारी, सच्चाई, भी कोई चीज है, जिसे मनुष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योकि इस धरा पर अगर आए हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे काम, नेक दिल से करते रहे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी नेक नियति बनी रहे। मजबूरियां को भुनाए नही, उसका गलत फायदा उठाने की आदत से बाज भी आइए, वर्ना, मजबूरियों को बनाने की आदत लोगों में पड़ गई है और आदमी जब मजबूर होता है तो उसका फायदा आदमी उठाकर मजे लेता है लेकिन यह मजा सजा बनकर सिर्फ दूसरे के साथ नहीं अपनों के साथ भी हो जाता है। तो दुख सा लगता है और यही दुख अगर हम अपनी मजबूरियों को मिटाने का काम करते हैं, तो समाप्त हो जाता है।कभी न कभी आप भी शिकार बन ही जाएगें और गाएगें हाय मजबूरियों ने हमें मार डाला। सही तो यह होगा कि मजबूरी में एक दूसरे का साथ दें उनका हाथ पकड़े और उनके मजबूरियों को समाप्त करने की दिशा में स्वयं को लगाकर खुशी अर्जित करें यही जीवन का लक्ष्य है जो होना चाहिए वही करना चाहिए मजबूरियों को भुनाने में सही चुहिया होगा कि मजबूरी में एक दूसरे का साथ दें कहां तक है और उनके मजबूरियों को समाप्त करने की दिशा में स्वयं को लगाकर खुशी अर्जित करें यही जीवन का लक्ष्य है जो होना चाहिए वही करना चाहिए। मजबूरियां एक नहीं अनेक होती हैं। जो व्यक्ति को परेशानी में डालती रहती है और इन परेशानियों से आदमी परेशान तो रहता ही है। लेकिन व्यक्ति को जिस तरह से परेशानी परेशान करती है, उसी तरह से लग करके उसमें समस्या के निदान की दिशा तलाशनी चाहिए और कभी भी समस्याओं से उलझना नहीं चाहिए बल्कि उन समस्याओं को जो उलझ गए हैं, उसको अपने सूझबूझ से समझाने में अपने ज्ञान और बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल कर समझ कर सुलझाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह जीवन है और जीवन में एक नहीं अनेक समस्याएं आती है इन समस्याओं से निजातपाने का उपाय? ढुढ़ना ही श्रेष्ठकर कहलाता है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें समस्याएं हैं और समाधान भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और समाधान का प्रयास करते हुए डटकर मुकाबला करना चाहिए मजबूरी किसे नहीं परेशान करती लेकिन जो धैर्यवान होते हैं, वे मजबूरियों से पार पा लेते हैं। यह सत्य है और सत्य को नकारा नहीं जा सकता। मजबूरियां इंसान से ना जाने क्या-क्या करा लेती है।

प्रभात वर्मा

आधुनिकता के नाम पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पारिवारिक सिद्धांत तार-तार और खंडित हो जाय

किसी भी परिवार के तीन सदस्य परिवार व्यवस्था के लिए एक दूसरे का पूरक होता है। खुशहाल परिवार के लिए सम्पन्नता की सीढ़ी कहलाता है तीन सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल। परिवार में सदस्यों का रिश्ता ही नहीं बल्कि स्नेह, करुणा, प्रेम, और अनुभवों से भरा व्यक्तित्व होता है जो एक चुटकी में किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। इसलिए परिवार के तीन सदस्यों यथा दादा, पिता और पोता में मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पिता और पोता में मतभेद होता है तो दोनों के बीच शॉक ऑब्जर्वर (स्थिति संभालने वाले) दादा ही होते है। देखा जाय तो वर्तमान पीढ़ियाँ आर्थिक प्रबंधन, भाषा और व्यवहार, धन संचय के प्रति रवैया, पीढ़ियों की धारणायें, पहनावा में कपड़ों का चयन आदि तीन सदस्यों को स्वीकारने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि सही मायने में पिता का दादा के द्वारा पालन-पोषण कैसे किया गया है, यह कहीं न कहीं पोते की उसके पिता द्वारा की जाने वाली परवरिश पर गहरा असर पड़ता है। इस प्रकार परिवार के तीन सदस्यों में से दो इकाइयाँ काम करती है वह होता है दादा-पिता और पिता-पुत्र। परिवार में पिता और पुत्र रिलेशन मॉडल ही मुख्यतः काम करता है। पुत्र अपने पिता से साफ, सरल और स्पष्ट भाषा मेंआधुनिकता के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे बनाये गये पारिवारिक सिद्धांत तार-तार होकर खंडित हो जाए, अपनी बात कहने से न हिचकें, बात में हमेशा लचीलापन रखें। पिता की धारणाएँ पुत्र के लिए सिद्धांत हो सकता है, लेकिन उनकी बातों से अलग राय रखने में विनम्रता और अनुभवों का लाभ उठाने में भी नही हिचकना चाहिए। परिवार में पारिवारिक समस्याओं में भावनात्मक हेराफेरी सीखने से सभी को बचना चाहिए। दादा और पिता से बेहतर और घर में स्थापित मूल्यों के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। आधुनिकता के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे बनाये गये पारिवारिक सिद्धांत तार-तार होकर खंडित हो जाए, क्योंकि खंडित हो जाने पर घर में स्थापित मूल्यों के सिद्धांत को कायम करने में कई पीढ़ी गुजर जाता है। संयुक्त परिवार में ही आर्थिक प्रगति संभव होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में साथ रहने से एक मनुष्य को उसकी अलग धारणाओं के साथ तीन पीढ़ियों का उनके अलग-अलग सिद्धांतों के साथ एक दूसरों को स्वीकारने की ताकत विकसित होता है। देखा जाय तो वर्तमान समय में पूंजीवाद के चलते संयुक्त परिवार तेजी से समाप्त हो रहा है। पिता में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है की वे सदैव हमेशा धीरज से काम लेते हैं और कभी खुद पर से आपा नहीं खोते है। पिता हर परिस्थिति में शांत भाव से सोच समझ कर गंभीर से गंभीर समस्याओं में भी धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं और संयम के साथ निर्णय करते है। इसलिए पुत्र हमेशा पिता से सीखता है, अपने आप पर से नियंत्रण कभी नहीं खोना, क्योंकि पिता हमेशा संयमित व्यवहार कुशलता से हर कार्य को सफलतापूर्वक समाधान करते हैं। पिता हमेशा परिवार को अनुशासन में रहना सिखाते हैं और वे खुद भी अनुशासित रहते हैं। पिता घर के सभी कार्यों और परिवार के सभी लोगों और उनके स्वास्थ्य के प्रति, पूरी तरह सजग होते हैं। वे कभी भी छोटी-छोटी बातों को नजर अंदाज नहीं करते बल्कि हर बात को गंभीरता से लेकर उसका महत्व समझाते हैं। पिता परिवार के सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, और घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते और परिवार के सदस्यों की जरूरतें और फरमाइशें भी पूरी करते हैं। किसी भी प्रकार की गलती होने पर डांटने के बजाए प्यार से समझाते हैं और दोबारा गलती न करने की सीख भी देते हैं। देखा जाय तो पिता अपनी तकलीफ को किसी से शेयर नही करना चाहते है लेकिन किसी बात पर गुस्सा होने पर हमेशा कुछ देर गुस्सा दिखाने के बाद उसे माफ कर देते हैं और घर के लोगों की हर जरूरत और तकलीफ का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पिता की महानता और अधिक बढ़ जाती है और उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं किया जा सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिता प्रत्येक बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए धरती पर ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं, क्योंकि वे संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भुलाकर हर सुविधा देना चाहते है जो उन्हें भी कभी नहीं मिली हो। कई बार छोटी सी तनख्वाह में भी पिता कर्ज में डूब जाता हैं लेकिन बच्चों और परिवार के सामने कभी कोई परेशानी जाहिर नहीं करते हैं, इसीलिए पिता, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

दस्तक प्रभात
जितेन्द्र कुमार सिन्हा

"आधुनिक परिवेश में परिवार और समाज"

सांझ के सदन में सिंदुरी परिधान सम्पन्न सूर्यवंशी सनातनी समृद्ध इतिहास के शुभ्र सुरुचिपूर्ण चिंतना ने हमारी विस्मृत आस्था, व्यथा, व्यग्रता, व्यवस्था, अव्यवस्थित आंखों की विस्तृत गहराई तक परिवार और समाज की समृद्ध जड़ों के मौन को तोड़ता हुआ बोल उठा_ हम समृद्ध संस्कृति की सूर्यवंशी उपज हैं।हमी राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, हमी युधिष्ठिर, भीम, अर्जून, नकूल, सहदेव, हमी कृष्ण भी, हमी सुदामा भी। हमारे लिए विश्व मानव हमारे, हम विश्व मानव के।यही तो हमारे भारत-भूमी की सुगंध है। किंतु किसी भी वाग में उगे-लगे पौध का स्वस्थ, सफल वृक्ष होना, उसमें स्वस्थ-सुंदर मीठा फल लगना और तप्त जीवात्मा के मन-शरीर को उसके छांव में शीतलता प्राप्त होना उस वाग के मिट्टी और उसके माली के बोधवान के सजगता, सक्रियता और सुचिता का सम्मिश्रण के उचित संम्भावना पर निर्भर करता है। परन्तु आज को जीने में साफ-साफ दिखाई पड़ता, हम विस्मृत संस्कृति के टेढ़े-मेढ़े आंगन में पतझड़ पेड़ बनकर रह गए हैं। तब आज के तरुण-तरुणियों, इनके माता-पिताओं व वुजुर्गों के जीवन में जिज्ञासा जगी।तरुणाई और वृद्धावस्था के भाव-भंगिमा, वाणी में मेरी आंखें अटक गई। तब कहना पर रहा _इक्कीसवीं सदी "एकरार" का पहचान बन गया।लड़के-लड़कियां माता-पिता के लिए शौक बन गया। अपेक्षाएं चरम पर पाल रखा हैबच्चों में कि वह बाजार की हर वो चीज खरीद ले जो ऐय्यासी के साधन हों।जिस कारण हर पद, पत्नी, बच बच्चे सभी बजारू हो चुका।हद तो तब लगने लगा जब माता-पिता व वुजुर्गों को भी बजारू बना दिया गया। फिर भी खुद में परिवार और समाज को ढूंढता थक हारकर गुनगुनाता_ अब जीता कहां कोई हंसने के लिए! दौड़ रहा सभी कंकरों के ढेर लगाने के लिए!! हरप रहा जमीन वो बड़ा लकीर खींचने के लिए! धरम बन गया दुसरों का कद छोटा करने के लिए!!

खड़ा सभी रिश्तों के तपती रेत पर जलने के लिए! क्योंकि राख पर अपना स्मारक बनाने के लिए!! आज के बुद्धिजीवियों, सुविधाभोगियों के गढ़े गए शब्दकोषों, संसार के नित्य घटित घटनाओं को रटने और उन रटे रटाए शब्दों से पाया गया जीवन बाजार को खरीदने में तो भले सक्षम हो सकता है, पर यह जीवन परिवार और समाज के समन्वय बिना वेचारा ही बनकर रह जाता।जवानी जब दो शरीर में सिमटकर सुविधाओं का उपार्जन करने पर उतारु हो जाये, तो भले दुनियां के सर्वोच्चता को प्राप्त किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है।अलवत्ता यहां जीवन तो दूर की बात, प्राण की गति भी रूक जाती है। महत्वाकांक्षा के समुद्र में परिवार और समाज की कल्पनाएं चिल्लाते-चिल्लाते सो जाती है।सोते-सोते चिल्लाने लगता।जो कर रहा होता, वह होना नहीं चाहता।जो हो रहा होता, वह करना नहीं चाहता। अंदर झूठ पालना नहीं चाहता, जीवन झूठ को निकलने देना नहीं चाहता। सत्य अगर इनके पक्षकार हो भी जाय, किंतु आज के लोग सत्य के पक्ष में खड़ा हो नहीं पाता। प्रत्येक दुसरे में विलय हो जाता, पर अपना लय खो देता।

शवों के दुर्गंध में जीना अभ्यास बन चुका।कसाईखाने का पहरेदार बना घूमता।भागफल के खोज करते-करते जीवन ही खोता जा रहा होता। दु:ख तो तब और बढ़ जाताकिसी समृद्ध घने वृक्ष के छांव में थक-हारकर कोई अपने मन-शरीर को शीतल कर रहा होता, तभी इसी परिवार और समाज के दलाल पक्षियों की भांति उसी पेड़ के डालियों पर बैठ थके-हारे के सिर पर विष्टा करके उन तप्त जीवन को और तप्त करता अट्टहास के साथ कलरव करने लगता। तब उन पवित्र तप्त जीवन में करुणा बहने लग जाता आज के परिवेश में परिवार और समाज पर।हृदय में संवेदनाएं सजने लगती।भाव के भवंर में समय सिहरने लग जाता_ "नदी के जलधारा को अपने किनारे संयमित बहते देखा।" _"और असंयमित धारा से कटते किनारे की मिट्टी से जल धारा को मटमैला होते देखा।"_"खड़ा किनारे विशाल वृक्ष को जल समाधि होते देखा।"_"वृक्षों में लगे फलों से भूखों का पेट भरते देखा।"_"देवों पर चढ़ाये फूलमालाओं को जलधारा में फेंके गए फूलों की सुगंध से जलधारा को सुगंधित होते देखा।" _"सत्य के पक्ष में जीवन को परिभाषित होते देखा।" अंतः जो बोधवान होता, ऋचाएं उसी की कामना करती। सामगान उसी के पास आता।ऐसे बोधवान माली से सोम (परिवार और समाज भी)भी अपनी मित्रता में सुखपूर्वक रहता।

दस्तक प्रभात/सुनील कुमार सिंह

साइकिल दिवस पर विशेष

साइकिल की विरासत

3 जून, अर्थात विश्व साइकिल दिवस। इस अवसर पर मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल साइकिल की महत्ता को दशार्ती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे साइकिल हमारे जीवन में एक सच्चे साथी की तरह होती है। यह कहानी मेरे दादाजी, रामनाथ की है, जो 80 साल की उम्र में भी साइकिल फरार्टे से चलाते थे। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में साइकिल को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया था। दादाजी हमेशा कहा करते थे कि साइकिल ने उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्वतंत्रता दी थी। एक शाम, दादाजी अपनी साइकिल को साफ कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, जो उनकी आँखों की चमक में झलक रही थी। "मेरी प्यारी साइकिल, तुमने मुझे हर कदम पर साथ दिया है। तुम्हारे बिना मैं शायद यह सफर नहीं कर पाता, " दादाजी स्नेहपूर्वक साइकिल से बोले। ऐसा लग रहा था जैसे साइकिल भी उनकी बात सुन रही हो, उसका चमचमाता रंग और सही हालत यह बता रही थी कि उसे भी अपने मालिक पर गर्व है। दादाजी की साइकिल के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी, यानि मेरी दादी, को साइकिल पर बैठाकर एक दूर गाँव के मेले में ले गए थे। वहाँ उन्होंने फोटो खिंचवाए, झूला झूले और बायिस्कोप भी देखा था। "तेरी दादी और मैंने मेले में कुल्फी खाई थी और खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाया था। याद है, जब आम के पेड़ से कच्ची केरी तोड़कर रोटी के साथ खाई थी?" दादाजी ने हँसते हुए कहा, उनकी आँखों में उस समय की मिठास और चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक बार की बात है, जब दादाजी अपने काम से लौट रहे थे, किसी ने गलती से उनकी साइकिल को गिरा दिया। दादाजी को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत अपनी साइकिल के पास पहुंचे और उसे उठाया। "ओह मेरी प्यारी साइकिल, तुम्हें चोट तो नहीं लगी?" उन्होंने स्नेहपूर्वक साइकिल को संभाला और उसकी जांच की। साइकिल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दादाजी का दिल बहुत दुखी था। उनकी आँखों में आँसू थे, लेकिन उन्होंने साइकिल को प्यार से देखा और कहा, "तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे निराश होने दे सकता हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे साथी हो, जिसने मुझे कदम दर कदम साथ दिया है।" दादाजी ने हमेशा साइकिल के फायदों के बारे में बताया था। उनका मानना था कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। साइकिल चलाने से शरीर का व्यायाम होता है, यह हृदय के लिए लाभकारी है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। दादाजी कहते थे कि साइकिल चलाने से उनका वजन हमेशा नियंत्रित रहा और उन्हें कभी भी घुटनों या जोड़ो में दर्द की समस्या नहीं हुई। साइकिल चलाने से मानसिक तनाव कम होता है, दादाजी का मानना था कि जब भी वे साइकिल चलाते थे, उनका मन शांत और प्रसन्न रहता था। प्रकृति के साथ साक्षात्कार करना और ताजी हवा में साँस लेना उन्हें हमेशा तरोताजा करता था। आजकल के युवाओं के बारे में दादाजी की चिंता जायज थी। वे कहते थे कि आजकल के युवा साइकिल चलाने से बचते हैं और छोटी-छोटी दूरी के लिए भी मोटरसाइकिल या कार का इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और वे मोटापा, डायबिटीज और अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दादाजी का मानना था कि अगर हम साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो हम न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अचानक से, पोते की आँखों में आंसू की धार लग गई क्योंकि वो अब सिर्फ अपने दादाजी की फोटो को निहारते हुए उनकी कही गई बातों को याद कर रहा था। पोते की आँखों से अविरल अश्रु की धारा बहे जा रही थी। तभी उसके पापा भी आ जाते हैं और अपने बच्चे को इस तरह दादाजी की फोटो के सामने बतियाते हुए देखकर कहते हैं, "बेटा, चल आज 3 जून साइकिल दिवस है। तुझे दादाजी की बातें याद आ रही हैं न? तो, हम दोनों दादाजी की साइकिल को आज निकाल कर मंदिर जायेंगे। इस तरह साइकिल के रूप में दादाजी की स्मृतियां भी हमारे साथ होंगी।" उस दिन से बाप-बेटे ने नियमित साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल दिवस का यह अनोखा और भावुक आरंभ वास्तव में सार्थक हो गया। दादाजी की साइकिल उनके जीवन का हिस्सा बन गई, और इसने उन्हें न केवल स्वास्थ्य का वरदान दिया, बल्कि दादाजी की यादों को भी हमेशा के लिए जीवित रखा। तो आइए, इस साइकिल दिवस पर, हम सभी संकल्प लें कि हम साइकिल को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे और इसे अपने साथी के रूप में अपनाएंगे। दादाजी की साइकिल यात्रा हमें यह सिखाती है कि साइकिल न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाने में भी मदद करती है।

दस्तक प्रभात
डॉ मंगलेश जायसवाल

वेदों में पर्यावरण सुरक्षा

प्राणी जगत को सब ओर से आवरण देने वाली प्रकृति के अंग पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु आदि पर्यावरण कहे जाते है - परितः आवृणोति श्रीमदभागवत गीता में प्रकृति के उपरोक्त पाँच महाभूत के अतिरिक्त मन, बुद्धि एवं अहंकार रूप अंतःकरण त्रितय माने गये है । भूमिरापोनलो वायु: खं मनो वृद्धिरेवच । अहंकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट.. यजुर्वेद में धौ, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्वेदेव, और ब्रह्मा को पर्यावरण का अंग माना गया है तथा इनके शुभ होने की कामना की गयी है -- ओम धौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिःपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवःशान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिःशान्तिरेव शान्तिःसा मा शान्तिरेधि।। ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।। प्रदूषित पर्यावरण की भयावह विभिषिका से सूरक्षा हेतु वेदों में यज्ञ क्रिया का उपदेश दिया गया है । यज्ञ के पाँचों अंगों- समिधा, गोघृत, पात्र, मंत्र, भावना । समिधा के रूप में गाय के गोबर में ---- मेन्थाल, अमोनिया, फिनाल, इन्डाल, नाईट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास का अंश पाया जाता है । गोधृत से हवन करके वायु प्रदूषण को दूर किया जा सकता है । अथर्वेद-13/1/28 पिरामिड के आधार का हवन पात्र विधुत्त चुम्वकीय शक्तियों वाला होता है। अमेरिकीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा में पिरामिड ऊर्जा को ऊर्जा से अधिक क्रांतिकारी माना है । ध्वनि प्रदूषण के लिए वेद में मौन का आदेश दिया गया है- -- उन्मादिता मौन येन वार्ता आ तस्थिमा वयम्-ऋग्वेद (10/136/3) पर्यावरण के उपद्रवों में वायु तत्व, उसके सहायक रूप में अंतरिक्षस्य विधुत तत्व, सौर मंडलीय प्रभाव का वर्णन विस्तृत रूप से यजुर्वेद में पाया जाता है वैदिक विज्ञान के अनुसार 49 तरह के मरुदगण में सात प्रकार के भंयकर, विनाशक कृत्योदपादक वात में -- उग्र (प्रचंड तेज गति वाला), भीम (अत्यन्त भयानक) ध्यांत (शब्द करने वाला) धुनि (अत्यंत कम्पायमान) विक्षिप (पदार्थ को एक स्थान से दूर स्थान में फेकने वाला) अभियुग्वा (टक्कर मारने वाला) सासहवान (तोङ-फोङ करने वाला)का वर्णन है तथा उसके विनाशक शक्ति को नष्ट करने हेतु यज्ञ में स्वाहाकार पूर्वक आहुतियां प्रदान करने से इनकी प्रतिकूलता तथा विजयता नष्ट होती है -- (*यज्ञ महाविज्ञान पृ०-135) यज्ञ के हविद्रव्यों मैं गोघृत प्रधान है इसे आज्य कहा गया है । यह प्रदूषण रूपी विष का प्रतिरोधक एवं इसमें पर्तयावरण शोध शक्ति अतुल मात्रा में होता है । यज्ञ में घी प्रधान हव्यद्रव चावलों में मिश्रित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति दी जाती है, तब इस आहुति के जलने से उत्पन्न चार गैसे अभी तक पहचानी जा चुकि है--- (क) एथिलीन आक्साईड (ख) प्रापिलीन आक्साईड (ग) फार्मलडिहाइड तथा (घ) बीटा प्रापियो लेक्टोन आहुति के बाद गोधृत से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है जो प्रखर उष्णता की ऊर्जा है जो प्रदूषित वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है । अधुना भौतिकवादी युग में प्रदूषण से निजात पाना आसान कार्य नहीं है । फलतः यज्ञ महाविज्ञान पृष्ट-38-40 के अंतर्गत विशेष प्रक्रिया का विधान दशार्या गया है जो प्रदूषित स्थानों यथा प्रदूषण उत्पत्ति के स्थानों में प्रति एक वर्ग किलोमीटर या प्रतिफैक्टरी या जहाँ कल कारखाने नहीं है, वहाँ प्रति ग्राम में एवं प्रति एक वर्ग किलोमीटर के कृषिक्षेत्र के मध्य 23 मीटर का स्थान नियत कर6060 से.मी. लंम्बा चौरा गहरा कुण्ड जो चतुर्थांशरूप में 15 से.मी. लम्बा चौङा सम चौरस चतुष्कोण हो । इस यज्ञ में आम, पलाश, बिल्व, चंदन, पीपल, खादिर, विकडकत, आक, शमी, देवदारू, युकेलिप्टस एवं अन्य सुगंधीत वृक्षों के 25 से.मी.मोटी 24 टूकङे हो जिनमें---- 6 समीधा 18 से.मी. 6 समीधा 25 से.मी. 6 समीधा 37.5 से.मी .6समीधा 45 सेमी. हव्य द्रव्य मोटे कूटे 400 ˇ गो घृत 150 ग्रा० को मिला कर उसे 16 भाग करके एक-एक मीनट के अंतराल पर गायत्री, विश्वानि देव 24 और मृंत्युजय मंत्रों को पढते हुए स्वाहा के साथ डालनी चाहिए ।

समय सीमा--30 मीनट । प्रभावित क्षेत्र-एक किलोमीटर । इस प्रकार यह प्रयोग कारखानों, मिलों में कार्य करने वाले एवं प्रदूषण से पीङित व्यक्तियों में शारीरिक कार्य क्षमता तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि, रेबियम धर्मिता, अनुशक्तिजनित कुप्रभावों से रक्षण में सहायक होगा। बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति संवर्द्धन होने से जनजीवन अपराध प्रवृति रहित बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का उन्माद भी घटेगा । इति । माता भूमिः पुत्रोंरहं पृथिव्याः।

दस्तक प्रभात
डा० नीलिमा वर्मा "निशिता"

कविता

....कनफूँकबा

उल्टी-सीधी बात सुझाकर,
जो जग को भरमाता है,
करने वाला कान में ' फू'
'कनफूँकबा'कहलाता है।
'कनफूँकबा' के चलते ही,
लूटी नगरी वैशाली,
दर्श न होता यदि बुद्ध का,
जाती छीन अम्बपाली।
स्वहित की खातिर देखो,
दिन को रात बताता है,
करने वाला 'कान' में 'फू',
'कनफूँकबा' कहलाता है।
ज्ञानी साबित करके खुद को,
फूँक-फूँक पर के कान में,
कहता, हो गये सीख हमीं से,
हरदम रखना ध्यान में।
काम के बदले दाम लगाकर,
अपना काम बनाता है,
करने वाला 'कान' में 'फू',
'कनफूँकबा' कहलाता है।
छोटी बात को बड़ी बताना
उसकी सदा बिसात में,
अच्छे को बुरा बतलाना
कोशिश रहती हर बात में।
अपने फेरे में डाल देख वह,
मुस्की छोड़ मुस्काता है,
करने वाला कान में 'फू',
कनफूँकबा कहलाता है।
रत्नसेन राजा पड़ा था,
कनफूँकबा के फेर में,
पद्मावती रानी पटरानी संग
जौहर रखी एक बेर में।
भरे कान, भड़के इंसान,
लक्षण उसका बतलाता है,
कान में करने वाला 'फू'
कनफूँकबा कहलाता है।
उसका है लक्षण शनैःशनैः,
मीठ-मीठ बतियाना,
होते बाध्य हैं लोग भले,
उसकी बात पतियाना,
जैसे शरीफ बन किसी काम को,
अहा! कैसे फरमाता है!
कान में करने वाला 'फू'
'कनफूँकबा' कहलाता है।
दोष ढूंढ़ता फिरता पर में,
स्व में देख न पाता है,
स्वार्थ सधता नहीं देखकर,
देखो जमात बनाता है।
विशिष्ट बताकर रहता सबको,
हरदम वो बहकाता है,
कान में करने वाला 'फू',
'कनफूँकबा' कहलाता है।
बात परोसे ऐसे जैसे,
परम संत व ज्ञानी हो,
शान बघारे सामने सबके,
उसकी जैसे न सानी हो,
प्रजाति उसकी होती अलग है,
उसे द्वेष फैलाना भाता है,
कनफुक्का को समझ सके वह
प्राणी सफल कहलाता है।

दस्तक प्रभात/अनिल कुमार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 4 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

बड़े फैसले का दिन

कई विवादों के बीच 18वीं लोकसभा के लिये हुए मतदान के परिणाम मंगलवार को घोषित होंगे जिससे तय हो जायेगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है या जनता उन्हें हटाकर विकल्प के रूप में उभरे इंडिया गठबन्धन को सरकार का आसन प्रदान करती है जिसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। यह भी देखना होगा कि इंडिया गठबन्धन सरकार की ओर से कौन प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इन नतीजों को लेकर एक उत्सुकता और भी है, वह यह कि भाजपा द्वारा 370 तथा उसके नेतृत्व में बने एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस) के भरोसे 400 सीटें लाने का दावा कितना खरा उतरता है। हालांकि अब यह लड़ाई पार्टी एवं चेहरों से बढ़कर 'निरंकुशता बनाम लोकतंत्र' की हो चुकी है। इसलिये मंगलवार का दिन बड़े फैसले का है।

सात चरणों में चली मतदान प्रक्रिया समाप्त होते और नतीजों के आते-आते पूरा देश भीषण गर्मी में तप रहा है। कई लोगों की इसके कारण होने वाली मौतों के चलते केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का यह निर्णय (लम्बी प्रक्रिया का) सवालों के घेरे में तो है ही, उसकी भूमिका सतत संदिग्ध रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को अपनी प्रेस कांफ्रेंस में इसे एक गलती माना है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष को लगातार शिकायत रही है कि आयोग सीधे-सीधे सरकार के पक्ष में काम करता दिखा है। फिर वह चाहे चुनावी कार्यक्रम बनाने का मसला हो या फिर भाजपा के स्टार प्रचारक नरेन्द्र मोदी समेत बड़े नेताओं को मानो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने की छूट मिली हो। मोदी के लगभग सारे भाषणों में घोर सांप्रदायिकता की श्रेणी में आने वाले बयान थे लेकिन उनकी ओर से अनसुनी कर आयोग केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर चाबुक चलाने में तत्पर रहा। कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर तथा उसके अनेक पिछले कामों के बारे में खुल्लमखुल्ला झूठ बोलकर श्री मोदी ने चुनावी माहौल को बहुत ही विषाक्त बनाया। उन्होंने धर्म का भी भरपूर उपयोग किया ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके।

लगभग डेढ़ वर्ष पहले तक जिन मोदी एवं भाजपा के लिये 2024 का चुनाव बेहद आसान माना जाता था, उसकी तस्वीर राहुल गांधी की दो यात्राओं ने बदल दी। मोदी-भाजपा के बरक्स चेहरे, विमर्श तथा संगठन तीनों ही स्तरों पर विकल्प तैयार हुए। इतना ही नहीं, संयुक्त विपक्ष भी खड़ा हुआ जो थोड़ी बहुत कमजोरियों व प्रारम्भिक कठिनाइयों के बावजूद सत्तारुढ़ दल को मजबूत टक्कर देने में कामयाब दिख रहा है और इसी के बल पर माना जा रहा है कि 370-400 तो दूर की कौड़ी है, भाजपा को सरकार बनाने के भी लाले पड़े हैं। बहुमत के लिये आवश्यक 272 का जादुई आंकड़ा भाजपा की पकड़ से दूर दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का विवाद भी रहा है जिसे लेकर माना जा रहा है कि भाजपा को अगर कोई जीत दिला सकती है तो वे यही मशीनें हैं जिनके बारे में भाजपा, उसकी सरकार व निर्वाचन आयोग को छोड़कर सभी मानते हैं कि उसकी कार्यपद्धति दोषपूर्ण है। यानी वह जनता के फैसले को सही तौर पर वोटों में नहीं बदलती। इसकी बजाये पुरानी प्रणाली यानी बैलेट पेपर के जरिये ही मतदान कराने की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट गये वरिष्ठ वकीलों तथा लोकतंत्र के पक्ष में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों ने भरसक कोशिश की थी कि यह व्यवस्था या तो खारिज हो अथवा पूर्णत: दोषमुक्त हो; लेकिन बात बनी नहीं। इस चुनाव में भी ईवीएम सरकार के पक्ष में ही काम कर सकती है- इसका अंदेशा बहुतेरों को है। यह मतदान भी इसी संदेहास्पद मशीनों के जरिये हो रहा है इसलिये इंडिया के घटक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं व पोलिंग एजेंटों को चौकन्ना रहने को कहा है। हालांकि उनकी निगरानी की एक सीमा है और अगर मशीनों के भीतर दर्ज जनता के निर्णयों को किसी तकनीक के बल पर बदला जाता है तो वे सिवा स्ट्रांग रूम्स के बाहर पहरेदारी करने के कुछ और कर सकने की स्थिति में नहीं है। जो होना होगा, वह दूर किसी रिमोट कंट्रोल के जरिये हो चुका होगा।

बहरहाल, चुनाव होने के ऐन पहले आये एक्जिट पोल्स ने अलग तरह की सनसनी फैला दी है। सरकार के साथ गलबहियां करने वाले मीडिया घरानों ने 1 जून की शाम से जो रूझान दिखाये हैं, तकरीबन उन सभी ने एक स्वर में फिर से भाजपा की बड़ी जीत के अनुमान बतला दिये हैं। आरोप ये हैं कि सरकार के इशारे पर दरबारी मीडिया भाजपा व एनडीए के पक्ष में वही संख्याएं बतला रहा है जो पाने का दावा अपने प्रचार में मोदी सहित बड़े भाजपा नेता करते रहे हैं। यह संख्या 350 से लेकर 390 तक है। हालांकि इन आंकड़ों की पोल इस प्रकार भी खुल रही है कि मुख्यधारा का मीडिया कई राज्यों में उतनी सीटों पर परिणाम दर्शा रहा है जितनी सीटें हैं भी नहीं। असली बात यह है कि लोग इन फर्जी आंकड़ों को, जिनमें भाजपा-एनडीए की बड़ी जीत बतलाई जा रही है, एक बड़े षड्यंत्र से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस व इंडिया के नेता मानते हैं कि यह कोई बड़ी गड़बड़ी करने की पूर्व तैयारी का हिस्सा है। ये आंकड़े जारी करने के बाद अगर ईवीएम के डेटा में फेरबदल कर भाजपा को जिताया जाता है तो कोई शंका नहीं करेगा और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने पर उसे तवज्जो भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही कृत्यों से पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र को जैसा कुचला गया है, मंगलवार के परिणाम मुहर लगाएंगे कि जनता उसके खिलाफ है या मोदी-भाजपा को इसी तरह से अगले पांच सालों तक राज करने के अधिकार देती है। इसलिये यह बड़े फैसले का दिन है।

आगे और कठिन लड़ाई है!

हैरानी की बात नहीं है कि एक्जिट पोल के बाद, शेयर बाजार ने भी नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में, दोनों हाथों से मतदान किया है। आखिरी चरण के मतदान की शाम ही, एक्जिट पोलों ने करीब एक राय से मोदी का पुन: राज्याभिषेक कर दिया था। और उसके तीन दिन बाद, छुट्टी के बाद शेयर बाजार एक जबर्दस्त धमाके के साथ खुला। लेकिन, एक्जिट पोलों में मोदी को लगभग चार सौ पार करा दिए जाने पर शेयर बाजार खुशी से उछल नहीं पड़ा होता, तो ही हैरानी की बात होती। आखिरकार, मोदी राज ने अपने दस साल में शेयर बाजार को खुश करने में अपनी ओर से तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। उसने एक ओर तो शेयर बाजार के असली खिलाड़ियों यानी कारपोरेटों के हाथ मजबूत करने के लिए, नोटबंदी तथा जीएसटी के हमलों के जरिए, छोटे या अनौपचारिक क्षेत्र को कमजोर करने तथा उसकी कीमत पर औपचारिक क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है। और दूसरी ओर कॉरपोरेट करों में कमी कर के सीधे-सीधे कारपोरेटों की तिजोरियां भरने का काम किया है। और यह सब मोदी राज में दरबारी पूंजीवाद को फलने-फूलने के लिए आम तौर पर खुला तथा सुरक्षित मैदान मुहैया कराए जाने के ऊपर से है।

वास्तव में पिछले दस साल में मोदी राज और कारपोरेट पूंजी का जैसा अटूट और आक्रामक गठजोड़ देखने को मिला है, उसका और भी सघन प्रदर्शन इस बार के लोकसभा चुनाव के लंबे प्रचार अभियान के दौरान हो रहा था। यह कोई संयोग ही नहीं था कि विपक्षी गठबंधन द्वारा अपने प्रचार के दौरान, जिसमें कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टियों समेत विपक्षी गठबंधन के चुनाव घोषणापत्र भी शामिल थे, मोदी राज में असमानता में पहले कभी के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी होने के सवाल उठाए गए थे। और विपक्ष द्वारा दस वर्षों में कारपोरेटों के 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण माफ किए जाने, जबकि आम किसानों के ऋण माफ करने से इंकार ही कर दिए जाने के भी सवाल उठाए गए थे, जिन सब का जवाब, मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने, ध्यान बंटाने की तिकड़मों का सहारा लेते हुए भी, बड़े हमलावर अंदाज में देने की कोशिश की थी।

असमानता में बढ़ोतरी के सवाल का सीधे जवाब देने या खंडन ही करने के बजाय, मोदी की भाजपा ने इस तरह के सारे सवालों को ही संपत्ति पर हमला बना देने की कोशिश की। इसके लिए, कांग्रेस के घोषणापत्र में जातिगत जनगणना के पूरक के रूप में आर्थिक स्थिति का सर्वे कराने की जो बात कही गयी थी, उसे पूरी तरह से सिर के बल खड़ा करते हुए, आम लोगों की संपत्ति पर हमले में ही तब्दील कर दिया गया। और वैचारिक सुविधा के लिए इसे वामपंथ के साथ जोड़ते हुए, कांग्रेस के घोषणापत्र को एक ओर मुस्लिम लीग और दूसरी ओर अर्बन नक्सल के विचारों से संचालित करार दे दिया गया।

साधारण लोगों की संपत्ति पर विपक्ष के हमले का सरासर ऊटपटांग हौवा खड़ा करते हुए और इस थीम को लगातार आगे बढ़ाते हुए, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की आर्थिक स्थिति के सर्वे को, जाहिर है कि सोची-समझी तोड़-मरोड़ में मंगलसूत्र पर हमले, घर के सोने तथा जमा-जथा की जांच व जब्ती, दो घर हों तो एक घर की और घर में चार कमरे हों तो दो कमरों की जब्ती, तक पहुंचा दिया। चुनाव प्रचार के आखिर तक आते-आते तो यह सिलसिला विपक्षी सरकार आ गयी तो पानी के नल की टोंटी ले जाएंगे, घर की चाभी छीन लेंगे, बिजली वापस कटवा देंगे, आदि तक पहुंच गयी। इस सब का मकसद, अपने कारपोरेट तथा धन्नासेठ चाहने वालों को इसकी याद दिलाना भी था कि उनकी सबसे बड़ी हितैषी, मोदी की भाजपा ही है।

लेकिन, कारपोरेटों के स्वार्थों की रक्षा का भरोसा, सिर्फ

राजेंद्र शर्मा

असमानता में बढ़ोतरी के सवाल का सीधे जवाब देने या खंडन ही करने के बजाय, मोदी की भाजपा ने इस तरह के सारे सवालों को ही संपत्ति पर हमला बना देने की कोशिश की। इसके लिए, कांग्रेस के घोषणापत्र में जातिगत जनगणना के पूरक के रूप में आर्थिक स्थिति का सर्वे कराने की जो बात कही गयी थी, उसे पूरी तरह से सिर के बल खड़ा करते हुए, आम लोगों की संपत्ति पर हमले में ही तब्दील कर दिया गया।

कारपोरेटों के स्वार्थों की रक्षा करने के भरोसे से नहीं दिलाया जा सकता था। उसके लिए तो, मोदी राज जिस कारपोरेट-सांप्रदायिक गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, उसके दूसरे जोड़ीदार का भी खेल के मैदान में उतरना जरूरी था। आखिरकार, आम जनता को तो उसी के जरिए भ्रमित किया जाना था। इसलिए, एक्स रे करा के छीन लेंगे, झपट लेंगे के साथ, मुसलमानों को बांट देंगे का झूठ जोड़ दिया गया। इस तरह, इस चुनाव का मोदी की भाजपा के प्रचार का असली हथियार तैयार हो गया, जिसे कम से कम पहले चक्र के मतदान के बाद से लगाकर, आखिरी चरण तक और वास्तव में इस प्रचार अभियान के प्रधानमंत्री के पंजाब के आखिरी भाषण तक, लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा था।

बेशक, इस लंबे चुनाव अभियान के दौरान इस हथियार में जरूरत के मुताबिक थोड़ी-बहुत तब्दीलियां भी की गयीं। मिसाल के तौर पर एक तब्दीली तो यही की गयी कि इसकी शुरूआत में नाम लेकर मुसलमानों को बांट देंगे का आरोप लगाने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने संभवत: चुनाव आयोग को अति से अधिक शर्मिंदा नहीं करने के विचार से, अपने मुंह से मुसलमान शब्द तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन जेहादी, वोट जेहादी, जेहादी वोट बैंक, तुष्टीकरण वाला वोट बैंक आदि, तरह-तरह के शब्दों का प्रयोग कर, अपने श्रोताओं के लिए इसमें किसी संदेह की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी की उनका आशय, हिंदुओं से छीनकर मुसलमानों को दिए जाने से है। हां! आदिवासी बहुल इलाकों में इस हमले का विस्तार कर, ईसाइयों को भी इस दायरे में समेट लिया गया।

इन तकनीकी तब्दीलियों से भिन्न, जो खासतौर पर जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन से तकनीकी तरीके से बचने की कोशिश में की गयी थीं, एक बड़ी तब्दीली यह की गयी कि चूंकि आम तौर पर संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दिए जाने का प्रचार, गरीबों के विशाल हिस्से के बीच, जिनके पास खोने के लिए संपत्ति के नाम पर कुछ खास था ही नहीं, खास उत्तेजना पैदा नहीं कर पा रहा था, इसे जल्द ही आरक्षण का अधिकार छीनकर बांट देंगे कर दिया गया। यह मोदी की भाजपा की नजर में एक साथ दो काम करता था—मुसलमानों को निशाना बनाए रखकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का काम और सामाजिक न्याय के विपक्ष के मुद्दे को भोंथरा करने का भी काम। इसलिए, जल्द ही मंगलसूत्र आदि छीन लेंगे के समांतर, आरक्षण छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे की थीम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया।

इस चुनाव प्रचार के दौरान ही, ओवरसीज कांग्रेस के नेता रहे सैम पित्रोदा के अमरीका में कई राज्यों में विरासत कर लगा होने के उल्लेख का, मोदी ने विपक्षी गठबंधन के संपत्तियां छीन लेने के अपने झूठे प्रचार के लिए जमकर दोहन किया। लेकिन, पित्रोदा का बयान बाद में भले ही उनके लिए आसान बहाना बन गया हो, संपत्तियां छीन लेंगे का झूठा तथा निराधार प्रचार, खासतौर पर कांग्रेस के घोषणापत्र के जवाब में इससे पहले ही शुरू किया जा चुका था। विरासत कर के मुद्दे पर मोदी की भाजपा के हमलावर रुख ने, उसकी कारपोरेटपरस्ती को और भी बेनकाब कर दिया, क्योंकि किसी से छुपा हुआ नहीं था कि विरासत कर हर जगह, विरसे में बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने के मामलों में ही लागू होता है और इस तरह इस कर का आक्रामक तरीके से विरोध करने वाले, वास्तव में उंगलियों पर गिने जा सकने लायक धनपतियों के स्वार्थ के लिए, बढ़ती असमानता को ही बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे।

इस बार के असामान्य रूप से लंबे प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने, अपने राज की दरबारी पूंजीपतिपरस्ती के आरोपों का हमला कर के जवाब देने की कोशिश में, तेलंगाना में एक सभा में प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पर ही यह आरोप जड़ दिया था कि उसे अडानी-अंबानी से टैंपो में भर-भर कर काला धन मिला था! इस दावे का सरासर बेतुकापन अपनी जगह, विपक्ष पर हमला करने की कोशिश में, उन्होंने जिस तरह अपने शीर्ष दरबारी कारपोरेट घरानों पर कालिख लगा दी थी, उससे मोदी भी एक बार को तो कांप ही गए होंगे। तभी तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दोबारा उन्होंने विपक्ष पर प्रचार के लिए, इस हथियार का सहारा लेने की गलती नहीं की। उल्टे जैसे अपने प्रिय कारपोरेट मित्रों की नाराजगी दूर करने के लिए भी, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टुडे परिवार के साथ एक साक्षात्कार में, बढ़ती असमानता पर एक शाकाहारी से सवाल के जवाब में मजाक उड़ाने की मुद्रा में पूछा था—सब को गरीब बना देना चाहिए क्या?

नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा जिस नवउदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को देश में चला रहे हैं, वह अपने चरित्र में ही असमानता बढ़ाने वाली व्यवस्था है। बहरहाल, इस व्यवस्था के दायरे में, असमानता पर अंकुश लगाने के प्रयास की जो गुंजाइश थी भी, उसके लिए भी मोदी राज ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसके लिए विकास के लिए सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है—कारपोरेटों को प्रोत्साहन देना। विकास कारपोरेटों को ही करना है। और कारपोरेटों को प्रोत्साहन देने में, सस्ते से सस्ता, ज्यादा से ज्यादा अरक्षित श्रम मुहैया कराना भी शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि तथा लघु उत्पादन क्षेत्र की बर्बादी आदि सब यही सुनिश्चित करने के साधन हैं। मोदी राज बहुत ही वफादारी से कारपोरेटों के हित में और मेहनत-मजदूरी से गुजारा करने वालों के खिलाफ, काम कर रहा है। कारपोरेटों ने भी उसे लगभग पूरी तरह से एकजुट समर्थन देकर, इसका प्रतिदान दिया है। इलैक्टोरल बांड तथा अन्य कारपोरेट चंदे के भाजपा की टंकी में खुले पतनाले, इसका सबूत हैं। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बीच भी मोदी की भाजपा ने कारपोरेटों के हितों की रक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई है। कारपोरेटों की ओर से भी इसका प्रतिदान, आम तौर पर गोदी मीडिया के पूर्ण समर्पण, तत्काल एक्जिट पोल के तमाशे और अब शेयर बाजार में खुशी के ज्वार के रूप में सामने आया है।

अंत में चुनाव के नतीजे जो भी निकलें, देश और जनता को इस कारपोरेट दुश्चक्र से निकलने के लिए बहुत कठिन लड़ाई की जरूरत होगी। कांग्रेस से उठे रैडीकल सुरों से कुछ आशा तो जगती है, मगर ये सुर क्या नवउदारवादी पूंजीवाद के तर्क को चुनौती देने तक जा सकते हैं, यह कहना मुश्किल है। दूसरी ओर, नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी की अपनी कथित ध्यान साधना के बाद देश के नाम अपनी संदेशनुमा लंबी चिट्ठी से साफ इशारा कर दिया है कि उनका राज कायम रहा तो सुधार यानी उनके और उनके कारपोरेट मित्रों के रास्ते में आने वालों की खैर नहीं। कन्याकुमारी में ध्यान से निकले मोदी के ज्ञान का व्यावहारिक निचोड़ है—हमें समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से मुक्त कराना होगा! यानी तीसरा कार्यकाल मिला तो—आलोचक-मुक्त भारत!

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

नयी सरकार को अधिक निवेश और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा

■ अंजन रॉय

सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए जीडीपी के नये आंकड़े का इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। संसदीय मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के साथ ही, 2023-24 के लिए जीडीपी के 8.2प्रतिशत के आंकड़े आये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की भारी वृद्धि दर को दर्शाते हैं। यदि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए चुनावों में जीतती है, जो सबसे संभावित घटना है, तो वित्तीय बाजार में उछाल की भविष्यवाणी की जा सकती है।

लेकिन ऐसी गुलाबी तस्वीर के पीछे क्या रहस्य है, विशेषकर तब जब बाकी दुनिया बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। चीन एक तरफ़ गिर रहा है और गंभीर वित्तीय संकट की संभावनाओं से घिरा हुआ है। अमेरिका निश्चित रूप से पूरी तरह स्वस्थ है और ब्याज दरों में वृद्धि के दौर के बावजूद मंदी की सभी भविष्यवाणियों को झुठला रहा है। हालांकि, अमेरिका में नीतिगत ब्याज दरें बहुत अधिक बनी हुई हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास के ट्रिगर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, समग्र निवेश में परिवर्तन की गतिशीलता, अंतिम उपभोग मांग का रुझान, निर्यात प्रदर्शन और विदेशों से धन के प्रवाह को देखना महत्वपूर्ण है।

> सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 29त्न के करीब पहुंच गया है जो एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। यह कई कारकों से संभव हो सका है, जिसमें राजस्व संग्रह में मजबूत वृद्धि और वास्तव में अंतिम राजस्व संग्रह बजट अनुमानों से अधिक है। जीएसटी की आमद लगातार महीने दर महीने 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी अंतिम खपत एक प्रमुख कारक है, जो सकल घरेलू उत्पाद के व्यय पक्ष का लगभग 60प्रतिशत है। यह मूल रूप से अर्थव्यवस्था की गति निर्धारित करती है। वास्तव में, कुछ साल पहले कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि भारत की वृद्धि निजी उपभोग के रुझानों पर बहुत अधिक निर्भर थी और यह एक अस्थिर मॉडल था, जिसे 'एकल इंजन की सवारी' के रूप में वर्णित किया गया था।

अर्थव्यवस्था के निरंतर मजबूत प्रदर्शन के लिए संरचना और ट्रिगर्स में सूक्ष्म परिवर्तन हैं। ये रुझान कुछ सुखद गतिशीलता दिखाते हैं जो अर्थव्यवस्था को संभावित दलदल से बाहर निकालते हैं।

विकास की वर्तमान लहर निवेश द्वारा संचालित है, विशेष रूप से सार्वजनिक निवेश द्वारा। सार्वजनिक निवेश, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामाजिक पूंजी में सरकार के नेतृत्व में निवेश है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।

सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 29त्न के करीब पहुंच गया है जो एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। यह कई कारकों से संभव हो सका है, जिसमें राजस्व संग्रह में मजबूत वृद्धि और वास्तव में अंतिम राजस्व संग्रह बजट अनुमानों से अधिक है। जीएसटी की आमद लगातार महीने दर महीने 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी है। इसने सार्वजनिक वित्त को एक आरामदायक क्षेत्र में सक्षम बनाया है। व्यय में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा 5.6त्न पर बना रहा।

सरकारी वित्त को एक सहयोगी रिजर्व बैंक द्वारा और मदद मिली है। केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को अभूतपूर्व उच्च लाभांश हस्तांतरित किया है। केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित बड़े अधिशेष ने भी केंद्र सरकार की व्यय योजनाओं को आगे बढ़ाया हो सकता है, फिर भी विवेकपूर्णराजकोषीयघाटा मापदंडों के भीतर रह सकता है।

अगले ट्रिगर की बात करें तो, नवीनतम आंकड़े संकेत देते हैं कि घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है। कुछ उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े ऑटो बिक्री, आवास ऋण, ईंधन खपत जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि की तीव्र गति का संकेत देते हैं। ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के बावजूद मांग कुछ हद तक कम बनी हुई है।

तीसरा, निर्यात में वृद्धि हो रही है, हालांकि यह धीमी गति से हो रही है। पिछली तिमाही में नकारात्मक से व्यापारिक निर्यात सकारात्मक क्षेत्र में आ गया है। आयात भी बढ़ रहा है, जो मजबूत घरेलू मांग का संकेत देता है। सेवा निर्यात निश्चित रूप से उछाल पर है, हालांकि नयेएआई उत्पादों के उभरने के साथ कुछ अनिश्चितताएं उभरी हैं।

नीति निर्माताओं, अर्थात् आरबीआई और नॉर्थब्लॉक के लिए, सौम्य मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण स्थिति और भी आरामदायक है। अप्रैल 2024 में सीपीआईमुद्रास्फीति4.8त्न थी, जो मार्च 2024 में 4.9त्न से कम थी। जनवरी 2024 से इसमें गिरावट का रुख है। नीचे की ओर दबाव मुख्य रूप से पेट्रोलियम से संबंधित कमोडिटी समूहों जैसे ईंधन, बिजली और परिवहन और संचार सेवाओं से उत्पन्न होता है।

अनुकूल समग्र पृष्ठभूमि को देखते हुए, अगली सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अपने उत्साही संसाधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था की गति को बनाये रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि ये ट्रिगर बनाये रखे जाते हैं, तो यह समय के साथ बड़े निजी क्षेत्र के निवेशों में फैल जायेगा। निजी निवेश तब आते हैं जब उनकी क्षमता का उपयोग बढ़ रहा है और बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा है। व्यापार विश्वास सर्वेक्षणों और अन्य संकेतकों से संकेत मिलते हैं कि बड़े निजी निवेश के लिए भावनाएं सकारात्मक हो रही हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। वास्तव में, भारतीय निजी निवेश के साथ-साथ कुछ बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियां भारत में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाते हुए, अधिक निवेशक भारत के बारे में उत्साहित महसूस कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नयी शुरुआत की उम्मीद है वे हैं कंप्यूटर चिप और सेमीकंडक्टर उद्योग।

अब तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन तकनीकी प्रकृति की टिप्पणियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि जीडीपी डिफ्लेटर, यानी वह तरीका जिससे सांख्यिकीविद् वास्तविक जीडीपी रुझानों पर एक नज़र डालने के लिए जीडीपी आंकड़ों पर बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभावों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उदार रहा है।

इन अर्थशास्त्रियों को लगता है कि अंतिम आंकड़ों की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीडीपी डिफ्लेटरसीपीआई संख्याओं की तुलना में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों को अधिक महत्व देने के लिए बहुत कम था। डब्ल्यूपीआई रुझान बहुत कम और कभी-कभी नकारात्मक रहे हैं, जबकि सीपीआई 5.4 प्रतिशत के आसपास मंडरा रहा है। वे सीपीआई के नेतृत्व वाले के खिलाफ डब्ल्यूपीआई भारी प्रतिनिधि के उपयोग पर सवाल उठाते हैं। पूर्व में सीपीआई भारी डिफ्लेटर का उपयोग करने की तुलना में विकास की दर कहीं अधिक है।

फिर भी, कुछ तकनीकी मुद्दों को छोड़कर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने कदमों में उछाल दिखा रही है। अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है और प्रतिकूल वैश्विक वातावरण में कोविड के बाद के चरण में तेजी से सुधार किया है। इन रुझानों को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की गति मजबूत बनी रहेगी और वित्तीय बाज़ार भी इसी तरह की बढ़त दिखा सकते हैं।

पावन प्रसंग

आचार्य शंकर को जब हुआ तत्वज्ञान

अपने गुरु गोविंदजी की आज्ञा को शिरोधर्या कर आचार्य ने विश्वनाथ के दर्शन करने काशी के लिए प्रस्थान किया। नर्मदाजी के तट से महीनों पैदल चलकर काशी पहुंचे। काशी आकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करके वे अभिभूत हुए, आह्लादित हुए, आनंदित हुए। भगवान विश्वनाथ के दर्शन मात्र में उनके रोम-रोम पुलकित हो उठा। भगवान के दिव्य दर्शन को उन्होंने अपने लिए अपने गुरु गोविंद भगवान विश्वनाथ की साक्षात कृपा माना। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु व भगवान विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम किया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के बाद वे काशी के मणिकर्णिका घाट के समीप एक स्थान पर रहने लगे। यहां रहते हुए उन्होंने कुछ जिज्ञासु विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा देना भी आरंभ किया।

आचार्य शंकर की अवस्था उस समय मात्र बारह वर्ष थी, पर उनका असाधारण पांडित्य देखकर काशी की विद्वानमंडली चकित हो गई। उनके असाधारण पांडित्य व ज्ञान से अभिभूत हो कई विद्वान उनके शिष्य बनने लगे। अद्वैत का जो अर्थ आचार्य शंकर ने अपने गुरु गोविंदपाद से सुना था- उसी की व्याख्या वे नित्य अपने छात्रों के सामने करते रहे। आचार्य की विद्वता से प्रभावित होकर अन्य अनेक छात्र भी उनसे अद्वैत वेदांत का ज्ञान ग्रहण करने लगे।

एक बार यहां एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था। आचार्य शंकर अपने विद्यार्थियों के साथ मध्यान्हकालीन पूजा उपासना के लिए गंगातट पर जा रहे थे तभी उन्होंने रास्ते में चार भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक भयंकर व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति आचार्य शंकर का रास्ता रोककर खड़ा था। आचार्य ने उन्हें रास्ते से दूर हट जाने के लिए कई बार कहा, पर रास्ते से हटने के स्थान पर वह बोले- आप संन्यासी हैं। आप विद्यार्थियों को अद्वैत तत्व की शिक्षा देते हैं, परंतु आपका मुझे आपके रास्ते से दूर हट जाने को कहना यह सूचित करता है कि आपने अद्वैत का तत्व कुछ भी नहीं समझा है। जब इस जगत का कोना- कोना उसी सच्चिदानंद परम ब्रह्म से व्याप्त हो रहा है तब कौन किसे छोड़ कर कहां जाए? कौन किसके रास्ते से दूर हटे? आपका ऐसा मानना भी तो आपका दुराग्रह ही है। उस व्यक्ति के मुख से ज्ञान की ऐसी बातें सुनकर आचार्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

तब आचार्य शंकर ने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा- जो चैतन्य विष्णु-शिव आदि देवताओं में प्रस्फुटित हो रहा है वही हर जीव में भी प्रस्फुटित हो रहा है। उसी चैतन्य को जो अपना स्वरूप समझता हो ऐसा दृढ़ बुद्धिवाला पुरुष चाहे कोई भी हो वह मेरा गुरु है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। दरअसल उस व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान शंकर आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने प्रकट हुए थे। इस प्रकार आचार्य की परीक्षा लेकर आचार्य के चिंतन में जो त्रुटि थी, उसे भगवान विश्वनाथ ने दूर कर दिया। भगवान शिव आदि गुरु हैं अपने शिष्य आचार्य शंकर की त्रुटि को दूर कर वे आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने स्वयं प्रस्तुत हुए। तब उस समय उस व्यक्ति का रूप त्यागकर विश्वनाथ अपना दिव्य शरीर प्रकट करते हुए बोले- वत्स, शंकर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार इस जगत में संपन्न करूं। तुम्हारे में किसी प्रकार की न्यूनता कमी या त्रुटि होना उचित नहीं है। जाओ तुम व्यासकृत ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य की रचना करो। वेदान्त का मुख्य तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन है, इसका सर्वज्ञ प्रचार करो। तुम्हारे इस शरीर से जो कार्य संपन्न होगा उसे मेरा ही कार्य जानना।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

आज कत्ल की रात कल ठंडे होंगे ताज़िए!

चुनाव परिणामों की तारीख आखिरकार आ ही गई-चार जून दिन मंगलवार। मतलब कल ताज़िए ठंडे हो जाएंगे। किसके? यह शायद सत्तारुढ़ पार्टी को ही पता है। आम जनता तो भौंचक रह जाती है परिणामों से। भाजपा के ज्योतिष के गर्भ में जो जीत का जादू छुपा हुआ है उसे जनता भली-भांति समझने लगी है इसलिए कह देती है वोट कहीं भी दो जीतेगा तो भाजपा ही हैं। एक्जिट पोल में यही बात सामने लाई जाती है वह जनता के व्यंग्य को सच मान लेते हैं। वस्तुत: अब तक वे जितनी जीत की सीट बताते हैं उतनी ही आती रही हैं। ये कैसे संभव होता है? ये तो चुनाव आयोग जाने। कोई विज्ञान गणित का सूत्र भी ऐसा नहीं कर सकता है।

मगर अब की बार चार सौ पार का नारा अचरज भरा लगता है। इतनी बड़ी कारगुजारी करने वाले ही भगवान का ध्यान लगाकर बताने की चेष्टा करते हैं यह सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। फिर जब कथित अवतारी ही साक्षात ध्यान लगा रहा हो तो सब मुमकिन है। बेशक हिंदुस्तान भी गजब का देश है। वह आज की सुख-सुविधा की अपेक्षा अगले जन्म के सुख के लिए मंदिर और बाबाओं का रुख करता है। रामजी आ गए हैं और क्या चाहिए?

इस सब के बावजूद देश में बहुत खलबली है। एक्जिट पोल शायद गलत हो जाएं क्योंकि जनता ने अपना बहुसंख्यक मत सरकार के ख़िलाफ़ दिया है। कुछ लोगों को भरोसा है सुप्रीम कोर्ट की डांट डपट के बाद चुनाव आयोग धांधली नहीं कर सकता। ये विश्वास देखिए इस बार कायम होता है या फिर टूटता है। क्योंकि गोदी मीडिया तो मोदीजी की हैट्रिक की घोषणा कर ही चुका है विपक्ष निराश ना हो ताज़िए उन्हीं के ठंडे होने जा रहे हैं जो जबरन जीत के ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल बात ये है इंडिया गठबंधन की स्थिति सुदृढ़ है। मानसिक तौर पर उसे परास्त करने का ये एक बड़ा और अंतिम हथकंडा है। मतगणना स्थल पर उपस्थित विपक्ष कड़ी नज़र रखें। परेशान ना हों। निडर होकर चुनौती का सामना करें। कोई समझौता कहीं ना हो पाए सतर्कता ज़रूरी है।

इंडिया गठबंधन ने जिस तरह के दौर में चुनाव लड़ा है वह ऐतिहासिक कठिन वक्त रहा जब विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई आईटी जैसे संस्थानों ने भरपूर सताया है। गठबंधन के दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सांसदी ख़त्म की गई, निवास छीना गया, उनकी बीमार मां से ईडी ने घंटों निरर्थक बकवास की। नफ़रत का भाव उनके ख़िलाफ़ पैदा किया गया लेकिन इससे जनता में उनकी लोकप्रियता ख़ूब बढ़ी। यह भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और चुनाव प्रचार के दौरान दिखी। वह तो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सरकार बदल रही है। इंडिया को अब इंडिया गठबंधन संभालने जा रहा है। यह विश्वास गठबंधन के सभी नेताओं ने जतलाया है।

दूसरी ओर सरकारी मशीनरी के साथ सरकारी धन के प्रलोभनों की खैरात और विपक्षी नेताओं पर जबरिया भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ने वाली सरकार, राफेल दलाली से लेकर चुनावी बांड की बिक्री, पीएम केयर फंड, नकली वेक्सीन आदि में खुद भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। जीती हुई सरकारों को धन की बदौलत तोड़ने वाली तिकड़मी सरकार एक बार चुनाव परिणामों में धांधली के लिए एक्जिट पोल का सहारा ले रही है। इसका मुकाबला वक्त पर सक्षम पहल कर ही करना होगा। जनमत आपके साथ है तो डरना कैसा? चोरों की बारात से डर कैसा? एक बुजुर्ग का कहना है- मंगलवार रामभक्त हनुमान का दिन है और उनकी गदा नकली रामभक्तों पर कहर ढाने वाली है। देखें क्या होता है?

-सुसंस्कृति परिहार

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

उक्ति

वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं। जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं। अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं। अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। नीच लोगों से धूर्तता पूर्ण व्यवहार करते हैं। विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते। दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं। बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं।

चाणक्य

पटना, मंगलवार, 04 जून 2024
www.live7tv.com

सचेतक है खडूर साहिब से उठती टीस

ज्योति मल्होत्रा

यह जानने के लिए आपको खडूर साहिब चुनाव क्षेत्र जाने की जरूरत नहीं कि क्योंकर सुदूर डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैद और आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए अमृतपाल सिंह के पक्ष में जीत की हवा चलती महसूस हो रही है और हो सकता है वह जीत भी जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 51 की ट्रैफिक लाइटें पार करके, चंडीगढ़-मोहाली की सीमा पर बुजुर्ग सिखों का समूह पिछले डेढ़ साल से वहां टेंटों को लगाकर धरने पर बैठा है, जिसका मकसद दशकों से जेल में बंद 22 सिख बंदियों की रिहाई की तरफ ध्यान दिलवाना है। जो कोई इस झुलसा देने वाली धूप में धरना देने वालों तक पहुंचे, उसे अंग्रेज सिंह नामक शख्स मीठे गर्म दूध का कप थमाता है। करनाल से सिख किसानों का एक जत्था उनका साथ देने इतनी दूर आया है। बातचीत का विषय केंद्र सरकार (यानी भाजपा) का पंजाब के प्रति भेदभाव पर आने में देर नहीं लगी, जिसके मूर्त रूप में दिखाने को वे बंदी सिंह प्रसंग से लेकर भिंडरांवाले का अवतार कहे जाने वाले अमृतपाल सिंह के प्रति अन्यायपूर्ण रुख का जिक्र करते हैं। सड़क के पार, खाली टेंटों और कुछ होर्डिंगों पर जरनैल सिंह भिंडरांवाले, दीप सिद्धू, अमृतपाल सिंह और बेअंत सिंह (इंदिरा गांधी का कातिल) इत्यादि के पोस्टर लगे हैं। एक पोस्टर के आधे भाग में, भिंडरांवाले के अगल-बगल में हरदीप सिंह निज्जर और जसवंत सिंह खालरा दिखाए हैं तो बाकी हिस्से में बीवी-बच्चों सहित कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के परिवार का चित्र है, जिस पर गुरुमुखी में धन्यवाद कनाडा लिखा है। जब आपका आईफोन गर्मी के कारण तपकर काम बंद करने की कगार पर हो और वक्त मानो थम गया हो, एकबारगी, कुछ पल के लिए, हैरानी होती है कि क्या यह 1984 का मंजर है (जब ऑपरेशन ब्लूस्टार हुआ) या 1988 (ऑपरेशन ब्लैक थंडर) या वर्तमान 2024 का दृश्य है। आपके समक्ष पंजाब के अवांछितों की चित्र वीथी है और सूचनाओं की मानें तो इनमें एक भावी सांसद भी हो सकता है। लेकिन गर्म होते अपने आईफोन और स्व को संभालिए। अधिकांश टेंट खाली पड़े हैं और कुछ बुजुर्ग किंतु अत्यंत वाकचातुर्य से लबरेज यह टोली इस पकी उम्र में भी तपती दोपहरियों को झेल रही है। वे कहते हैं, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमें हमारे हक चाहिए, बंदी सिंहों को घर जाने दिया जाए, वे बहुत लंबी सजा जेल में काट चुके हैं। यहां तक कि कुंभकर्ण भी कुछ महीनों बाद जाग जाता था लेकिन यह सरकार जागने का नाम नहीं ले रही। अमृतपाल सिंह को अकारण गलत समझा जा रहा है, वह तो केवल इतना चाहता है कि सिख समुदाय में सुधार हो, वह युवाओं को नशे से दूर करना और उनकी मांओं के आंसू पोंछना चाहता है। वह खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। जो भी है, भारत में वे भी तो हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। लेकिन उनकी यह टीस दोपहर की भीषण गर्मी में तुरंत भाप बनकर उड़ भी जाती है। यहां तक कि इन बुजुर्गों को भी यह अनकहा सच मालूम है कि यदि खडूर साहिब, फरीदकोट और संगरूर, जहां से क्रमशः अमृतपाल, इंदिरा गांधी के कातिल बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा और अकाली दल (अमृतसर) के मुखिया सिमरनजीत सिंह मान प्रत्याशी हैं, उन्हें पृथक राष्ट्र खालिस्तान का बिल्ला तो तभी उतारकर रखना पड़ गया जब चुनाव पर्चा भरते वक्त उन्होंने भी तमाम प्रत्याशियों की तरह भारत के संविधान की रक्षा करने की शर्त पर सहमति जताई। अस्सी के दशक की भयावहता का सबक यही है कि आज इन तीनों को, विशेष रूप से सिमरनजीत सिंह मान को- जिसने विगत में चुनाव तो बहुत लड़े किंतु जीत केवल 1989 में मिली,पता है कि अपने श्रोताओं-समर्थकों को प्रभावित करने को उनके पास बोलने, अभिव्यक्ति और विरोध करने का जो हक है, वह भी संविधान में दी गई गारंटी की बदौलत है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती यह कि वह इन जैसों को इस प्रक्रिया से अंतिम छोर तक छूट लेने की इजाजत देती है और फिर जब वे इसे और अधिक न खींच पाएं तो अपनी वापसी पुनः केंद्र (मुख्यधारा) की ओर करने की इजाजत भी देती है। स्पष्टतः यह तीनों अपने आदर्श पुरुष और विचार स्रोत भिंडरांवाले से कहीं अधिक चतुर हैं, जिसने झुकने की बजाय टूटना चुना। सिमरनजीत सिंह को 2022 के संगरूर संसदीय उपचुनाव में बमुश्किल यानी महज 5000 वोटों के फर्क से विजय तब मिली जब उसी वक्त भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने। यही कारण है कि पंजाब में मुख्यधारा की राजनीति जीवित है और अच्छी तरह चल रही है। अगरचे खडूर साहिब की सीट संभावित पृथकतावादी अमृतपाल सिंह जीत गया तो दुनियाभर का मीडिया वहां पहुंचकर पंजाब को अविवेकी, संवेदनहीन और अज्ञानता भरी तूलिका से रंगने लगेगा- जबकि तथ्य यह है कि पंजाब के 2.14 करोड़ मतदाताओं ने पहले ही मध्यमार्ग चुन रखा है। वहां असल लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच है क्योंकि मुद्दे असली हैं अर्थात? वह कृषि संकट जो स्थाई हो चला है। औद्योगिकी तरक्की के लिए माहौल अनुकूल नहीं। पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है। जनसंख्या बुढ़ाती जा रही है और गांव युवाओं से खाली हो रहे हैं। खडूर साहिब के इर्द-गिर्द की भावावेश वाली नाटकीयता में दरअसल संभावित सिविल-नाफरमानी-आंदोलन की आहट छिपी है। राजसत्ता के अहंकार का मर्दन करने में, पंजाब की प्रतिरोध वाली प्रवृत्ति रही है। पंजाबी बंदा खुद को भारी नुकसान के बावजूद शांतिपूर्ण विरोध करने को तैयार रहता है। 2020-21 में किसानों द्वारा दिल्ली की घेराबंदी इसकी एक बानगी है। माना जाता है कि मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानून वापस लिए जाने पर सहमति से पहले इस आंदोलन में लगभग 750 किसानों की मौत हुई। हालिया हफ्तों में, जैसे-जैसे चुनाव प्रचार मुद्दाविहीन होता चला गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा अड़ियल रवैया अपनाने से क्षुब्ध हुए किसानों ने न केवल भाजपा प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाकर नाराजगी जताई बल्कि उन्हें गांवों में न घुसने देने पर अड़ गए। पंजाबियों की एक पुरानी मांग यह भी है कि अटारी-वाघा और हुसैनीवाला सीमा को पाकिस्तान से व्यापार और बेहतर रिश्तों के लिए पुनः खोला जाए। तथापि, कदाचित यह समय है खडूर साहिब से उठती टीस पर ध्यान देने का। जो कह रही है, हमसे संवाद कीजिए, चीजों को अलग ढंग से करें, मानो दिल्ली के तख्त पर जल्द बैठने जा रहे शासक से पंजाब कह रहा हो, हमें आखिरी हद तक न धकेलें, हम भी वहां तक जाना नहीं चाहते।

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

समृद्ध हुआ लोकतंत्र

आखिरकार सबसे लंबी अवधि वाले चवालीस दिनी आम चुनाव का समापन शनिवार को 57 सीटों पर मतदान के साथ हो गया। झुलसाती गर्मी व तूफान के बावजूद सात चरणों वाले लंबे चुनाव अभियान में मतदाताओं का उत्साह दुनिया को भारतीय लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। बड़ी-बड़ी रैलियों, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों में मतदाताओं की उपस्थिति भारतीय लोकतंत्र के उज्ज्वल भविष्य को ही दर्शाती है। बेहतर होता कि बेहद जटिल मौसमी परिस्थितियों में यह चुनाव कार्यक्रम इतना लंबा न होता। छिटपुट हिंसा घटनाओं को छोड़कर कमोबेश यह चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि तमाम सांस्कृतिक, भौगोलिक व राजनीतिक रुझान में विविधताओं वाले इस देश में आज भी चुनाव प्रक्रिया विश्वसनीय मानी जाती है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से वर्षों से सक्रिय चुनाव आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान से मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ता है। भारत को यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता। हमारी 18वीं लोकसभा के लिये संपन्न चुनाव में विश्व का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग सक्रिय रहा। देशभर में कुल 96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत रहे। इतने बड़े मतदाता वर्ग के लिये सुगम मतदान की व्यवस्था करना निश्चित ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन एक बात तय है कि 19 अप्रैल को शुरू हुए पहले चरण के मतदान से शनिवार को संपन्न सातवें व अंतिम चरण के मतदान कार्यक्रम को यदि कुछ सप्ताह कम किया जाता तो मई के अंत की भीषण गर्मी से मतदाताओं को दो-चार न होना पड़ता। कई राज्यों से चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लू से मरने की विचलित करने वाली खबरें भी आईं। वहीं लंबी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आचार-संहिता लंबे समय तक लागू रहने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। बहरहाल, चुनाव कार्यक्रम निर्धारण को केंद्र में सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकता भी प्रभावित करती है तो वहीं कानून-व्यवस्था व कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी चुनाव कार्यक्रम को लंबा बनाती हैं। बहरहाल, एक बात तय है कि चुनाव चरणों का लम्बा समय व मौसम की प्रतिकूलताएं मतदाताओं को उदासीन बनाती हैं। कुछ चुनावी पंडित मतदान प्रतिशत में पिछले बार के मुकाबले गिरावट आने की यही वजह बताते हैं। वहीं विश्वसनीयता खोते राजनेता तथा नकारात्मक चुनाव प्रचार भी मतदाताओं की चुनावों में दिलचस्पी को कम कर देता है। लेकिन इसके बावजूद हालिया तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल के दुर्गम इलाकों लाहौल-स्पीति तक में मतदाताओं ने उत्साह से चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। इस बार के चुनाव में एक सकारात्मक पक्ष यह भी दिखा कि वयोवृद्ध व अशक्त लोगों को घर से मतदान करने का अवसर मिला। चुनाव ड्यूटी में लगे करोड़ों कर्मचारियों का डाक से अपना मतदान करने का उत्साह भी लोकतंत्र की खूबसूरती को ही दर्शाता है। अभी भी मतदान प्रक्रिया को और अधिक मतदाताओं के अनुकूल बनाने की जरूरत है।

समावेशी विकास को गति देते हुनरमंद

सतीश सिंह

मौजूदा समय में शिक्षा और कौशल विकास के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है। शिक्षा के माध्यम से कौशल का विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे अकादमिक कल-कारखानों से लाखों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए आदि की भारी-भरकम डिग्रियां लेकर युवा बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कौशलयुक्त एवं ज्ञानवान नहीं हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन होनहार के लिए रोजगार की कमी नहीं है। तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले, भले ही डिग्री एवं अंग्रेजी के मामले में पीछे होते हैं, लेकिन वे हर किस्म की मुश्किलों को आसानी से सुलझा सकते हैं। किसी कार्य को करने के लिए डिग्री से ज्यादा कौशल की जरूरत होती है। हमारे देश के स्कूल व कॉलेज के अध्यापकों का मानना है कि जो बच्चा लगातार हर परीक्षा में अव्वल आ रहा है, उसी को सिर्फ होनहार माना जा सकता है। इसमें दो मत नहीं है कि स्कूल-कॉलेजों में प्राप्त अच्छे अंक छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, किंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम इसे मेधावी होने या न होने का प्रमाण मानें। किसी विषय में कम या ज्यादा अंक प्राप्त करने से किसी भी छात्र को मेधावी या कमअक्ल नहीं माना जा सकता है। हर विषय में हर छात्र की रुचि का होना जरूरी नहीं है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की रुचि केवल भौतिक विज्ञान में थी। महान वैज्ञानिक अलबर्ट आइंस्टीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लता मंगेशकर की भी गणित या विज्ञान में रुचि नहीं थी। सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी का अकादमिक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में महान हैं। समाज में ऐसे जीनियसों के सैकड़ों उदाहरण हैं। दूसरा पहलू यह है कि परीक्षा के समय में कोई छात्र बीमार हो सकता है या फिर उसकी रुचि पढ़ाई के प्रति गलत संगत के कारण शुरूआती दिनों में नहीं हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे छात्र सही वक्त पर मेहनत करके हमेशा जागरूक रहने वाले छात्रों से जीवन की परीक्षा में बाजी मार लेते हैं। यहां फंडा जब जागा तभी सवेरा वाला काम करता है। जिस छात्र के अंदर जीवन में सफलता हासिल करने की जिजीविषा जाग्रत हो जाती है वह हर कक्षा में तृतीय या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बावजूद आईएएस की परीक्षा में शीर्ष 20 या 50 में स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। नौकरी को यदि सफलता का पैमाना नहीं भी मानें तो भी ऐसा कुछ करने के लिए कृत संकल्पित छात्र जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने में सफल हो जाता है। फिल्म थ्री इडियट्स में दिखाये गए दर्शन को भी हम नकार नहीं सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। आज दुनिया में करने के लिए इतने सारे क्षेत्र हैं कि आप किसी बच्चे को कमतर नहीं मान सकते हैं। यह बस आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप किसे होनहार मानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने वर्ष, 2013 में पहली बार प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के अंकों को सार्वजनिक किया था, जिसमें 1004 अभ्यर्थी सफल हुए थे और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ने समग्र रूप 53 प्रतिशत अंक हासिल किये थे, जबकि अंतिम पायदान पर सफल रहने वाले अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे। पूर्व में यह धारणा थी कि यूपीएससी की परीक्षा में 75 से 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही सफल होते हैं। यूपीएससी की बात छोड़ दें तो अभी भी बहुत सारी सरकारी एजेंसियां मसलन, राज्य सेवा आयोग, बैंक, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग आदि सफल उम्मीदवारों के अंकों को सार्वजनिक नहीं करते हैं। एक तरफ दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में छात्र 100 प्रतिशत नंबर ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपीएससी की परीक्षा में एक सामान्य वर्ग का उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सिर्फ 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अंतिम रूप से चयनित हो जाता है। सवाल का उठना लाजिमी है कि क्या आजकल दसवीं और बारहवीं में 100 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं या वे शामिल तो हो रहे हैं, पर उनकी होनहारता की धार कुंद पड़ गई है या फिर दसवीं और बारहवीं में दिये जा रहे 100 प्रतिशत अंक का पैमाना गलत है? हालात तो इतने बदतर हैं कि बैंक या अन्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कर्मचारियों की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 100 तो छोड़िए 60 प्रतिशत अंक भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीआई एवं अन्य रोजगारपरक शिक्षा की शुरूआत जरूर की गई है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों की सार्थकता नाममात्र की है। यहां से पढ़कर बाहर निकलने के बाद भी अधिकांश युवा कौशलहीन होते हैं, जबकि हुनरमंद युवा देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में हमेशा आगे रहते हैं। हुनरमंद बेरोजगार नहीं रहता है। वह आसानी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर लेता है। बढ़ई, लोहार, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, राज मिस्त्री, वाहन की मरम्मत करने वाले कारीगर आदि कभी भी भूखे नहीं मरते हैं। ये सरकार को कर भी देते हैं और देश के अर्थ चक्र को गतिमान भी रखते हैं। अस्तु, आज सरकार को डिग्री बांटने की जगह युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्हें योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सभी के ज्ञान का स्तर एक समान नहीं होता है, पर निरंतर मेहनत सभी कर सकते हैं। मामले में अंकों की बाजीगीरी की तह तक पहुंचने की भी आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार और लोग स्वतः कौशल विकास को प्राथमिकता देंगे।

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

कब सुधरेंगी हमारी गलतियां, गणतंत्र के भविष्य के लिए जरूरी है इनका ठीक होना

रामचंद्र गुहा

इस बार का चुनाव बहुत ही कठिन रहा और पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी। इसके परिणाम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। जो भी पार्टी या गठबंधन अगली सरकार बनाएगा, उसे उन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें चुनाव अभियान ने पीछे धकेल दिया है। भारत के सामने आज गलतियों की एक लंबी लिस्ट है, जिसे अच्छी तरह सुधारा नहीं गया तो एक गणतंत्र के रूप में हमारा भविष्य कमजोर हो सकता है। पहली गलती पार्टी प्रणाली का भ्रष्टाचार है। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होता है, जिसमें नेता स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और वे अपनी पार्टी के सहयोगियों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारतीय राजनीति आज इस मॉडल से बिल्कुल अलग है। यहां राजनीतिक पार्टियां या तो व्यक्तित्व के साये तले हैं या एक पारिवारिक फर्म बन गई हैं। व्यक्तित्व के साये तले वाली बात का ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। पिछले एक दशक में पूरी पार्टी और सरकारी तंत्र का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी को दिव्य व्यक्तित्व वाला बनाने में जुटा रहा है। हालांकि भौगोलिक तौर पर अपने सीमित क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, केरल में पिनाराई विजयन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह कि मानो वे ही शासन करते रहेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं का दिखावा करने वाली पारिवारिक पार्टियां भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है। उसने पार्टी के लिए दशकों तक काम करने वालों को नजरअंदाज कर प्रियंका गांधी को रातों-रात महासचिव बना दिया। गांधी परिवार से पीछे न रह जाएं, इस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा की अपनी पुरानी सीट अपने दामाद को दे दी, जबकि उनका एक बेटा पहले से ही कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, सपा उत्तर प्रदेश में और डीएमके तमिलनाडु में ऐसी पार्टियां हैं, जो एक ही परिवार के नियंत्रण में रही हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली को हमने अपनाया, उससे हम कितने अलग हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने कोई धर्म-पंथ नहीं है। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता केर स्टार्मर किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। वे दोनों आज जिस मुकाम पर हैं, वहां अपनी मेहनत और पार्टी के सहयोगियों के समर्थन से हैं। जब भी वे समर्थकों का विश्वास खो देंगे, बिना किसी हंगामे के अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह पर ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, जो किसी राजनीतिक वंशावली से नहीं होगा। भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता इस बात से भी और कम हुई है कि नागरिकों को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है और वर्षों तक जेल में रखा जा सकता है। कानूनों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की असहमति जताने वालों को डराने और चुप कराने के लिए किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग में अदालतें भी शामिल हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि हमारी राजनीतिक कमियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के दावों के आडंबरों के पीछे छिपी हैं। दूसरा दावा विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण की वजह से गरीबी में तो कमी आई है, लेकिन इससे असमानता भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई। शिक्षित वर्गों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और इसके पर्यावरणीय रिकॉर्ड विनाशकारी रहे हैं। आर्थिक तौर पर भारत के सबसे समृद्ध शहर बेंगलुरु में जल संकट और भारत के वैश्विक उत्थान वाले शहर नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की उच्च दर इस बात का प्रतीक है कि हमने संसाधनों का कितना दुरुपयोग किया है। जैसा कि मैंने पहले लिखा है, हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा पर्यावरण संकट है। जहरीली हवा, गिरता जल स्तर, दूषित मिट्टी और विलुप्त होती जैव विविधता की वजह से करोड़ों भारतीयों की आजीविका और सेहत खतरे में पड़ गई है और ये भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे औद्योगिक और आर्थिक संसाधन टिकाऊ हैं? कई दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इसमें सबसे अधिक बनती है। उसका कहना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उसके बाद से स्थिति और खराब होती गई। हम जिसे सांप्रदायिक समस्या कहते हैं, वह भी कोई नई नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए, उन्हें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए आश्वस्त किया था कि पाकिस्तान में जो भी अधिकार दिए गए हैं, वही समान नागरिक अधिकार यहां भी दिए जाएंगे। लेकिन उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा गया। धर्मों के बीच की यह खाई राजीव गांधी के शासनकाल में बढ़ती गई, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम, दोनों के बीच कट्टरता को बढ़ावा दिया। 2014 के बाद से भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना कई गुना बढ़ गई, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अपनी हिंदू बहुसंख्यकवादी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर दिया था। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में धर्म का बोलबाला बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री ने खुद को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजे गए उस हिंदू राजा की तरह दिखाया, जो हिंदुओं की सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों ने खुद को इतना डरा हुआ कभी महसूस नहीं किया, जितना अब कर रहे हैं। ये भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, कहना मुश्किल है। एक अंतिम समस्या, जो मैं उठाना चाहता हूं, वह है राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध। भाजपा समर्थक 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्त करने और इंदिरा गांधी के बार-बार अनुच्छेद 356 का उपयोग करने पर चर्चा तो करना पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे दलों के शासन वाले राज्यों के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल में उन राज्यों की ओर कम ध्यान दिया गया, जहां भाजपा का शासन नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों का मजाक उड़ाया गया। जान-बूझकर ऐसे राज्यपालों को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर हर मोड़ पर राज्य सरकार के काम में बाधा पहुंचाई है। यहां तक कि गणतंत्र दिवस परेड जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों की झांकियों को हटाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि भारत के प्रत्येक राज्य में भाजपा का शासन नहीं हो जाता। उनके इस व्यवहार से अधिनायकवाद और निरंकुशता की बू आती है। हमने अभी देखा है कि आम चुनाव में करोड़ों भारतीयों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। हालांकि यह कहना सही है कि ये वोट गैर प्रतिनिधित्व वाली पार्टी, समझौता किए गए संस्थानों, अलोकतांत्रिक कानून, गिरती अर्थव्यवस्था, असुरक्षित अल्पसंख्यक और संघीय ढांचे के बढ़ते तनाव के संदर्भ में दिए गए थे। आने वाले समय में जो भी सरकार सत्ता में आएगी, उसके लिए सबसे पहला काम इन सभी गलतियों को सुधारना होगा।

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

https://t.me/AllNewspaperPdf

पर्यावरण बने प्राथमिकता

धरती का तापमान बढ़ना आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ा संकट है, जिसका तात्कालिक समाधान नहीं किया गया, तो मानव समेत तमाम जीवों का अस्तित्व निश्चित ही खतरे में पड़ जायेगा. इस संकट के प्रभाव के गंभीर परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, बेमौसम व औचक बरसात, चक्रवात, आंधी, वनों में आग, भू-स्खलन, ग्लेशियरों में बर्फ पिघलना, समुद्र का तापमान बढ़ना और समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी आदि जैसी समस्याएं सघन हो रही हैं. विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल पांच जून को मनाया जाता है, के अवसर पर इस वर्ष का मुख्य विषय 'भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा निरोध' है. पर्यावरण का समुचित संरक्षण नहीं होने तथा भूमि की उर्वरा को बनाये रखने के प्रति समुचित संवेदनशीलता की कमी से भारत समेत कई देश भूमि क्षरण की समस्या का सामना कर रहे हैं. बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई, भूजल के अत्यधिक दोहन तथा रासायनिक खेती के कारण भूमि क्षरित हो रही है. इससे मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है. अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रेखांकित किया है कि मानवता भूमि पर निर्भर है, फिर भी समूचे विश्व में प्रदूषण, जलवायु अव्यवस्था और जैव-विविधता के ह्रास से स्वस्थ भूमि मरुभूमि में तथा जीवंत पारिस्थितिकी मृत क्षेत्र में परिवर्तित हो रही हैं. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न प्रयासों के साथ-साथ इस ओर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है. दुनियाभर में तीन अरब से अधिक लोग भूमि क्षरण से प्रभावित हैं. साथ ही, पीने योग्य पानी का तंत्र भी तबाह हो रहा है. भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को स्वस्थ भूमि और जैव-विविधता की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है. इस संबंध में भारत सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं, पर इस प्रक्रिया में हम सभी की भागीदारी आवश्यक है. कम पानी एवं खाद की आवश्यकता वाले तथा अधिक पौष्टिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी पहल है. स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक देश आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में यह संकल्प रखा था कि हमारा देश 2070 तक कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य के स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. स्वच्छ ऊर्जा के अधिक उत्पादन से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी घटेगी, जिनके खनन, वितरण, ऊर्जा उत्पादन और उपभोग से पारिस्थितिकी को भारी नुकसान होता है. जिस प्रकार हम प्रकृति से स्वच्छ ऊर्जा हासिल कर रहे हैं, उसी तरह हमें वर्षा जल के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए. पर्यावरण बचाने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक साझा प्रयासों की आवश्यकता है.

भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को स्वस्थ भूमि और जैव-विविधता की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है.

चुनाव के दौरान नकदी और नशीली चीजों की जब्ती

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

एक पखवाड़े पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने मार्च और पांचवें चरण के बीच नौ हजार करोड़ रुपये मूल्य की नगदी, आभूषण, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किया. एजेंसियों ने हर दिन औसतन सौ करोड़ रुपये काला धन पकड़ा है, जिसे नोटबंदी के बाद खत्म हो जाना था. सातवें चरण तक 10 हजार करोड़ रुपये बरामद होने का अनुमान है, जबकि यह आंकड़ा 2019 में साढ़े तीन हजार और 2014 में लगभग एक हजार करोड़ रुपये रहा था.

कार्ल मार्क्स ने 1843 में लिखा था कि लोगों के लिए धर्म अफीम है. उन्होंने रेखांकित किया है कि यह उत्पीड़ितों की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है और आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है. उस दौर में उपचार में महत्व के कारण अफीम बहुत कीमती होता था. आज वे अफीम और उसके आधुनिक रूपों के बारे में क्या कहते, जिनका चुनावी इस्तेमाल पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए हो रहा है? उसके लिए उन्हें भारत आना पड़ता, जिसके बारे में उनकी धारणा थी कि यहां ब्रिटिश शासन ने तबाही मचायी, पर यह 'एशिया के एकमात्र सामाजिक क्रांति के लिए' जरूरी कीमत थी. पर उन्हें यहां अब यह दिखता कि चुनावी जीत सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ देकर अपने पाले में लाना बन गया है. एक पखवाड़े पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने मार्च और पांचवें चरण के बीच नौ हजार करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, आभूषण, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किया. एजेंसियों ने हर दिन औसतन सौ करोड़ रुपये काला धन पकड़ा है, जिसे नोटबंदी के बाद खत्म हो जाना था. सातवें चरण तक 10 हजार करोड़ रुपये बरामद होने का अनुमान है, जबकि यह आंकड़ा 2019 में साढ़े तीन हजार और 2014 में लगभग एक हजार करोड़ रुपये रहा था.

अगर लोकतंत्र सबसे बड़ा उत्सव है, तो राजनीतिक दल इसे सबसे अधिक मनाते हैं. आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बरामद नगदी केवल 850 करोड़ रुपये है, पर जब्त नशीले पदार्थों का मूल्य चार हजार करोड़ रुपये है. बरामद शराब का दाम भी आठ सौ करोड़ रुपये से अधिक है. यदि जांच एजेंसियों के आधिकारिक पैमानों को मानें, तो 80 हजार करोड़ रुपये की नगदी और अन्य चीजें उनकी निगाह से बच गयीं. संख्याएं राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के बारे में बहुत सी कहानियां बता रही हैं. सर्वाधिक नकदी- 377 करोड़ रुपये- चार दक्षिणी राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश- में बरामद हुई है. महंगे धातुओं की बरामदगी में भी दक्षिण आगे रहा है. एजेंसियों ने चुनाव के दौरान 1,260 करोड़ रुपये के आभूषण पकड़े हैं, जिसमें इन राज्यों का हिस्सा 441 करोड़ रुपये का है. लेकिन राजनीति के प्रेरक संभावित मतदाताओं को नशे में लाने के लिए कुछ आगे ही बढ़ गये. इन चार राज्यों में 337 करोड़ रुपये की शराब जब्त की गयी है. तमिलनाडु में 330 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ बरामद हुए है. गुजरात, पंजाब, बिहार से अचरज भरी कहानी सामने आ रही है. गुजरात और बिहार में आधिकारिक रूप से पूर्ण शराबबंदी है और शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ बेचना आपराधिक है.

गुजरात में एजेंसियों ने मात्र 8.61 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है, लेकिन जब्त शराब की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है. राज्य में लगभग 1,200 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद हुए, जो पूरे देश में जब्त नशीले पदार्थों की कीमत (4,000 करोड़ रुपये) का लगभग 30 प्रतिशत है. गुजरात उन पांच राज्यों में भी एक है, जहां सबसे अधिक 128.50 करोड़ मूल्य के आभूषण बरामद किये गये. लेकिन नकदी के मामले में बिहार गरीब राज्य निकला, जहां चुनाव आयोग के दूतों को मात्र 14 करोड़ रुपये ही मिल सके. लेकिन राज्य के शराब माफिया से 48 करोड़ रुपये मूल्य की शराब जब्त की गयी. पंजाब में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों और शराब के बरामद किये जाने से इस धारणा को भी बल मिला है कि राज्य एक ताकतवर नशा माफिया के चंगुल में है, जिसने चुनाव में भी भागीदारी की है. चुनाव आयोग और अन्य एजेंसियों ने राज्य में 650 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किया है. पर कृषि के क्षेत्र में समृद्ध पंजाब के राजनीतिक बाजार में आयोग को केवल 15.50 करोड़ रुपये ही हाथ लग सके. महाराष्ट्र व दिल्ली ने राजनीतिक और वित्तीय रूप से एक पैमाना ही स्थापित कर दिया. चुनाव की घोषणा के बाद से ही आयोग और अन्य एजेंसियों की नजरें इन दो राज्यों में पैसे और अन्य चीजों की आवाजाही पर टिकी हुई थीं. इन दो राज्यों से 300 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किये गये, जो समूचे देश में जब्त महंगे धातुओं का लगभग 25 प्रतिशत है.

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आभूषणों की सबसे अधिक बरामदगी दिल्ली में हुई. यहां 195 करोड़ रुपये के महंगे धातु पकड़े गये. दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, जहां जब्त आभूषणों की कीमत 188 करोड़ आंकी गयी. दिल्ली और महाराष्ट्र में एजेंसियों ने क्रमशः 90.79 तथा 75 करोड़ से अधिक की नकदी पकड़ी. जैसे-जैसे सोने और अन्य आभूषणों की मांग में भारी बढ़ोतरी होती गयी, राजस्व इंटेलिजेंस से जुड़ी एजेंसियों तथा चुनाव आयोग की निगाह आभूषण विक्रेताओं पर लगातार बनी रही. उल्लेखनीय है कि दिल्ली से बरामद प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बाजार कीमत 350 करोड़ से अधिक आंकी गयी. पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और झारखंड में कहानी कुछ अलग है. चुनाव से पहले राजनेताओं के यहां से बड़ी मात्रा में नकदी पकड़ी गयी, पर चुनाव के दौरान आयोग अवैध नकदी तक नहीं पहुंच सका. उसे पश्चिम बंगाल में 31, ओडिशा में 17, झारखंड में 45.53 और असम में महज 6.75 करोड़ रुपये ही नकद मिल पाये. लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां 90 करोड़ रुपये की अवैध शराब पकड़ी गयी, वहीं यह आंकड़ा ओडिशा में 35 करोड़ रुपये रहा. झारखंड में 56 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किये गये. पश्चिम बंगाल उन शीर्षस्थ राज्यों में एक रहा, जहां 60 करोड़ रुपये मूल्य की महंगे धातुओं से बनी चीजें जब्त की गयीं.

यह विडंबना ही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य उत्तर भारतीय राज्य बड़े शरीफ दिखे. इन राज्यों में देशभर से बरामद नकदी और आभूषणों का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा जब्त किया गया. हिमाचल प्रदेश में 50 लाख रुपये बरामद हुए, तो पूर्वोत्तर के अधिकतर छोटे राज्यों में यह राशि एक करोड़ रुपये से भी कम रही. यहां तक कि 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसियों को केवल 35 करोड़ रुपये नकद ही हाथ लग सके. अधिकतर मतदाताओं के लिए चुनाव में तीन विकल्प ही थे- पैसा, जहरीली बातें और नशीली चीजें. अब यह उन पर है कि वे उनका वोट चाहने वालों से अधिक परिपक्वता दिखायें. किताब की जगह अवैध चीजें अब लोकतांत्रिक निर्णयों को अधिक प्रभावित कर रही हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बढ़ते तापमान से मुश्किल में जीवन

अनिल प्रकाश जोशी
प्रतिष्ठित पर्यावरण कार्यकर्ता
dranilpjoshi@gmail.com

विश्व पर्यावरण दिवस (पांच जून) पर विशेष

हमने अपनी जीवनशैली को कुछ इस तरह बना दिया है कि अब हम उन आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ गये हैं जो जीवन का आधार मात्र थीं. हमने विलासिताओं को भी आवश्यकताओं में बदल दिया है, जिनके चलते पृथ्वी के हालात गंभीर होते चले गये.

इस बार पर्यावरण दिवस पर यूनाइटेड नेशंस ने जिस विषय पर चर्चा का आह्वान किया है, वह बंजर पड़ती जमीन और बढ़ता मरुस्थल है. पर्यावरण के आज के हालात कम-से-कम यह तो समझा ही रहे हैं कि सब कुछ अब हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है. इस बार के ग्रीष्म काल को ही देख लीजिए, जिसने फरवरी से ही गर्मी का अहसास दिला दिया और जून में पहुंचते-पहुंचते इसने प्रचंड रूप दिखा दिया है. पूरी दुनिया में औसत तापक्रम बढ़ा है. दुनिया में अब प्रचंड गर्मी के दिन धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं. आज दुनिया में 80 प्रतिशत लोग गर्मी झेल रहे हैं. पहले इस तरह के दिनों की संख्या 27 प्रतिवर्ष के आसपास होती थी, आज वर्ष में 32 दिन ऐसे हैं जो खतरे की सीमा तक गर्मी को पहुंचा देंगे. बिहार, जैसलमेर, दिल्ली समेत देश के तमाम कोनों से खबरें आ रही हैं कि हीटवेव ने परिस्थितियां बदतर कर दी हैं.

बढ़ती गर्मी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने पृथ्वी और प्रकृति के बढ़ते असंतुलन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया. दुनियाभर में एक-एक कर प्रकृति के सभी संसाधन या तो बिखर गये या फिर घटते चले गये. हमने अपनी जीवनशैली को कुछ इस तरह बना दिया है कि अब हम उन आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ गये हैं जो जीवन का आधार मात्र थीं. हमने विलासिताओं को भी आवश्यकताओं में बदल दिया है, जिनके चलते पृथ्वी के हालात गंभीर होते चले गये. हमारी जीवनशैली में आया बदलाव, बढ़ता शहरीकरण और ऊर्जा की अत्यधिक खपत के कारण ग्लेशियर हो या नदियां, सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं. दुनिया में करीब 24 प्रतिशत भूमि अब मरुस्थलीय लक्षण दिखा रही है और इसमें भी कुछ देश तो ऐसे हैं, जिनमें हालत ज्यादा गंभीर हैं. इनमें बोलीविया, चिली, पेरू में तो 27 से 43 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीय हो चुकी है. अर्जेंटीना, मेक्सिको, प्राग के भी ऐसे ही हालात हैं जहां की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि बंजर हो चुकी है. आज दुनियाभर में बढ़ते ग्रासलैंड व सवाना जैसे मरुस्थल इसी ओर संकेत करते हैं कि ये भूमि उपयोगी नहीं रही. मरुस्थलीय परिस्थितियां उसे कहते हैं जहां कुछ भी पैदा होना संभव नहीं होता. पूरी धरती लवणीय हो जाती है और पानी की भारी कमी हो जाती है.

अपने देश में यह मानकर चला जा रहा है कि 35 प्रतिशत भूमि पहले ही डिग्रेड हो चुकी है और इसमें भी 25 प्रतिशत मरुस्थलीय बनने की राह पर है. ऐसी स्थिति अधिकतर उन राज्यों में है जो संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे. जैसे झारखंड, गुजरात, गोवा. इनमें दिल्ली और राजस्थान भी शामिल हैं. इन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि बंजर पड़ने के लिए तैयार बैठी है. जरा सी राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मिजोरम में अभी 10 प्रतिशत ही बंजरपन दिखाई दे रहा है. यदि इनके कारणों को तलाशने की कोशिश करें, तो पता चलता है कि दुनियाभर की 50 प्रतिशत भूमि को अन्य उपयोग में डाल दिया गया है जहां पहले वन, तालाब या प्रकृति के अन्य संसाधनों के भंडार हुआ करते थे. इनमें से 34 प्रतिशत देशों में ये अत्यधिक बदलाव की श्रेणी में है, जबकि 48 प्रतिशत देशों में मध्यम रूप से बदलाव आया है. वहीं 18 प्रतिशत देशों में ज्यादा भूमि उपयोग नहीं बदला है. दक्षिण एशिया में तो 94 प्रतिशत भूमि उपयोग बदल चुका है और यूरोप में 90 प्रतिशत. अफ्रीका में यह प्रतिशत 89 है. भूमि उपयोग में बदलाव का ही प्रताप है कि आज प्रकृति हमारा साथ तेजी से छोड़ रही है. जब से उद्योग क्रांति आयी, तब से हमने 68 प्रतिशत वनों को खो दिया. आज दुनिया में मात्र 31 प्रतिशत वन बचे हैं. इस तरह, एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 0.68 ही वृक्ष आयेंगे. अपने देश के हालात तो और भी गंभीर हैं. दावा किया जाता है कि हमारे पास 23 प्रतिशत भूमि वनों में है. यदि इसे भी मान लें, तो भी देश के प्रति व्यक्ति के हिस्से 0.08 भूमि है. दूसरी चिंता की बात यह है कि देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां व्यवसाय के रूप में खनन ने अपना पैर नहीं फैलाया है.

दुनिया में खेती के पैटर्न में भी बहुत अधिक बदलाव आया है. अब खेती व्यावसायिक हो चली है और इसमें रसायनों का भी अधिकाधिक उपयोग होता है. इस कारण खेती वाली भूमि भी बंजर हो गयी. पानी के अभाव के कारण भी कई स्थानों पर खेती को त्याग दिया गया है. ये सब भी मरुस्थलीय परिस्थितियों की तरफ चल चुकी हैं. बंजर हालातों के लिए क्लाइमेटिक वेरिएशन भी कारण बना है. हमारी जंगलों पर निर्भरता भी कुछ हद तक घातक बनी है. हमारे पास आज कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा है या गंभीर योजना पर कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही है कि हम बंजर भूमि को वापस ला सकें. सिवा केवल एक प्रयोग के कि यदि हम वन लगाने को जन आंदोलन में बदल दें, तो शायद कुछ आशा बन पायेगी. हमें वनों की प्रजाति पर भी उतना ही गंभीर होना होगा, क्योंकि स्थानीय वन ही वहां की प्रकृति को जोड़ते हैं और साथ देते हैं. आज दुनियाभर में बढ़ती गर्मी और समुद्र से उठे तूफान कम से कम हमें कुछ तो समझा पायेंगे कि हम आज एक ऐसी सीमा पर खड़े हैं, जहां आने वाले समय में बंजर होती दुनिया हमें डुबा देगी. फिर संभवतः हमारे लिए जीने का कोई कारण नहीं बचेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस का सत्य

जब भी दो पक्षों के बीच टकराव होता है, तो कमजोर पक्ष के प्रति सहानुभूति रखना मानव स्वभाव है. ऐसा तब और भी अधिक होता है जब कमजोर व्यक्ति मासूमियत के साथ चिल्ला रहा हो. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बीते सप्ताह शांगरी-ला डायलॉग में अपने शुरुआती भाषण के दौरान स्वयं को और अपने प्रशासन को एक ऐसे शूरवीर के रूप में चित्रित करने की कोशिश की जो एक अवैध, जबरदस्त, आक्रामक और कपटी दिग्गज के सामने खड़ा होने का साहस कर रहा है. परंतु इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है, और वह यह कि अवैध, जबरदस्त, आक्रामक और कपटी चरित्र स्वयं फिलीपींस है. मार्कोस जूनियर ने दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र पर फिलीपींस के स्वामित्व को साबित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों और घरेलू कानूनों की एक सूची पेश की. उनमें से कुछ स्पष्ट करते हैं कि 118 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम का क्षेत्र फिलीपींस का नहीं है. उदाहरण के लिए, हुआंगयान द्वीप स्पष्ट रूप से फिलीपींस के क्षेत्रीय सीमा के बाहर है. रेनाई जिआओ भी फिलीपींस के क्षेत्र से बाहर है. अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन अपनी सीमाओं से थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़कर बाहर के क्षेत्रों को हथियाने के लिए यथास्थिति को तोड़-मरोड़ रहा है, और रो रहा है कि चीन हठधर्मिता कर रहा है. अब जबकि पुराने तनाव और विवाद अनसुलझे हैं, फिलीपींस नये टकराव पैदा करने की जुगत में है. ऐसे में दक्षिण चीन सागर को लेकर प्रश्न उठता है कि क्या इस बात का मूल्यांकन करते समय कोई सार्वभौमिक मानक नहीं होना चाहिए कि कौन सा देश इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता में योगदान देता है या उसे बाधित करता है. मनीला कहानी का अपना संस्करण प्रस्तुत करने में कुशल प्रतीत होता है और पश्चिमी देश उसके झांसे में आ गये हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि फिलीपींस का संस्करण वास्तविक सत्य है. **-ली ऐशिन**

बोधि वृक्ष

सृष्टि का आधार

जीवन एक 'प्रवाह' है, थम जाना मृत्यु है. जो आपको सृष्टि ने दिया है उसे वापस सृष्टि को लौटाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं या विकास की सीढ़ी पर ऊपर उठ सकते हैं. ये न भूलें की दूषित से दूषित जल प्रवाहित होने से स्वच्छ हो जाता है, और स्वच्छतम जल भी स्थिर होने पर सड़ने लगता है. इसलिए, जो मिला है उसे आगे बांटें. योग ही प्रकृति है, प्रकृति ही योग है. यदि आप प्रकृति के विरुद्ध जायेंगे, तो वह भी आपके विरुद्ध होगी, फिर भला दोनों के बीच तारतम्य या सामंजस्य कैसे होगा? कर्म ही सृष्टि का आधार है तथा कर्म विधान ही इसे नियंत्रित करता है, आप जो भी देंगे वह कई गुना होकर आपके पास लौट आयेगा. योग के प्रारंभ में आप स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं. आपके स्वयं के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और जब आप योग में आगे बढ़ने लगते हैं, तो आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं. जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इस सृष्टि में उन्मुक्त हो जाती है, बदले में इस ऊर्जा की एक विपरीत प्रतिक्रिया हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप आपको कोई चोट पहुंचाता है या पीड़ा देता है. प्रत्येक सुख या भोग के रूप में आप इस सृष्टि से कुछ लेते हैं. भोग गलत नहीं है, किंतु उसके बदले में आपको भी कुछ देना पड़ता है. जो शक्ति इस सृष्टि का संचालन कर रही है वह एक सुपर कंप्यूटर की तरह है. उसके पास हर किसी का और हर चीज का लेखा-जोखा है. अपनी जरूरत से अधिक लेते ही हमें वह वापस चुकाना पड़ता है. यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो उसे आगे बांटें. यदि आप सौ लोगों का हित करते हैं तो उसका हजार गुना अच्छा आपके साथ होगा. यदि आप भूखे-गरीब को भोजन खिलाते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा, आप बीमारों की सहायता करते हैं तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप लोगों को शिक्षा देते हैं तो आपके पास विद्या की कभी कमी नहीं होगी. आप जो देंगे वह कई गुना आपको प्राप्त होगा. यही नियम हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करता है, यही विधि का विधान है. **-योगी अश्विनी**

कुछ अलग

हर मसले पर राय रखनेवाले सेलिब्रिटी

आलोक पुरिणक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

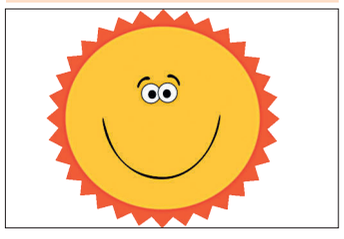

सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटा वह होता है, जो कुछ रुपये पकड़कर कुछ भी बेच सकता है. ऐसे ऐसे सेलिब्रिटा और सेलिब्रिटा राफा का जिक्र करने लगे, जिन्हें यह भी ना पता का राफा है क्या. राफा पान मसाले का ब्रांड है या पेन का, यह भी जिन्हें ना पता, वो भी राफा के लिए परेशान हो गये. राफा को कोई सेलिब्रिटा या सेलिब्रिटी याद ना करती, सब सिर्फ अपनी रकम को याद रखते हैं. तमाम टीवी पर विदेशी मामलों पर बोलने वाले एक्सपर्ट को मैं अभी समझा कर आया हूं कि राफा दुनिया के नक्शे में है कहां. तमाम तरह के टीवी चैनल एक्सपर्टों और हर मसले पर राय रखनेवाले सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटा में फर्क यह होता है कि सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटा को तो अपने अज्ञान के ठीक पैसे मिल जाते हैं, पर अधिकतर एक्सपर्टों के मामले में ऐसा ना होता.

सेलिब्रिटा कुछ भी बेच सकता है, भाव बढ़े हुए मिलने चाहिए. सेलिब्रिटा हर विषय पर राय रख सकता है, अगर पैसे मिलें. गाजा पट्टी, इजरायल, फिलिस्तीन ऐसे मसले हैं, जिन पर बात करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है. बड़े बड़े ज्ञानी इन विषयों पर बहुत संभलकर बोलते हैं. पर सेलिब्रिटा हर विषय का ज्ञानी होता है. करीना कपूर शेयर बाजार पर बोल सकती हैं और अमिताभ बच्चन सिंचाई पंप पर बोल सकते हैं. खैर, बात तो इन दिनों सूरज की और गर्मी की हो रही है. सारी चर्चा इलेक्शन पर हो रही थी. सूरज को बुरा लग गया. तो गर्मी का यह लेवल आ गया कि अब सूरज की बात करनी पड़ेगी.

अब की बार चार सौ पार टेंपरेचर- उत्तर भारत में इन दिनों सूरज यही कहता दिखता है. हे सूरज देवता, नेता मत बनो, अपना टेंपरेचर इस तरह गिरा दीजिये, जैसे आम आदमी की इज्जत गिरती है, जैसे चुनाव हारकर नेता का मुंह गिर जाता है. कई नेताओं के मुंह इन दिनों गिरे हुए हैं, चुनाव से पहले ही पता लग गया कि वो पीएम नहीं बनने वाले. पालिटिक्स ऐसा धंधा है, जिसमें कोई किसी से मार्गदर्शन ना लेता, फिर भी मार्गदर्शक मंडल पाये जाते हैं पालिटिक्स में. अब पालिटिक्स में कुछ नये मंडलों की जरूरत है. न हुए पीएम का मंडल- इसकी दरकार है. शरद पवार अस्सी के पार जा चुके हैं, इस बार पीएम ना बने, तो शायद फिर ना बन पायें. उधर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी हैं. न हुए पीएम का मंडल बने, तो सभी को यथायोग्य सम्मान मिले. कई पीएम हालांकि ऐसे भी हुए हैं, जो न हुए बराबर हैं, उन्हें भी इस मंडल में जगह दी जा सकती है. सबका साथ सबका विकास- इस नारे पर कुछ ऐसे अमल हो सकता है. गर्मी का विकास न हो, बस यह दुआ की जाए.

आपके पत्र

मोबाइल से बिगड़ी बच्चों की सेहत

कोरोना काल से ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण बच्चे मोबाइल के काफी करीब आ गये. धीरे-धीरे छोटे-छोटे बच्चों में इसकी लत लग गयी, जिससे इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. बच्चे बाहर खेलने-कूदने के बदले मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं. इससे उनमें अवसाद आ रहा है. कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली है. इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए. उन्हें घर से बाहर पार्क, मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करें. इससे इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और मोबाइल की लत खत्म होगी.

संतोष कुमार, लखीसराय

पशु-पक्षियों को बचाने का हो प्रयास

इन दिनों पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है. कई शहरों में अधिकतम तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों का जीवन भी खतरे में है. इसलिए लोगों को पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी व उचित छायादार आवास की व्यवस्था करनी चाहिए. स्थानीय प्रशासन को भी आवारा पशुओं के लिए छायादार स्थान व जल की व्यवस्था करनी चाहिए. शास्त्रों के अनुसार मूक प्राणियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है. इसलिए भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए.

अंकित सोनी, इमेल से

संपादकीय

"अपने नागरिकों को सुरक्षित और खुशहाल बनाना ही सरकार का कर्तव्य है। - थॉमस जेफरसन

लोकसभा चुनाव के दरम्यान तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई ही, मतदान के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता की बर्बर हत्या और संदेशखाली की महिलाओं को धमकाया जाना दर्शाता है कि इस राज्य की राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में कुछ भी नहीं बदला है।

बंगाल अब भी वही है

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दरम्यान हुई हिंसा वहां राजनीति के हिंसक चरित्र को तो बताती ही है, लेकिन आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में भाजपा के एक कार्यकर्ता की जिस बर्बर ढंग से हत्या की गई और अब संदेशखाली की महिलाओं को धमकाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, वह घोर निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दो महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता हफीजुल शेख को गोली मारी और फिर जब वह भागने लगा, तो उसकी गर्दन काट कर ले गए। इससे पूर्व, छठे चरण के मतदान से पहले पूर्वी मिदनापुर में एक तृणमूल कार्यकर्ता की भी हत्या हुई थी। यही नहीं, अंतिम चरण में ही दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने जबरन मतदान केंद्रों में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को पास के तालाब में फेंक दिया था। ध्यान रहे कि ये घटनाएं तब हो रही हैं, जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की। सातवें और अंतिम चरण में तो पश्चिम बंगाल के नौ निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 967 कंपनियों और राज्य पुलिस के 33,292 कर्मियों को तैनात किया गया था, जो बाकी राज्यों की तुलना में एक रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी बीते अप्रैल में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, तो वर्ष की शुरुआत में राशन घोटाले की जांच करने बंगाल पहुंचे ईडी के अधिकारियों के साथ भी अराजक सुलूक हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि आज के बंगाल की हालत बीस-पच्चीस साल पहले के बिहार जैसी है, जहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। दरअसल, अपने लंबे शासन के दौरान माकपा ने हिंसा और दबाव की जिस राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया, 'परिवर्तन' के

नारे के साथ राज्य की सत्ता से उसे बेदखल करने वाली ममता बनर्जी ने इसे खत्म करने के बजाय जारी रहने दिया। ताजा हिंसा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने उचित ही बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट के दो मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देने के साथ यह फैसला भी सुनाया है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति देखते हुए केंद्रीय बलों की 400 टुकड़ियां कम से कम 19 जून तक राज्य में रहेंगी। ऐसे में, आज पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन यह शीशे की तरह साफ है कि इस राज्य को राजनीतिक हिंसा की कुसंस्कृति से मुक्त करने की लड़ाई अभी बहुत लंबी है।

नई सरकार का एजेंडा क्या हो

नई सरकार का व्यापक एजेंडा घरेलू और बाहरी क्षेत्र की उचित नीतियों के जरिये भारत की क्षमता को बेहतर बनाने में मददगार होना चाहिए। सरकार का ध्यान निजी निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक कर्ज घटाने पर केंद्रित हो। बाहरी क्षेत्र की नीतियां उन रणनीतियों पर केंद्रित हों, जो वैश्विक झटकों के जोखिम को कम करें।

पिनाकी चक्रवर्ती
अर्थशास्त्री एवं एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

आज 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक नई सरकार अपना कार्यभार संभाल लेगी। आइए, चुनावी दौर की तल्ख बयानबाजी से थोड़ा अलग हटकर हम आर्थिक नीति के क्षेत्र में नई सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं।

हालांकि भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन भू-राजनीतिक कारणों से अब भी झटके लगने की आशंका एवं अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत इससे अछूता नहीं है। हालांकि मूडीज और एस ऐंड पी जैसी प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अलावा, विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तक ने भारत की विकास दर की तारीफ की है। फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। इसलिए नई सरकार का व्यापक एजेंडा घरेलू और बाहरी क्षेत्र (अंतरराष्ट्रीय) के लिए उचित नीतियों के माध्यम से भारत की क्षमता को बेहतर बनाने में मददगार होना चाहिए। घरेलू क्षेत्र की नीतियों के तहत सरकार का ध्यान निजी निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक कर्ज घटाने पर केंद्रित होना चाहिए। बाहरी क्षेत्र की नीतियों को उन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो व्यापार के खुलेपन पर प्रतिबंध लगाए बिना भारत के लिए वैश्विक झटकों के जोखिम को कम करे। अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिन पर नई सरकार अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेगी।

भारत की राष्ट्रीय समृद्धि अलग-अलग राज्यों की समृद्धि से जुड़ी हुई है। आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्र सरकार का काम नीति एवं विश्वास का एक सक्षम ढांचा तैयार करना है। आर्थिक सुधार के 25 वर्ष बाद यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों की आर्थिक नीति संबंधी कार्रवाइयां लोगों की आर्थिक नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए आने वाली सरकार को

विकास एवं समृद्धि का लाभ उठाने की खातिर केंद्र-राज्य संबंधों को और मजबूत बनाना होगा।

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका को व्यापक तरीके से बढ़ाया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। उसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने इस प्रक्रिया को और मजबूत ही बनाया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहद सामंजस्यपूर्ण रिश्ते देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हाल के महीनों में विभिन्न मुद्दों पर हमने केंद्र और राज्यों के रिश्तों में तनाव देखा है। बेशक, इनमें से कुछ मुद्दे चुनावी मौसम होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संसाधनों पर राज्यों के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता तथा केंद्र एवं राज्यों की विषम शक्तियां ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान एक संघीय देश को हमेशा करने की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यदि इनका समाधान न किया जाए, तो ये जरूर असामान्य हो सकते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच चर्चा, बहस और बातचीत के लिए इस तरह से एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए कि वह केंद्र-राज्य संबंधों के सभी मुद्दों का भरोसे के आधार पर समाधान सुझाए।

हमारे देश का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। वर्ष 2030 तक शहरी आबादी के मामले में भारत सबसे ज्यादा शहरीकृत देशों में से एक होगा। चूंकि तेज शहरीकरण के साथ-साथ विस्थापन भी तेजी से बढ़ेगा, इसलिए तेज शहरीकरण के लिए जरूरी संसाधनों के वित्तपोषण की खातिर उचित तरीके के बारे में सोचने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था और समाज में दूरगामी बदलावों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रावधान महत्वपूर्ण है और इसे रणनीतिक जरूरत ही माना जाना चाहिए। शहरीकरण का लाभ उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक निवेश संबंधी समर्थन महत्वपूर्ण होगा। नई सरकार को नए शहरी विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

साझा बाजार के विकास, उच्च आर्थिक विकास और राजस्व के मामले में जीएसटी का व्यापक लाभ उठाने के लिए जीएसटी संरचना के ढांचे को और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है। दो-दर वाली जीएसटी संरचना तैयार करने के लिए जीएसटी ढांचे में और सुधार की खातिर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। असल में, जीएसटी ढांचे में परिवर्तन केवल जीएसटी परिषद में ही किया जा सकता है। इसलिए इस दिशा में कदम उठाना जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के दीर्घकालीन समाधान के लिए फायदेमंद होगा। नया जीएसटी ढांचा इस तरह तैयार किया जाना चाहिए, जिसका आधार व्यापक हो, लेकिन कर की दर कम हो। यह आसान काम नहीं है। राजस्व और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ऐसे बदलावों के निहितार्थ को समझने के लिए प्रमुख नीति विश्लेषण एवं आम सहमति बनाने की जरूरत होगी।

चूंकि भारत व्यापक आर्थिक समृद्धि हासिल करने की ओर तेजी से अग्रसर है, इसलिए देश में बढ़ती आर्थिक असमानता से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। इसके लिए सरकारी खर्च को अधिक से अधिक पुनर्वितरित करने की आवश्यकता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने के बारे में काफी चर्चा हुई, लेकिन विभिन्न देशों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि संपत्ति पर कर लगाकर प्रगति की गुंजाइश बहुत कम है। इस मामले में भारत का अपना अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए व्यापक आधार पर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकारी खर्च के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा मददगार साबित होगा।

अंत में, नई सरकार का दीर्घकालीन एजेंडा प्रौद्योगिकी में निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार व उसका विनियमन करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए उचित नीतिगत ढांचा तैयार करने पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बनाए रखा जा सके।

जीवन धारा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला, तो फिर इसका आना व्यर्थ गया; क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'राम' के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ ही गया।

विषयों में आनंद की खोज ही मनुष्य की भूल

लोक-परलोक के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को ठुकराकर परमार्थ-पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं, तो एक बार हमारे हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; आनंद का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिए विवश कर देता है। वे गा उठते हैं; क्योंकि गाए बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके फक्कड़पन को क्या समझे? संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाहंशाह है। दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज के मोहरे हैं। फक्कड़पन, अलमस्ती और लापरवाही ही उसकी संपत्ति है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शय्या है। जहां जी में आया सो लिया। सिर के नीचे अपनी बांह का कोमल उपधान, मुलायम तकिया लगा लिया। और चंदोवा? चंदोवा भी उसका कितना सुंदर है-नीला-नीला आकाश, जिसमें सूरज, चांद और तारों के छोटे-बड़े, रुपहले, सुनहले सुंदर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मंद-मंद समीरण पंखा झल रहा है। चंद्रमा उसके विशाल आंगन में-जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी है-प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और विरक्ति-वनिता संग में आनंद की नव-नव लहरें उत्पन्न कर रही हैं। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है-बेचारे बादशाह इस सुख को क्या जानें?

चौरासी लाख योनियों में भूलता-भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला, तो फिर इसका आना व्यर्थ गया; क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'राम' के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह-परिग्रह, कुटुंब-कबीला, महल-अटारी आंखें मुंद जाने पर क्या काम आएंगी? साधना-पथ में एकमात्र प्रभु की अनुकंपा करके ही साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस मार्ग में क्या सहायक होगा? साधक का ध्यान सदा-चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो-प्रभु के चरण-कमलों में ही रहना चाहिए। एकांत निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधना-मार्ग का रहस्य है-सदैव अखंड रूप से श्रीहरि-चरणों का आश्रय लिए रहना। आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो ईश्वर का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है। शर्त यह है कि अत्यंत झीना-सा आवरण भी न रहे। मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है, वह तो ठीक ही है; परंतु जहां खोज रहा है वहां वह वस्तु है नहीं, और जब वह वहां है ही नहीं, तो मिले कैसे? मनुष्य 'सुख', 'आनंद' खोज रहा है; परंतु वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में; सारी भूल यहीं है। यहां तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है; कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, और फिर इस नश्वर से शरीर के भीतर की भूख-प्यास बुझेगी ही कैसे? अंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर आना नहीं चाहते; फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पाएं?

भगवान हमें देख रहा

सूत्र

भक्त की और भगवान की आंखें जब चार होती हैं, तभी प्रीति का उदय होता है। भगवान तो अहर्निश हमारी ओर देख रहा है; परंतु हमारी आंखें जगत के विषयों पर लुभाई हुई हैं-यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं रमण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है-अंतर का पट हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन हो तो कैसे? यही अमृत-रस का पान है।

दूसरा पहलू

महज साढ़े छह लाख की आबादी वाले इस देश में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त होने पर भी आधी आबादी निजी वाहनों का प्रयोग करती है।

लक्जमबर्ग : जहां मुफ्त है सार्वजनिक परिवहन

लक्जमबर्ग सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश है। वर्ष 2020 से वहां के नागरिक टिकट लिए बिना ही ट्रेन, ट्राम और बस के जरिये देश के भीतर आवाजाही कर रहे हैं। इस तरह निशुल्क सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर वहां का प्रत्येक नागरिक साल भर में औसतन 400 यूरो यानी तकरीबन 36 हजार रुपये तक की बचत करता है। लक्जमबर्ग की सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। लक्जमबर्ग के लिए यह कदम इसलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वहां वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का आधा हिस्सा केवल गाड़ियों के धुएं से आता है। एक सर्वे के मुताबिक, वहां सार्वजनिक बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19 प्रतिशत ही होता है। शेष 49 फीसदी लोग दफ्तर या अन्य जगह आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में प्रति हजार व्यक्तियों में कारों की संख्या भी लक्जमबर्ग में ही सर्वाधिक है। दरअसल, जीडीपी का सवा तीन प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक परिवहन में खर्च करने के बावजूद वहां की सड़कों पर निजी गाड़ियों की बहुतायत होती थी, जिससे वहां ट्रैफिक और वायु-ध्वनि प्रदूषण की समस्या आम हो चुकी थी। अब लोग निजी वाहनों से इतर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वायुमंडल में जहरीली गैसों के फैलने की प्रक्रिया धीमी हो रही है। निशुल्क आवाजाही का यह निर्णय सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने, सुव्यवस्थित परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कारगर कदम है। इसका अनुकरण अन्य सक्षम देशों को भी करना चाहिए। भारत में उदारीकरण के बाद निजी वाहनों की संख्या में तीव्रतर वृद्धि हुई है, जिससे यहां जाम और वायु प्रदूषण की समस्या आम है। सार्वजनिक बसों एवं ऑटो में बैठ हिचकोले खाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना आखिर पसंद ही कौन करता है? देश में एक समय सार्वजनिक वाहनों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जो अब घटकर एक प्रतिशत ही रह गई है। यह चिंता की बात है। सार्वजनिक यातायात को प्राथमिकता देकर तथा छोटी दूरी साइकल से या पैदल तय कर हम भी इस दिशा में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

सुधीर कुमार

लक्जमबर्ग की सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी।

लक्जमबर्ग के लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर एक वर्ष में औसतन 400 यूरो यानी 36,000 रुपये की बचत करते हैं। इनमें बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19 प्रतिशत होता है।

आंकड़े

आईपीएल दूसरे नंबर पर

दुनिया में प्रमुख खेल लीग के प्रसारण अधिकार के मामले में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दूसरे नंबर पर पहुंच गई है।

एनएफएल	3.6
आईपीएल	1.51
ईपीएल	1.12
एमएलबी	0.96
एनबीए	0.21

नोट : आंकड़े करोड़ डॉलर में | स्रोत : Forbes

अंतर्यात्रा

संकलित

वृत्रासुर इंद्र को मारना चाहता था। इंद्र ने महर्षि दधीचि से वज्र के लिए उनकी हड्डियां मांगीं। उन्होंने कहा, मैं देह त्यागने से पहले सभी तीर्थ करना चाहता हूं।

नैमिषारण्य में सभी तीर्थ

एक बार इंद्र को अभिमान हो गया कि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति से इतना क्यों डरें। गुरु बृहस्पति के सभा में आने पर इंद्र और अन्य देवता अपने सिंहासन से नहीं उठे। देवगुरु इंद्र के मन का भाव ताड़कर उसी वक्त लौट गए।

यह बात असुरों को मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से स्वर्ग पर धावा बोलकर अधिकार कर लिया। इंद्र दौड़े-दौड़े भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा-त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। लेकिन विश्वरूप अपना हिस्सा असुरों को भी देते थे, इससे असुरों की ताकत और बढ़ गई। इंद्र को यह बात पता चली, तो उन्होंने पीछे से विश्वरूप का सिर काट लिया। इससे इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। यह बात त्वष्टा ऋषि को पता चली, तो उन्होंने इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने इंद्र को बताया कि नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियों से तुम अपना वज्र बना लो, तो वृत्रासुर को मार सकते हो।

इंद्र ने महर्षि दधीचि से प्रार्थना की, तो उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं देह छोड़ने से पहले सभी तीर्थ करना चाहता हूं। इंद्र ने सभी तीर्थ नैमिषारण्य में ही बुलवा दिए। इसके बाद इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर का वध किया।

आज का इतिहास

चीन के थ्येनआनमन चौक पर युवा प्रदर्शनकारियों पर टूटा सेना का कहर

चार जून एक ऐसी तारीख है, जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। ऐसी ही एक घटना चार जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में घटी, जहां चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसे इतिहास में थ्येनआनमन स्क्वायर नरसंहार के तौर पर जाना जाता है।1896: हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। 1936 : हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म। 1940: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया। 1944: अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया। 1958 : तीन सदस्यीय पर्वतारोही दल ने गढ़वाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 7011 मीटर ऊंचे त्रिशूल पर्वत शिखर को फतह किया।

ताकि दूर हो पानी की किल्लत

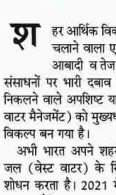

प्रयुक्त जल का प्रबंधन वर्तमान की आवश्यकता बन गया है। इसके लिए राज्य स्तर के अलावा शहरी निकायों को भी कार्ययोजना बनानी होगी।

कार्तिकेय चतुर्वेदी | उपाय

शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, तो पानी उन्हें चलाने वाला एक बेहद जरूरी ईंधन। बढ़ती आबादी व तेज शहरीकरण ने स्वच्छ जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। अब महानगरों से निकलने वाले अपशिष्ट या प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूज्ड वाटर मैनेजमेंट) को मुख्यधारा में लाना एक आशाजनक विकल्प बन गया है।

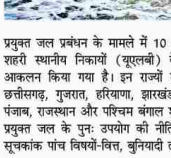

अभी भारत अपने शहरों से निकले कुल अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) के सिर्फ 28 प्रतिशत हिस्से का शोधन करता है। 2021 में उपलब्ध शोधित अपशिष्ट जल का दैनिक बाजार मूल्य 63 करोड़ रुपये आंका गया था। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की हालिया रिपोर्ट ने पहला शहरी प्रयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने रखा है। इसके माध्यम से

प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में 10 राज्यों के 503 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहां प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की नीति लागू है। यह सूचकांक पांच विषयों-वित्त, बुनियादी ढांचा, कुशलता, प्रशासन, और आंकड़े व सूचना पर शहरी स्थानीय निकायों की एक तुलनात्मक रैंकिंग करता है। हमारा विश्लेषण बताता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पानी की किल्लत का सामना करने वाले राज्यों ने प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इसकी वजह से सूचकांक में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इनमें हरियाणा शीर्ष पर है। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य भी पांच अंकों में से सिर्फ क्रमशः 1.94 व 1.74 अंक ही पा सके। यह दर्शाता है कि पूरे देश में जल सुरक्षा पर उच्च प्राथमिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। शहरी निकायों में अपशिष्ट जल शोधन और उसके पुनः उपयोग की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसे, सूरत नगर निगम ने 2019 में शोधित अपशिष्ट जल के शोधन और पुनः उपयोग के लिए एक कार्य योजना अपनाई थी, जिसका लक्ष्य 2025 तक 70 प्रतिशत और 2030 तक 100 प्रतिशत पुनः उपयोग स्तर को पाना है। भारत के शहरी स्थानीय निकायों में प्रयुक्त जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला-राज्यस्तरीय व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। इस मामले में हरियाणा से सीखा जा सकता है, जिसने 2014 से 2023 तक 73 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 433 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। अभी 10 राज्यों ने ही शोधित प्रयुक्त जल नीति लागू की है। दूसरा-राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों और मांगों के अनुरूप विशेष उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। धान उत्पादक पंजाब ने शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी है। साथ ही कृषि को पुनः उपयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। सिंचाई के लिए 5,541 हेक्टेयर क्षेत्र तक शोधित अपशिष्ट जल पहुंचाने के लिए 2020 तक 94 करोड़ रुपये की लागत से 47 परियोजनाएं पूरी कर डाली थीं। तीसरा-राज्यों को प्रयुक्त जल प्रबंधन में एक-दूसरे से सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। यह पहल गुजरात जैसे राज्यों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। यहां के चार शहरी स्थानीय निकाय -सूरत, वडोदरा, राजकोट और जामनगर प्रयुक्त जल प्रबंधन में शीर्ष 10 शहरी निकायों में शामिल हैं, जबकि राज्य पांचवें स्थान पर है, जो राज्य के भीतर विभिन्न शहरी निकायों के प्रदर्शन में अंतर को दिखाता है। शोधित अपशिष्ट जल से व्यापक आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 में उपलब्ध शोधित अपशिष्ट जल को अगर चुनिंदा बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो राष्ट्रीय स्तर पर 966 अरब रुपये का राजस्व पैदा कर सकता था।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 109 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 93

जलवायु परिवर्तन की चुनौती

मौसम के उतार-चढ़ाव की बढ़ती घटनाएं और देश के अधिकांश भागों में लू के थपेड़े हमें यह याद दिला रहे हैं कि जलवायु कितनी तेजी से बदल रही है और भारत जैसे देश पर इसका क्या असर हो सकता है। भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या को विकासशील देश अपने ही स्तर पर हल नहीं कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इस संदर्भ में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक नई रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि वर्षों तक जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं के मामले में पिछड़ने के बाद विकसित देश आखिरकार 2022 में विकासशील देशों के लिए 115.9 अरब डॉलर की राशि जुटाने में कामयाब रहे जो 100 अरब डॉलर के वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही। यह लक्ष्य 2020 के लिए तय किया गया था लेकिन दो वर्ष बाद यानी 2022 में इसे हासिल करने में कामयाबी मिली। इस वादे को पूरा करने में हुई देरी के कारण नाराजगी पैदा हुई और विकासशील देशों के मन में भविष्य की जलवायु फंडिंग के वादों को लेकर संदेह भी पैदा हुआ। ऐसे में तय लक्ष्य को पार करने को एक छोटा लेकिन अहम कदम बताया जा रहा है जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्रम में मजबूती प्रदान करेगा।

वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक हर वर्ष 100 अरब डॉलर का फंड जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके बाद 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के समय ये देश इस बात पर सहमत हुए कि 2025 तक मिलकर 100 अरब डॉलर की राशि जुटाई जाएगी और उसके बाद एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य तय किया जाएगा। यह नया लक्ष्य शायद इस वर्ष अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप29) में अपना लिया जाए। वर्ष 2022 में जो कुल राशि जुटाई गई उसमें 80 फीसदी हिस्सेदारी सार्वजनिक जलवायु वित्त (द्विपक्षीय और बहुपक्षीय) की है। निजी जलवायु वित्त हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है लेकिन अभी भी यह सार्वजनिक स्त्रोतों से हासिल फंड की तुलना में काफी कम है। कुल जलवायु वित्त का करीब 60 फीसदी उत्सर्जन कम करने के उपायों पर केंद्रित है। खासतौर पर ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में। जलवायु अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए जुटाई गई राशि काफी कम है।

बहरहाल, अधिकांश सहयोग ऋण के रूप में है, न कि अनुदान और इक्विटी निवेश के रूप में। यह जलवायु न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा चूंकि ऋण के रूप में है इसलिए इसका बड़ा अंश गैर रियायती प्रकृति का है। इससे अधिकांश क्षेत्रों और आय समूहों पर ऋण का दबाव बढ़ता है। विकासशील देशों में भी कम और मध्य आय वाले देश इसके मुख्य लाभार्थी बने रहते हैं। उसके बाद उच्च मध्य आय वाले देश आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष की राशि पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु लक्ष्य हासिल करने में विकासशील देशों की कुछ खास मदद नहीं करती नजर आती। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन के वित्तीय मदद संबंधी ताजा विश्लेषण के मुताबिक विकासशील देशों को 2030 तक करीब छह लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकता होगी। यह राशि भी उनके मौजूदा राष्ट्रीय निर्धारित सहयोग की आधी जरूरत ही पूरी कर पाएगी।

स्पष्ट है कि 100 अरब डॉलर का लक्ष्य जरूरत पर आधारित नहीं था। इसके बजाय इसने एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में काम किया जिसने विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने की विकसित देशों की प्रतिबद्धता को चिह्नित किया। जीवाश्म ईंधन परियोजना को वित्तीय मदद भी जारी है। इस क्षेत्र में नई कंपनियों को सालाना एक लाख करोड़ डॉलर तक की राशि दी जा रही है। इससे जलवायु वित्त पोषण को लेकर प्रश्न पैदा होते हैं। विभिन्न देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे पहले पर्यावरण के लिए नुकसानदेह परियोजनाओं के बारे में कुछ बुनियादी बातों पर सहमति बनाएं। इसमें डॉलर में राशि से लेकर हर देश की हिस्सेदारी तक शामिल हैं।

एआई क्षेत्र में छलांग के लिए भारतकंप्यूट होगा कारगर

भारत को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना से आगे बढ़कर अपनी विशाल प्रतिभा का लाभ उठाने पर केंद्रित हो। बता रहे हैं अजय कुमार

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमता चार प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होती है। इनमें अल्गोरिद्म, डेटा (जानकारियां), प्रतिभा और एआई कंप्यूट हैं। इन चारों में एआई कंप्यूट प्रायः सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) एआई कंप्यूट की मानक माप बन गए हैं जिसे देखते हुए पूरी दुनिया में भारी भरकम जीपीयू क्षमता तैयार करने की होड़ बढ़ गई है।

भारत सरकार ने भी एआई मिशन पहले के अंतर्गत 10,000 जीपीयू से अधिक क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में सरकार का यह निर्णय एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यह प्रयास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत पूरा किया जाना है। यह इस बात का संकेत है कि भारत निजी क्षेत्र की ताकत का फायदा उठाने में अब दिलचस्पी लेने लगा है। पहले सरकार अधिक पूंजी निवेश से पूरी होने वाली ऐसी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित रखती थी।

भारत की एआई कंप्यूट क्षमता इस खंड में विशेष मुकाम हासिल कर चुके देशों अमेरिका और चीन की तुलना में साधारण है। वर्ष 2022 में वैश्विक जीपीयू बाजार 23 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था, जिनमें 1 से 2 अरब जीपीयू मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में थे। दोनों देशों ने पिछले एक दशक के दौरान काफी तेजी से जीपीयू क्षमता हासिल की है और अपनी एआई कंप्यूट क्षमताएं बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी योजनाएं भी मौजूद हैं।

अमेरिका ने इस वर्ष जनवरी में नैशनल एआई रिसर्च रिसोर्स कार्यक्रम शुरू किया था जबकि चीन वर्ष 2025 तक 10 एक्सास्केल सिस्टम (अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रणाली) सहित कुल कंप्यूट पावर क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक इजाफा करना चाहता है। भारत को इन दोनों देशों की नकल करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसे समझदारी से काम लेना चाहिए और कोई कदम उठाने से पहले बाजार में दिखने वाले परिणामों पर नजर रखनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को मैं भारतकंप्यूट कहता हूं।

अब प्रश्न यह है कि एआई कंप्यूट इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है? एआई में पेचीदा कार्य (प्रशिक्षण एवं एआई मॉडल का परिचालन आदि) करने के लिए आवश्यक गणना शक्ति (कंप्यूटेशनल पावर) को 'कंप्यूट' कहा जाता है। यह डीप लर्निंग मॉडल को संतुलित एवं आवश्यक स्तर तक ले जाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, कंप्यूट पावर तत्काल प्रतिक्रिया (रियल-टाइम इंटरफरेंस) के लिए जरूरी है जिससे नए डेटा को लेकर अनुमान लगाना आसान हो जाता है। लार्ज लैंग्वेज-मॉडल (एलएलएम) की गणना संबंधी आवश्यकताएं बढ़ने से पिछले एक दशक के दौरान दुनिया में एआई कंप्यूट की मांग काफी बढ़ी है। मगर अब एलएलएम हर जगह उपलब्ध हो गई है इसलिए एआई कंप्यूट की मांग स्थिर होने लगी है और सबकी नजरें अब इमेज प्रोसेसिंग मॉडल, गेमिंग, मल्टी-मोडल एआई और अन्य मॉडलों पर टिक गई हैं। ये ऐसे मॉडल में जिनमें कम कंप्यूट पावर की जरूरत होती है। भारतकंप्यूट आर्थिक, सामाजिक एवं रणनीतिक खंडों में आधारभूत प्रारूप विकसित करने को प्राथमिकता दे सकता है और इस क्रम में वह मौजूदा ओपन सोर्स एलएलएम का फायदा उठाएगा। कम कंप्यूट संसाधनों के साथ भी यह दृष्टिकोण लाभकारी प्रतीत हो रहा है।

भारतकंप्यूट को एआई में प्रगति के लिए भारत की मौजूदा सेंट्रल प्रोसेसिंग (सीपीयू) आधारित कंप्यूट पावर का लाभ लेने पर विचार करना चाहिए। भारत में मजबूत सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग और उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या व्यापक स्तर पर सीपीयू-आधारित कंप्यूट पावर उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह, जीपीयू में भारत की कमजोर स्थिति की भरपाई हो जाती है। एआई कार्यों के लिए सीपीयू धीमा होने के बावजूद इस संसाधन का लाभ उठाने से लागत में कमी के अलावा अन्य लाभ भी मिलेंगे।

भारतकंप्यूट पहल सरकार द्वारा स्थापित एआई कंप्यूट ढांचे की हिमायत करती है जो उन लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जो बाजार दरों पर इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इस समय एआई कंप्यूट पर प्रति जीपीयू घंटा 1 से 4 डॉलर का खर्च आता है और इसके साथ मेमरी और आईटी ढांचे पर आने वाले अतिरिक्त खर्च भी शामिल होते हैं। एआई स्टार्टअप की संख्या बढ़ने के बाद सरकार से मिलने वाली सब्सिडी से ऐसी और इकाइयां एआई क्षेत्र में कदम रख सकती हैं। स्टार्टअप भारतकंप्यूट की सफलता में बड़ा योगदान दे रही हैं। सरकार भारतीय जरूरतों के हिसाब से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल सहित अन्य खंडों में भी आधारभूत मॉडल विकसित करने को प्राथमिकता दे सकती है।

भारतकंप्यूट को भारत की संप्रभु एआई आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, खासकर रणनीतिक एवं सुरक्षा खंड में। इस समय एआई कंप्यूट बाजार काफी हद तक क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है जिस पर अमेरिका और चीन की इकाइयों का दबदबा है। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका स्थित एमेजॉन वेब सर्विसेस, माइक्रोसॉफ्ट एजर और गूगल क्लाउड का दुनिया में सार्वजनिक क्लाउड बाजार के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण है। शेष बाजार के एक बड़े हिस्से पर चीन की तकनीकी कंपनियों अलीबाबा, हुआवे और टेनसेंट का नियंत्रण है। पब्लिक क्लाउड के साथ निजता एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। सुरक्षा एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए भारतकंप्यूट के लिए यह जरूरी है कि कंप्यूट ढांचा भारत में हो और यह एक भारतीय क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे। सरकार संवेदनशील या वर्गीकृत ऐप्लिकेशन के लिए कंप्यूट ढांचे का एक भाग सुरक्षित एवं नॉन-क्लाउड परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से रख सकती है।

पीपीपी ढांचे पर एआई कंप्यूट क्षमता स्थापित करना एक स्वागत योग्य कदम है। भारतीय वेंडरों की एक सूची बनाकर इसे परिचालित किया जा सकता है। ये वेंडर 10,000 जीपीयू के कोष में योगदान देते हैं। एक नया संयंत्र स्थापित करने की तुलना में ऐसी प्रक्रिया काफी तेज होगी और लागत के अनुकूल एवं उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देने वाला तंत्र भी सुनिश्चित करेगी। निजी क्षेत्र अपने साथ संसाधन, कौशल एवं नवाचार लेकर आएगा। मगर पीपीपी ढांचे की संभावित त्रुटियों को भी दूर करना होगा। मसलन, वेंडर बदलने की स्थिति में निरंतरता बनाए रखना, वेंडर लॉक-इन से बचना, डेटा सुरक्षा एवं निजता संबंधी विषय और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों एवं स्टार्टअप तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी होगा। लिहाजा, भारतकंप्यूट का प्रबंधन एक स्वायत्त इकाई करे तो अच्छा होगा। इस इकाई का नेतृत्व पेशेवर विशेषज्ञता वाले उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। इस इकाई में सरकारी प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होनी चाहिए।

एआई कंप्यूट बाजार अब भी शुरुआती अवस्था में है। भारतीय उद्योग जगत एआई कंप्यूट ढांचे का तेजी से विकास कर रहा है। कुछ कंपनियां निजी इस्तेमाल के लिए इसका विकास कर रही हैं और अन्य सेवा के रूप में इसकी पेशकश कर रही हैं। मगर भारतकंप्यूट को 10,000 जीपीयू स्थापित करने तक ही सीमित रहकर कुछ अन्य उपाय भी करने चाहिए। इसे तुलनात्मक रूप से बड़े एआई कंप्यूट बाजार को आगे बढ़ाना चाहिए और उद्योग जगत को क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 10,000 जीपीयू के लिए घरेलू कंपनियों को तरजीही पहुंच देने से उद्योग जगत को अत्यंत जरूरी शुरुआत मिल सकती है। एआई कंप्यूट ढांचे में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए करों में छूट का प्रस्ताव और संस्थापक मॉडलों के लिए एआई चिप-विकास जैसे सुझाव कारगर साबित हो सकते हैं।

भारत में बढ़ता कस्टमाइज एआई चिप का बाजार तेजी से उभरती संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। एनवीडिया का विकास, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन का 7 लाख करोड़ डॉलर का चिप निर्माण उद्यम और माइक्रोसॉफ्ट एवं एमेजॉन का एआई चिप डिजाइन में प्रवेश से यह बात साबित हो जाती है। चिप डिजाइन में भारत के पास क्षमताओं की कोई कमी नहीं है और इसके बूते वह इसमें अवसरों का लाभ उठाने के लिए मजबूत स्थिति में दिख रहा है। एआई में आगे कदम बढ़ाने के लिए भारतकंप्यूट एक रणनीति के तहत शुरू की गई है।

(लेखक आईआईटी कानपुर में अतिथि प्राध्यापक एवं पूर्व रक्षा सचिव हैं)

स्टोर और ऑनलाइन बिक्री का संयोजन देगा अपार मौके!

महामारी का दौर खत्म होने के बाद से ही दुकानों में खरीदारों की अपार भीड़ देखी जा रही है। आप किसी भी सप्ताहांत मॉल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि स्टोर में आपकी मदद के लिए कोई कर्मचारी खाली नहीं मिलेगा। आपको जिस साइज या रंग वाली चीजों की तलाश होगी उसे पाना मुश्किल होगा। मुमकिन है कि आप यह भी सोच लें कि आपका वहां जाना ही व्यर्थ था और आप उन चीजों को आसानी से ऑनलाइन ढूंढ़ सकते थे और ये चीजें किफायती भी मिल सकती थीं। लेकिन जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तब आप चीजों को खरीदने से पहले छू कर और उसे महसूस कर देखना चाहते हैं।

नतीजतन अब स्मार्ट रिटेलर इस अंतर को महसूस करते हुए इसे अपने कारोबार के लिए एक बेहतर मौके के तौर पर देख रहे हैं ताकि ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाते हुए स्टोर और ऑनलाइन बिक्री को जोड़कर संचालन की रणनीति (ब्लेंडेड कॉमर्स) की ताकत का फायदा उठाया जाए। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है लेकिन रिटेलर अब इस तरह के कारोबार के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं जिसमें ग्राहकों को बाधारहित खरीदारी का अनुभव मिले।

आप किसी एक ऐसे ग्राहक की कल्पना करें जो किसी स्टोर में दफ्तर के किसी खास मौके पर पहने जाने के लिए एक ड्रेस की तलाश में जाते हैं। अगर यह ड्रेस वहां उपलब्ध नहीं है तब क्या स्टोर का कोई सहायक कर्मचारी अपने सिस्टम से यह जांच करके पता कर पाएगा कि शहर के किसी स्टोर में वह ड्रेस स्टॉक में उपलब्ध है या नहीं? अगर यह स्टॉक में है तब क्या वह उस ग्राहक के लिए उसे रिजर्व कर देंगे और ग्राहकों को यह विकल्प देंगे कि वे उसे उस स्टोर से ले लें या फिर उस ड्रेस की डिलिवरी समय पर उनके घर पर कर दी जाएगी? अगर स्टोर के सीमित स्टॉक से इतर ज्यादा विकल्प उपलब्ध है तब क्या सहायक खरीदारों को ऑनलाइन खरीदारी के अनुभव के साथ वह सामान चुनने का विकल्प दे सकते हैं और उसे निश्चित समय-सीमा के भीतर नजदीकी वेयरहाउस से उसकी डिलिवरी करा सकते हैं?

ऐसे में ऑफलाइन स्टोर की एक नई भूमिका तैयार हो रही है। यह न केवल उपलब्ध सामान को दिखाने के साथ ही ग्राहकों को चीजें आजमाने का मौका भी देता है। इसके अलावा यहां सामान की बिक्री पर स्टोर कुछ अतिरिक्त लाभ की पेशकश भी करते हैं, अगर ग्राहक अपने किसी नजदीकी स्टोर या वेयरहाउस से डिलिवरी कराने के लिए तैयार हों। ऑफलाइन स्टोर में ऑनलाइन जैसी सहूलियत दिए जाने वाला ब्लेंडेड कॉमर्स रिटेल क्षेत्र के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर तब जब भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश को कवर करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। टियर-1 शहरों और इससे इतर भी मौके मिलने शुरू हो गए हैं। बड़े रिटेलर भी अब स्टोर खोलने के लिए तैयार हैं लेकिन इसमें वक्त लगेगा।

रणनीतिक कदम

इंद्रजित गुप्ता

ऐसे में अगर सावधानी से सोच-विचार करके ई-कॉमर्स और ऑफलाइन स्टोर का मिला-जुला रूप तैयार हो तब इस अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।

हालांकि इसके बारे में कहना आसान है करना मुश्किल होगा। एक बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर ने यह पाया कि स्टोर का विस्तार काफी धीमा और जटिल है। ऐसे में इसके लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और आपूर्ति श्रृंखला परिचालन का नियंत्रण लेकर ई-कॉमर्स का विस्तार बड़े पैमाने पर करना एक बेहतर समाधान हो सकता था। ऐसा माना जाता है कि सेवा के स्तर में सुधार, तेज डिलिवरी और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कंपनी ने अपना खुद का एक बड़ा गोदाम बनाया और उसे चलाने के लिए एक लॉजिस्टिक्स साझेदार को जोड़ा। गोदाम की आधी जगह ई-कॉमर्स का सामान रखने के लिए तय की गई थी।

लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनका ई-कॉमर्स का कारोबार सफल नहीं हो सका। ग्राहक दुकानों पर ही सामान खरीदने आते रहे और कंपनी को अतिरिक्त गोदाम के लिए किराये के साथ और अधिक शुल्क चुकाना पड़ा। अब, इस तरह के करार में बंधे होने के कारण इस जटिल व्यवस्था से बाहर निकलना आसान नहीं था। ऐसे में समझदारी वाला तरीका यही होता कि शुरुआत में किसी तीसरे पक्ष के गोदामों का इस्तेमाल किया जाए जब तक कि ऑनलाइन बिक्री न बढ़े और अपना खुद का गोदाम बनाना आर्थिक रूप से फायदेमंद न हो जाए।

दूसरा विकल्प है, स्टोर आधारित आपूर्ति। भारत में, इस साल की शुरुआत में, आइकिया ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 62 जिले में लोगों के घरों तक डिलिवरी की पेशकश करने के लिए अपना कारोबार बढ़ाने की घोषणा की। अलग से गोदाम स्थापित करने के बजाय, कंपनी हैदराबाद, बेंगलूरु और मुंबई में अपने बड़े स्टोरों का इस्तेमाल मांग पूरी करने और 7-10 दिन के भीतर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए करेगी। आईकिया को उम्मीद है कि वह अगले साल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अपना पहला स्टोर खोलेगी, जिससे इसे उत्तर भारत के बाजारों में अपने ई-कॉमर्स कारोबार का विस्तार करने का मौका मिलेगा।

ऐसे बड़े स्टोर न सिर्फ गोदाम के तौर पर काम करते हैं, जिससे लागत कम होती है बल्कि इनके काम करने का तरीका भी आसान हो जाता है। यही नहीं, अमेरिका में वॉलमार्ट ने अपने बड़े सुपरस्टोर के नेटवर्क को ही फुलफिलमेंट सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया है। वहां लगभग 90 प्रतिशत ग्राहक वॉलमार्ट सुपरस्टोर से एक घंटे की दूरी वाले दायरे में रहते हैं और उनके पास बड़ी गाड़ियां भी होती हैं। ग्राहक खासतौर पर किराने के सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर देना पसंद करते हैं और काम से घर वापस आते समय नजदीकी स्टोर से खुद सामान ले जाते हैं। भारत में, स्थिति थोड़ी अलग है। यहां कारों की संख्या कम है और शहर का ट्रैफिक भी अप्रत्याशित होता है। इसलिए, आमतौर पर लोग सामान सीधे घर मंगवाना पसंद करते हैं।

ब्लेंडेड कॉमर्स को सफल बनाने के लिए, इन ऑफलाइन स्टोर और ई-कॉमर्स टीमों के बीच एक समान दृष्टिकोण, रणनीति और टीम के साथ मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है। दुकानों की मर्केंडाइजिंग टीम को आमतौर पर अपने आसपास के ग्राहकों की पसंद की बेहतर समझ होती है। ई-कॉमर्स टीमें इसका शुरुआती स्तर पर लाभ उठा सकती हैं। निश्चित रूप से खरीदारी प्रक्रिया को समझना (चाहे दुकान से हो या ऑनलाइन) ग्राहकों को एक बेहतर अनुभव देने के लिए आवश्यक है।

(लेखक फाउंडिंग फ्यूल के सह संस्थापक हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

अग्निकुल के अग्निबाण ने रचा नया इतिहास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास से जुड़ी अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल द्वारा निजी प्रक्षेपण केंद्र से पहला थ्री-डी प्रिंटेड रॉकेट का प्रक्षेपण बहुत गौरवान्वित करने वाला पल था। ऐसी हाइब्रिड सेमी क्रायोजेनिक इंजन की सुविधा तो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अभी विकसित ही कर रहा है। यह बात और भी गौरवशाली है कि अग्निबाण अपनी तरह का विश्व में पहला रॉकेट है। एक स्टार्टअप की यह उपलब्धि निश्चित रूप से विज्ञान क्षेत्र में शोध कर रहीं कंपनियों और स्टार्टअप के लिए बहुत प्रेरणा-दायक है। इसके पहले भी एक अन्य स्वदेशी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम एस को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। भारत की शोध एवं नवोन्मेष में 40 वें स्थान की रैंकिंग है परंतु चंद्रयान-3 और आदित्य एल-1 ने विश्व में सर्वश्रेष्ठता दिला दी है। अग्निबाण हमारे विभिन्न

बीते दिनों अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने निजी प्रक्षेपण केंद्र से पहले थ्री-डी प्रिंटेड रॉकेट का प्रक्षेपण कर देश में नया इतिहास रच डाला

इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के छात्रों को ऐसी ही उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है। हमारे माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालय अपने सिलेबस में इस प्रकार की स्वदेशी उपलब्धियों को समाविष्ट करके किशोर छात्रों को भविष्य के वैज्ञानिक बनाने में प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम आधुनिकतम वैज्ञानिक शोध एवं तकनीकी सूचना के लिए विदेश में तलाश करते हैं परंतु देश में ही विश्व के आधुनिकतम वैज्ञानिक शोध उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश भर में हरेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक उत्कृष्ट साइंस कॉलेज चिह्नित कर सकता है जहां सभी शोधकर्ता और शोध प्रेमी छात्र वहां प्रवेश लेकर आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। शिक्षा को सरकार के भारी बजट की आवश्यकता है। छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो, ऐसे प्रयास विद्यालयों में होना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

हर साल तेजी से बढ़ रही बैंकिंग धोखाधड़ी

देश में एक साल में बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाएं 166 प्रतिशत बढ़ी हैं। साल 2023-24 में कुल 36,075 लोग बैंक धोखाधड़ी के शिकार हुए। उससे पहले साल 2022-23 में इनकी संख्या 13,564 की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 80 प्रतिशत धोखाधड़ी क्रेडिट, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी थी। 11 प्रतिशत धोखाधड़ी डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी थी। 5.5 फीसदी लोग बैंकों में नकद जमा कराने के दौरान फर्जीवाड़े के शिकार हुए। साल 2022-23 में धोखाधड़ी की इन्हीं घटनाओं के कारण लोगों ने 26.12 हजार करोड़ रुपये गंवाए हैं जो 2023-24 में घटकर 13. 93 हजार करोड़ रुपये रह गए। रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट निश्चित ही चौंकाने वाली है। साथ ही सचेत होने की भी जरूरत है। भले ही धोखाधड़ी की राशि 2023-24 में कम हुई है फिर भी अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इस तरह गंवाना लोगों के लिए भारी नुकसान है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत', उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सोमवार को ताज एक्सप्रेस के तीन डिब्बों में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है और सभी यात्री समय रहते प्रभावित डिब्बों से बाहर निकलने में सफल रहे। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चला है।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । मंगलवार, 4 जून 2024

संस्था की गरिमा

18वीं लोकसभा के लिए पड़े मतों की गिनती का समय करीब आने के साथ ही नतीजों को लेकर गहमागहमी बढ़ना स्वाभाविक है। इस क्रम में अगर दोनों पक्ष चुनाव आयोग (EC) के सामने अपनी आशंकाएं रख रहे हैं तो इसे भारत के धड़कते लोकतंत्र का प्रमाण माना जा सकता है। बशर्ते सभी पक्ष यह सावधानी बनाए रखें कि उनकी शिकायतें चुनाव आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने की हद तक न चली जाएं।

EC का सही कदम | इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतगणना की तारीख से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन पक्ष-विपक्ष की ओर से जिस तरह के बयान जारी हो रहे थे, उसके मद्देनजर मीडिया के जरिए देशवासियों के सामने चुनाव से जुड़ी अहम सूचनाएं स्वयं रखने का यह फैसला सराहनीय है।

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कम पुनर्मतदान | हर बार की तरह इस बार भी देश में चुनाव के दौरान कई वर्ल्ड रेकॉर्ड बने। लेकिन चुनाव आयोग की सतर्कता और कौशल की कसौटी पर देखें तो यह तथ्य अहम है कि इस बार पुनर्मतदान पिछले चुनावों के मुकाबले काफी कम रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 540 पुनर्मतदान हुए थे, लेकिन इस बार यह संख्या महज 39 रही। उनमें भी 25 रीपोलिंग केवल दो राज्यों में हुई।

सही सबक | एक अच्छी बात यह रही कि चुनाव आयोग ने इस बार के अनुभव से यह सही सीख ली और उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया कि इतनी भीषण गर्मियों में इतना लंबा चुनाव करवाना उचित नहीं था। चुनाव एक महीने पहले समाप्त हो जाना चाहिए था। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे चुनाव कार्यक्रम तय करते हुए आयोग इस सबक को ध्यान में रखेगा।

आरोप-प्रत्यारोप | इसमें शक नहीं कि हाल के वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपसी रिश्तों में थोड़ी तल्खी बढ़ी है। इसका प्रभाव दोनों तरफ से होने वाले बयानों और एक-दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोपों पर दिखना स्वाभाविक है। लेकिन इस क्रम में अगर संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर अनावश्यक संदेह का माहौल बनने लगे तो यह चिंता की बात है।

दलों की बदलती भूमिका | चुनाव में जीत-हार होती रहती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर दलों की भूमिका में बदलती रहती है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया की प्रामाणिकता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता एक राष्ट्र के रूप में हमारी ऐसी उपलब्धि है, जिस पर गर्व किया जा सकता है। देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिहाज से भी यह ऐसी थाती है जिसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। बेहतर होगा कि सभी राजनीतिक दल चुनावी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ते हुए भी इस बात का ख्याल रखें।

धूप-छांव

पल दो पल

प्रणव प्रियदर्शी

एक पल और दूसरे पल के बीच फर्क यूं देखिए तो कुछ नहीं। इतना भी नहीं कि इन पलों को एक-दूसरे से अलग कर सकें। बड़ी मुश्किल से कैलेंडरों और घड़ियों के सहारे इन्हें एक-दूसरे से अलग करके देखने का जतन किया है हमने, लेकिन सारे प्रयास एक तरह से बेकार ही हैं। हमने मुंह में कौर लिया इस पल और उसे गटक गए दूसरे पल। अब इन दोनों पलों के बीच अंतर भला कौन और कैसे नोट करे। नोट करके भी क्या होना है। मगर ये दोनों पल एक हैं नहीं। एक पल में मुंह में लिया गया कौर अगर दूसरे पल गटकते हुए गले में अटक जाए तो दो पलों के बीच की दूरी अचानक मीलों लंबी लगने लगती है। तब पता चलता है कि ये दूरी तो इतनी लंबी है कि शायद अनंत काल में भी पाटी न जा सके।

मगर यह अपवाद है। जिंदगी और मौत अगर पलों को अलग करने लगे तो फर्क तो विकराल हो ही जाएगा। इसलिए चुनना हो तो 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह को लेना चाहिए। इनके बीच फर्क को हमने चाहे जितना भी महिमामंडित कर दिया हो, हकीकत यही है कि वह सुबह किसी भी सामान्य सुबह जैसी ही होती है। सुबह उठिए तो घर-परिवार, दोस्त-मित्र, रिश्तेदार-सहकर्मी सब पिछली रात जैसे ही होते हैं। हालात भी कमोबेश वैसे ही होते हैं। फिर फर्क कहां हुआ? फर्क होता है हमारे महसूस करने में। हम मानते हैं कि नया साल आ गया और यह साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उम्मीदों से भरा है। यह उम्मीद ही आने वाले हर नए पल को ताजगी देती है। वही इसे पुराने पलों से अलग करती है।

यह उम्मीद ही है जो इन पंक्तियों के लिखे जाने और इनके पढ़े जाने के बीच के फर्क को रेखांकित कर रही है। जब ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं तब हम सब यानी यह पूरा देश एक रहस्य में लिपटा हुआ है। चुनाव हो चुके हैं। वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। जनादेश EVM में बंद हो चुका है। एग्जिट पोल हों या विश्लेषकों का अपना अलग-अलग आकलन- सब इस बात की कयासबाजी है कि वोटर के उस जनादेश में क्या लिखा है। इन आकलनों और कयासों की टकराहट का रोमांच भी कम मजेदार नहीं। लेकिन वास्तविक रिजल्ट जानने की उत्कंठा को यह रोमांच कम नहीं कर सकता।

तो आज की तारीख में रोमांच और उत्कंठा के बीच के अंतराल को जो चीज भर रही है वह है उम्मीद। सवाल यह है कि जो भी नतीजा आएगा उसे हम वैसी ही उम्मीद के साथ देख पाएंगे जैसे नए साल की पहली सुबह को देखते हैं, जैसे हर नई सुबह को देखना चाहिए?

बोल वचन

चिमिरखी राज

राहुल पाण्डेय

कुछ शब्द जुबान पर तो रहते हैं, लेकिन शब्दों के बाजार में उन्हें कहीं भी जल्दी दुकान यानी शब्दकोश में जगह नहीं मिल पाती है। चिमिरखी ऐसा ही एक शब्द है। चिमिरखी, यानी दुबला-पतला चंचल युवक या युवती। लेकिन यह सिर्फ इंसानों के लिए ही यूज नहीं होता। पेड़-पौधों से लेकर कुत्ते और बैल के लिए भी इसका प्रयोग होता है। किसी का कुत्ता अगर बहुत पतला-दुबला है तो अवध की ओर उसे कहते हैं कि ये तो एकदम चिमिरखी है। लेकिन जब यह शब्द इंसानों में आता है, तो यह व्यवहार भी बन जाता है। अगर कोई बात-बात पर बहुत चंचल होता है, तो उसे डांट लगाकर कहते हैं- ज्यादा चिमिरखीपना ना करो। यानी ज्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है। और जैसी कि रीत रही है, लोक व्यवहार नाम भी बन जाते हैं, चिमिरखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाजीपुर में चकबंदी की एक फाइल में मुझे एक महिला का नाम चिमिरखी देवी लिखा मिला, तो बस्ती जिले के कुछेक सरकारी कागजात में से चिमिरखी प्रसाद भी झांकते दिखाई दिए। चिमिरखी के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। हो भी नहीं सकता, क्योंकि खुद हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, सिवाय इसके कि दुबला-पतला कुपोषित सा शख्स। लेकिन चिमिरखी खूब हैं। किसी भी साल की भारत की कुपोषण की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। चलिए, वो थोड़ी गंभीर बात है, उसे मत देखिए, रील्स ही देख लीजिए। हर जगह इन दिनों चिमिरखियों का धमाल है। दुनिया ने भले उन्हें किनारे कर रखा हो, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में अक्सर उन्हीं का राज चलता है।

Subrata Dhar

अदालत में दोषी करार दिए जाने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं

राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का क्या होगा

रहीस सिंह

मैनहटन कोर्ट में जैसे ही ज्यूरर्स से पूछा गया कि वे किस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो एक ज्यूरर ने माइक्रोफोन में कहा, 'दोषी'। ट्रंप ने आंखें बंद की और 'नो' में सिर हिला दिया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की तरह ही अमेरिका की जनता भी इस अपराध से आंखें मूंद लेगी और ट्रंप को वोट करेगी?

फुल स्टॉप या स्पीड ब्रेकर | मई की शुरुआत में ABC न्यूज और इप्सोस सर्वेक्षण में 16% ट्रंप समर्थकों को यह कहते पाया गया था कि यदि उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो वे अपने समर्थन पर फिर से विचार करेंगे, जबकि 4% ने कहा था कि वे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब सवाल उठता है कि कोर्ट का यह फैसला ट्रंप के राजनीतिक जीवन के आगे 'फुलस्टॉप' लगाएगा या सिर्फ 'स्पीड ब्रेकर' साबित होगा? दूसरे विकल्प की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ट्रंप ने बड़ी सावधानी के साथ इस कहानी को गढ़ा है कि कुछ ताकतें उन्हें सत्ता से बाहर रखना चाहती हैं।

कांटे की टक्कर | यह कहानी 'पोस्ट ट्रुथ' थिअरी को और पक्का करेगी जो ट्रंप को अमेरिका का पूरक बनाकर पेश करती रही है। मैनहटन कोर्ट ने ट्रंप को 'हश मनी' से संबंधित सभी 34 मामलों में दोषी पाया है। 11 जुलाई को उन्हें इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। स्वाभाविक है कि ट्रंप इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन जनता क्या करेगी? अब तक पोल्स से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को हल्की सी बढ़त भी मिलती दिख रही है, लेकिन अभी इन्हें परिणामों के रूप में नहीं देख सकते। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

डॉनल्ड ट्रंप से क्या हैं आशंकाएं
- यूरोपीय हितों के खिलाफ जाएंगे
- यूक्रेन युद्ध से पीछे हटने का डर
- पूतिन की जीत का रास्ता होगा साफ

ट्रंप को नुकसान नहीं | इतिहास बताता है कि ऐसे मामले अमेरिका में विशेष महत्व नहीं रखते। बिल क्लिंटन सहित कई राष्ट्रपतियों से संबंधित स्कैंडल्स पर जनता की प्रतिक्रिया से सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसी संदर्भ में रिपब्लिकन वुमन फॉर प्रोग्रेस की सह संस्थापक ए एच डेविस कहती हैं कि मुझे नहीं लगता यह मामला उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाएगा।

विक्टिम कार्ड | फिर यह बात भी है कि ट्रंप विक्टिम कार्ड खेलने वाले पुराने महारथी हैं। यदि वे यह कार्ड सही ढंग से खेल गए तो आश्चर्य नहीं कि नुकसान के बजाय यह मामला उन्हें फायदा पहुंचा जाए। वे अमेरिकी मतदाता उनके साथ खड़े दिखेंगे जो 'पोस्ट ट्रुथ' थिअरी से प्रभावित हैं। वे यह मानकर चल रहे हैं कि उनके नेता में लाख खामियां हों पर वही सर्वश्रेष्ठ हैं, अमेरिका को फिर से महान वही बना पाएंगे।

बाइडन की खामियों पर फोकस | ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि ट्रंप का असल उभार अभी बाकी है? इसकी संभावना इसलिए भी दिखती है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्य कमिटमेंट के साथ इसे ट्रंप की शहादत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और जनता का ध्यान ट्रंप के आचरण और व्यवहार से हटाकर जो बाइडन की खामियों पर केंद्रित कर रहे हैं। ट्रंप अपने नाटक की पटकथा पहले ही लिख चुके हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि बाइडन प्रशासन उनकी हत्या का आदेश दे चुका है। साफ है कि ट्रंप अपने समर्थकों और मतदाताओं को पहले ही बता चुके हैं कि कोर्ट यही निर्णय करेगा और यह कोर्ट का निर्णय नहीं होगा बल्कि बाइडन प्रशासन का निर्णय होगा। अब यदि यह कहानी ठीक से जनता के बीच पहुंच गई तो ट्रंप को कौन रोक पाएगा!

ऐतिहासिक चुनाव | बहरहाल, सर्वेक्षणों में ट्रंप अभी राष्ट्रपति बाइडन से आगे दिख रहे हैं। लेकिन प्रफेसर एलन लिक्टमैन का मानना है कि ये सर्वेक्षण 'स्नैपशॉट' हैं, जिनका चुनाव के संदर्भ में अभी कोई खास मूल्य नहीं है। जो भी हो, अमेरिका नई चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है और ये चुनौतियां अमेरिका के मौलिक चरित्र को धीरे-धीरे खत्म कर रही हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चुनाव अमेरिका के लिए ऐतिहासिक महत्व का होगा।

यूक्रेन युद्ध का सवाल | एक बात और, यूरोपीय देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की संभावना को लेकर डरे हुए हैं। उनकी नजर में ट्रंप अमेरिका-यूरोप रिश्तों के लिए बेहतर साबित नहीं होंगे। पिछले कार्यकाल में उन्होंने यूरोपीय हितों के खिलाफ काम किया था। ट्रंप की छवि एक अस्थिर व्यक्तित्व वाले नेता की है। इसलिए अमेरिकी विदेश नीति पुनः अनिश्चितता की तरफ जा सकती है। ट्रंप के चुने जाने से संभवतः यूक्रेन युद्ध की भी दिशा बदल जाए। यूरोपीय देशों को आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध से पीछे हट सकते हैं। ऐसा हुआ तो रूसी राष्ट्रपति पूतिन यूक्रेन पर कब्जा करने में सफल हो जाएंगे। ऐसी कोई भी घटना विश्व राजनीति की दिशा बदल देगी।

लोकतंत्र की चिंता | जो भी हो, यदि कैपिटल हिल जैसी घटना के बाद भी ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वह अमेरिकी राजनीति के लिए अपरिहार्य हो चुके हैं। और अगर ऐसा है तो अमेरिका को अपने लोकतंत्र की चिंता करनी शुरू कर देनी चाहिए।

(लेखक विदेश मामलों के जानकार हैं)

करप्शन का 'क' बोलके बेज्जत नईं होने का!

दीपक पाचपोर

भिड़ू, क्या तुम बताने कूं सकताए कि अबी इलेक्शन का टाइम पे अक्खा लोग किस बात कूं लेके सबसे जास्ती मगजमारी करताए? इलेक्शन का बखत में बोले तो जास्ती लोग एक बात का भीतर सबसे जास्ती टाइम पास करताए - कऊन जीतेंगा? सबका एकईच टेंशन होताए। तुम सोचेंगा कि वोटर इस वास्ते सोचता होएंगा कि उसका आईडियालॉजी वाला जीतेंगा कि हारेंगा। तो अईसा नईं, ब्रादर! इदर आईडियालॉजी गएली तेल लेने कूं। तुमारा टेंशन खाली एकईच होताए कि तुमारा जान-पैचान वाला, सगा वाला, गांव वाला जीतेंगा कि नईं।

अपुन का खास फ्रेंड बाबूराव अपुन कूं टोटल आईडिया दिएलाए कि जास्ती आईडियालॉजी के पीछे रखड़ने का नईं। पैले ये देखने का कि तुमकूं इदर कोई काम पड़ताए तबी तुमारा बाजू में कऊन खड़ा होएंगा। कबी बोले तो तुमारा वो पॉवर कंपनी वाला आके मीटर का आड़ा तिरछा बिलिंग करके बोले उत्ता बिल फाड़ के जाएंगा। बाजू वाला तुमारा प्लॉट दो फुट बढ़ाके भीतर लेंगा, तुमारा छोकरा अच्छा कॉलेज मांगताए पन उदर का प्रिंसिपल मचमच करताए तबी तुमारा बात सुनके लेने वाला कोई मांगताए कि नईं?

बाबूराव कहेला कि जिस दिन कूं इलेक्शन का नोटिस आताए उसी दिन का फर्स्ट डे से वो पत्ता करेंगा कि कऊन कूं तिकिट मिलताए। वो किदर कूं रहताए? कोई को बी इलेक्शन का भीतर खड़ा होन दो, तुमकूं बस इत्ताईच करने का कि उसका टच में रैने का। काम होएंगा तो बी ठीक, नईं होएंगा तबी बी वांदा नईं। वईसा तुमकूं क्या लगताए कि तुमारा खासदार, सांसद कोई बी होन दो, तुमारा वास्ते क्या करेंगा? थोड़ा सोच के बोलने का! पैले तुम सोचताए कि घर का बाहर साफ-सफाई का कम्प्लेंट करेंगा। तुम जबी एमपी का बेंग्लो में जाएंगा तबी उसका पीए तुमकूं एसी रूम का भीतर बईठाएंगा। पानी लेके उसका प्यून आएंगा। तुम सोचेंगा कि अपना टोटल प्रॉब्लेम उसकूं बताएंगा पन जबी एमपी बाहेर आएंगा तबी तुम सोचेंगा कि अईसा हल्का बात करेंगा तबी इंप्रेशन अच्छा नईं गिरेंगा। इस करके तुम अपना राज्य का टोटल प्रॉब्लेम का बात करने का सोचेंगा।

Ai Image

खाली पीली

फिर तुमारा दिमाग का भीतर आएंगा कि आईल्ला, इसकूं तो अपुन दिल्ली का काम करने का वास्ते बैठाएला। फिर इदर स्टेट का लफड़ा काएंकू लेके बैठने का? तुम कहेंगा कि 'कंट्री का भीतर महंगाई भौत हुएला। सबका रेट कमती करना मांगताए।' वो मुंडी हिलाके कहेंगा- 'करताए.., कुछ करताए!' तुमारा बात पूरा बी नईं होएंगा तबी तुमारा नेता बोलेंगा कि इस पे बाद में बात करेंगा। अबी उसकूं कोई अर्जेंट मीटिंग में जाना मांगताए।

भिड़, तुम समजा कि नईं? अक्खा लोचा इदरईच होताए। महंगाई होएंगा, छोकरा लोग बिगर काम-धंधा का टाइम खोटी करताए तबी मेन प्रॉब्लेम करप्शन का होताए पन तुमकूं बोलने नईं देंगा। तुमारा बोलने का पैलेईच साहेब का मीटिंग आएंगा। इस करके जबी कोई नेता कूं मिलने का वास्ते जाएंगा न, कोई बी बात करने का पन मुं से करप्शन का बात नईं निकालने का। अबी तुम सोचता होएंगा कि खाली सत्ता पक्ष वाला का पास करप्शन का 'क' मुं से नईं निकालने का, तबी अईसा नईं। कोई बी पक्ष होन दो - करप्शन पर चुप बईठने का। ।

फाइनल सल्ला तुमकूं इत्ताईच देताए कि जबी करप्शन का बात नईं करने का तबी महंगाई, बेरोजगारी का बात करके तुमकूं क्या मिलेंगा? भाऊ से हात मिलाने का, चा पीने का अऊर पतली गल्ली से निकल जाने का। जान-पैचान भी रहेंगा, मान बी रहेंगा अऊर बेज्जत भी नईं होएंगा। उसकूं बी बेज्जत नईं करने का।

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं
nbtreader@timesgroup.com पर,
और सब्जेक्ट में लिखें-**'खाली पीली'**

इलेक्शन में फिर काम कर गया मोदी का नाम?

नरेन्द्र नाथ

इस आम चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का नाम चला। पार्टी और उम्मीदवार को पीछे रखते हुए मोदी ने एक रणनीति के तहत पूरे देश में अपने काम और अपने नाम पर ही वोट मांगे। एग्जिट पोल को देखकर लग रहा है कि यह रणनीति सफल साबित हुई है।

मोदी लहर | नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल स्टाइल का बना दिया है। ऐसी स्टाइल जिसमें उम्मीदवार और कभी-कभी तो पार्टी तक गौण हो जाती है। 2014 और 2019 में मोदी लहर के भरोसे ही BJP ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। मोदी के पहले टर्म में पार्टी को 282 और दूसरे टर्म में 303 सीटें मिली थीं। लेकिन, प्रेसिडेंशियल स्टाइल के लिहाज से 2024 सबसे प्रभावी रहा। पार्टी सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए मोदी ने पूरे चुनाव का भार अपने कंधों पर ले लिया। उन्होंने अपने नाम से विपक्ष की रणनीति को बेअसर करने की कोशिश की।

विपक्ष का प्रयास | विपक्ष को इस बात का अहसास था कि भले ही 10 साल के बाद मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे हों या BJP सांसदों के खिलाफ उनके निर्वाचन क्षेत्रों में नाराजगी हो, लेकिन ब्रैंड मोदी पहले की तरह मजबूत बना हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष ने केंद्रवार और सीटवार रणनीति तैयार की, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई। विपक्ष और BJP, दोनों ने पूरा प्रयास किया कि चुनाव अपनी-अपनी पिच पर लड़ा जाए। हालांकि आखिर में सफल रहे मोदी।

प्रियंका का सवाल | कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने मोदी की ओर से चुनाव को प्रेसिडेंशियल फार्म की ओर ले जाने पर NBT को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'अगर देश के नीति-निर्माताओं ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं चुना तो इसमें उनका विवेक जरूर होगा। इसे आज बदलने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि एक व्यक्ति के हाथों में ही सारी सत्ता होनी चाहिए। क्या सिर्फ इसी वजह से हम अपनी पूरी कार्यशैली और संवैधानिक प्रक्रिया बदल डालें? मुझे यह उचित नहीं लगता।'

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

सांसदों से नाराजगी | चुनाव से पहले तमाम ओपिनियन पोल में मोदी की लोकप्रियता में बड़ी उछाल दर्ज की गई। लेकिन, इन्हीं ओपिनियन पोल ने दिखाया कि BJP के सांसदों को लेकर उनके अपने इलाकों में बहुत नाराजगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फीडबैक लिया था उसमें भी सांसदों को लेकर जनता में गुस्से की बात सामने आई थी। इसी के चलते कई सांसदों के टिकट काटे गए। इसी के बाद मोदी ने तय किया कि जीत की हैटट्रिक लगाने के लिए इलेक्शन को अपने चेहरे के इर्द-गिर्द रखना होगा।

ग्राउंड रिपोर्ट | मोदी और BJP की रणनीति कितनी सफल रही इसका अंदाजा चुनाव के दौरान विभिन्न जगहों से आई ग्राउंड रिपोर्ट से लगा। कई जगह लोगों के जेहन में प्रत्याशियों का नाम तक नहीं था। वे बस मोदी को जानते थे और उनका कहना था कि मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे। पार्टी के कई नेताओं का भी मानना था कि मौजूदा हालात में मोदी को केंद्रित करके चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कई सीटों पर BJP उम्मीदवार कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन मोदी फैक्टर जुड़ने के बाद मजबूत बनकर उभर गए।

मेसेज देने में सफल | मोदी ने अपनी हर रैली में 400 सीटों की बात दोहराई और वोटर्स को यह संदेश दिया कि उनकी जीत तभी है, जब BJP उम्मीदवार जीतेगा। यह मेसेज लोगों तक पहुंचाया गया कि उनका वोट सीधे मोदी के लिए है। मोदी ने पूरे चुनावी अभियान को अपने कंधों पर ले लिया। आंकड़ों में देखें तो पिछले साल दिसंबर से ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था और अधिसूचना जारी होने के पहले ही करीब सौ रैलियां कर ली थीं।

टीम BJP | हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी इस नैरेटिव को खारिज करते रहे हैं। इंटरव्यू में NBT ने उनसे सवाल किया था कि, 'BJP का पूरा चुनाव प्रचार आप पर केंद्रित है। क्या इससे सांसदों के काम करने और लोगों के संपर्क में रहने जैसे कामों के प्रति तवज्जो कम हो गई है और नेता सिर्फ मोदी मैजिक से ही चुनाव जीतने के भरोसे हैं।' मोदी का जवाब था कि, 'BJP एक टीम की तरह काम करती है। इस टीम का हर सदस्य चुनाव जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। चुनावी अभियान में जितना महत्वपूर्ण पीएम है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है।'

मोदी का जवाब | मोदी ने इंटरव्यू में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यह परिवारवादी पार्टियों का फैलाया गया प्रपंच है। क्या हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज रैली नहीं कर रहे? क्या हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी रोड शो और रैलियां नहीं कर रहे? मैं पीएम के तौर पर जनता से कनेक्ट करने जरूर जाता हूं, लेकिन लोग उम्मीदवारों के माध्यम से ही हमसे जुड़ते हैं। मैं लोगों के पास नैशनल विजन लेकर जा रहा हूं, उसे पूरा करने की गारंटी दे रहा हूं, तो हमारा उम्मीदवार स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने का भरोसा दे रहा है। हमने उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया है, जो हमारे विजन को जनता के बीच पहुंचा सकें। विकसित भारत की सोच से लोगों को जोड़ने के लिए जितनी अहमियत मेरी है, उतनी ही जरूरत हमारे उम्मीदवारों की भी है। हमारी पूरी टीम मिलकर हर सीट पर कमल खिलाने में जुटी है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ मतदान कर्मियों की सुरक्षा

लोकतंत्र के महा उत्सव में 75 मतदान कर्मियों की तेज़ धूप व लू की चपेट में आने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 17, बिहार में 14, उड़ीसा में 5 और झारखंड में 4 कर्मियों की मौत हुई है, कई लोगों को उल्टी, दस्त, रक्तचाप की शिकायत भी हुई। चुनाव आयोग को इस प्रकार की स्थितियों का आंकलन करने में कहां चूक हो गई। कर्मियों की सुरक्षा चुनाव आयोग की जवाबदेही है। इन कर्मियों की मृत्यु पर मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें।

-अंजनी दाधीच (मुंबई), ईमेल से

■ सोना वापस लाने की सच्चाई

निवेश के लिए शेयर, रियल एस्टेट और गोल्ड निवेशकों का पसंदीदा विकल्प है। गोल्ड के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में सोने का बहुत बड़ा बाजार है। बैंक आफ इंग्लैंड में भारत सहित कई देशों का स्वर्ण भंडार रखा हुआ है। लॉजिस्टिक लागत कम करने के उद्देश्य से इंग्लैंड से सोना खरीद कर भारत वहां रखता आया है। पिछले सप्ताह 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना भारत लाया गया। इसका 1991 में 47 टन सोना गिरवी रखकर जापान व इंग्लैंड से 40 करोड डॉलर का कर्ज लेने से कोई संबंध नहीं है। उस कर्ज को पहले ही चुका दिया गया था। 2023 में भारत का स्वर्ण निवेश 2.31 लाख करोड रुपये था, जो 2024 में 19.06% बढकर 2.75 लाख करोड रुपये हो गया है।

-धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी (डोंबिवली), ईमेल से

■ प्रॉपेगैंडा से ज्यादा कुछ नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाने गए थे। इस पर सियासत भी हुई। अब यह ध्यान स्वहित (सत्ता या कुर्सी) के लिए था या देश व जनहित में, यह तो वही जानें, मगर खेद की बात यह है कि जिस तरह टीवी चैनल्स, बहसों, सोशल मीडिया व पत्र-पत्रिकाओं पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें छपी है, उसे देखकर लगता नहीं कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने ही गए थे। ध्यान के लिए इतने कैमरे की क्या आवश्यकता? यह प्रॉपेगैंडा से ज्यादा कुछ नहीं है।

-हेमा हरि उपाध्याय, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबरः केजरीवाल ने कहा, 'चलो मान लिया अनुभवी चोर हूं, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं।'
टिप्पणीः अनुभवी चोर सबूत थोड़े ही छोड़ता है सर जी!

-रॉबिन इमलीवाला, ईमेल से

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

खुद को माहौल के मुताबिक ढालने का वक्त आ गया

प्रणव पण्ड्या

यह बदलाव का समय है। इस समय मानव सामूहिक रूप से एक नए जमाने के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा है। वह जमाना जिसमें प्रवेश करते ही सारी परिस्थितियां बदली हुई मिलेंगी। ऐसी दशा में सभी की जिम्मेदारी बन गई है कि जमाने के अनुसार अपने आपको ढाल लें। बदले परिवेश के अनुसार अपने आपको बदल लें। जिसमें जितनी संवेदनाएं विकसित होंगी, वह उतना ही सुयोग्य साबित होगा, उतना ही कारगर, सक्रिय बनेगा।

पहाड़ों पर चढ़ने वालों को महीनों पहले वहां की जलवायु को सह सकने की क्षमता देने वाले अभ्यासों से गुजरना होता है। शरीर और मन दोनों की क्षमताएं निखारनी पड़ती हैं। जो अपने को जितना अधिक प्रशिक्षित कर सके, वह उतना ही सफल पर्वतारोही साबित होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के पहले सालों-साल खास जीवनशैली का अभ्यास कराया जाता है। हवा का दबाव सहा जा सके, गंतव्य के गुरुत्वाकर्षण में चल-फिर सके, इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तब कहीं अंतरिक्ष में, अन्य ग्रहों में जाने का काम करने का गौरव हासिल होता है। जो इन प्रशिक्षणों को कष्ट देने वाला बताकर अस्वीकार करते हैं, उनके लिए बदली हुई परिस्थितियों में खुद को बनाए रख पाना आसान नहीं होता है। ठीक यही बात भावी समाज के अनुरूप अपने आपको ढालने के मामले में भी लागू होती है। यह बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर आने वाले समय के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए यह जरूरी है।

वैसे संवेदनाओं का स्थान बौद्धिकता से सर्वदा ऊपर रहा है। आत्मजागरण या अध्यात्म की शुरूआत यहीं से होती है। यह एक ऐसा तालाब है जिसमें अनेकानेक सद्गुण अपने आप सिमट-सिमट कर आ भरते हैं। इतना सब कुछ होते हुए इस ओर गति न होने का कारण है बुद्धिवाद की सांकल । सवाल उठ सकता है यह सांकल कैसे टूटेगी? युग तो बुद्धि का है, भाव की तरफ गति कैसे होगी? सारे जीवन की व्यवस्था का संचालन बुद्धि से होता मालूम पड़ता है। तब भाव की ओर रास्ता कैसे खुले?

जीवन का एक विचित्र नियम है। वह यह कि एक अति पर जा पहुंचने पर दूसरी अति की ओर चल पड़ना आसान हो जाता है, ठीक घड़ी के पेंडुलम की तरह। आज का जमाना न सिर्फ बुद्धि से ग्रस्त है, बल्कि त्रस्त और पीड़ित भी है। बौद्धिकता अपने चरम पर है। अब स्वाभाविक है कि जीवन भावनाओं की ओर बढ़े। धरती पर शीघ्र ऐसा समय आने वाला है, जब मनुष्य की भाव संवेदनाएं गहरी और विस्तृत होंगी। कारण कि पहले मानव जाति ने बुद्धि का स्वाद नहीं चखा था। अब चख लेने, इससे उकता जाने के कारण एक सामंजस्य जन्म लेगा।

संवेदनाओं की सक्रियता की शुरुआत होने का लक्षण है सहानुभूति और प्रखर होने का चिह्न है सेवा। इसकी परिणति है अपनत्व का विस्तार, अपने-पराए के भेद का अभाव। इसकी सामयिक आवश्यकता समझकर स्वयं में इसका विकास करना चाहिए। तभी नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना संभव होगा। आइए, उसके लिए आज और अभी से ही हम तैयारी शुरू कर दें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भाजपा-एसकेएम की सरकार

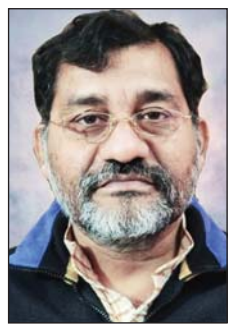

भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 46 सीटें जीत कर बहुमत हासिल कर लिया। राज्य में 60 में से 50 विधानसभा सीटों के लिए लोक सभा चुनाव के साथ मतदान हुआ था। भाजपा ने बाकी की दस सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। राज्य में भाजपा के लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यकर्ताओं की सराहना की। वहीं सिक्किम में 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार जीतने वाले दल को इस दफा प्रचंड बहुमत मिला है। 2019 तक लगातार 25 साल शासन करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को केवल एक सीट मिली। पूर्व मुख्यमंत्री

पवन चामलिंग की पार्टी प्रेम सिंह तमांग उर्फ गोले के आगे बुरी तरह धराशायी हो गई। वहां भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों का खाता भी नहीं खुला। अरुणाचल में कांग्रेस को एक सीट मिली। अरुणाचल भाजपा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन कहा और भाजपा के रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खांडू ने इसे एंटी इनकंबेंसी की बाजाए प्रो-इनकंबेंसी करार दिया। वह पहले कांग्रेस में थे मगर 2016 में मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। मगर दो महीने बाद ही खांडू भाजपा के साथ आ गए। पिछले चुनाव में राज्य में दूसरे बड़े दल के तौर पर जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी यू) उभरी थी इसलिए माना जा रहा था कि वह खांडू को कड़ी टक्कर देगी। क्योंकि ग्राम पंचायत व जिला परिषद में उसे बेहतर समर्थन प्राप्त था, परंतु विपक्ष के गठबंधन इंडिया में सीटों को लेकर लंबे समय तक सहमति नहीं बन पाई। जिसका लाभ भाजपा को ले गई लगती है। सिक्किम की जीत के नायक तमांग शिक्षक की नौकरी छोड़ कर राजनीति में आए थे। 2013 में अपना नया दल बना कर पहली बार 2014 का चुनाव लड़ा, जिसमें दस सीटें लेकर नेता प्रतिपक्ष बन गए। 2016 में भ्रष्टाचार के मामले में जेल व विधायक होने से अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद 2019 में 17 सीटें जीत कर 24 साल पुरानी चामलिंग सरकार को जड़ से उखाड़ दिया। हालांकि वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं इसलिए लोक सभा कर मात्र एक सीट को लेकर सब निश्चिंत ही नजर आ रहे हैं।

फिजूल का आरोप

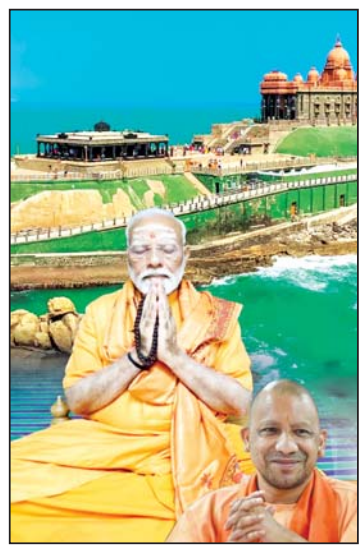

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोप पर केंद्रीय चुनाव आयोग का सख्त रवैया न्यायोचित ही कहा जाएगा। रमेश ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 से ज्यादा जिलाधिकारियों (डीएम) से बात किया। रमेश का आशय इसी ओर इशारा करता है कि देश के गृह मंत्री चुनाव में हार को देखते हुए जिलाधिकारियों को मतगणना में हेर-फेर करने का दबाव बना रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर देखें तो यह काफी ज्यादा गंभीर आरोप हैं, मगर हकीकी रूप से इन आरोपों में कोई दम इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि रमेश के पास इस आरोप का कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है। यही वजह है कि उनके इस 'रेडिमेड' आरोप पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया और उनसे इस सतही आरोपों का सबूत मांग लिया। हवा-हवाई तरीके से बात करना इतने बड़े और अनुभवी राजनेता को कतई शोभा नहीं देता है। ठीक-ठाक तरीके से मनन

करें तो राजनीति में आरोप लगाना हमेशा से हर नेताओं के लिए 'बाएं हाथ का खेल' सरीखा रहता है। मगर बात देश के गृह मंत्री की और उस संस्था (चुनाव आयोग) की है तो इसमें पूरी साफगोई और सच्चे तथ्य तो सार्वजनिक होने बेहद जरूरी हैं। आरोप लगाकर भाग निकलने की प्रवृत्ति से हर किसी को बचना चाहिए। राजनीति की हाल के वर्षों में दुर्गति की एक अहम वजह यही है कि इसने भरोसा खोया है। हम सब इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि साख बनने में वर्षों लग जाते हैं, मगर इसे धराशायी होने में क्षण भर का समय भी पर्याप्त है। होना तो यही चाहिए था कि रमेश पूरे सबूत के साथ अपनी बात कहते। इससे उनकी और उनके साथ-साथ उनकी पार्टी की भी विश्वसनीयता भी मजबूत होती। निःसंदेह आयोग का कहना तार्किक मालूम पड़ता है कि इस तरह के पोस्ट से चुनाव प्रक्रिया पर शंका पैदा होती है और आम जनता भी भ्रमित होती है। फिलहाल, रमेश के आरोप लगाने और चुनाव आयोग से सबूत सामने लाने की बात वहीं तक सीमित है। सभी को इस बात पर ऐतबार तो करना ही चाहिए कि 44 दिनी चुनाव कार्यक्रम छिटपुट हिंसा और विवाद के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जहां तक निष्पक्षता की बात है तो यह हर राजनीतिक पार्टियों और संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य है कि वह इसे कितनी इज्जत बख्शता है। हां, शक का इलाज तो वाकई आज कोई नहीं खोज सका है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

हारे हुए नेता के लिए

चुनाव के रिजल्ट सामने हैं। चुनाव में कई कारोबार चल निकलते हैं। अब उन लोगों का कारोबार चमकेगा, जो हारने वालों को कंसल्टेंसी देंगे। हारने के बाद कैंडीडेट तरह तरह की कंसल्टेंसी खोजता है, यह अलग बात है कि हारने वाले को कंसल्टेंसी देना जोखिम का काम है। जो कैंडीडेट हार जाता है, उसे कई तरह के बंदे खोजते हैं, भुगतान वसूलने के लिए। तो पहली कंसल्टेंसी चुनावी कंसल्टेंसी देने वालों के लिए यह है कि सावधानी से कंसल्टेंसी दीजिए। डूबे हुए कैंडीडेट के साथ रकम भी डूबने का खतरा है। हारने के बाद ये बहाने दिए जा सकते हैं-

गरमी बहुत थी चुनाव के दिन। चुनाव अगर ठंड में हों तो तर्क यह दिया जा सकता है कि ठंड बहुत थी। एक बहाना यह भी दिया जा सकता है कि नैतिक जीत में मेरी हुई है। नैतिक जीत इन दिनों फैशनेबल हो गई है। हालांकि नैतिक तौर पर जीते हुए को सब बेवकूफ ही मानते हैं, क्योंकि नैतिकता के लिए कोई चुनाव न लड़ता। चुनाव सब जीतने के लिए ही लड़ते हैं। हार हाथ आ जाती है, तो कहते हैं कि नैतिक जीत हो गई है। नैतिक जीत हार की पैकिंग में आती है। नैतिक जीत कोई चाहता नहीं है, मिल जाती है यह बस। नैतिक जीत का मतलब होता है कि धक्का खाकर गिरें, तो बताएं कि यह तो हमारी स्टाइल है। गिरना भी स्टाइल होता है।

एक और बहाना ईवीएम, जो जीत जाता है, वह जीतकर घर जाता है, जो हार जाता है, वह ईवीएम की जान को रोता है। ईवीएम का हाल घर की उस प्रताड़ित बहू की तरह का है, जो चाय जल्दी बनाकर सास को दे दे, सास कोसती है-इतनी सुबह चाय बनाकर दे दी, बहू चाहती ही नहीं कि मैं ढंग से नींद ले सकूं। नींद पूरी ना होगी, तो हार्ट अटैक आ सकता है। ये बहू मुझे मार के ही मानेगी। बहू चाय थोड़ी देर से बनाकर दे, तो फिर सास कोसे-बताओ दोपहर होने को आई, अब तो खाने का वक्त हो गया और यह बहूरानी चाय पिला रही है। चाय पिला-पिलाकर हेल्थ खत्म करना चाहती है मेरी यह बहू। ईवीएम और प्रताड़ित बहू में एक फर्क यह है कि प्रताड़ित बहू का वक्त बदलता भी है।

ध्यान साधना पर हंगामा

सामयिक

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी के विवेकानंद शिला स्मारक में ध्यान करना जितने बड़े विवाद और बवंडर का विषय बना उसे बिल्कुल स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। भारत सहित विश्व समुदाय को प्रेरणा देने वाले विवेकानंद के ध्यान स्थल से जुड़े इस केंद्र पर प्रधानमंत्री जाकर ध्यान करते हैं तो इसका संदेश सर्वत्र जाता है और लोगों में भी विवेकानंद के जैसा बनने, विपरीत परिस्थिति में ध्यान करने और स्वयं को नियंत्रित कर देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है।

विपक्ष ने यद्यपि बुद्धिमत्तापूर्वक कहा कि वे ध्यान साधना का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से भाजपा को चुनावी लाभ हो जाएगा। इसलिए इसके टीवी कवरेज पर आपत्ति व्यक्त की गई। अलग-अलग पार्टियां चुनाव आयोग के पास गई भी। प्रधानमंत्री या कोई नेता चुनाव प्रचार के बाद या बीच में किसी धर्मस्थल या प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, वहां पूजा, प्रार्थना, ध्यान या अन्य साधना करें उस पर चुनाव आयोग या कोई भी संवैधानिक संस्था कैसे रोक लगा सकती है? विपक्ष के नेताओं ने भी पूरे चुनाव में परिश्रम किया है और उन्हें भी ध्यान साधना और शारीरिक, मानसिक संतुलन व शांति के लिए पहले से ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए थी। भारत में अनेक ऐसे धार्मिक साधना स्थल हैं जहां जाकर आप शारीरिक-मानसिक थकान से आध्यात्मिक कृतियों के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी जगह भी है जहां जाकर एक दो दिनों के विश्राम से आपको विशेष शांति और शक्ति मिलती है।

अगर विपक्ष के नेताओं में ऐसी दृष्टि नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री या कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का नेता उस दिशा में न सोचें न करें। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी चाहें तो कहीं न कहीं ऐसी साधना कर सकते थे और उन्हें भी टेलीविजन या मीडिया का कवरेज मिलता। नेताओं में वाकई ध्यान और साधना की प्रतिस्पर्धा हो तो यह देश और संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होगा। जब आध्यात्मिक दृष्टि से आपके शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित होता है तो उसके साथ सकारात्मक दृष्टि भी विकसित होती है जहां से केवल सबके कल्याण के भाव से ही विचार पैदा हो सकते हैं। जब 2014 का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शिवाजी के रायगढ़ किले में जाकर ध्यान किया था। शिवाजी हमारे देश में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की दृष्टि से प्रेरक और आदर्श व्यक्तित्व हैं। शिवाजी जैसे महापुरुष के प्रति अगर विपक्ष के अंदर ऐसा भाव पैदा नहीं होता तो इसके लिए वही दोषी हैं। 2019 के चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के केदारनाथ गए थे

और वहां उन्होंने गुफा में ध्यान और साधना की। यह मान लेना कि इस प्रकार की ध्यान साधना या पूजा पाठ के मीडिया कवरेज के प्रभाव में आकर पहले से किसी और को मत देने का मन बनाए मतदाता अचानक पलट कर भाजपा को वोट देने लगेंगे उचित नहीं लगता। मतदाताओं के पास भी सही गलत का निर्णय करने का विवेक है। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी के मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति मानता था तो उसे भी इसकी काट में रणनीति अपनानी चाहिए। विरोधियों ने प्रधानमंत्री की ध्यान साधना को राजनीतिक मुद्दा बना दिया।

किसी भी देश का शीर्ष ध्यान साधना या अपने आध्यात्मिक कर्मकांड या फिर छुट्टियां मनाने जाएगा तो उसे मीडिया का कवरेज मिलेगा। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री को जितना कवरेज मिलेगा उतना किसी अन्य नेता को नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरे नेता अपना कार्यक्रम इतने ही प्रेरणादायी व सकारात्मक बनाएं तो मीडिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैसे भी विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उनके प्रति भी विरोधियों का रवैया यही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले केवल मोदी बोलते थे अब उसमें योगी को जोड़ दिया। योगी समर्थक यह बोलते हैं कि विरोधियों को उनके भगवा वस्त्र से, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई से या हिंदुत्व के प्रति प्रखरता से समस्या है तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता। विवेकानंद शिला स्मारक पर जाने वाले या उसकी प्रशंसा करने वाले ज्यादातर नेताओं को शायद यह पता नहीं होगा कि उसके निर्माण के पीछे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य भूमिका थी। 1963 में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी के समय लोगों ने उस चट्टान के पास एक स्मारक बनाने का निश्चय किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। संघ ने अपने उस समय के वरिष्ठ प्रचारक एकनाथ रानडे को इस काम में लगाया। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम ने स्मारक में मदद से मना कर दिया। तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर ने भी सहयोग से इनकार किया।

संघ ने निर्णय कर लिया था और उनके लोग लग गए थे तो वे लगे रहे। सांसदों से भेंट की गई। 300 से ज्यादा सांसदों से हस्ताक्षरित समर्थन लिया गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसके निर्माण की अनुमति दी। 1972 में विवेकानंद केंद्र बना जो वहां अनेक प्रकार के कार्यक्रम करता है। भारत सहित विश्व के हजारों लोगों ने उस स्थान से अपना जीवन बदला या समाज को बदलने का की प्रेरणा लेकर काम किया है। बहुत सारे लोग तो आज अभी कहेंगे कि संघ विवेकानंद की क्यों बात करती है, विवेकानंद के हिंदुत्व से संघ का क्या लेना देना।

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की आलोचना केवल लंबे समय से पाले गए और स्वाभाविक दुराग्रह की परिणति होती है। वहीं से ऐसे विरोध पैदा होते हैं जिनका आम जनता पर असर न के बराबर होता है। राजनीति और विशेष कर चुनावी रणनीति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री द्वारा विवेकानंद शिला स्मारक में किया जा रहा ध्यान और साधना इस देश की शांति समृद्धि का कारण बने ऐसी हम सबको कामना करनी चाहिए। अच्छा हो कि देश के ज्यादातर शीर्ष नेता इसी तरह कोई स्थान चुनकर आत्मोन्नित और भारत राष्ट्र तथा मानवता के कल्याण का लक्ष्य लेकर सिद्ध स्थलों पर ध्यान साधना आदि करें। कल्पना करिए अगर नेताओं के बीच ऐसी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो जाए तो फिर कितना सुखद वातावरण बनेगा तथा उसका सकारात्मक असर हम सब पर होगा।

> वैसे भी विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उनके प्रति भी विरोधियों का रवैया यही है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले केवल मोदी बोलते थे अब उसमें योगी को जोड़ दिया। योगी समर्थक यह बोलते हैं कि विरोधियों को उनके भगवा वस्त्र से, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई से या हिंदुत्व के प्रति प्रखरता से समस्या है तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता

हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन में ओआरएस रामबाण

- **जानकार बताते हैं कि डायरिया से पीड़ित सिर्फ 60.6 फीसद भारतीय बच्चों को ही जीवन रक्षक ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) मिल पाता है। ऐसे में ओआरएस को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है**
- **हीट स्ट्रोक, तेज गर्मी के दौरान हैजा, डायरिया और शरीर में पानी की कमी जैसी परेशानियों को खत्म करने में ओआरएस अमृत का काम करता है लेकिन सही ओआरएस का चयन जरूरी है**

(मीडिया इन्पुट्स)

संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है।

चुनाव में ध्यानाकर्षण ध्यान होता है।

राहुल देव, पत्रकार
@rahuldev2

सम्मिलित प्रयास से दूर होंगी दुश्वारियां

पर्यावरण दिवस | **अनिरुद्ध गौड़**

देश में चुनावी पारा चरम सीमा पर है तो प्रचंड गर्मी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्यों के कई शहरों ने तमाम रिकार्ड तोड़ दिए हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र तल बढ़ रहा है, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में सर्दी, इलाके सूख रहे हैं तो कहीं वनों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। चिंता का विषय है कि वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में भारी बदलाव हो रहा है। इन चरम मौसमी घटनाओं से भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भी कई देशों में कहर बरपा है। वैश्विक स्तर पर माना गया है कि इसके लिए कहीं-न-कहीं मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं।

आप देखेंगे कि मई के महीने में दिल्ली और आसपास के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राज्यों में 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया। इसके कारण हीट वेव की स्थिति बनी रही। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में 135 किलोमीटर की रफ्तार से रेमल तूफान ने दस्तक दी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नार्थ ईस्ट और बंगलादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई। अप्रैल में कई राज्यों के जंगल धधक उठे। आग से वनों का क्षरण, बहुमूल्य संपदा और कार्बन नष्ट होते हैं। अब मानसून असंतुलित हो गए हैं। भू-जल रसातल में पहुंच गया है, जिसके चलते भारत के बेंगलुरू, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर आदि महानगरों सहित कई शहरों में पानी का संकट गहराया हुआ है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि ऐसा ही रहा तो पानी के संकट से और भी कई शहर जद में आ सकते हैं। कई नदियां पानी की कमी से सूख रही हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बढ़ते वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी और मौसम के बदलावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में 1992 में आयोजित 'रियो अर्थ समिट' में चिंता की गई थी। फिर 1997 के क्योटो प्रोटोकाल के जरिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और 2015 में आयोजित कॉप-15 पेरिस, फ्रास में पेरिस समझौते के जरिए जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा, सहयोग और समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर सीमित कर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का प्रयास किया जाएगा। जीवन स्तर में बेहतरी की दौड़ में जीवाश्म ईंधन के

अनियंत्रित प्रयोग और औद्योगिकीकरण का जलवायु परिवर्तन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन उत्सर्जन और उससे बढ़े ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व में चरम मौसमी घटनाएं हो रहीं है। समुद्र के बढ़ते जलस्तर से द्वीपीय विकासशील देशों और आबादी को खतरा है। महत्त्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला, पर्यटन और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अस्थिर तटीय विकास, समुद्र से अत्यधिक मछली दोहन, गहरे समुद्र में खनन, अनियंत्रित प्रदूषण और प्लास्टिक कचने की समुद्र में मौजूदगी से समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। इन सबसे बचने के लिए हमें गैस उत्सर्जन कम करना होगा। हाल ही में केरल के कोच्चि में संपन्न 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक एटीसीएम और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति सीईपी में ध्रुव पर बढ़ती गतिविधियों पर 60 देशों के प्रतिनिधि इस ठंडे महाद्वीप के भविष्य पर चिंता व्यक्त की गई। अंटार्कटिका में विश्व के प्रमुख देश अनुसंधान कर रहे हैं तो यहां कुछ वर्षों से पर्यटकों की बढ़ती संख्या में वृद्धि, चिंता और मुद्दा बन गया है। 1966 से एटीसीएम में पर्यटन को विनियमित करने पर चर्चा चल रही है, लेकिन यह एजेंडा आइटम, सत्र, कागजात या संकल्प तक ही सीमित रहे हैं। मुद्दा उठा है कि अब जरूरी है कि उत्तरदायित्वपूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम बनाए जाएं। मई के महिने में रिलीज हुई 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' की 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायर्नमेंट 2024 इन फिगर्स रिपोर्ट' ने भारत के पर्यावरण संबंधी आंकड़े दिए हैं।

रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2022 में जहां 365 दिन में 314 चरम मौसमी घटनाओं को देखा गया वहीं 2023 में यह 318 दिन रहा। 2023 में देश में रिकार्ड तोड़ तापमान बढ़ा और बारिश हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समस्या में सबसे बड़ा योगदान विकसित देशों का है। हालांकि अभी संयुक्त राष्ट्र की कॉप 26 (ग्लासगो), कॉप 27 (शर्म अल शेख) और कॉप 28 (दुबई) में अहम फैसले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी सफलता हानि एवं क्षति कोष और ऊर्जा उत्पादन जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमति के अलावा ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन शमन पर दृढ़ संकल्प निर्णय हुए। वहीं, भारत की कुल 4,44,969 मेगावाट उत्पादित ऊर्जा में से 48 प्रतिशत थर्मल पावर, 33 प्रतिशत अक्षय उर्जा, 11 प्रतिशत हाइड्रो, 6 प्रतिशत गैस और 2 प्रतिशत न्यूक्लियर उर्जा से उत्पादित है। अक्षय ऊर्जा में बदलना है, जबकि कुल एनर्जी आवश्कताओं को 2030 तक 45 प्रतिशत कम करना और 2070 तक नेट जीरो करना है। भारत की जिम्मेदारी बनती है उसे बहुत सारी नीतियों पर काम करना पड़ेगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि विकास की आवश्यकता की गति धीमी भी ना हो।

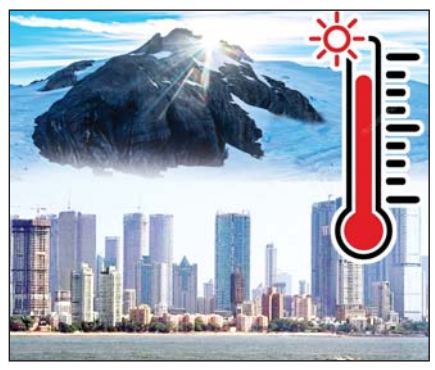

प्रेम अतर्क्य है | **ओशो**

गैलेलियो ने पहली दफा कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी का नहीं। यह एक तर्क निष्पत्ति थी और बिल्कुल सही थी, लेकिन ईसाइयत ने विरोध किया। रोम खिलाफ हो गया। सारा ईसाइयों का

फैला हुआ जाल गैलेलियो की बात स्वीकार करने को राजी नहीं था। क्योंकि बाइबिल में कहा है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सारी दुनिया के लोग मानते रहे हैं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दिखाई भी यही पड़ता है। सुबह ऊगता है पूरब, सांझ डूबता है पश्चिम, फिर पूरब ऊगता है, चक्कर लगाता हुआ मालूम पड़ता है। गैलेलियो के बाद भी सारी दुनिया की भाषाओं में शब्द तो वही हैं-सूर्योदय, सूर्यास्त। न तो सूर्य का कोई उदय होता है, न अस्त होता है; सिर्फ पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी जगह है। न ऊगता है, न डूबता है। पृथ्वी ही उसके आसपास घूमती है। गैलेलियो ने जब पहली दफा यह बात कही, तो उसने तर्क से पूरी तरह सिद्ध कर दी, लेकिन पोप ने उसे बुलाया और कहा कि तुम क्षमा मांग लो, अन्यथा तुम्हारा जीवन तुम्हारे जीवन को खतरा है। गैलेलियो ने घुटने टेककर क्षमा मांग ली। यह बड़ी कठिन बात रही है और विचारशील लोग सोचते रहे हैं कि गैलेलियो जैसा प्रतिभासंपन्न आदमी क्या अपने जीवन के लिए डर गया? लेकिन मैं सोचता हूं कि जीवन के लिए गैलेलियो नहीं डरा। वह अपना जीवन दे सकता था, लेकिन एक छोटे से तर्क के लिए कौन जीवन देने को तैयार होता है! इससे क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है! गैलेलियो क्यों जीवन दे इस व्यर्थ की बकवास के लिए? उसने देखा कि इतनी सी बात के लिए कि पृथ्वी चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, मैं क्यों जीवन दूं! मैं मानता हूं गैलेलियो बुद्धिमान आदमी था। कोई बुद्ध होता तो शायद मरने को तैयार हो जाता। क्योंकि तर्क के लिए कोई बुद्ध ही मर सकता है। गणित की एक निष्पत्ति के लिए कौन अपना जीवन देने को तैयार होगा! आखिर जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन एक छोटे से प्रेम के लिए आदमी पूरे जीवन को दे सकता है। प्रेम पूरे जीवन को घेर लेता है; पूरे अस्तित्व को पकड़ लेता है। तर्क तो केवल बुद्धि के एक कोने को पकड़ता है। आज तक बुद्धि के लिए किसी ने जीवन नहीं दिया है। और जिस चीज के लिए आप जीवन नहीं दे सकते, वस्तुतः उसका जीवन से ज्यादा मूल्य नहीं हो सकता।

रीडर्स मेल

ट्रंप की मुश्किलें

एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 34 मामलों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया गया है। इस अभ्भुतपूर्व फैसले के बाद अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव सीधे सीधे प्रभावित होंगे और इसका दूरगामी प्रभाव अमेरिका के इतिहास पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो ट्रंप दोषी पाए जाने के बाद भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि वह अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी बाइडेन से सिर्फ कुछ मार्जिन से ही आगे चल रहे हैं प्री ट्रायल चुनाव में तो यह फैसला नवम्बर में उनके करियर के लिए घातक भी साबित हो सकता है। वैसे तो जैसा अपेक्षित था ट्रंप ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका कितना असर वोटर्स पर होगा यह तो समय ही बताएगा। वैसे तो चुनाव नवम्बर में होने हैं, लेकिन 11 जुलाई का इंतजार न केवल अमेरिका बल्कि पूरा विश्व कर रहा है।

बाल गोविंद, नोएडा

उपाय तो तलाशने ही होंगे

पिछले दो हफ्ते में उत्तर मध्य भारत गंभीर हीटवेब के चपेट में है। सैकड़ों लोग गर्मी से बेहाल अपनी जान गंवा चुके हैं। आम चुनाव के दौरान तमाम चुनाव कर्मियों की मौत की वजह हीटवेब रही। गर्मी कई पुराने रिकार्ड तोड़ रही है और नया रिकार्ड बना रही है। एक तरफ प्रचंड गर्मी का कहर दूसरे पानी की किल्लत। दिल्ली सरकार पानी बचाने और पानी बर्बाद न करने के निर्देश दे रही। इसके बावजूद सुबह-शाम लोग सड़कों को तर करने में कोई कोताही नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे लोगों को पानी की किल्लत से कुछ लेना-देना न हो। जो भी हो, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम करने की जगह हम उसे बढ़ाने में ही लगे हैं। पिछले वर्षों में बरसात के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में बरसात कम हुई, लेकिन अक्टूबर में कई प्रदेशों में इतनी अधिक बरसात हुई कि बाढ़ की समस्या पैदा हो गई। ये सारी बातें संकेत करती हैं कि जलवायु परिवर्तन में बदलाव आ रहा है और पश्चिम एशिया के तमाम देश इससे प्रभावित हो रहे हैं जिस पर गौर करने की जरूरी है।

अखिलेश आर्येन्दु, ई मेल से

क्या सच होगा एग्जिट पोल

एग्जिट पोल 2024 में भाजपा (एनडीए) की तीसरी बार शानदार वापसी के साथ दक्षिण में महत्त्वपूर्ण बढ़त का अनुमान लगाया है। यह रुझान महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में पैठ बनाने के लिए काफी जतन किए हैं। भाजपा को 2019 की 303 सीटों की संख्या से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और सहयोगियों के साथ मिलकर वह 'अब की बार, 400 पार' के अपने नारे को साकार करने के करीब भी पहुंच सकती है। कन्याकुमारी मे ही तिरुवल्लुवर को श्रद्धाजलि देने पीएम मोदी 100 से ज्यादा सीढ़िया चढ़े तो साबित हो गया है कि ये पीएम रुकेगा नहीं। ये चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में वाकई अलग माना जाएगा क्योंकि दस साल के शासन के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर काम के लिए वोट मांगा है। यानी पार्टी को पक्का यकीन है कि देश की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। एंटी इन्कमबेंसी मानो हाशिए पर ही चली गई, जब देश भर का वोटर मोदी-मोदी के नारे लगाता नजर आया।

प्रियंका सौरभ, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 291
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

शेयर बाजार में तेजी

एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जब सोमवार को भारतीय शेयर बाजार खुले, तो सूचकांक तेजी से चढ़ने लगा। बीएसई जहां 2,000 से भी ज्यादा अंकों तक उछला, तो निफ्टी में भी लगभग उतनी ही बढ़त देखी गई। एक दिन में देश के दोनों शेयर बाजार के सूचकांक का तीन-तीन प्रतिशत से ज्यादा बढ़ना बहुत मायने रखता है। पहली संभावना यही है कि बाजार में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद केंद्र सरकार की स्थिरता को बल मिला है, जिससे निवेशकों का मनोबल बढ़ा है। विपक्षी दल चूंकि आर्थिक रूप से बड़े परिवर्तन के साथ सत्ता संभालने के इच्छुक हैं, इसलिए निवेशकों में आशंका है। ऐसे में, भाजपा के पक्ष में परिणाम आते देखे, निवेशकों का उत्साह बढ़ा हो, तो अचरज की बात नहीं। बाजार को यथास्थिति या फिर आर्थिक संबल-सहयोग की जरूरत होती है। यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय हर प्रकार के निवेशकों को बल मिला है, इसी का परिणाम है कि साल 2014 में बीएसई 25,000 अंकों से ज्यादा पर था और अब 76,400 अंकों से ज्यादा पर पहुंच गया है। यह वृद्धि गौरवान्वित करती है। यह संकेत करती है कि भारत में आर्थिक निवेश बढ़ रहा है।

विगत दस वर्षों में सूचकांक में तीन गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। वैसे मनमोहन सिंह सरकार के दस वर्षों में भी शेयर बाजार में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई थी। मंदी का बुरा दौर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी देखा और नोटबंदी व लॉकडाउन का नुकसान नरेंद्र मोदी सरकार को भी बहुत हुआ है। तमाम चुनौतियों के बावजूद बुनियादी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी मांग है और इसी वजह से अर्थव्यवस्था सही तरीके से संचालित हो रही है। चूंकि भारत स्वयं ही एक बढ़ता हुआ बड़ा बाजार है, इसलिए यहां शेयर बाजार में तेजी का बने रहना बहुत चौंकाता नहीं है। दूसरी ओर, केवल एग्जिट पोल की वजह से नहीं, बल्कि व्यापकता में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक भाव के चलते यह वृद्धि हो रही है। निवेशक एग्जिट पोल के बाद दो दिन इंतजार भी कर सकते थे, नतीजे आने के बाद निवेश ज्यादा आश्वस्तकारी होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से निवेशकों को धन कमा लेने की जल्दी है। ऐसे में, बड़े निवेश सलाहकार यही सलाह देते हैं कि छोटे निवेशकों को निवेश के लिए कुछ इंतजार करना चाहिए। तीन प्रतिशत से ज्यादा की लगभग ऐतिहासिक छलांग में निवेश के कुशल खिलाड़ी ही भाग लें, तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा लगता भी है कि सोमवार की बड़ी छलांग के पीछे कुशल खिलाड़ी ही ज्यादा सक्रिय रहे हैं।

वर्ष 2014 में बीएसई 25,000 अंकों से ज्यादा पर था और अब 76,400 अंकों से ज्यादा पर पहुंच गया है। यह संकेत है कि भारत में आर्थिक निवेश बढ़ रहा है।

आने वाले दिन शेयर बाजार के लिए बहुत अहम होंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 जून को होने वाली है। ज्यादा संभावना यही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार, अर्थव्यवस्था अभी ठीक स्थिति में है, अतः किसी तरह का मौद्रिक जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। रिजर्व बैंक आज मजबूत स्थिति में है और उसने केंद्र सरकार को भी धन दिया है। रिजर्व बैंक भारतीय रुपये का समर्थन करने के लिए तरलता का ध्यान रखेगा। चुनाव खत्म होने के साथ ही तरलता की कमी दूर हो सकती है, आने वाले महीनों में सरकारी खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकारी खर्च जब बढ़ेगा, तो फिर शेयर बाजार को संबल मिलेगा। कुल मिलाकर, इस वर्ष शेयर बाजार की बढ़त-चमक बनी रहेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 04 जून, 1949

फ्रांस के हथकंडे

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष डाक्टर गुयेरेरो ने घोषणा की है कि भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर भारत की तथाकथित आर्थिक नाकेबन्दी की जांच करने और बाद में वहां के जनमत-संग्रह का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने अपनी वैयक्तिक हैसियत से दो निरीक्षक नियुक्त किये हैं। इस घोषणा में जहां एक ओर साम्राज्यशाही हथकंडों की काली छाया दिखाई देती है, वहां यह सम्भावना भी छिपी हुई है कि ऐसी चालबाजियां कहीं फ्रांस और भारत में इतनी कटुता न उत्पन्न कर दें कि जिस समस्या को आज सद्भावना सहित सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके लिए सक्रिय संघर्ष का सहारा लेना पड़े।

सबसे पहली बात तो यह है कि भारत पर आर्थिक नाकाबन्दी करने का जो आरोप लगाया गया है, वह सरासर झूठ और निराधार है। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विदित है कि सन् १९४१ में फ्रांस के अनुरोध पर भारत सरकार ने चुंगी संबंधी प्रतिबन्धों को हटा लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने सम्मिलित चुंगी समझौते को समाप्त करने का निश्चय किया और मार्च सन् १९४९ में फ्रांस को इस संबंध में एक वर्ष का नोटिस भी दे दिया। फिर भी अवधि के समाप्त होने से दो मास पूर्व भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार को लिखा कि वह जनमत संग्रह तक समझौते को जारी रखने को तैयार है। किंतु फ्रांस की सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। हां, अवधि की समाप्ति से १५ दिन पूर्व उसने एक नया विकल्प अवश्य उपस्थित किया, किंतु वह विकल्प भारत सरकार को मान्य नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बड़ी-बड़ी उलझनें थीं और इतने कम समय में उन्हें सुलझाना संभव नहीं था। अतः १ अप्रैल, १९४९ से फ्रांसीसी बस्तियां विदेशी प्रदेश मानी जाने लगीं और उन पर आयात तथा निर्यात संबंधी प्रतिबन्ध लागू हो गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन प्रतिबन्धों में कोई नवीनता अथवा विशेष कठोरता नहीं है। जो प्रतिबन्ध अन्य विदेशों के लिए है, वे ही फ्रांसीसी बस्तियों के लिए भी हैं। इन्हें ''आर्थिक नाकेबन्दी'' का नाम देना गर्हित प्रचार मात्र है। आज भी फ्रांसीसी बस्तियों में सभी आवश्यक पदार्थ भेजे जाते हैं; वास्तविक प्रतिबन्ध तो केवल उन लोगों के लिए है, जो भारत का सामान चोरी से फ्रांसीसी बस्तियों में ले जाया करते थे। ऐसे अवैध व्यापार को रोकना प्रत्येक सरकार का स्वाभाविक कर्तव्य है।

सबक सीख आगे बढ़े चुनाव आयोग

यहां स्कैन करें

ओपी रावत | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

जब मुकाबला कड़ा होता है, तब मतों की गिनती चुनौतीपूर्ण कसरत मानी जाती है। आयोग पर इसकी जवाबदेही बढ़ जाती है कि प्रत्याशियों के संदेह का तत्काल निराकरण हो।

किसी भी निर्वाचन-प्रक्रिया का अंतिम अहम हिस्सा है मतगणना। चुनाव आयोग ने इसके बारे में बहुत विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनको समयानुकूल अपडेट भी किया जाता रहा है। इस बार नतीजों से एक दिन पहले आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें मतदाताओं की संख्या बताने के साथ-साथ सुचारु मतगणना-कार्य को लेकर चर्चा की गई। दो सीख मिलने की बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही, जिनमें पहली है- तेज गरमी में मतदान नहीं कराना चाहिए था, बल्कि इसे एक महीना पहले खत्म किया जा सकता था। और दूसरा सबक, आयोग अपने खिलाफ तैयार किए जा रहे फेक नैरेटिव से अब किस तरह लड़ेगा।

इस संवाददाता सम्मेलन की जरूरत इसलिए भी महसूस हुई, क्योंकि वोटर टर्नआउट, यानी मतदाताओं की असली संख्या को लेकर बार-बार सवाल उठे हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने 'वोटर टर्नआउट' नामक एक एप बनाया, जिसके जरिये मतदान के आंकड़े तत्काल मुहैया कराने के दावे किए गए थे। यह फॉर्म 17-सी जैसा था, जिसमें मतों का पूरा लेखा होता। इस एप को लेकर लोगों में शुरू-शुरू में उत्साह तो खूब रहा, लेकिन यह समय पर अपडेट नहीं हो सका, क्योंकि मतदानकर्मियों की पहली प्राथमिकता चुनाव कराने की होती है और उनको बाकी काम तुलनात्मक रूप से कमतर लगते हैं। चूंकि एप में आंकड़े अपडेट नहीं हुए, और आंकड़े भी कभी प्रतिशत, तो कभी अंक में दिए गए, इसलिए मत-प्रतिशत को लेकर कुछ विवाद पैदा हो गया।

निस्संदेह, फॉर्म-17(सी) किसी चुनाव का काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि मतदान-केंद्र पर जो ईवीएम इस्तेमाल की गई, वह सही है और उसमें उतने ही वोट पड़े हैं, जितने की गिनती हुई है। यह 'क्रॉस चेकिंग' का बड़ा औजार है। चूंकि चुनाव आयोग पर कोई सवाल न उठे, इसलिए यह अनिवार्य किया जाता है कि फॉर्म-17 (सी) और

डाले गए वोटों का मिलान हो और सभी काउंटिंग टेबल पर तमाम एजेंट इससे पूरी तरह संतुष्ट हों। हां, यदि ईवीएम सही परिणाम नहीं दिखा पा रही, तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर, यानी पीठासीन अधिकारी को वापस सौंप दिया जाता है, लेकिन अन्य टेबलों पर ईवीएम से वोटों की गिनती बदस्तूर जारी रहती है। अंत में, जब प्रत्याशियों की हार-जीत का अंतर उस ईवीएम में पड़े कुल वोटों से अधिक पाया जाता है, तो उसे किनारे कर दिया जाता है, अन्यथा उसमें दर्ज आंकड़ों को फिर से जुटाने की कोशिश होती है।

मतगणना का कार्य बहुत ही संवेदनशील होता है। मतगणना-स्थल पर तनाव कम करने के हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। गड़बड़ी दिखते ही उसके निराकरण की तत्काल व्यवस्था की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के हर विधानसभा क्षेत्रों के पांच मतदान-केंद्रों पर वीवीपैट के मिलान की व्यवस्था की है। यह काम बहुत मुस्तैदी से किया जाता है। यहां तक कि वीवीपैट पर्चियों को उन स्थानों पर गिना जाता है, जहां तेज हवा का झोंका न आए, क्योंकि छोटी-छोटी पर्चियां हवा में उड़ सकती हैं और संबंधित मतदान केंद्र पर पड़े वोटों की संख्या से मिलान प्रभावित हो सकता है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं, इसलिए आयोग इसको लेकर विशेष संजीदा रहता है।

पहले चुनाव मतपत्रों से होते थे, तो सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना अगले दिन सुबह चार बजे तक भी चलती रहती थी। उस समय मतपत्रों की गिनती सीधे नहीं होती थी, बल्कि मतपेटियों से सभी मतपत्रों को एक जगह निकालकर 25-25 का बंडल बनाया जाता था और फिर उसे आपस में मिलाकर हर टेबल पर बांट दिया जाता था। इससे यह पता नहीं चल पाता कि किस मतदान-केंद्र का मतपत्र किस टेबल पर आया है। यह बेशक एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी, पर ऐसा करना अनिवार्य समझा गया था, क्योंकि जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उन्होंने यह महसूस किया था कि विजेता प्रत्याशी आमतौर पर उन मतदान-केंद्रों के मतदाताओं के प्रति रूखा व्यवहार रखता था, जहां से उसे कम वोट मिले होते हैं। विजेता प्रत्याशियों की इसी दुर्भावना की काट उन्होंने मतपत्रों को आपस में मिलाने और 25-25 के बंडल में हर टेबल पर बांटने के रूप में निकाली थी।

वैसे, मतों की गिनती के इस कार्य में मील का पत्थर सिर्फ यही एक प्रयास नहीं है। पहले के दो आम चुनावों में, यानी 1952 और 1957 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम की मतपेटी रखी जाती थी और मतदाता अपने चुनिंदा प्रत्याशी की मतपेटी में पर्ची गिरा देते थे, जिनकी गिनती करके नतीजे का एलान किया जाता था। बाद में मतपत्रों की व्यवस्था की गई, लेकिन शुरुआती दौर में मतदान-केंद्रों के आधार पर मतपत्रों की गिनती होती थी, जिसे टीएन शेषन ने बदल दिया। ईवीएम ने मतगणना के कार्य को काफी आसान बना दिया। इसमें छह-सात घंटों में ही परिणाम आने लगा। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका के बाद वीवीपैट की व्यवस्था शुरू हुई, ताकि मतदाता को पता चल सके कि उसने जिस प्रत्याशी के नाम का बटन दबाया है, वोट उसे ही मिला है। फिर, हरेक विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्ची मिलाने की व्यवस्था की गई, जिसे बढ़ाकर अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच-पांच मतदान केंद्रों तक कर दिया गया है।

जब मुकाबला कड़ा होता है, तब मतों की गिनती काफी चुनौतीपूर्ण कसरत मानी जाती है। आयोग पर इसकी जवाबदेही बढ़ जाती है कि प्रत्याशियों के संदेह का तत्काल निराकरण हो। आयोग इसमें सफल रहा है, इसलिए उसकी साख पूरी दुनिया में है। जितने मत यूरोप व अमेरिका में डाले जाते हैं, उनसे कहीं अधिक भारत में मतदान होता है। यहां पश्चिमी देशों की तरह मतदाताओं में साक्षरता नहीं है, फिर भी हमारे यहां चुनाव ऐतिहासिक होते हैं और सभी पार्टियां नतीजों को स्वीकार करती हैं। नतीजों के खिलाफ याचिकाएं भी नाममात्र की डाली जाती हैं। इसकी वजह यही है कि आयोग आपत्तियों का निपटारा करने में सक्षम है। इस बार भी यदि किसी प्रत्याशी को आपत्ति हो और वह प्रथम दृष्टया अपने आरोपों का तथ्यात्मक आधार देने में सफल होता है, तो उसकी शिकायत पर पीठासीन अधिकारी तत्काल कार्रवाई करेगा। संतुष्ट न होने पर चुनाव आयोग को प्रतिवेदन भी भेजा जा सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नई पीढ़ी को ही करना होगा विश्व पर्यावरण का उद्धार

यहां स्कैन करें

अनिता भटनागर जैन | पूर्व आईएएस अधिकारी

मार्च में बेंगलुरु महानगर में 500 वर्ष में पहली बार पानी के लिए हेल्पलाइन खोलनी पड़ी। कई लोगों ने पानी की समस्या के चलते कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दिया। जल के लिए तरसते शहरों में बेंगलुरु कोई अकेला नहीं है। यह एक चुभने वाला तथ्य है कि अप्रैल 2024 में भारत के 22 राज्यों में 150 मुख्य वाटर रिजरवॉयर या जलाशयों में एक-तिहाई से कम पानी बचा था। यह भी चुभने वाला तथ्य है कि मई 2024 में अनेक राज्यों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहा। जब जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का अभाव होने लगे, जब मौसम प्रतिकूल हो, तब पर्यावरण की चिंता बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार पर्यावरण दिवस का विषय है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति में बदलाव। ये तीनों मुद्दे परस्पर जुड़े हैं और इस बार का नारा है - हमारी भूमि, हमारा भविष्य, हम हैं उद्धार करने वाली पीढ़ी।

गौर करने की बात है कि पृथ्वी की 75 प्रतिशत से अधिक भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में भी 30 प्रतिशत से अधिक भूमि में उत्पादकता समाप्त हो चुकी है और 25 प्रतिशत कुल भूमि मरुस्थलीकरण श्रेणी में है। विश्व में सूखा पड़ने की संख्या और अवधि में 29 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यदि युद्ध-स्तर से रोकथाम नहीं की गई, तो 2050 तक दुनिया की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी सूखाग्रस्त हो जाएगी। आज मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पता चल रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस बार जनवरी में गुलमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फ नहीं गिरी, जिससे न केवल पर्यटन पर प्रभाव पड़ा, नदियों में पानी कम होने के कारण पीने व सिंचाई हेतु जल का अभाव हो गया।

शहरी लोगों को सचेत होना पड़ेगा। विश्व की आधी आबादी अभी शहरों में रहती है, साल 2050 तक 66 फीसदी हो जाएगी। कल पर्यावरण दिवस-

आज गंगा जैसी नदी भी मुश्किल में है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय गंगा में 70 प्रतिशत पानी हिमालय के झरनों और छोटी नदियों से आता था। हिमालय के 30 लाख झरनों में से 50 प्रतिशत सूख चुके हैं। 2030 तक देश में भूगर्भ जल 409 मीटर गिरने का अनुमान है और इससे भूजल में रासायनिक जहर की वृद्धि होगी। भूमि क्षरण के कारण सूखा बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक भूख को समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति अब संभव प्रतीत नहीं होती है। 2023 में 28.20 करोड़ लोग तीव्र भूख से ग्रसित रहे। भारत में वर्ष 2022 में गरम हवाओं या लू की वजह से गेहूं की फसल में 35 प्रतिशत गिरावट आई। अब खामोश सूखा भी पाया जाता है यानी भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होने से धान और गेहूं की गुणवत्ता 45 प्रतिशत कम हो गई है। इनमें जिंक व आयरन जैसे आवश्यक तत्वों में भी 33-27 प्रतिशत तक गिरावट आई है। जब भोजन में उपयुक्त पौष्टिकता नहीं रह जाएगी, तब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और लोग बार-बार बीमार पड़ेंगे और इससे भी देश की उत्पादकता व आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

ध्यान रहे, भूमि क्षरण का संबंध केवल मनुष्यों से नहीं है, भूमि पर केवल हम ही नहीं, 60 प्रतिशत जीव भी उसी में रहते हैं। 95 प्रतिशत भोजन जो हम खाते हैं, वह भूमि से ही उत्पादित होता है। स्वस्थ भूमि कार्बन डाइऑक्साइड को भी जज्ब करती है। 75 प्रतिशत प्रतिशत फल और बीज परागीकरण के लिए मधुमक्खियों आदि पर निर्भर हैं। भूमि पर निर्भर ये सभी जीव जलवायु परिवर्तन, खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों के उपयोग से खत्म हो रहे हैं। जैव विविधता प्रभावित हो रही है। खेतों में या भूमि पर कीटाणु न मिलने के कारण पक्षियों को भोजन नहीं मिल पा रहा है और तालाबों के सूखने से पक्षियों के रहने के स्थान भी समाप्त होते जा रहे हैं। यह खतरा अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियां नहीं रह जाएंगी।

सबसे पहले शहर में रहने वालों को सचेत होना पड़ेगा। विश्व की आधी आबादी अब शहरों में रहती है और 2050 तक यह 66 प्रतिशत हो जाएगी। शहरी क्षेत्र पृथ्वी के 75 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और 50 प्रतिशत से अधिक कूड़ा व 68 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्पादित कर रहे हैं। शहरों के बढ़ने के साथ आसपास की प्राकृतिक दुनिया समाप्त होती जा रही है, जीवन बचाने के लिए सजग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

तभी होगा सामाजिक बदलाव

समाज क्या है? समाज अपने में कुछ नहीं है। जो आपने और मैंने अपने संबंधों में निर्मित किया है, वही समाज है। समाज हमारी तमाम आंतरिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का ही प्रक्षेपण है। इसलिए अगर आप और मैं स्वयं को नहीं समझते, तो केवल उस बाह्य को रूपांतरित करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, जो भीतर का ही प्रक्षेपण है। तात्पर्य यह है कि समाज में तब तक कोई महत्वपूर्ण बदलाव संभव नहीं है, जब तक मैं आपके साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता।

अपने संबंध में भ्रांत होने के कारण मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करता हूं, जो मेरा ही प्रतिरूप है, जो मेरी ही वास्तविकता की बाहरी अभिव्यक्ति है। यह एक स्पष्ट तथ्य है, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर हम विमर्श कर सकते हैं कि क्या समाज ने, इस बाह्य अभिव्यक्ति ने मुझे निर्मित किया है, अथवा मैंने समाज को निर्मित किया है।

क्या यह एक स्पष्ट तथ्य नहीं है कि दूसरों के साथ अपने संबंध में जो कुछ मैं हूं, उसी ने समाज को निर्मित किया है और बिना स्वयं में आमूल परिवर्तन लाए समाज की आधारभूत कार्यप्रणाली में कोई रूपांतरण संभव नहीं है? जब हम समाज में परिवर्तन के लिए किसी व्यवस्था-प्रणाली को खोजते हैं, तो हम समस्या को बस टाल रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था मनुष्य में आमूल परिवर्तन नहीं ला सकती। मनुष्य ही व्यवस्था को बदलता है। इतिहास यही दर्शाता है। जब तक आपके साथ संबंध में मैं स्वयं को नहीं समझ पाता, मैं ही इस अशांति, क्लेश, विनाश, भय और बर्बरता का कारण बना रहूंगा। अपने को समझने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती; मैं ठीक इसी क्षण अपने को समझ सकता हूं। यदि मैं यह कहता हूं, 'मैं खुद को कल समझूंगा', तो मैं अव्यवस्था व क्लेश ही पैदा करूंगा, मेरा कार्य विनाशकारी होगा। जिस क्षण मैं यह कहता हूं कि 'समझूंगा', मैं समय को बीच में ले आता हूं और इस तरह मैं भ्रांति और विनाश के तूफान में फंस जाता हूं। बोध तो तत्क्षण होता है, कल नहीं। कल आलसी मन के लिए, प्रमादी मन के लिए होता है, उस मन के लिए, जो निरुत्साही है।

क्या यह तथ्य नहीं है कि दूसरों के साथ अपने संबंध में जो कुछ मैं हूं, उसी ने समाज को निर्मित किया है और बिना स्वयं में आमूल परिवर्तन लाए समाज में कोई रूपांतरण संभव नहीं है?

जब आपकी किसी चीज में सचमुच रुचि होती है, तब आप उसे तुरंत करते हैं, वहां तुरंत बदलाव आ जाता है। यदि आप अभी, इसी क्षण नहीं बदलते हैं, तो आप कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वह परिवर्तन जो कल होता है, एक संशोधन मात्र है, वह मौलिक परिवर्तन नहीं होता। रूपांतरण केवल तत्काल हो सकता है। क्रांति इसी क्षण है, कल नहीं।

ऐसा होने पर आप समस्या से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब स्व अपने विषय में चिंतित नहीं होता; तब आप विनाश की पहुंच से परे होते हैं।

जे कृष्णमूर्ति

सचिन तेंदुलकर | पूर्व क्रिकेटर

जब मैं क्रिकेट में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर रहा था, तब मेरे पिता ने मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण सलाह दी थी कि कभी तंबाकू को बढ़ावा नहीं देना। मैंने इसको जिया है। आप भी तंबाकू की जगह सेहत को चुनिए!

परिणाम के करीब होते एग्जिट पोल

बुद्धिजीवी पत्रकारों और मतदाताओं का मिजाज पढ़ने वालों का समूह हर मतदान-केंद्र, हर निर्वाचन-क्षेत्र और हर मतदाता व उसकी भावनाओं से बहुत करीब से जुड़ा होता है, जिसके लिए वह परिश्रम भी करता है। उसकी इस मेहनत पर विश्वास करना लाजिमी है। नेताओं या राजनीतिक पार्टियों के विश्लेषण अपने हितों के मद्देनजर होते हैं। तभी तो ज्यादातर नेता अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कही गई बातें ही दोहराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के परिणाम भले ही एग्जेक्ट न निकलें, पर उसके करीब जरूर होते हैं। मसलन, हाल के चुनावी एग्जिट पोल पर यदि हम नजर डालें, तो उनमें जिस-जिस दल की सरकार बनने की बात कही गई, नतीजे कमोबेश उसी के अनुरूप आए, भले सीटें कुछ ऊपर-नीचे हुईं। इसीलिए इस बार भी माना जा रहा है कि एग्जिट पोल देश का सही मूड बता रहे हैं और विपक्ष अपने लिए इसमें बहुत उम्मीदें न देखे। वास्तव में, एग्जिट पोल में अलग-अलग समूहों का मन टटोला जाता है। चूंकि अपने यहां मतदान काफी हद तक एक सामूहिक कर्म ही है, इसलिए मतदान के दिन किसी भी समूह की बहुतायत आबादी किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद दिखती है। यही कारण है कि एग्जिट पोल काफी हद तक सच के करीब होते हैं।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

सटीक होते पूर्वानुमान

एग्जिट पोल के ज्यादातर नतीजे अगर वास्तविक परिणाम से मेल खा जाते हैं, तो इसके पीछे शायद वह शोध अध्ययन काम करता है, जिसे अंजाम देने वालों को 'सेफॉलोजिस्ट' कहा जाता है। सवाल उठता है कि उनके अनुमान आखिर सटीक कैसे बैठते हैं, जबकि उनकी पहुंच कुछेक हजार मतदाताओं तक होती है? दरअसल, यह पूरी कवायद एक तरह से मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, जो भारत जैसे देश में काफी आसान है, क्योंकि जाति, धर्म और लाभार्थी समूह के गुणा-भाग के दृष्टिगत हर राजनीतिक दल का अपना मतदाता समूह होता है। प्रबुद्ध वोटिंग हमारे देश में अब भी दूर है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं है या मतदाता परिपक्वता का परिचय नहीं देते हैं। बावजूद इसके एक सम्मोहन तो है ही जाति-धर्म का। अगर यह सम्मोहन न रहा होता, तो मतदाता मुखर नहीं होता। तब शायद पूर्वानुमान में लगी एजेंसियों के कार्य कठिन जरूर होते। स्पष्ट है, ऐसे पूर्वानुमानों को छद्म तरीके से मतगणना से ठीक पहले चलाना दरअसल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने जैसा है, राजनीतिक दलों ने इस बार इन्हें अपने-अपने पक्ष में खूब दिखाया।

मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार

इससे पूरे देश का मूड नहीं जान सकते

आम चुनाव के अंतिम चरण के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल जारी किए और यह अंदाजा लगाया कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देश की बागडोर कौन संभालने जा रहा है? इन सवालों का सही-सही जवाब तो आज दोपहर तक पता चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल पर इसलिए संदेह होते हैं, क्योंकि ये देश का जनादेश जानने के लिए अवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। भारत गांवों का देश है, जहां शायद ही कोई एजेंसी सर्वेक्षण करने जाती है। वे तो शहर में ही कुछ लोगों से अपना सर्वेक्षण करा लेती हैं और अगर उनको जरूरत महसूस होती है, तो गांवों में टेलीफोन करके वहां की जनता का रुख जानने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करते हुए एजेंसियां भूल जाती हैं कि मतदाता अब कहीं अधिक जागरूक हो चला है। वह यूं ही अपने मन की बात किसी एजेंसी को नहीं बताता। मगर एजेंसियां हैं कि मानती नहीं। इसका नुकसान टीवी चैनलों को होता है और जनता में उनका विश्वास कम होता है। एग्जिट पोल के झूठे साबित होने से दर्शकों का विश्वास समाचार चैनलों से खत्म होने लगता है। हर चुनाव में इस तरह की भविष्यवाणियां की जाती हैं और ज्यादातर बार ये गलत साबित हुई हैं। हां, कभी-कभी जनमत सर्वेक्षण सही भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अपवाद ही माना जाना चाहिए। व्यापकता में उसे स्वीकार करना गलत होगा। वैसे भी, करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में कुछेक हजार लोगों का रुझान लेकर आप सही अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जनता का मूड किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अवैज्ञानिक तरीका

जनमत सर्वेक्षण जुटाने का आधार क्या है? एजेंसियां चंद लोगों को कुछ समय के लिए नियुक्त करती हैं, उनको एक फॉर्म दिया जाता है और कहा जाता है कि जनता से फॉर्म भरवाया जाए। मगर ऐसे लोगों में से अधिकतर अपने मन की बातें ही फॉर्म में भरकर एजेंसी के दफ्तर में जमा कर देते हैं। एजेंसियां फोन का सहारा भी लेती हैं और चुनाव खत्म होते ही कुछ मतदाताओं को फोन करके उनके रुख को जानने का प्रयास करती हैं, मगर मतदाता जागरूक हो गए हैं, इसलिए वे फोन करने वाले की मानसिकता समझकर अपने रुख का इजहार करते हैं। इस तरह जनमत सर्वेक्षण में वैज्ञानिक तरीके का शायद ही पालन हो पाता है, इसलिए इनके नतीजों पर यकीन करना काफी कठिन माना जाता है।

राजीव कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

कड़े परिश्रम का परिणाम सदैव सुखद होता है

चुनावों का सही समय

आखिरकार चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि उसे एक माह पहले चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन अच्छा होता कि आम चुनावों की घोषणा करने के पहले ही उसे इसका आभास हो गया होता कि मई-जून की भीषण गर्मी में मतदाताओं के साथ-साथ चुनाव कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे यह आभास इसलिए हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने मौसम विभाग से इस बारे में विचार-विमर्श किया था कि मई-जून में बढ़ते तापमान की क्या स्थिति रहेगी? अब तो जो होना था, वह हो गया, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मई-जून में चुनाव न कराए जाएं। इसलिए और भी, क्योंकि लू के चलते अनेक मतदानकर्मियों के साथ सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई। उचित तो यह होगा कि हर सूरत में मई के पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने में कोई परेशानी भी नहीं है। चुनाव आयोग को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कम रहने का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी माना जा रहा है। वैसे तो मतदान प्रतिशत कम रहने के कुछ अन्य भी कारण हैं, लेकिन प्रतिकूल मौसम की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग को केवल अनुकूल मौसम में ही चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चुनाव की अवधि कम से कम कैसे हो। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया लगभग ढाई माह तक चली। यह ठीक है कि हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव आयोग को कहीं अधिक तैयारी करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन समय की मांग यही है कि चुनाव प्रक्रिया यथासंभव छोटी हो। आखिर यह एक तथ्य है कि अतीत में चार-पांच चरणों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। इन स्थितियों में भविष्य में अधिक से अधिक चार-पांच चरणों में ही चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी चुनाव प्रक्रिया का मतलब है लंबे समय तक आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहना। इस आचार संहिता के चलते एक तरह से समस्त सरकारी कामकाज ठप हो जाते हैं। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। वास्तव में अब तो चुनाव आयोग को लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की भी तैयारी करनी चाहिए। निःसंदेह यह बड़ा काम होगा, लेकिन यदि इच्छाशक्ति हो तो यह काम किया जा सकता है। यह वक्त की जरूरत है कि राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के सुझाव पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करें। यह वह विचार है, जिसके अमल का समय आ गया है।

कुत्तों का आतंक

कोई समस्या यदि इतनी गंभीर हो जाए कि जनजीवन के लिए संकट पैदा करे और राज्य की मशीनरी उसके प्रति उदासीन दिखाई दे तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करना ही चाहिए और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ऐसा ही किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम कर अदालत ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। वह इस प्रकरण को लेकर कितना गंभीर है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने तल्ख टिप्पणी भी की कि बच्चों पर आवारा कुत्ते हमला करें तो हम आंख नहीं बंद कर सकते। साथ ही नगर निगम से पूछा है कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब जब कोर्ट ने व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है तो समस्या के समाधान की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन इसके लिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इस संबंध में किसी योजना के अमल में क्या-क्या समस्याएं आती हैं। लखनऊ से पहले प्रदेश के अन्य महानगरों में भी सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के हमले में बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। इसलिए इस समस्या को नगर निगमों के दायरे से बाहर आकर राज्य के स्तर पर सोचा जाना चाहिए। एनीमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, प्रिवेंशन आफ एनीमल क्रुअल्टी एक्ट तथा यूपी म्यूनिसपल कारपोरेशन एक्ट के प्रविधानों को सामने रखते हुए ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए, ताकि सड़क पर निकलने वाले स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। जानवरों के अधिकारों के लिए लड़नेवाली संस्थाओं को इस बात का भी संज्ञान लेना होगा कि मनुष्यों को भी जीवन का अधिकार है। किसी बच्चे की मौत उसके परिवार को जिंदगी भर का दंश दे जाती है जिससे वह कभी उबर नहीं पाते, यह समझना होगा।

चुनावों के बाद की राजनीति

हृदयनारायण दीक्षित

एक तल्ख चुनाव अभियान निपटने के बाद अब राष्ट्र की समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता ही राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीय विचार होना चाहिए

अवधेश राजपूत

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लिए चुनाव संपन्न हुए। सात चरणों में चली इस मैराथन चुनाव प्रक्रिया पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। भरी गर्मी के बीच हुए चुनावों में सियासी पारा भी खासा ऊपर चढ़ा हुआ था, पर बंगाल और बिहार जैसे छिटपुट अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बंगाल में कायम चुनावी हिंसा राष्ट्रीय चिंता का विषय है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का कटुतापूर्ण वातावरण था। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विमर्श कम था। विकसित भारत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अर्थपूर्ण बहस नहीं हुई। अर्थनीति पर भी सार्थक विमर्श नहीं हुआ।

अब नई लोकसभा से तमाम उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय विमर्श ही भारत की एकता का आधार है। हम भूमंडलीय ताप पर चर्चा करते हैं। हम संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में विश्व शांति की कामना करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अभिकर्ता हो जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् भारत की अभिलाषा है। भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक राष्ट्र है। राष्ट्र की रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीय विचार होना चाहिए। आम सहमति के मुद्दे सुस्पष्ट हैं और असहमति के मुद्दे भी। सतत विमर्श, असहमतियों पर चर्चा और राष्ट्रीय मुद्दों पर मतैक्य होना ही चाहिए। राष्ट्रीय विमर्श से देश का आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। राष्ट्रीय एकता-अखंडता और सारी दुनिया के प्रति हमारा दायित्व आदि मुद्दे चुनाव के दौरान गहन विचार-विमर्श का विषय बनते तो ज्यादा अच्छा होता। असहमति के मुद्दों पर विमर्श से साझा दृष्टिकोण विकसित होता है। वाद, विवाद और संवाद में भी साझा दृष्टिकोण की जरूरत होती है।

जीत को लेकर सबके अपने-अपने दावे और तर्क हैं। नतीजा पूर्व सर्वेक्षणों में राजग भारी बहुमत से आगे है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। हालांकि नतीजों से पहले सभी जीतने की बात कर रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। मतदाताओं का जनादेश सबको साथ लेकर चलने की प्रतिभूति होगा। जनता ही बहुमत पक्ष को सत्ता संचालन का जनादेश देती है और जनता ही किसी दल या समूह को प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर देती है। अल्पमत समूह जनता द्वारा खारिज नहीं किया जाता। वह सत्ता पक्ष को लोक कल्याण के सुझाव देता है। सरकार की आलोचना करता है। ब्रिटिश संसदीय परंपरा में विपक्ष को 'प्रतीक्षारत सरकार' कहते हैं। देश के सभी दलों/समूहों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। कभी-कभी पराजित दल चुनाव परिणामों को गरिमापूर्वक स्वीकार नहीं करते। वे चुनाव परिणामों को गलत सिद्ध करने के लिए बहानेबाजी करते हैं। ईवीएम का बहाना सर्वविदित है। ऐसी बयानबाजी से चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर चोट लगती है। जीते-हारे सभी पक्षों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बेशक लंबे चले चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आक्षेप से वातावरण तनावपूर्ण है, लेकिन जनादेश का सम्मान सबका कर्तव्य है।

भारत के इतिहास में 14 अगस्त, 1947 की तिथि ऐतिहासिक है। उस दिन संविधान सभा की बैठक मध्यरात्रि के बाद तक चली। उस बैठक में सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि, 'हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि गरीबी, भूख, बीमारी, शोषण और भेदभाव मुक्त सुंदर जीवन वाला समाज बनाने की अथक कोशिश करते रहेंगे।' डा. राधाकृष्णन ने कहा, 'एक चिर प्रतीक्षा की रजनी के अवसान पर जो भाग्य निर्णायक शुभ घटनाओं से परिपूर्ण है, स्वातंत्र्य सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। हम उत्साह के साथ इसका स्वागत करते हैं।' उन्होंने अधिकार मोह और भ्रष्टाचार के समूल विनाश की चर्चा की और कहा जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम शासन व्यवस्था को समुन्नत नहीं बना सकते। डा. राधाकृष्णन के शब्द आज भी प्रेरक हैं। उन्होंने इसी भाषण में कहा था, 'सबमें स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखने वाला ही स्वराज पाता है।' देश के सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संविधान और संविधान निर्माताओं का संकल्प याद रखना चाहिए। उस रात सभी सदस्यों ने एक प्रतिज्ञा पढ़ी। सदस्यों ने प्रतिज्ञा दोहराई। प्रतिज्ञा यह थी, 'अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तपस्या से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं संविधान सभा का सदस्य स्वयं को हिंदवासियों की सेवा में अर्पित करता हूं, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित गौरवपूर्ण स्थान पा सके।'

संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा ली गई यह शपथ महत्वपूर्ण है। इस प्रतिज्ञा में भारत को प्राचीन देश कहा गया है, लेकिन भारत के कथित लिबरल और वामपंथी भारत को प्राचीन राष्ट्र नहीं मानते। प्राचीन इतिहास एवं स्वाधीनता आंदोलन में भी भारत प्राचीन राष्ट्र ही माना गया। संविधान निर्माताओं के ऐसे संकल्प और उनकी अभिलाषाएं सदा याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे विषयों पर बहस होती रहनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए ही एक आदर्श संविधान गढ़ा था। इस संविधान में सशक्त कार्यपालिका है, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। देश के प्रत्येक छोटे-बड़े हिस्से से चुनकर आने वाले सदस्यों से लोकसभा बनती है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक एवं व्याख्याता है ही। अब तक 17 लोकसभा गठित हो चुकी हैं। अधिनियमों का पारण, सरकार को जवाबदेह बनाए रखना और विधायी कार्य के साथ संविधान संशोधन का सुदीर्घ इतिहास है। 18वीं लोकसभा से भी राष्ट्र को ऐसी ही तमाम उम्मीदें हैं।

स्वप्नदर्शी होना अच्छा है। स्वप्नों को यथार्थ में बदलने के लिए परिश्रम करना और अच्छा है। विकसित भारत, शिक्षित और स्वाभिमानी भारत, विश्व के प्रत्येक जन के हित में सोचने वाला भारत, गरीबी मुक्त और स्वस्थ-समृद्ध भारत हम 140 करोड़ लोगों का स्वप्न है। देश के प्राचीन इतिहास में सभा समितियों के उल्लेख हैं। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में विचार भिन्नता के बावजूद साथ-साथ चलने एवं परस्पर विमर्शरत रहने की स्तुति है। सबको साथ लेकर सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में सबको जुड़ जाना चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

अस्तित्व के लिए संघर्षरत कई दल

उमेश चतुर्वेदी

आम चुनावों के प्रतिकूल नतीजे कई राजनीतिक दलों के भविष्य को अंधकारमय बना सकते हैं

संकट में हैं अकाली दल और बसपा जैसी पार्टियां। फाइल

यह आम चुनाव कुछ दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई का भी है। यदि मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया तो उनकी डगर कठिन हो जाएगी। इनमें कई छोटे-बड़े दल हैं। ये दल अपने-अपने राज्यों की सत्ता में रहे हैं अथवा सत्ता में साझीदार रहे हैं। एक दौर में इन्हें भविष्य का दल माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनका आधार निरंतर कमजोर होता गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो इनकी स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी।

सबसे पहले बसपा की चर्चा करते हैं। वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल करके गठबंधन सरकारों के सिलसिले पर विराम लगाया। बसपा के जनाधार में गिरावट 2014 के आम चुनावों से दिखने लगी। तब पार्टी को 19.62 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। इसके बाद हुए 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को वोट तो करीब इतना ही मिला, लेकिन सीटें मात्र 19 मिलीं। जिस पार्टी को दो चुनाव पहले स्पष्ट बहुमत मिला हो, उसके लिए ये आंकड़े निराशाजनक ही कहे जाएंगे। शायद यही वजह रही कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी धुर-विरोधी सपा से गठबंधन करने से भी परहेज नहीं किया। गठबंधन के दम पर उसके दस सांसद बने, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठजोड़ खत्म हो गया तो पार्टी मात्र एक सीट ही जीत पाई। बसपा के बारे में माना जा रहा है कि पार्टी का गैर-जाटव दलित मतदाता उससे छिटक गया है। इसी कड़ी में जदयू को रखा जा सकता है।

कभी भाजपा की विश्वस्त सहयोगी रही जदयू ने बीते दस वर्षों में कई बार पालाबदल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले उतरी और उसे 15.78 प्रतिशत वोट और सिर्फ दो सीटें मिल पाईं। इन नतीजों से निराश नीतीश ने उन लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिनके विरोध में अलग पार्टी का गठन किया था। उस गठबंधन के दम पर पार्टी ने राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन समय-समय पर नीतीश का 'हृदय परिवर्तन' होता रहा। 2020 के विधानसभा चुनावों में जदयू को बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाई। तब उसे सिर्फ 15.39 प्रतिशत वोट और 43 सीटों पर ही जीत मिली। अधिक सीटें हासिल करने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया।

शिवसेना भी कभी भाजपा की स्वाभाविक सहयोगी थी, लेकिन 2019 में उसने भाजपा से अपनी राह अलग कर ली। मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी ने अड़ियल रवैया अपनाया तो भाजपा से गठबंधन टूट गया। सत्ता के लिए शिवसेना उस कांग्रेस और शरद पवार की राकांपा के साथ खड़ी हो गई, जिसके खिलाफ उसकी राजनीति हमेशा आक्रामक रही। बाद में पार्टी टूटी और उसका एक धड़ा अब महाराष्ट्र की सत्ता में है, जिसे राकांपा से टूटा एक धड़ा सहयोग भी कर रहा है। अब उसके सामने अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर मतदाताओं का क्या रुख है और वे किस शिवसेना के साथ हैं-शिंदे की या उद्धव की? राकांपा के दोनों धड़ों के भाग्य का फैसला भी लोकसभा के चुनाव नतीजे करेंगे।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल यानी शिअद भी भाजपा की पुरानी सहयोगी पार्टी रही, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि सुधार कानूनों के विरोध के चलते वह उससे अलग हो गई। पंजाबी अस्मिता की राजनीति करने वाली शिअद को भाजपा से अलग होने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 18.38 प्रतिशत वोट और तीन सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब वह संकट से दो-चार है।

हरियाणा में इनेलो भी कभी भाजपा की सहयोगी रही, लेकिन 2014 के बाद से उसका भी आधार लगातार घटा है। 2014 के आम चुनाव में पार्टी को वोट तो 24.36 प्रतिशत मिले, लेकिन सीटें महज दो मिलीं। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उसे वोट तो करीब इतने ही मिले, लेकिन विधायक 19 चुने गए। बाद में घरेलू कलह में पार्टी टूट गई। इसके बाद जजपा का गठन हुआ। इनेलो से निकली जजपा को लोकसभा में 5.25 प्रतिशत वोट मिले, हालांकि सीट एक भी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में जरूर जजपा को 14.84 प्रतिशत वोट मिले और उसके दस विधायक चुने गए और वह भाजपा के साथ सरकार का हिस्सा भी बनी। यह गठजोड़ कुछ समय पहले ही टूट गया।

दक्षिण पर दृष्टि डालें तो कर्नाटक की जेडीएस राज्य की सत्ता में रही। उसके नेता एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन 2014 से जेडीएस लगातार कमजोर हो रही है। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में उसे 10.97 प्रतिशत वोट मिले और उसके दो सांसद चुने गए। इस कमजोर हालात की वजह से पार्टी ने चार साल बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसकी वजह से उसे 18.36 प्रतिशत वोट मिले, जबकि 37 विधायक चुने गए। वह सत्ता में भी शामिल हुई। 2019 के आम चुनाव में उसे बेहद कम यानी 9.67 प्रतिशत ही वोट मिले, जबकि सिर्फ एक सांसद चुना जा सका। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को लोकसभा की तुलना में करीब चार प्रतिशत ज्यादा वोट मिले। तेलंगाना में यही स्थिति तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनी बीआरएस की रही। राज्य की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही इस पार्टी को गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में 37 प्रतिशत वोट ही मिले और वह सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव भले ही केंद्रीय सत्ता का फैसला करने के लिए हुए हों, पर कई दलों के भाग्य की रेखा इन चुनावों के नतीजों के साथ जुड़ी है। इनमें तेदेपा व बीजद समेत उत्तर-दक्षिण के कुछ अन्य दल भी शामिल हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय का सदुपयोग

जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का रहस्य समय के सदुपयोग में निहित है। समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों में उलझ जाता है उसका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। इसलिए जीवन में उपलब्धियों के आकांक्षियों को चाहिए कि वे समय की धारा के साथ सही कदमताल करें। काम कल पर टाल देने से कार्य का भार दोगुना हो जाता है।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर समय के कुशल प्रबंधक थे। जब वह कालेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देख ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी एक मिनट भी आगे-पीछे नहीं चलते। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का प्रमुख आधार स्तंभ रहा है कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग समय गंवाकर आलस्य-प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं। समय सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। भौतिक धन-संपदा से भी अधिक बहुमूल्य। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह समय के मोल को नहीं समझेगा तो अपेक्षित परिणामों से वंचित रहेगा।

प्रकृति का प्रत्येक कार्य निश्चित समय पर होता है। समय पर ग्रीष्म तपता है, समय पर पानी बरसता है। चंद्रमा-सूर्य, ग्रह-नक्षत्र सभी समय के अनुसार गतिमान रहते हैं। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब जीवन के एक-एक क्षण को सावधानी के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा में निवेश करे। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ-साथ अनिश्चित एवं अज्ञात भी है। इसलिए हमें निरंतरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

समराज चौहान

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की अनदेखी

देवेंद्रराज सुथार

सेप्टिक टैंक व सीवर की सफाई व्यवस्था में मशीनों का उपयोग करने से श्रमिकों को जोखिम से बचाया जा सकता है

हाल ही में राजस्थान के भरतपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, देशभर में सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की मौत की ऐसी ही खबरें आती रहती हैं।

भारत में मैला ढोने का काम लंबे समय से उपेक्षा, सामाजिक उदासीनता और अपर्याप्त नियामक निगरानी में उलझा हुआ मुद्दा रहा है। इस प्रथा में शौचालय, सीवर, सेप्टिक टैंक और रेलवे ट्रैक से मानव मल को हाथ से साफ करना और उसका निपटान करना जैसे कार्य शामिल हैं। हालांकि 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक दबाव, विकल्पों की कमी और प्रणालीगत उपेक्षा के कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग विभिन्न रूपों में जारी है। भरतपुर में हुई मौतें उन भयावह परिस्थितियों को उजागर करती हैं जिनमें सफाई कर्मचारी काम करते हैं। अक्सर ये कर्मचारी बहुत कम या बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सेप्टिक टैंक और सीवर में प्रवेश करते हैं। इन सीमित स्थानों में जमा होने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसें दम घुटने और मौत का कारण बनती हैं।

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और इन श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कानूनी ढांचे के बावजूद सामाजिक कलंक और आर्थिक बाधाएं उन्हें इस खतरनाक व्यवसाय में फंसाए रखती हैं। हालांकि कानून मैला ढोने पर रोक लगाता है और इसमें लगे लोगों के पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अनियमित रहा है। अपर्याप्त धन, नौकरशाही जड़ता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने प्रभावी पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के प्रयासों को बाधित किया है। इसके अलावा, नीति एवं व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जमीन पर सुरक्षा नियमों के प्रवर्तन और सुरक्षात्मक उपकरणों के प्रविधान में गंभीर कमी है। लिहाजा मैला ढोने के विरुद्ध वर्तमान कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए ठोस प्रयास होना चाहिए।

इस पूरी व्यवस्था का मशीनीकरण करने से श्रमिकों को जोखिमों से बचाया जा सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र को सस्ती, प्रभावी सफाई तकनीकों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए सहयोग करना चाहिए। श्रमिकों को ऐसी मशीनरी चलाने व वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में बदलने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता और सामाजिक लामबंदी भी समाधान के महत्वपूर्ण घटक हैं। **(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)**

भारत को विकसित बनाने का संकल्प

'साधना से निकले नए संकल्प' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साधना और संकल्प की शक्ति को रेखांकित करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आलेख के माध्यम से साधना के संकल्प और स्वप्न पूर्ति के लिए प्रयास करने की शक्ति जुटाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी का यह लेख एक सामान्य भारतीय नागरिक को भी गहराई से छूता है। उनकी यात्रा और विचार हमें प्रेरित करते हैं कि कैसे हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उनका यह लेख न केवल एक राजनेता के विचार हैं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उनका संदेश साफ है-हमें हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी, नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता को अपनाना होगा। स्वामी विवेकानंद के 1897 के आह्वान को स्मरण करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि अगले 25 साल हमें केवल राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित करने चाहिए। यह विचार हमारे लिए एक संकल्प है, जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें यह अहसास दिलाता है कि देश की प्रगति में हमारा भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमें एकजुट होकर, सकारात्मक सोच के साथ, अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें हर चुनौती को अवसर में बदलना है। साधना और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

मेलबाक्स

साधना से निकले नए संकल्प

''साधना से निकले नए संकल्प'' शीर्षक आलेख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सटीक लिखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। याद रहे कि सकारात्मकता की गोद में ही सफलता पलती है। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद राक मेमोरियल में 45 घंटे तक मौन साधना की समाप्ति के बाद ऊर्जा से लबरेज प्रधानमंत्री ने सौ दिन के रोड मैप के लिए तैयारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों को अगली सरकार के सौ दिन के कामकाज का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एग्जिट पोल में भाजपा को तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाने की बात कही गई है। संभावित तीसरी पारी के लिए पीएम मोदी ने कुछ अलग तरह की योजनाएं तैयार की हैं। भारत का विकास वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अब नए सपने देखना जरूरी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए एकता और समर्पण के आह्वान में अगले 25 वर्ष केवल देश के लिए समर्पित करने की भावना निहित है। इसके लिए भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझना जरूरी है। इनका उपयोग विश्व के लाभ के लिए करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का लक्ष्य जरूरी है, ताकि भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

विपक्ष का विचित्र रवैया

विपक्षी नेता एक ओर कह रहे हैं कि उन्हें 295 सीटें प्राप्त होंगी, वहीं दूसरी ओर भ्रम भी पैदा कर रहे हैं कि मतगणना में गड़बड़ी होगी। पहली बात तो ये कि 295 का आंकड़ा आया कहां से। इसको राज्य दर राज्य सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बताना चाहिए था कि यहां से इतनी सीटें और वहां से इतनी सीटें मिलेंगी। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की जिसे विपक्षी मोदी का पोल या फिर फर्जी एग्जिट पोल बता रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में चार सौ से अधिक सीटें बता रहा है। हम कंजर्वेटिव आंकड़े भी लें तो भी एनडीए को बहुमत प्राप्त हो रहा है। विपक्षी दल जब-जब चुनाव हारते हैं, ईवीएम निशाने पर आ जाता है। कई बार वे सुप्रीम कोर्ट में मुंहकी खा चुके हैं। इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि यही जनता इन्हें कुछ राज्यों में जीत का सेहरा बांधती है तो संसद के चुनाव में क्यों हरा देती है।

बाल गोविंद, सेक्टर-44, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(8) मंगलवार, 4 जून, 2024 : ज्येष्ठ कृष्ण-13 वि. 2081

कड़े परिश्रम का परिणाम सदैव सुखद होता है

चुनावों का सही समय

आखिरकार चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि उसे एक माह पहले चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन अच्छा होता कि आम चुनावों की घोषणा करने के पहले ही उसे इसका आभास हो गया होता कि मई-जून की भीषण गर्मी में मतदाताओं के साथ-साथ चुनाव कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षाकर्मियों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे यह आभास इसलिए हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने मौसम विभाग से इस बारे में विचार-विमर्श किया था कि मई-जून में बढ़ते तापमान की क्या स्थिति रहेगी? अब तो जो होना था, वह हो गया, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मई-जून में चुनाव न कराए जाएं। इसलिए और भी, क्योंकि लू के चलते अनेक मतदानकर्मियों के साथ सुरक्षाकर्मियों की भी जान चली गई। उचित तो यह होगा कि हर सूरत में मई के पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने में कोई परेशानी भी नहीं है। चुनाव आयोग को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कम रहने का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी माना जा रहा है। वैसे तो मतदान प्रतिशत कम रहने के कुछ अन्य भी कारण हैं, लेकिन प्रतिकूल मौसम की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को केवल अनुकूल मौसम में ही चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चुनाव की अवधि कम से कम कैसे हो। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया लगभग ढाई माह तक चली। यह ठीक है कि हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव आयोग को कहीं अधिक तैयारी करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन समय की मांग यही है कि चुनाव प्रक्रिया यथासंभव छोटी हो। आखिर यह एक तथ्य है कि अतीत में चार-पांच चरणों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। इन स्थितियों में भविष्य में अधिक से अधिक चार-पांच चरणों में ही चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लंबी चुनाव प्रक्रिया का मतलब है लंबे समय तक आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहना। इस आचार संहिता के चलते एक तरह से समस्त सरकारी कामकाज ठप हो जाते हैं। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। वास्तव में अब तो चुनाव आयोग को लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की भी तैयारी करनी चाहिए। निःसंदेह यह बड़ा काम होगा, लेकिन यदि इच्छाशक्ति हो तो यह काम किया जा सकता है। यह वक्त की जरूरत है कि राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के सुझाव पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करें। यह वह विचार है, जिसके अमल का समय आ गया है।

कार्रवाई की जरूरत

राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी की शिकायतें नई नहीं हैं। आयुर्वेदिक अस्पताल में तो मरीज दवा की कमी से परेशान हैं ही अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में भी यह समस्या खड़ी हो गई है। राज्य के बड़े अस्पताल हों या छोटे इस समस्या का निराकरण न हो पाना निश्चित रूप से प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फिर भी कुछ व्यवस्थागत कमियों के कारण व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इन कारणों को चिन्हित करने की जरूरत है। साथ ही जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई के दायरे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन वजहों से सरकार की साख को ही चोट लगती है। साधन संपन्न लोग तो निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के लोगों का आसरा सिर्फ सरकारी चिकित्सा सेवा ही है। इसे सुदृढ़ बनाकर ही स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है। यह देखने की भी जरूरत है कि क्या जान बूझकर दवा की किल्लत पैदा की जाती है। यदि ऐसा है तो इसका लाभ किसे मिल रहा है। क्योंकि इस लाभ-हानि के खेल में गरीबों की बची-खुची कमाई लुट जा रही है। अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। कुछ हद तक इसपर लगाम लगी है, लेकिन जब मरीज दवा ही नहीं ले पाएंगे तो वे स्वस्थ कैसे होंगे। इसपर थोड़ा और आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। क्योंकि चिकित्सा ऐसा विषय नहीं, जिसे कुछ दिनों के लिए टाला जाए। मर्ज है तो हर हाल में दवा जरूरी है। इस मामले में और गंभीर होने की जरूरत है।

सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जिम्मेदार लोग कहीं जान-बूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर बार-बार सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपनी साख गिरा ली है?

आज का सवाल
क्या चुनाव आयोग को खुद पर झूठे आरोप लगाने वालों को दंडित करना चाहिए?

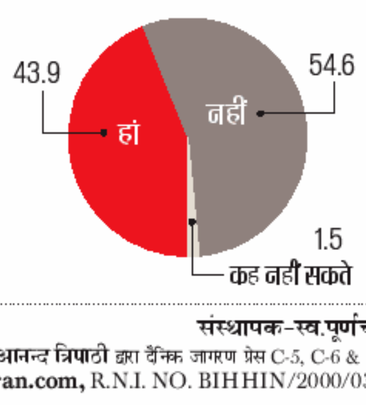

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

चुनावों के बाद की राजनीति

हृदयनारायण दीक्षित

एक तल्ख चुनाव अभियान निपटने के बाद अब राष्ट्र की समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता ही राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीय विचार होना चाहिए

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद के लिए चुनाव संपन्न हुए। सात चरणों में चली इस मैराथन चुनाव प्रक्रिया पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। भरी गर्मी के बीच हुए चुनावों में सियासी पारा भी खासा ऊपर चढ़ा हुआ था, पर बंगाल और बिहार जैसे छिटपुट अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बंगाल में कायम चुनावी हिंसा राष्ट्रीय चिंता का विषय है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का कटुतापूर्ण वातावरण था। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विमर्श कम था। विकसित भारत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अर्थपूर्ण बहस नहीं हुई। अर्थनीति पर भी सार्थक विमर्श नहीं हुआ।

अब नई लोकसभा से तमाम उम्मीदें हैं। राष्ट्रीय विमर्श ही भारत की एकता का आधार है। हम भूमंडलीय ताप पर चर्चा करते हैं। हम संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में विश्व शांति की कामना करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अभिकर्ता हो जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम् भारत की अभिलाषा है। भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक राष्ट्र है। राष्ट्र की रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि के प्रति लोक प्रतिबद्धता राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीय विचार होना चाहिए। आम सहमति के मुद्दे सुस्पष्ट हैं और असहमति के मुद्दे भी। सतत विमर्श, असहमतियों पर चर्चा और राष्ट्रीय मुद्दों पर मतैक्य होना ही चाहिए। राष्ट्रीय विमर्श से देश का आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। राष्ट्रीय एकता-अखंडता और सारी दुनिया के प्रति हमारा दायित्व आदि मुद्दे चुनाव के दौरान गहन विचार-विमर्श का विषय बनते तो ज्यादा अच्छा होता। असहमति के मुद्दों पर विमर्श से साझा दृष्टिकोण विकसित होता है। वाद, विवाद और संवाद में भी साझा दृष्टिकोण की जरूरत होती है।

जीत को लेकर सबके अपने-अपने दावे और तर्क हैं। नतीजा पूर्व सर्वेक्षणों में राजग भारी बहुमत से आगे है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभालेंगे। हालांकि नतीजों से पहले सभी जीतने की बात कर रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। मतदाताओं का जनादेश सबको साथ लेकर चलने की प्रतिभूति होगा। जनता ही बहुमत पक्ष को सत्ता संचालन का जनादेश देती है और जनता ही किसी दल या समूह को प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर देती है। अल्पमत समूह जनता द्वारा खारिज नहीं किया जाता। वह सत्ता पक्ष को लोक कल्याण के सुझाव देता है। सरकार की आलोचना करता है। ब्रिटिश संसदीय परंपरा में विपक्ष को 'प्रतीक्षारत सरकार' कहते हैं। देश के सभी दलों/समूहों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। कभी-कभी पराजित दल चुनाव परिणामों को गरिमापूर्वक स्वीकार नहीं करते। वे चुनाव परिणामों को गलत सिद्ध करने के लिए बहानेबाजी करते हैं। ईवीएम का बहाना सर्वविदित है। ऐसी बयानबाजी से चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर चोट लगती है। जीते-हारे सभी पक्षों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बेशक लंबे चले चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आक्षेप से वातावरण तनावपूर्ण है, लेकिन जनादेश का सम्मान सबका कर्तव्य है।

अवधेश राजपूत

भारत के इतिहास में 14 अगस्त, 1947 की तिथि ऐतिहासिक है। उस दिन संविधान सभा की बैठक मध्यरात्रि के बाद तक चली। उस बैठक में सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि, 'हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि गरीबी, भूख, बीमारी, शोषण और भेदभाव मुक्त सुंदर जीवन वाला समाज बनाने की अथक कोशिश करते रहेंगे।' डा. राधाकृष्णन ने कहा, 'एक चिर प्रतीक्षा की रजनी के अवसान पर जो भाग्य निर्णायक शुभ घटनाओं से परिपूर्ण है, स्वातंत्र्य सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। हम उत्साह के साथ इसका स्वागत करते हैं।' उन्होंने अधिकार मोह और भ्रष्टाचार के समूल विनाश की चर्चा की और कहा जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम शासन व्यवस्था को समुन्नत नहीं बना सकते। डा. राधाकृष्णन के शब्द आज भी प्रेरक हैं। उन्होंने इसी भाषण में कहा था, 'सबमें स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखने वाला ही स्वराज पाता है।' देश के सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संविधान और संविधान निर्माताओं का संकल्प याद रखना चाहिए। उस रात सभी सदस्यों ने एक प्रतिज्ञा पढ़ी। सदस्यों ने प्रतिज्ञा दोहराई। प्रतिज्ञा यह थी, 'अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तपस्या से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं संविधान सभा का सदस्य स्वयं को हिंदवासियों की सेवा में अर्पित करता हूं, ताकि यह प्राचीन देश संसार में अपना उचित गौरवपूर्ण स्थान पा सके।'

संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा ली गई यह शपथ महत्वपूर्ण है। इस प्रतिज्ञा में भारत को प्राचीन देश कहा गया है, लेकिन भारत के कथित लिबरल और वामपंथी भारत को प्राचीन राष्ट्र नहीं मानते। प्राचीन इतिहास एवं स्वाधीनता आंदोलन में भी भारत प्राचीन राष्ट्र ही माना गया। संविधान निर्माताओं के ऐसे संकल्प और उनकी अभिलाषाएं सदा याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे विषयों पर बहस होती रहनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए ही एक आदर्श संविधान गढ़ा था। इस संविधान में सशक्त कार्यपालिका है, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। देश के प्रत्येक छोटे-बड़े हिस्से से चुनकर आने वाले सदस्यों से लोकसभा बनती है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक एवं व्याख्याता है ही। अब तक 17 लोकसभा गठित हो चुकी हैं। अधिनियमों का पारण, सरकार को जवाबदेह बनाए रखना और विधायी कार्य के साथ संविधान संशोधन का सुदीर्घ इतिहास है। 18वीं लोकसभा से भी राष्ट्र को ऐसी ही तमाम उम्मीदें हैं।

स्वप्नदर्शी होना अच्छा है। स्वप्नों को यथार्थ में बदलने के लिए परिश्रम करते रहना और भी अच्छा है। विकसित भारत, शिक्षित और स्वाभिमानी भारत, सामर्थ्यवान भारत, विश्व के प्रत्येक जन के हित में सोचने वाला भारत, गरीबी मुक्त और स्वस्थ-समृद्ध भारत हम 140 करोड़ लोगों का स्वप्न है। देश के प्राचीन इतिहास में सभा समितियों के उल्लेख हैं। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में विचार भिन्नता के बावजूद साथ-साथ चलने एवं परस्पर विमर्शरत रहने की स्तुति है। सबको साथ लेकर सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन में सबको जुड़ जाना चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

अस्तित्व के लिए संघर्षरत कई दल

उमेश चतुर्वेदी

आम चुनावों के प्रतिकूल नतीजे कई राजनीतिक दलों के भविष्य को अंधकारमय बना सकते हैं

संकट में हैं अकाली दल और बसपा जैसी पार्टियां • फाइल

यह आम चुनाव कुछ दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई का भी है। यदि मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया तो उनकी डगर कठिन हो जाएगी। इनमें कई छोटे-बड़े दल हैं। ये दल अपने-अपने राज्यों की सत्ता में रहे हैं अथवा सत्ता में साझीदार रहे हैं। एक दौर में इन्हें भविष्य का दल माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनका आधार निरंतर कमजोर होता गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर इन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं मिला तो इनकी स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी।

सबसे पहले बसपा की चर्चा करते हैं। वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल करके गठबंधन सरकारों के सिलसिले पर विराम लगाया। बसपा के जनाधार में गिरावट 2014 के आम चुनावों से दिखने लगी। तब पार्टी को 19.62 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। इसके बाद हुए 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को वोट तो करीब इतने ही मिला, लेकिन सीटें मात्र 19 मिलीं। जिस पार्टी को दो चुनाव पहले स्पष्ट बहुमत मिला हो, उसके लिए ये आंकड़े निराशाजनक ही कहे जाएंगे। शायद यही वजह रही कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी धुर-विरोधी सपा से गठबंधन करने से भी परहेज नहीं किया। गठबंधन के दम पर उसके दस सांसद बने, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठजोड़ खत्म हो गया तो पार्टी विधानसभा में मात्र एक सीट ही जीत पाई। बसपा के बारे में माना जा रहा है कि पार्टी का गैर-जाटव दलित मतदाता उससे छिटक गया है। इसी कड़ी में जदयू को भी रखा जा सकता है।

कभी भाजपा की विश्वस्त सहयोगी रही जदयू ने बीते दस वर्षों में कई बार पालाबदल किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अकेले उतरी और उसे 15.78 प्रतिशत वोट और सिर्फ दो सीटें मिल पाईं। इन नतीजों से निराश नीतीश ने उन लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिनके विरोध में अलग पार्टी का गठन किया था। उस गठबंधन के दम पर पार्टी ने राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन समय-समय पर नीतीश का 'हृदय परिवर्तन' होता रहा। 2020 के विधानसभा चुनावों में जदयू को बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाई। तब उसे सिर्फ 15.39 प्रतिशत वोट और 43 सीटों पर ही जीत मिली। अधिक सीटें हासिल करने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया।

शिवसेना भी कभी भाजपा की स्वाभाविक सहयोगी थी, लेकिन 2019 में उसने भाजपा से अपनी राह अलग कर ली। मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी ने अड़ियल रवैया अपनाया तो भाजपा से गठबंधन टूट गया। सत्ता के लिए शिवसेना उस कांग्रेस और शरद पवार की राकांपा के साथ खड़ी हो गई, जिसके खिलाफ उसकी राजनीति हमेशा आक्रामक रही। बाद में पार्टी टूटी और उसका एक धड़ा अब महाराष्ट्र की सत्ता में है, जिसे राकांपा से टूटा एक धड़ा सहयोग भी कर रहा है। अब उसके सामने अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर मतदाताओं का क्या रुख है और वे किस शिवसेना के साथ हैं-शिंदे की या उद्धव की? राकांपा के दोनों धड़ों के भाग्य का फैसला भी लोकसभा के चुनाव नतीजे करेंगे।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल यानी शिअद भी भाजपा की पुरानी सहयोगी पार्टी रही, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि सुधार कानूनों के विरोध के चलते वह उससे अलग हो गई। पंजाबी अस्मिता की राजनीति करने वाली शिअद को भाजपा से अलग होने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 18.38 प्रतिशत वोट और तीन सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब वह संकट से दो-चार है।

हरियाणा में इनेलो भी कभी भाजपा की सहयोगी रही, लेकिन 2014 के बाद से उसका भी आधार लगातार घटा है। 2014 के आम चुनाव में पार्टी को वोट तो 24.36 प्रतिशत मिले, लेकिन सीटें महज दो मिलीं। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में उसे वोट तो करीब इतने ही मिले, लेकिन विधायक 19 चुने गए। बाद में घरेलू कलह में पार्टी टूट गई। इसके बाद जजपा का गठन हुआ। इनेलो से निकली जजपा को लोकसभा में 5.25 प्रतिशत वोट मिले, हालांकि सीट एक भी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में जरूर जजपा को 14.84 प्रतिशत वोट मिले और उसके दस विधायक चुने गए और वह भाजपा के साथ सरकार का हिस्सा भी बनी। यह गठजोड़ कुछ समय पहले ही टूट गया।

दक्षिण पर दृष्टि डालें तो कर्नाटक की जेडीएस राज्य की सत्ता में रही। उसके नेता एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन 2014 से जेडीएस लगातार कमजोर हो रही है। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में उसे 10.97 प्रतिशत वोट मिले और उसके दो सांसद चुने गए। इस कमजोर हालात की वजह से पार्टी ने चार साल बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसकी वजह से उसे 18.36 प्रतिशत वोट मिले, जबकि 37 विधायक चुने गए। वह सत्ता में भी शामिल हुई। 2019 के आम चुनाव में उसे बेहद कम यानी 9.67 प्रतिशत ही वोट मिले, जबकि सिर्फ एक सांसद चुना जा सका। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को लोकसभा की तुलना में करीब चार प्रतिशत ज्यादा वोट मिले। तेलंगाना में यही स्थिति तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनी बीआरएस की रही। राज्य की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही इस पार्टी को गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में 37 प्रतिशत वोट ही मिले और वह सत्ता से बाहर हो गई। स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव भले ही केंद्रीय सत्ता का फैसला करने के लिए हुए हों, लेकिन कई दलों के भाग्य की रेखा इन चुनावों के नतीजों के साथ जुड़ी है। इनमें तेदेपा और बीजद समेत उत्तर-दक्षिण के कुछ अन्य दल भी शामिल हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय का सदुपयोग

जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का रहस्य समय के सदुपयोग में निहित है। समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों में उलझ जाता है उसका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। इसलिए जीवन में उपलब्धियों के आकांक्षियों को चाहिए कि वे समय की धारा के साथ सही कदमताल करें। आज का काम कल पर टाल देने से कार्य का भार दोगुना हो जाता है।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर समय के कुशल प्रबंधक थे। जब वह कालेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी एक मिनट भी आगे-पीछे नहीं चलते। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का एक प्रमुख आधार स्तंभ रहा है कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग समय गंवाकर आलस्य-प्रमाद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं। समय सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। भौतिक धन-संपदा से भी अधिक बहुमूल्य। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह समय के मोल को नहीं समझेगा तो अपेक्षित परिणामों से वंचित रहेगा।

प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर संपन्न होता है। समय पर ग्रीष्म तपता है, अपने समय पर पानी बरसता है और सही समय आने पर शीत दस्तक देता है। चंद्रमा-सूर्य, ग्रह-नक्षत्र सभी समय के अनुसार गतिमान रहते हैं। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब जीवन के एक-एक क्षण को सावधानी के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा में निवेश करे। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ-साथ अनिश्चित एवं अज्ञात भी है। इसलिए हमें निरंतरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

समराज चौहान

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

भारत को विकसित बनाने का संकल्प

'साधना से निकले नए संकल्प' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साधना और संकल्प की शक्ति को रेखांकित करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आलेख के माध्यम से साधना के संकल्प और स्वप्न पूर्ति के लिए प्रयास करने की शक्ति जुटाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी का यह लेख एक सामान्य भारतीय नागरिक को भी गहराई से छूता है। उनकी यात्रा और विचार हमें प्रेरित करते हैं कि कैसे हमें अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उनका यह लेख न केवल एक राजनेता के विचार हैं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। उनका संदेश साफ है-हमें हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी होगी, नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता को अपनाना होगा। स्वामी विवेकानंद के 1897 के आह्वान को स्मरण करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि अगले 25 साल हमें केवल राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित करने चाहिए। यह विचार हमारे लिए एक संकल्प है, जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें यह अहसास दिलाता है कि देश की प्रगति में हमारा भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमें एकजुट होकर, सकारात्मक सोच के साथ, अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें हर चुनौती को अवसर में बदलना है। साधना और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

मूल भाव हो श्रेष्ठता

'साधना से निकले नए संकल्प' शीर्षक आलेख में नरेन्द्र मोदी ने सटीक लिखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। सकारात्मकता की गोद में ही सफलता पलती है। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद राक मेमोरियल में 45 घंटे तक मौन साधना की समाप्ति के बाद ऊर्जा से भरे पीएम नरेन्द्र मोदी ने 100 दिन के रोड मैप की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों को अगली सरकार के 100 दिन के कामकाज का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एग्जिट पोल में भाजपा को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई है। अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए पीएम मोदी ने कुछ अलग हट कर योजनाएं बनाई हैं। अब भारत का विकास वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसके लिए नए सपने देखना जरूरी है। 2047 तक विकसित भारत के लिए एकता और समर्पण का आह्वान किया। अगले 25 वर्ष केवल देश के लिए समर्पित करें। भारत की आंतरिक क्षमताओं का समझना आवश्यक है। इनका उपयोग विश्व के लाभ के लिए करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों एवं सदियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का लक्ष्य, ताकि भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश, पूरा करने के लिए एक मिशन, प्राप्त करने के लिए एक नीयत होती है। हमें बिना एक भी पल बर्बाद किए बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें नए स्वप्न देखने होंगे, उन्हें जीना शुरू करना होगा।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

साइकिल संस्कृति को बढ़ावा

विश्व साइकिल दिवस (तीन जून) के अवसर पर चंद मिनट साइकिल चला लेने से इस दिवस की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। दुनिया भर में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साइकिल विकास और यातायात का प्रतीक है। इस दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। साइकिल की सवारी स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। दुनिया के कई देशों में साइकिलिंग की संस्कृति है। चीन में लगभग 38 प्रतिशत, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में 48 प्रतिशत, जापान में 57 प्रतिशत और फिनलैंड में 60 प्रतिशत लोग साइकिल चलाते हैं, जबकि भारत में केवल 10 प्रतिशत लोगों के पास ही साइकिल है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री साइकिल से ही कार्यालय जाया करते हैं। भारत में साइकिल की सवारी करना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। देश में साइकिल की सवारी गरीबों के लिए हो गई है। देश में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए नेताओं और नौकरशाहों को भी साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। बड़े शहरों में तेज रफ्तार वाली गाड़ियों के बीच में साइकिलिंग जानलेवा हो चुकी है। साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक की व्यवस्था होनी चाहिए। वायु प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में 21 भारत में हैं। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इससे अमीर-गरीब का भेद भी मिटेगा।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

रवीना टंडन बहुत बहादुर हैं। एक उग्र भीड़ के सामने वह अपने ड्राइवर के बचाव में खड़ी रहीं। उनके संग अभद्रता भी हुई, लेकिन वह पीछे नहीं हटीं। अगर रवीना टंडन वहां नहीं होतीं तो शायद ड्राइवर अस्पताल में होता।

रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

राजग को अगर 400 सीटें आईं तो यह तीन चौथाई बहुमत होगा। कुछ अन्य दल भी बाद में समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने राजग के लिए 200-250 सीटों का आकलन किया था, उन्होंने अपनी इच्छा बताई थी।

मानक गुप्ता@manakgupta

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने वहां 40 हजार से ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल 19 जून तक तैनात रखने का फैसला किया है। यह असाधारण फैसला तो है, लेकिन है बिल्कुल सही।

संदीपन देब@sandipanthedeb

एक्जिट पोल के नतीजों से सहमति या असहमति एक मुद्दा है, लेकिन विपक्षी नेताओं के कुछ बयान बेहद चिंताजनक हैं, जो जनादेश को खारिज करने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। चुनाव में भले ही किसी की जीत हो, लेकिन भारत में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण रहा है। आशा है कि यह सिलसिला इसी प्रकार कायम रहेगा।

बरखा दत्त@BDUTT

जनपथ

दावे-प्रतिदावे हुए खूब चली तकरार,
अब तो मिलने जा रही एक नई सरकार।
एक नई सरकार शुरू होगी अब गिनती,
बैठो दिल को थाम यही है सबसे विनती!
जिसके जैसे काम वोट वह वैसे पावे,
मिले उन्हीं को हार खोखले जिनके दावे!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिप्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 53

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अपने नागरिकों को सुरक्षित और खुशहाल बनाना ही सरकार का कर्तव्य है। - थॉमस जेफरसन

लोकसभा चुनाव के दरम्यान तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई ही, मतदान के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता की बर्बर हत्या और संदेशखाली की महिलाओं को धमकाया जाना दर्शाता है कि इस राज्य की राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में कुछ भी नहीं बदला है।

बंगाल अब भी वही है

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दरम्यान हुई हिंसा वहां राजनीति के हिंसक चरित्र को तो बताती ही है, लेकिन आखिरी चरण के मतदान के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में भाजपा के एक कार्यकर्ता की जिस बर्बर ढंग से हत्या की गई और अब संदेशखाली की महिलाओं को धमकाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, वह घोर निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दो महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता हफीजुल शेख को गोली मारी और फिर जब वह भागने लगा, तो उसकी गर्दन काट कर ले गए। इससे पूर्व, छठे चरण के मतदान से पहले पूर्वी मिदनापुर में एक तृणमूल कार्यकर्ता की भी हत्या हुई थी। यही नहीं, अंतिम चरण में ही दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में गुस्साई भीड़ ने जबरन मतदान केंद्रों में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को पास के तालाब में फेंक दिया था। ध्यान रहे कि ये घटनाएं तब हो रही हैं, जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की। सातवें और अंतिम चरण में तो पश्चिम बंगाल के नौ निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 967 कंपनियों और राज्य पुलिस के 33,292 कर्मियों को तैनात किया गया था, जो बाकी राज्यों की तुलना में एक रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी बीते अप्रैल में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, तो वर्ष की शुरुआत में राशन घोटाले की जांच करने बंगाल पहुंचे ईडी के अधिकारियों के साथ भी अराजक सुलूक हुआ। ये घटनाएं बताती हैं कि आज के बंगाल की हालत बीस-पच्चीस साल पहले के बिहार जैसी है, जहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। दरअसल, अपने लंबे शासन के दौरान माकपा ने हिंसा और दबाव की जिस राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया, 'परिवर्तन' के

नारे के साथ राज्य की सत्ता से उसे बेदखल करने वाली ममता बनर्जी ने इसे खत्म करने के बजाय जारी रहने दिया। ताजा हिंसा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने उचित ही बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट के दो मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश देने के साथ यह फैसला भी सुनाया है कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति देखते हुए केंद्रीय बलों की 400 टुकड़ियां कम से कम 19 जून तक राज्य में रहेंगी। ऐसे में, आज पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन यह शीशे की तरह साफ है कि इस राज्य को राजनीतिक हिंसा की कुसंस्कृति से मुक्त करने की लड़ाई अभी बहुत लंबी है।

नई सरकार का एजेंडा क्या हो

नई सरकार का व्यापक एजेंडा घरेलू और बाहरी क्षेत्र की उचित नीतियों के जरिये भारत की क्षमता को बेहतर बनाने में मददगार होना चाहिए। सरकार का ध्यान निजी निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक कर्ज घटाने पर केंद्रित हो। बाहरी क्षेत्र की नीतियां उन रणनीतियों पर केंद्रित हों, जो वैश्विक झटकों के जोखिम को कम करें।

आज 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक नई सरकार अपना कार्यभार संभाल लेगी। आइए, चुनावी दौर की तल्ख बयानबाजी से थोड़ा अलग हटकर हम आर्थिक नीति के क्षेत्र में नई सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं।

हालांकि भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन भू-राजनीतिक कारणों से अब भी झटके लगने की आशंका एवं अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत इससे अछूता नहीं है। हालांकि मूडीज और एस ऐंड पी जैसी प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अलावा, विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तक ने भारत की विकास दर की तारीफ की है। फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। इसलिए नई सरकार का व्यापक एजेंडा घरेलू और बाहरी क्षेत्र (अंतरराष्ट्रीय) के लिए उचित नीतियों के माध्यम से भारत की क्षमता को बेहतर बनाने में मददगार होना चाहिए। घरेलू क्षेत्र की नीतियों के तहत सरकार का ध्यान निजी निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक कर्ज घटाने पर केंद्रित होना चाहिए। बाहरी क्षेत्र की नीतियों को उन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो व्यापार के खुलेपन पर प्रतिबंध लगाए बिना भारत के लिए वैश्विक झटकों के जोखिम को कम करे। अब हम कुछ ऐसे क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिन पर नई सरकार अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेगी।

पिनाकी चक्रवर्ती
अर्थशास्त्री एवं एनआईपीएफपी के पूर्व निदेशक

भारत की राष्ट्रीय समृद्धि अलग-अलग राज्यों की समृद्धि से जुड़ी हुई है। आर्थिक समृद्धि के लिए केंद्र सरकार का काम नीति एवं विश्वास का एक सक्षम ढांचा तैयार करना है। आर्थिक सुधार के 25 वर्ष बाद यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों की आर्थिक नीति संबंधी कार्रवाइयां लोगों की आर्थिक नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए आने वाली सरकार को

विकास एवं समृद्धि का लाभ उठाने की खातिर केंद्र-राज्य संबंधों को और मजबूत बनाना होगा।

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों ने आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका को व्यापक तरीके से बढ़ाया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। उसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने इस प्रक्रिया को और मजबूत ही बनाया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहद सामंजस्यपूर्ण रिश्ते देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि हाल के महीनों में विभिन्न मुद्दों पर हमने केंद्र और राज्यों के रिश्तों में तनाव देखा है। बेशक, इनमें से कुछ मुद्दे चुनावी मौसम होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संसाधनों पर राज्यों के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता तथा केंद्र एवं राज्यों की विषम शक्तियां ऐसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान एक संघीय देश को हमेशा करने की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। यदि इनका समाधान न किया जाए, तो ये जरूर असामान्य हो सकते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच चर्चा, बहस और बातचीत के लिए इस तरह से एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए कि वह केंद्र-राज्य संबंधों के सभी मुद्दों का भरोसे के आधार पर समाधान सुझाए।

हमारे देश का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। वर्ष 2030 तक शहरी आबादी के मामले में भारत सबसे ज्यादा शहरीकृत देशों में से एक होगा। चूंकि तेज शहरीकरण के साथ-साथ विस्थापन भी तेजी से बढ़ेगा, इसलिए तेज शहरीकरण के लिए जरूरी संसाधनों के वित्तपोषण की खातिर उचित तरीके के बारे में सोचने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था और समाज में दूरगामी बदलावों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रावधान महत्वपूर्ण है और इसे रणनीतिक जरूरत ही माना जाना चाहिए। शहरीकरण का लाभ उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक निवेश संबंधी समर्थन महत्वपूर्ण होगा। नई सरकार को नए शहरी विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

साझा बाजार के विकास, उच्च आर्थिक विकास और राजस्व के मामले में जीएसटी का व्यापक लाभ उठाने के लिए जीएसटी संरचना के ढांचे को और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है। दो-दर वाली जीएसटी संरचना तैयार करने के लिए जीएसटी ढांचे में और सुधार की खातिर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। असल में, जीएसटी ढांचे में परिवर्तन केवल जीएसटी परिषद में ही किया जा सकता है। इसलिए इस दिशा में कदम उठाना जीएसटी ढांचे को सरल बनाने के दीर्घकालीन समाधान के लिए फायदेमंद होगा। नया जीएसटी ढांचा इस तरह तैयार किया जाना चाहिए, जिसका आधार व्यापक हो, लेकिन कर की दर कम हो। यह आसान काम नहीं है। राजस्व और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ऐसे बदलावों के निहितार्थ को समझने के लिए प्रमुख नीति विश्लेषण एवं आम सहमति बनाने की जरूरत होगी।

चूंकि भारत व्यापक आर्थिक समृद्धि हासिल करने की ओर तेजी से अग्रसर है, इसलिए देश में बढ़ती आर्थिक असमानता से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। इसके लिए सरकारी खर्च को अधिक से अधिक पुनर्वितरित करने की आवश्यकता है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान विरासत में मिली संपत्ति पर कर लगाने के बारे में काफी चर्चा हुई, लेकिन विभिन्न देशों के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि संपत्ति पर कर लगाकर प्रगति की गुंजाइश बहुत कम है। इस मामले में भारत का अपना अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए व्यापक आधार पर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकारी खर्च के पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा मददगार साबित होगा।

अंत में, नई सरकार का दीर्घकालीन एजेंडा प्रौद्योगिकी में निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार व उसका विनियमन करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के लिए उचित नीतिगत ढांचा तैयार करने पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बनाए रखा जा सके।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

चौरासी लाख योनियों में भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला, तो फिर इसका आना व्यर्थ गया; क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'राम' के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ ही गया।

विषयों में आनंद की खोज ही मनुष्य की भूल

__लोक-परलोक__ के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को ठुकराकर परमार्थ-पथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई अपने अनुभव की बात हमें सुनाते हैं, तो एक बार हमारे हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; आनंद का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिए विवश कर देता है। वे गा उठते हैं; क्योंकि गाए बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह और परिग्रह के चक्कर में पड़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमस्ती, उनके फक्कड़पन को क्या समझे? संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, शाहंशाह है। दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज के मोहरे हैं। फक्कड़पन, अलमस्ती और लापरवाही ही उसकी संपत्ति है। पृथ्वी ही उसकी सुकोमल शय्या है। जहां जी में आया सो लिया। सिर के नीचे अपनी बांह का कोमल उपधान, मुलायम तकिया लगा लिया। और चंदोवा? चंदोवा भी उसका कितना सुंदर है-नीला-नीला आकाश, जिसमें सूरज, चांद और तारों के छोटे-बड़े, रुपहले, सुनहले सुंदर जगमगाते हुए लट्टू लटक रहे हैं। मंद-मंद समीरण पंखा झल रहा है। चंद्रमा उसके विशाल आंगन में-जो सीमाहीन है, जिसके ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी है-प्रकाश की स्निग्ध कोमल किरणें बिखेर रहा है और विरक्ति-वनिता संग में आनंद की नव-नव लहरें उत्पन्न कर रही हैं। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है-बेचारे बादशाह इस सुख को क्या जानें?

चौरासी लाख योनियों में भूलता-भटकता हुआ जीव मनुष्य का शरीर पाकर यदि नहीं संभला, तो फिर इसका आना व्यर्थ गया; क्योंकि फिर वह उसी चौरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। 'राम' के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो जीवन व्यर्थ ही गया। संसार के सारे संग्रह-परिग्रह, कुटुंब-कबीला, महल-अटारी आंखें मुंद जाने पर क्या काम आएंगी? साधना-पथ में एकमात्र प्रभु की अनुकंपा करके ही साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस मार्ग में क्या सहायक होगा? साधक का ध्यान सदा-चाहे वह कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो-प्रभु के चरण-कमलों में ही रहना चाहिए। एकांत निष्ठा ही इस मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधना-मार्ग का रहस्य है-सदैव अखंड रूप से श्रीहरि-चरणों का आश्रय लिए रहना। आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो ईश्वर का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है। शर्त यह है कि अत्यंत झीना-सा आवरण भी न रहे। मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है, वह तो ठीक ही है; परंतु जहां खोज रहा है वहां वह वस्तु है नहीं, और जब वह वहां है ही नहीं, तो मिले कैसे? मनुष्य 'सुख', 'आनंद' खोज रहा है; परंतु वह खोज रहा है उसे इस जगत के विषयों में; सारी भूल यहीं है। यहां तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है; कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, और फिर इस नश्वर से शरीर के भीतर की भूख-प्यास बुझेगी ही कैसे? अंधेरे घर में जैसे बालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर हम बाहर आना नहीं चाहते; फिर ज्योति कैसे मिले, प्रकाश कैसे पाएं?

भगवान हमें देख रहा

सूत्र

भक्त की और भगवान की आंखें जब चार होती हैं, तभी प्रीति का उदय होता है। भगवान तो अहर्निश हमारी ओर देख रहा है; परंतु हमारी आंखें जगत के विषयों पर लुभाई हुई हैं-यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साईं रमण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है-अंतर का पट हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर मिलन हो तो कैसे? यही अमृत-रस का पान है।

दूसरा पहलू

महज साढ़े छह लाख की आबादी वाले इस देश में सार्वजनिक परिवहन मुफ्त होने पर भी आधी आबादी निजी वाहनों का उपयोग करती है।

लक्जमबर्ग : जहां मुफ्त है सार्वजनिक परिवहन

लक्जमबर्ग सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश है। वर्ष 2020 से वहां के नागरिक टिकट लिए बिना ही ट्रेन, ट्राम और बस के जरिये देश के भीतर आवाजाही कर रहे हैं। इस तरह निशुल्क सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर वहां का प्रत्येक नागरिक साल भर में औसतन 400 यूरो यानी तकरीबन 36 हजार रुपये तक की बचत करता है।

लक्जमबर्ग की सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। लक्जमबर्ग के लिए यह कदम इसलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वहां वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का आधा हिस्सा केवल गाड़ियों के धुएं से आता है। एक सर्वे के मुताबिक, वहां सार्वजनिक बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19 प्रतिशत ही होता है। शेष 49 फीसदी लोग दफ्तर या अन्य जगह आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में प्रति हजार व्यक्तियों में कारों की संख्या भी लक्जमबर्ग में ही सर्वाधिक है।

सुधीर कुमार

लक्जमबर्ग की सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी।

लक्जमबर्ग के लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर एक वर्ष में औसतन 400 यूरो यानी 36,000 रुपये की बचत करते हैं। इनमें बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19 प्रतिशत होता है।

दरअसल, जीडीपी का सवा तीन प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक परिवहन में खर्च करने के बावजूद वहां की सड़कों पर निजी गाड़ियों की बहुतायत होती थी, जिससे वहां ट्रैफिक और वायु-ध्वनि प्रदूषण की समस्या आम हो चुकी थी। अब लोग निजी वाहनों से इतर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वायुमंडल में जहरीली गैसों के फैलने की प्रक्रिया धीमी हो रही है। निशुल्क आवाजाही का यह निर्णय सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने, सुव्यवस्थित परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कारगर कदम है। इसका अनुकरण अन्य सक्षम देशों को भी करना चाहिए।

भारत में उदारीकरण के बाद निजी वाहनों की संख्या में तीव्रतर वृद्धि हुई है, जिससे यहां जाम और वायु प्रदूषण की समस्या आम है। सार्वजनिक बसों एवं ऑटो में बैठ हिचकोले खाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना आखिर पसंद ही कौन करता है? देश में एक समय सार्वजनिक वाहनों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जो अब घटकर एक प्रतिशत ही रह गई है। यह चिंता की बात है। सार्वजनिक यातायात को प्राथमिकता देकर तथा छोटी दूरी साइकल से या पैदल तय कर हम भी इस दिशा में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

आंकड़े

आईपीएल दूसरे नंबर पर

दुनिया में प्रमुख खेल लीग के प्रसारण अधिकार के मामले में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दूसरे नंबर पर पहुंच गई है।

एनएफएल	3.6
आईपीएल	1.51
ईपीएल	1.12
एमएलबी	0.96
एनबीए	0.21

नोट : आंकड़े करोड़ डॉलर में | स्रोत : Forbes

वृत्रासुर इंद्र को मारना चाहता था। इंद्र ने महर्षि दधीचि से वज्र के लिए उनकी हड्डियां मांगीं। उन्होंने कहा, मैं देह त्यागने से पहले सभी तीर्थ करना चाहता हूं।

नैमिषारण्य में सभी तीर्थ

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार इंद्र को अभिमान हो गया कि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति से इतना क्यों डरें। गुरु बृहस्पति के सभा में आने पर इंद्र और अन्य देवता अपने सिंहासन से नहीं उठे। देवगुरु इंद्र के मन का भाव ताड़कर उसी वक्त लौट गए।

यह बात असुरों को मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की अनुमति से स्वर्ग पर धावा बोलकर अधिकार कर लिया। इंद्र दौड़े-दौड़े भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा-त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। लेकिन विश्वरूप अपना हिस्सा असुरों को भी देते थे, इससे असुरों की ताकत और बढ़ गई। इंद्र को यह बात पता चली, तो उन्होंने पीछे से विश्वरूप का सिर काट लिया। इससे इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। यह बात त्वष्टा ऋषि को पता चली, तो उन्होंने इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने इंद्र को बताया कि नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियों से तुम अपना वज्र बना लो, तो वृत्रासुर को मार सकते हो।

इंद्र ने महर्षि दधीचि से प्रार्थना की, तो उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं देह छोड़ने से पहले सभी तीर्थ करना चाहता हूं। इंद्र ने सभी तीर्थ नैमिषारण्य में ही बुलवा दिए। इसके बाद इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर का वध किया।

अमर उजाला — पुराने पन्नों से — 10 नवंबर, 1953

पार्टीबाजी खत्म करो, अनुशासन भंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पार्टी बाजी समाप्त करो
अनुशासन भंग करने वालों के विरुद्ध
सख्त कार्यवाही की जाय

पंजाब विधानसभा के कांग्रेस सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि वह पार्टी में मनमुटाव और पार्टीबाजी का अंत देखना चाहते हैं। जो लोग अनुशासन भंग करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ताकि दूर हो पानी की किल्लत

प्रयुक्त जल का प्रबंधन वर्तमान की आवश्यकता बन गया है। इसके लिए राज्य स्तर के अलावा शहरी निकायों को भी कार्ययोजना बनानी होगी।

कार्तिकेय चतुर्वेदी

उपाय

शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, तो पानी उन्हें चलाने वाला एक बेहद जरूरी ईंधन। बढ़ती आबादी व तेज शहरीकरण ने स्वच्छ जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। अब महानगरों से निकलने वाले अपशिष्ट या प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूज्ड वाटर मैनेजमेंट) को मुख्यधारा में लाना एक आशाजनक विकल्प बन गया है।

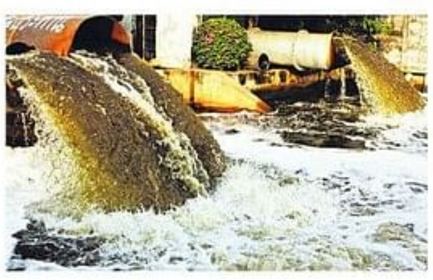

अभी भारत अपने शहरों से निकले कुल अपशिष्ट जल (वेस्ट वाटर) के सिर्फ 28 प्रतिशत हिस्से का शोधन करता है। 2021 में उपलब्ध शोधित अपशिष्ट जल का दैनिक बाजार मूल्य 63 करोड़ रुपये आंका गया था। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट ऐंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की हालिया रिपोर्ट ने पहला शहरी प्रयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक सामने रखा है। इसके माध्यम से प्रयुक्त जल प्रबंधन के मामले में 10 राज्यों के 503 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश,

छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जहां प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की नीति लागू है। यह सूचकांक पांच विषयों-वित्त, बुनियादी ढांचा, कुशलता, प्रशासन, और आंकड़े व सूचना पर शहरी स्थानीय निकायों की एक तुलनात्मक रैंकिंग करता है। हमारा विश्लेषण बताता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पानी की किल्लत का सामना करने वाले राज्यों ने प्रयुक्त जल प्रबंधन के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इसकी वजह से सूचकांक में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इनमें हरियाणा शीर्ष पर है। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य भी पांच अंकों में से सिर्फ क्रमशः 1.94 व 1.74 अंक ही पा सके। यह दर्शाता है कि पूरे देश में जल सुरक्षा पर उच्च प्राथमिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

शहरी निकायों में अपशिष्ट जल शोधन और उसके पुनः उपयोग की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसे, सूरत नगर निगम ने 2019 में शोधित अपशिष्ट जल के शोधन और पुनः उपयोग के लिए एक कार्य योजना अपनाई थी, जिसका लक्ष्य 2025 तक 70 प्रतिशत और 2030 तक 100 प्रतिशत पुनः उपयोग स्तर को पाना है। भारत के शहरी स्थानीय निकायों में प्रयुक्त जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई बातों पर ध्यान दिया जा सकता है।

पहला-राज्यस्तरीय व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। इस मामले में हरियाणा से सीखा जा सकता है, जिसने 2014 से 2023 तक 73 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 433 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। अभी 10 राज्यों ने ही शोधित प्रयुक्त जल नीति लागू की है। दूसरा-राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों और मांगों के अनुरूप विशेष उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। धान उत्पादक पंजाब ने शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी है। साथ ही कृषि को पुनः उपयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। सिंचाई के लिए 5,541 हेक्टेयर क्षेत्र तक शोधित अपशिष्ट जल पहुंचाने के लिए 2020 तक 94 करोड़ रुपये की लागत से 47 परियोजनाएं पूरी कर डाली थीं। तीसरा-राज्यों को प्रयुक्त जल प्रबंधन में एक-दूसरे से सीखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। यह पहल गुजरात जैसे राज्यों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। यहां के चार शहरी स्थानीय निकाय -सूरत, वडोदरा, राजकोट और जामनगर प्रयुक्त जल प्रबंधन में शीर्ष 10 शहरी निकायों में शामिल हैं, जबकि राज्य पांचवें स्थान पर है, जो राज्य के भीतर विभिन्न शहरी निकायों के प्रदर्शन में अंतर को दिखाता है।

शोधित अपशिष्ट जल से व्यापक आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 में उपलब्ध शोधित अपशिष्ट जल को अगर चुनिंदा बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो राष्ट्रीय स्तर पर 966 अरब रुपये का राजस्व पैदा कर सकता था। भारतीय राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अब समय आ गया है कि वे शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को प्राथमिकता दें। यह स्वच्छ जल पर दबाव को घटाने में मददगार होगा, जिसकी कमी से कई भारतीय शहर जूझ रहे हैं। यह शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व सृजन के अतिरिक्त विकल्पों को भी खोलेगा। -साथ में आयुषी कश्यप

संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें।

– चार्ल्स डार्विन

हिंसा का चुनाव

निर्वाचन आयोग के समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के अलावा चुनावी हिंसा पर लगाम लगाना भी बड़ी चुनौती होती है। इसी के मद्देनजर वह मतदान की तारीखों का निर्धारण और सुरक्षाबलों की तैनाती करता है। चुनावी हिंसा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में हिंसा की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहां शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो, जब हिंसा और उपद्रव न होता हो। हालांकि इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में कहा जा सकता है कि हिंसा कम हुई, पर कोई ऐसा चरण नहीं गुजरा, जिसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें न हुई हों। सातवें और अंतिम चरण के मतदान की रात नदिया जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर वहां तनाव पैदा हो गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसकी हत्या की। तृणमूल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश के चलते वह हत्या हुई। इसी तरह बिहार के नालंदा में एक जद(एकी) कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि वह कार्यकर्ता सातवें चरण के दौरान एक मतदान केंद्र पर एजंट था। जद(एकी) का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और माकपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हार की बौखलाहट में वह हत्या कर दी।

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच उत्तेजना और परस्पर टकराव कोई अनहोनी बात नहीं। वैचारिक टकराव जीत के जुनून में अक्सर हिंसा का रूप ले लेते हैं। इसके पीछे निस्संदेह राजनीतिक दलों के प्रचारकों का भी बड़ा हाथ होता है। वे मंचों से जिस तरह के उत्तेजक भाषण देते हैं, उससे कार्यकर्ताओं का आवेशित होना स्वाभाविक है। इसी आवेश में वे अपने नेता और राजनीतिक दल के लिए मर मिटने को तैयार नजर आने लगते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि राजनीतिक दल अब धनबल के साथ-साथ बाहुबल को भी प्रश्रय देने लगे हैं। कई राजनीतिक दल बाहें फैला कर बाहुबली नेताओं का स्वागत करते देखे जाते हैं। बेशक कुछ नेता सार्वजनिक मंचों से अपने कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने की नसीहत देते हैं, पर सच्चाई यही है कि कोई भी अपने उपद्रवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाता। पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की उपद्रवी गतिविधियों को संरक्षण देते देखे जाते हैं। ऐसे में वहां हिंसा का वातावरण सदा बना रहता है। न केवल चुनाव के दौरान, बल्कि चुनाव के बाद भी। विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान यह कुछ बढ़ जाता है।

दरअसल, उन्हीं जगहों पर चुनावी हिंसा अधिक होती है, जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं में वैचारिक के बजाय निजी स्वार्थों का संघर्ष अधिक होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी लाभ के लोभ में राजनेताओं से जुड़े रहते हैं। अगर सत्तापक्ष के राजनेता होते हैं, तो वे अपने कार्यकर्ताओं को किसी काम का ठेका, किसी योजना के संचालन में हिस्सेदारी, अनुदान वगैरह देकर उन्हें उपकृत करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में यह कुछ अधिक देखा जाता है। इसलिए हर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए संघर्ष करता देखा जाता है। राजनीतिक दल अपना जनाधार कार्यकर्ताओं के बल पर ही बढ़ा पाते हैं। मगर उन्हें वैचारिक स्तर पर ही संवेदित किया जाए, तभी लोकतंत्र के मायने रहते हैं, उन्हें स्वार्थ से जोड़ कर हिंसा में झोंक देना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता।

पानी का प्रबंध

गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत हर जगह नजर आने लगती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पारंपरिक जल स्रोतों के सूखते जाने से यह संकट हर वर्ष कुछ बढ़ा हुआ दर्ज होने लगा है। खासकर महानगरों में पानी की समस्या गर्मी का मौसम शुरू होते ही बढ़ जाती है। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। हर गर्मी में हरियाणा के साथ उसकी ठन जाती है कि हरियाण समझौते के अनुसार उसके हिस्से का पानी नहीं छोड़ता। इस बार भी मामला अदालत तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के मकसद से व्यर्थ पानी बहाने वालों पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाने का ऐलान किया। इसके लिए जल बोर्ड को दो सौ निगरानी दल गठित करने को कहा गया। पानी के बंटवारे पर अदालत का फैसला जो भी आए, पर हर वर्ष की इस स्थायी बन चुकी समस्या के मद्देनजर यह जरूरत सदा रेखांकित होती रही है कि अगर ठीक से पानी का प्रबंधन हो, तो इस समस्या से काफी हद तक पार पाया जा सकता है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी के मसले पर केवल सरकार की नाकामियां गिनाने और उसके मत्थे दोष मढ़ कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेने की कोशिशों से काम नहीं चलेगा। इसमें नागरिक दायित्व निर्वहन की भी जरूरत है। जब तक लोग खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि बेवजह पानी बहाना कोई शान की बात नहीं, तब तक डंडे के जोर पर उन्हें नहीं रोका जा सकता। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं कि इससे जल बोर्ड की जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं। जगह-जगह पाइपों के फटने से दिन भर पानी बहता रहता है। महीनों उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। फिर, वर्षों पहले वर्षा जल संचय के लिए दिल्ली में जलाशय बनाने की जो योजना पेश की गई थी, उस पर अपेक्षित काम नहीं हो पाया है। संगठनों के सहयोग से जल संकट से पार पाने के उपायों पर कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि जल बंटवारे को लेकर जिस तरह अनेक राज्यों के बीच अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं, उसके लिए भी व्यावहारिक कदम की अपेक्षा बनी हुई है।

बढ़ता खर्चा और घटती आमदनी

अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो इनके लिए किए जाने वाले खर्च की राशि भी बढ़ती है। बढ़ी हुई महंगाई गरीब, मध्यवर्गीय और गरीबी से नीचे के लोगों को प्रभावित करती है।

अजय जोशी

पिछले कुछ वर्षों से देश के परिवारों, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इस अनुपात में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही, इस कारण उनकी बचत भी निरंतर घट रही है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में परिवारों की शुद्ध बचत पिछले तीन वर्षों में नौ लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर वित्तवर्ष 2022-23 में केवल 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई। मंत्रालय द्वारा जारी ताजा राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 के अनुसार वित्तवर्ष 2020-21 में परिवारों की शुद्ध बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी, और उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। वित्तवर्ष 2021-22 में देश के परिवारों की शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रुपए रह गई। यह पिछले पांच वर्षों में बचत का सबसे निचला स्तर है।

बचत घटने का सबसे बड़ा कारण परिवारों के जीवन निर्वाह व्यय और अन्य व्ययों में बढ़ोतरी है। जीवन निर्वाह व्यय किसी एक खास स्थान और समय अवधि के दौरान आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर जैसे मूलभूत व्ययों के लिए जरूरी धन की मात्रा है। अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो इनके लिए किए जाने वाले खर्च की राशि भी बढ़ती है। बढ़ी हुई महंगाई गरीब, मध्यवर्गीय और गरीबी से नीचे के लोगों को प्रभावित करती है। महंगाई का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है।

दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी से आम भारतीय परिवारों की जीवन स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार महंगाई घटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बाजार में वह कहीं नजर नहीं आती। व्यवहार में छोटी-मोटी वस्तुएं, जो कुछ वर्ष पहले रुपए-दो रुपए में मिलती थी, पहले वह पांच रुपए की हुई, अब दस रुपए की है। दस रुपए एक तरह से मुद्रा की न्यूनतम इकाई हो गई है। इस तरह छोटी-मोटी वस्तुओं की कीमत पांच से दस गुना तक बढ़ गई। पिछले कुछ वर्षों में यह चलन आम हो गया है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई न दिखे, इसलिए निर्माताओं ने मूल्य वही रखते हुए उसकी मात्रा या वजन घटा दिया। इससे वह जल्दी-जल्दी समाप्त होने लगी, बार-बार खरीदने की जरूरत के चलते जिस वस्तु का मूल्य घटा हुआ दिखता है, वह वास्तव में पहले से ज्यादा महंगी पड़ने लगी है।

जो परिवार किराए के घर में रहता है, उसके किराए में कुछ वर्षों में ही डेढ़ गुना तक वृद्धि हो चुकी है। सार्वजनिक परिवहन की लागत भी कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ी है। जिस व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पूरे शहर में यात्रा करनी पड़ती है, उसके लिए बस, टैक्सी, मेट्रो आदि का किराया और पेट्रोल आदि का खर्च भी काफी बढ़ गया है। यह गत पांच वर्षों में लगभग तीन गुना से ज्यादा हो गया है।

खर्च के साथ-साथ परिवारों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है। टिकाऊ

उपभोक्ता उत्पादों के आक्रामक विज्ञापनों ने एक सामान्य परिवार की जरूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया है। व्यक्ति अपनी क्रय क्षमता न होते हुए भी चीजें 'जीरो परसेंट फाइनेंस' जैसे विज्ञापनों से आकर्षित होकर खरीद लेता है। परिणाम यह होता है कि उसकी मासिक किश्त परिवार के खर्च को बढ़ा देती है। यह बात टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एअर कंडिशनर, स्मार्ट फोन आदि जैसे उत्पादों के मामले में लागू होती है। बढ़ी हुई किश्त के कारण परिवार की आय की लगभग पचहतर फीसद राशि केवल इन सबमें ही खर्च हो जाती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अपने परिवार की मूलभूत जरूरतों में कटौती करनी पड़ती या और उधार लेना पड़ता है।

> बढ़ते खर्च के अनुपात में सामान्य परिवार की आय में वृद्धि नहीं हुई है। इससे भी परिवार की बचत प्रभावित हुई है। पारिवारिक आय वह आय है, जो किसी परिवार के सभी सदस्यों के सभी स्रोतों से आती है। इसमें परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत आदि सब कुछ शामिल है। 'इंडियाज पर्सनल फाइनेंस पल्स' नाम से किए गए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि 69 फीसद परिवार अपनी वित्तीय असुरक्षा और कमजोरी का सामना कर रहे हैं।

बढ़ते खर्च के अनुपात में सामान्य परिवार की आय में वृद्धि नहीं हुई है। इससे भी परिवार की बचत प्रभावित हुई है। पारिवारिक आय वह आय है, जो किसी परिवार के सभी सदस्यों के सभी स्रोतों से आती है। इसमें परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज तथा परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत आदि सब कुछ शामिल है। 'इंडियाज पर्सनल फाइनेंस पल्स' नाम से किए गए एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया कि 69 फीसद परिवार अपनी वित्तीय असुरक्षा और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। इस रपट के अनुसार देश में औसतन 4.2 सदस्यों वाले एक परिवार की आय लगभग तेईस हजार रुपए प्रति माह है। वहीं 46 फीसद से अधिक परिवारों की औसत आय पंद्रह हजार रुपए प्रति माह से भी कम है। इस सर्वेक्षण रपट में यह भी बताया गया है कि देश के सिर्फ तीन फीसद परिवारों का ही जीवन-स्तर विलासितापूर्ण है और उनमें से अधिकतर परिवार उच्च आयवर्ग के हैं। आय के इन आंकड़ों से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए जीवन की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति ही उनके लिए मुश्किल है। बचत बढ़ना तो दिवा स्वपन्न जैसा ही है।

आय और बचत के असंतुलन का मुख्य कारण बढ़ती बेरोजगारी और घटता हुआ गुणवत्तापूर्ण रोजगार भी है। अगर हम भारत में बेरोजगारी दर के वर्ष 2008 से 2024 तक के रुझानों को देखें बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) के अनुसार जनवरी-मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर एक साल पहले के 8.2 फीसद थी जो घटकर 6.8 फीसद हो गई। जनवरी 2024 में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे कम रही है। हालांकि, 2023 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में बीस से तीस वर्ष की आयु के युवाओं में बेरोजगारी में वृद्धि दर्ज की गई है। बीस से चौबीस वर्ष आयु के युवाओं में बेरोजगारी बढ़कर 44.49 फीसद हो गई, जो जुलाई-सितंबर तिमाही में 43.65 फीसद थी। इसी तरह 25 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी 2023 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 14.33 फीसद हो गई, जो पिछली तिमाही में 13.35 फीसद थी। ऐसे बहुत से रोजगार हैं, जिनमें वर्ष के तीन-चार माह ही काम मिलता है, शेष अवधि में नहीं। इसी तरह दिहाड़ी मजदूरों को सामान्यतया पूरे महीने काम नहीं मिलता। इस तरह से देखें तो वास्तविक बेरोजगारी जारी होने वाले आंकड़ों कहीं अधिक होती है।

परिवार की आय और खर्च में संतुलन की दृष्टि से यह जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिल-जुल कर आपनी आय के स्रोत बढ़ाएं। घर के खर्च का एक आदर्श बजट बनाएं और उसके अनुरूप ही खर्च तय करें। जहां तक हो सके ऋण से बचें, अगर जरूरी ही है तो उसको चुकाने के स्रोत और अवधि का पूर्व निर्धारण कर लें। घर खर्च का इस प्रकार से नियोजन करें कि एक राशि बचत के रूप में सुरक्षित निवेश करें।

कुदरत के पड़ते थपेड़े

कृष्ण कुमार रत्तू

बदलते मौसमी चक्कर का जो परिदृश्य इन दिनों देखने को मिल रहा है, वह भयावह और भयभीत करने वाला है। असल में यह एक प्राकृतिक चेतावनी है कि अगर अब भी हमने अपनी इस धरती को बचाने के लिए कुछ नहीं सोचा तो फिर जल, जीवन, जंगल और पहाड़ तथा मानवीय सभ्यता लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आज समूचे विश्व को पर्यावरणीय समस्याओं ने अपनी चपेट में ले लिया है और पर्यावरण के नाम पर जिन रासायनिक गैसों का कुप्रबंधन और कबाड़ से भरे हुए हमारे घर से लेकर मैदान और दूषित पानी वाली हमारी पवित्र नदियां, धरती से दोहन किया जाने वाला पानी, हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में 'डार्क जोन' की डरावनी तस्वीर को दिखा रहा है। अब लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अगर हमने धरती और हवा को लेकर अपनी चेतना को नहीं जगाया तो वह दिन दूर नहीं, जब हम पानी और हवा के लिए तरस जाएंगे।

इन दिनों परमाणु विस्फोटकों से भरी हुई धरती और विज्ञान की नई तकनीकी और गैस उत्सर्जन के नए मुकाम क्या दिखा रहे हैं? हमारे यहां स्थिति और भी भयावह है, जहां जागरूकता और जमीन हकीकत चौंकाने वाली है। तमाम सभ्यताओं में पानी, हवा, पहाड़, वातावरण की शुद्धता का जितना खयाल रखा गया है, उतना ही जीव-जंतुओं के संरक्षण की कथाओं से हमारी विरासत के पन्ने भरे हुए हैं। मगर पिछली एक शताब्दी में, विशेष कर पिछले दो दशकों में जिस तरह से ई-कचरे से लेकर गंदगी के अंबार और कचरे के कबाड़ से हमारी धरती को दूषित किया गया है, यह एक बड़ी समस्या है। जिस तरह से हमने समुद्र, नदियां, जल और घर-परिवार, अपने सामुदायिक और सार्वजनिक स्थान को प्रबंधन के कारण कचरा स्थानों में कर रखे हैं। जिस तरह से हमने अपने जल, जंगल, जीवन और अन्य संसाधनों का दोहन किया है, उससे लगता है कि हम जंगल को खत्म करने पर तुले हुए हैं। गौरतलब है कि दुनिया के मध्य-पूर्व में दुबई जैसे शहरों में अब बरसात की वजह से बाढ़ आने लगी है और हमारे यहां सूखा रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है।

दरअसल, उत्तर भारत का दोआब का इलाका जिस तरह से रेगिस्तान में बदल रहा है, वह इंसान और जमीन के लिए जिस तरह की विविधताओं की खोजबीन और विनाश का कारण मनुष्य के लापरवाह होने के कारण बना है, वह देखने लायक है। पूरे देश में जिस तरह का विकास का माडल चल रहा है, वह आवश्यक हो सकता है और उसकी जरूरत भी है, पर उसके साथ हमारे कंक्रीट के जंगल हमारे पहाड़ों में खुदाई और संसाधनों का दोहन कर इतिहास के पन्नों को नष्ट किया जा रहा है।

क्या हम कभी जागरूक हो पाएंगे? पर्यावरण की समस्याओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों का असर कितना होता है? इधर दक्षिण अफ्रीका जैसा देश 'डार्क जोन' में चला गया है। अफ्रीकी देशों से लेकर दक्षिण एशियाई देशों तक में पानी की 'राशनिंग' शुरू हो रही है। भारत में भी वह दिन दूर नहीं है, जब पानी की 'राशनिंग' शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत जैसे हरे-भरे और सब्ज इलाके में पानी का संकट खड़ा हो रहा है। हमारे पहाड़ जिस तरह से वृक्षों की अवैध कटाई और गलत प्रबंधन की सच्चाई और यथार्थ के कारण अग्नि के भेंट चढ़ रहे हैं, वह भी एक चेतावनी है कि हम अपनी धरोहर को किस तरह से बचाएंगे। हर साल पराली पर हल्ला होता है, रेल बंद होती है, धरने होते हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है। हमने कीटनाशकों और आधुनिक खादों से जिस तरह अपनी धरती को नष्ट किया है, वह हमें क्या दिखाता है? ऐसा लगता है कि हम दुनिया के उन राष्ट्रों में शामिल हो गए हैं जो अपने जीने की संभावनाओं की अवहेलना कर रहे हैं।

इन दिनों हमारे गांव सूने हो रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याएं और उस तरह के संकट बढ़ रहे हैं, वहीं गांवों-कस्बों में खत्म होते पेड़, कम होते जंगल क्या कह रहे हैं। गंगोत्री से लेकर हिमालय तक हिमनद खत्म हो रहे हैं। नदियों में कटाव हो रहा है, पर किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। अगर यह ऐसे ही चला रहा तो फिर धरती की गर्मी, सूर्य की धूप और तापमान कहीं भी पहुंचा दे सकती है। पानी के स्रोत और आक्सीजन देने वाली ताजा हवा के स्रोत और सांस लेने वाले पेड़-पौधे धीरे-धीरे खत्म हो जाएं तो फिर जीवन का क्या होगा, क्या कभी हमने सोचा है?

कहने को हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस मना लेंगे, मगर इसके बाद हमें इस बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं मिलेग। फिलहाल हम सब इस स्थिति में हैं, जब इस पर सोच सकते हैं। जीवन बार-बार नहीं मिलता। यह संस्कृति, यह धरती, यह विरासत हम सबकी है और इसे बचा कर रखना हम सबका दायित्व है। अब भी नहीं संभले तो फिर परमाणु कचरे से लेकर रासायनिक अपशिष्ट आदि सामग्री समुद्र से लेकर धरती के सारे जीवन को खत्म कर देगी। फिर आदमी की नस्ल कहां बचेगी? पर्यावरण बचाने का संदेश यही है कि हम जीने के लिए अपने वातावरण की स्वच्छता और खुशबू को जिंदा रखें। इसी में जिंदगी की लय और सौंदर्य है, जिसे आदमी जीना चाहता है और अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। कहते हैं कि पेड़ों की छांव में ही जन्नत होती है और मां जैसी घनी छांव में एक अपनापन होता है। यह धरती स्वर्ग हो सकती है, अगर हम पर्यावरणीय मुद्दों को अपने देवता की तरह बना लें!

दुनिया मेरे आगे

> फिलहाल हम सब इस स्थिति में हैं, जब इस पर सोच सकते हैं। जीवन बार-बार नहीं मिलता। यह संस्कृति, यह धरती, यह विरासत हम सबकी है और इसे बचा कर रखना हम सबका दायित्व है। अब भी नहीं संभले तो फिर परमाणु कचरे से लेकर रासायनिक अपशिष्ट आदि सामग्री समुद्र से लेकर धरती के सारे जीवन को खत्म कर देगी।

हादसों का सिलसिला

देश में बढ़ते सड़क हादसे राष्ट्रीय चिंता का विषय हैं। जम्मू-कश्मीर में अखनूर के पास गहरी खाई में एक बस के गिरने से बीस से अधिक श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों लोगों का घायल होना हृदयविदारक है। इस घटना के बाद भी सरकार ने शोक जताया और मुआवजे की घोषणा कर दी। अगर सरकारें पहले की घटनाओं से सबक लेतीं, तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। हमारे देश में यातायात पुलिस कर्मियों की बेहद कमी है। यातायात नियमों को तोड़ना लोग अपनी शान समझते हैं। सड़क हादसों की अन्य वजहों में खराब सड़कें, सड़क किनारे झुग्गी-झोपड़ी, खस्ताहाल गाड़ियां, नौसिखिए चालक और अनियंत्रित गति प्रमुख हैं। इनमें से कुछ कारणों को सरकार को दूर करना चाहिए, कुछ वजहों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। मानव जीवन को बचाना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

कुदरत से छेड़छाड़

मानव जन्म से ही स्वार्थी रहा है। उसने अपने लालच के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है। उसी का परिणाम आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, भू जलस्तर का घटना आदि के रूप में हमारे सामने है। अत्यधिक गर्मी से मानव समेत सभी जीवों की दशा अत्यंत दयनीय है। ब्राजील के कई क्षेत्रों में हाऊलर बंदरों का गर्मी से मरकर पेड़ो से जमीन पर गिरना मानवीय विकास के गाल पर तमाचा है। हमने विकास के नाम पर प्रकृति को दयनीय बना दिया है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग नौ हजार सालों की तुलना में पिछले सौ सालों में मानव ने अत्यधिक संख्या में पेड़ काटे हैं। पशु पक्षियों की न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। नदियां, तालाब सूख रहे हैं। मानव तो अपने लिए सुख-सुविधाओं का इंतजाम कर सकता है, किंतु बाकी जीवों के सामने यह अनुत्तरित प्रश्न है। स्वस्थ प्रकृति समस्त जीवो के लिए परम आवश्यक है।

– दीपक, बीएचयू, वाराणसी

पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति

वर्तमान पाकिस्तान सत्तारूढ़ पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत की पहल पर शुरू की गई शांति की पहल को पाकिस्तान द्वारा ही पलीता लगाया गया था और कारगिल हुआ था। सवाल है कि शरीफ द्वारा पिछली गलती को स्वीकार करना क्या संबंधों में फिर से विश्वास बहाली का मार्ग प्रशस्त करना है या फिर यह कोई नई कुटिल चाल है। ऐसे पिछले कई उदाहरण हैं, जहां कई बार पाकिस्तान अपनी बात कहकर फिर पलटा है। फिर पाकिस्तान की सेना ही वहां आतंकवाद को प्रश्रय देती रही है, तब सत्ताधीश पर क्या विश्वास करें। सबसे बड़ी बात यही है कि आज पाकिस्तान के हालात विश्व भर में बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसकी गिनती आज भिखारी मुल्कों में की जाती है, तब भी भारत की तरक्की से उसकी जलन बरकरार हैं। इसलिए उसकी दोस्ती को सात बार सोच कर फिर स्वीकार करना होगा।

– मनमोहन राजावतराज, शाजापुर, मप्र

हांगकांग की आजादी

हांगकांग जो कभी आजादी और लोकतंत्र का उदहारण हुआ करता था, आज तानाशाही के हाथों लहूलुहान है। अभिव्यक्ति की आजादी और स्वछंद जीवन जीने की जो आजादी हांगकांग के लोगों के पास थी, आज वह सब कुछ छिन चुकी है। 1984 के चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणापत्र में वे शर्तें तय की गई थीं, जिनके तहत हांगकांग को हस्तांतरित किया जाना था, जिसमें चीन ने पचास वर्षों की अवधि के लिए 'एक देश, दो प्रणाली' के सिद्धांत के तहत सरकार और अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचनाओं को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की थी। जुलाई 1997 को चीन ने न सिर्फ वादे को बीच में ही तोड़ दिया, बल्कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' हांगकांग वासियों पर लाद कर, राष्ट्र सुरक्षा एवं देशद्रोह के नाम पर आम लोगों को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर रोक दिया। मतलब, दमन का यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहां के लोग चीन के प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं कर लेते।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

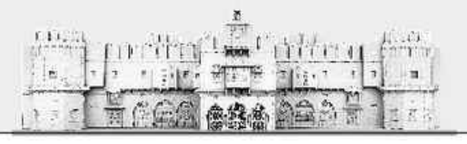

विश्व के लिए मिसाल है भारतीय लोकतंत्र

लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। देश में अस्सी दिन के लोकतंत्र के महापर्व का समापन मंगलवार को चुनाव नतीजों के साथ ही हो जाएगा। ये नतीजे ही बताएंगे कि मतदाता अगले पांच साल के लिए किसके हाथों सत्ता की चाबी सौंपने जा रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे दल व नेता हार-जीत के कितने ही दावे करें, जनता के मन में क्या है यह नतीजों से ही पता लगेगा। सही मायने में यह देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग विचारधाराओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के सियासी भविष्य के फैसले का दिन है।

सात चरणों में अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में मतदान का बंदोबस्त करने के लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है, वहीं देश की जनता को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने भीषण गर्मी के दौर में भी वोट के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो देश भर में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इसके बावजूद यह खबर चौंकाने वाली है कि अकेले उत्तरप्रदेश और बिहार में 25 मतदान कर्मियों की लू के कारण मौत हो गई। इसे देखते हुए भविष्य में मतदान कार्यक्रम मौसम की अनुकूलता को देखते हुए तय करने की आवश्यकता है। मतदाताओं के साथ-साथ मतदानकर्मियों की सुरक्षा की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में इतने बड़े पैमाने पर चरणबद्ध चुनाव कराने की मजबूरी हो सकती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की लम्बी अवधि को कम भी किया जाना चाहिए। फिर भी कहना न होगा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती रखती आई है। दूसरे देश भारतीय लोकतंत्र की मिसाल भी देते हैं। इसका कारण भी है कि हमारे यहां जनादेश का सम्मान कर नेता व दल अपनी हार-जीत को सिर माथे लेने में देर नहीं लगाते। केन्द्र व राज्यों में चुनावों के बाद लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के होता रहा है। आपातकाल के दौर को छोड़ दें तो लोकतंत्र की इसी खूबसूरती को लेकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र भारत के लिए सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बल्कि इसका स्वभाव बन गया है।

जनता अपना फैसला सुना देगी। इसके बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर काम करेंगे। इसके लिए यह भी जरूरी है कि राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोपों के बजाय एक दूसरे से संवाद करने की आदत डालें।

सामयिक : धरती को मां का स्वरूप मानने के बावजूद इसकी रक्षा के स्थान पर किया जा रहा है निरंतर दोहन

पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली से ही बचेगी धरती

डॉ. विवेक एस. अग्रवाल
संचार और शहरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ
@patrika.com

धरती को उर्वरा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने आहार, व्यवहार, जीवनशैली को पारिस्थितिकी अनुकूल ढालें और अपने सुखद, हरित एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करें।

यह तथ्य सभी के लिए चिंता की बात है कि पूरे विश्व में बंजर भूमि का निरंतर विस्तार हो रहा है। पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद यह सिलसिला रुकता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। तथ्य यह है कि हर वर्ष लगभग दो करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करने वाली सवा करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर हो जाती है जो सीधे-सीधे समूचे विश्व में खाद्य एवं जल की कमी का कारण बन जाती है। साथ ही हर वर्ष लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग सूखे की चपेट में होते हैं जिससे समस्त प्राणी और वानस्पतिकी प्रभावित हो जाती है। हालात गंभीर हैं और लगातार बदतर होते जा रहे हैं। यदि यही क्रम चलता रहा तो अगले पच्चीस वर्षों में पारिस्थितिकीजन्य कारणों से दस ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की हानि हो जाएगी।

धरती को मां का स्वरूप मान कर उसकी पूजा करने वाले भारत में भी इसकी रक्षा करने की बजाय इसका निरंतर दोहन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उर्वरा भूमि बंजर होती जा रही है। परिणामस्वरूप जीवन के लिए आवश्यक वानस्पतिकी का भी क्षरण हो रहा है। पर्यावरण के नाम पर मात्र वृक्षारोपण कर इतिश्री कर दी जाती है, जबकि समस्या अत्यंत विकट है और यह एक मात्र समाधान नहीं है। इसी कारण इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के आयोजनों का ध्येय भूमि पुनर्स्थापना, बढ़ते रेगिस्तान को रोकना तथा सूखे की परिस्थितियों पर विवेक सम्मत दृष्टिकोण अपनाना रखा गया है। इस बार ध्येय के केंद्र में धरती को बचाए रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी को जनरेशन रेस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना की पीढ़ी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया गया है।

विश्व की 40 प्रतिशत यानी करीब 320 करोड़ आबादी जो मूलतः गांवों में रहने वाले किसान या आर्थिक रूप से वंचित हैं, भूमि के निम्नीकरण या बंजर होने से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होते हैं। प्रभाव तो संपूर्ण मानवता, जीवों एवं जैव पारिस्थितिकी पर होता है लेकिन बंजर होती भूमि के कारण खाद्यान्न की कमी, फसलों का खराब होना, बढ़ती महंगाई और बदले वातावरण के कारण उत्सर्जित कार्बन के कारण वंचित वर्ग भीषण रूप से प्रभावित हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार भूमि के स्वरूप में निम्नता आने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हर वर्ष लगभग 12 प्रतिशत की कमी होगी और वर्ष 2040 तक महंगाई 30 प्रतिशत से भी अधिक तक बढ़ जाएगी। साथ ही वर्ष 2030 तक वातावरण की विभीषिका के मद्देनजर करीब साढ़े तेरह करोड़ लोगों के विस्थापित होने का अनुमान भी है। इस नई श्रेणी को पर्यावरण की दृष्टि से जुड़े विस्थापनों की नई श्रेणी में रखा जाएगा। संभवतया इनमें युवा पीढ़ी की संख्या बहुतायत में होगी जो संसाधनों एवं अवसरों के अभाव में विस्थापन के लिए विवश होंगे। विस्थापन से जुड़ी अनेकानेक समस्याओं के मध्य स्वास्थ्य, खाद्य, जल और स्वच्छ वातावरण भी अपने आप में चुनौती बन कर खड़े होंगे। इससे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण असंतुलन का एक नया चक्र प्रारंभ होगा, जिसमें स्वयं के अस्तित्व को कायम रखना नए वैश्विक क्रम को जन्म देगा। बीते वर्षों में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए क्षेत्रीय विकास की महत्ता को प्रतिपादित किया जाता रहा है किंतु व्यावहारिक रूप में आमजन इस पर अमल करने से स्वयं को अलग करता रहा है।

वास्तविकता यह है कि हमारी मिट्टी में 60 प्रतिशत तक जैव प्रजातियां रहती हैं जिनमे जैविक प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले सूक्ष्मजीव, औषधीय, फंगस और स्तनधारी जीव भी होते हैं। इस मिट्टी से ही 95 प्रतिशत भोजन उत्पन्न होता है और यह बहुतायत में कार्बन उत्सर्जन को समाहित करने की क्षमता भी रखती है। माना जाता है कि एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में उतने जीव होते हैं, जितने पृथ्वी पर इंसान। संभवतया यही कारण है कि मिट्टी को पवित्रता की दृष्टि से उच्च स्थान पर रखा जाता है एवं शुद्धि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मुश्किल यह है कि जलवायु परिवर्तन, घटते वन क्षेत्रों और उपज की चाह में भूमि का क्षरण होता जा रहा है। पर्यावरण दिवस के आयोजनों में पौधरोपण की बहुतायत रहती है किंतु यथार्थ में इससे कहीं भिन्न करने की आवश्यकता है और उसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान आहार परिवर्तन का है। भोजन में दाल एवं अन्य पारिस्थितिकी सम्मत खाद्य सामग्री के उपयोग से भूमि को उर्वरा बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही, रसोई में उत्पन्न कूड़े से खाद निर्माण करना भी बेहतर वातावरण एवं उपजाऊ भूमि को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। भूमि के बंजर बनने या बढ़ते रेगिस्तान के लिए सर्वाधिक दोषी हैं भौतिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा रहा निरंतर कटाव। वर्तमान की आरामदायक जिंदगी की प्रत्याशा में भविष्य के लिए शूल की नींव रखी जा रही है। आवश्यकताओं पर अंकुश और भविष्य की आशंकाओं के मद्देनजर ही सार्थक जीवनयापन किया जा सकता है। धरती पर चोट से पहले उसके दूरगामी प्रभाव का चित्रण संभवतया उत्तरदायी व्यवहार के प्रति जागरूक करे। हमारा गैर उत्तरदायी व्यवहार आने वाली पीढ़ी के लिए विकट परिस्थितियां विरासत में छोड़ जाएगा।

अतएव धरती मां को खुशहाल, जीवनदायनी और उर्वरा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने आहार, व्यवहार, जीवनशैली को पारिस्थितिकी अनुकूल ढालें और अपने सुखद, हरित एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। बेहतर जीवन के लिए परिवर्तन की प्रथम कड़ी स्वयं से ही प्रारंभ होगी।

दक्षिण अफ्रीका : एएनसी को चुनाव में नहीं मिला बहुमत

गठबंधन युग की शुरुआत, भारत को रखनी होगी नजर

दक्षिण अफ्रीका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के नेतृत्ववाली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) को तगड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है जब एएनसी बहुमत के लिए जरूरी 50 फीसदी मत प्राप्त नहीं कर पाई है। पिछले तीन दशकों से एएनसी सत्ता में है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण अब एशियाई देशों की तरह दक्षिण अफ्रीका भी गठबंधन की राजनीति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेटिक अलायंस (डीए) को 22 फीसदी और पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की पार्टी उम्खोंटो वी सिजवे (एमके) ने करीब 15 फीसदी मत हासिल किए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एमके के साथ मिलकर एएनसी सरकार बना सकती है।

डॉ. एन. के. सोमानी
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

भारत को लेकर गठबंधन सरकार का क्या रुख रहता है? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है।

रंगभेद की समाप्ति व नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से एएनसी लगातार सत्ता में रही है। राष्ट्रपति रामाफोसा के चमत्कारिक नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। देश गरीबी और भुखमरी से बाहर निकला, लेकिन सवाल यह है कि सभी के लिए बेहतर जीवन व्यवस्था और रंगभेद को खत्म करने का नारा देकर सत्ता में आने वाली एएनसी के प्रति लोगों में गुस्से की वजह क्या है। दरअसल, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में ठहराव के कारण पिछले दशक में एएनसी का जनाधार आश्चर्यजनक तरीके से कम हुआ है। अफ्रीकी मतदाताओं की नाराजगी को न समझ पाने का परिणाम यह हुआ कि एएनसी के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो गया। भारत के साथ अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों का दौर उस अवधि से चला रहा है जब महात्मागांधी ने एक शताब्दी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 1994 नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में व्यापक बदलाव आया। ब्रिक्स, इब्सा तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध और मजबूत हुए। राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हुए। साल 2010 में तत्कालिक राष्ट्रपति जैकब जुमा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश वर्ष 2012 तक द्विपक्षीय व्यापार में 10 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए काम करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति रामाफोसा के कालखंड के दौरान यह संबंध लगातार आगे बढ़े हैं। एएनसी का नजरिया भारत के प्रति हमेशा से ही अनुकूल रहा है। दोनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को एक जीवंत संगठन बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

वैश्विक संगठनों विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए दक्षिण अफ्रीका भारत के आह्वान का समर्थन करता है। दूसरी ओर अफ्रीका के बिजली संकट को देखते हुए भारत ने 48 सदस्यीय परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में अफ्रीका का समर्थन किया था। अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय निवेश और उद्यम के लिए दक्षिण अफ्रीका प्रवेश द्वार का काम करता है। यहां एक सौ से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इसलिए दक्षिण अफ्रीका का राजनीतिक घटनाक्रम भारत के लिहाज से काफी अहम है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका उन अफ्रीकी देशों में से एक है जिसे चीन सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। ऐसे में देखना होगा कि भारत को लेकर गठबंधन सरकार का क्या रुख रहता है। क्या वह दक्षिणपंथ के रूप में आगे बढ़ेगा या वामपंथी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ेगा? इसका उत्तर बहुत हद तक भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।

दृष्टिभ्रम : इंद्रप्रस्थ के महल की याद दिलाता है इटली का गिरजाघर

इटली के फ्लोरेंस शहर में स्थित प्राचीन प्रधान गिरजाघर का फर्श संगमरमर की मोजेक टाइलों से बना हुआ है। इसे देखकर कुछ उसी तरह का दृष्टिभ्रम हो जाता है, जिस तरह पांडवों के बनाए गए इंद्रप्रस्थ के महल में नजर आता था। दुर्योधन इस महल में दृष्टिभ्रम का शिकार हुआ था, जिसे देखकर द्रौपदी हंस पड़ी थी और कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे, जिससे दुर्योधन ने अपने आपको अपमानित महसूस किया था। यहां भी यह जटिल ज्यामिति एक विशाल गड्ढे का भ्रम पैदा करती है। इसे देखकर लगता है कि इसमें गिर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव : ढाई महीने से चल रहे राजनीतिक महाकुंभ का समापन आज

परिणाम का इंतजार खत्म, अब नई सरकार के कदमों पर नजर

इंतजार की घड़ियां खत्म। चंद घंटों में साफ हो जाएगा कि मतदाताओं ने किस दल अथवा गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर विश्वास किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जाहिर है कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद पर लगातार तीसरी बार नरेन्द्र मोदी का बैठना तय है। तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई तो दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं कि वह सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। सिक्के के दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि अगर एग्जिट पोल के अनुमान धरे रह गए तो? बीस साल पहले की तरह तमाम अनुमानों को झुठलाते हुए कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी कर जाती है तो क्या होगा?

पहले बात सिक्के के पहले पहलू की। यानी मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं तो देश की राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं? अपनी चुनावी सभाओं में मोदी अनेक बार साफ कर चुके हैं कि 'पिक्चर तो अभी बाकी है।' मतलब साफ है कि उनके दिमाग में कुछ बड़े विचार चल रहे हैं। आमजन में उत्सुकता उठना स्वाभाविक है कि आखिर बीते दस साल का शासन अगर 'ट्रेलर' था तो पिक्चर कैसी होगी? अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके बड़े फैसले क्या होंगे? क्या भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का साहस दिखाएगा? क्या बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगेगी? क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा?

अनंत मिश्रा
वरिष्ठ पत्रकार
@patrika.com

आमजन में उत्सुकता उठना स्वाभाविक है कि आखिर बीते दस साल का शासन अगर 'ट्रेलर' था तो पिक्चर कैसी होगी? अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनें तो उनके बड़े फैसले क्या होंगे? क्या भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का साहस दिखाएगा?

क्या चुनाव सुधार की दिशा में कुछ बड़े और साहसिक फैसले लिए जाएंगे? विशाल देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जरूरत इन समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करने की है। सबसे बड़ी जरूरत राजनीति में आ रही अस्पृश्यता को दूर करने की है। आज के राजनेता एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। सबका उद्देश्य येन-केन प्रकारेण सत्ता के दरवाजे तक पहुंचना भर रह गया है। राजनीति में पावर से पैसा और पैसे से पावर बनाने की जैसे अंधी होड़ मची हुई है। चिंताजनक बात यह है कि राजनीति में धनबल, बाहुबल और परिवारवाद जैसी बीमारियां लाइलाज होती दिखाई देने लगी हैं।

चुनाव नतीजे अगर कांग्रेस और सत्ता की राह में बाधा बने तो बड़ा सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने भी खड़ा होगा। सवाल यह कि तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस आखिर मतदाताओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही? क्या मोदी के मुकाबले राहुल गांधी का करिश्मा कमजोर साबित हो रहा है? कांग्रेस को चिंतन इस बात का भी करना होगा कि विपक्षी दलों को एकजुट रखने के लिए वह क्या करने जा रही है? इंडिया गठबंधन की पांच बैठकों के बावजूद भाजपा विरोधी एक छाते के नीचे क्यों नहीं आ पाए? इस सवाल का जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता व जनता जानना चाहते हैं।

अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आते हैं तो एक सवाल और खड़ा होता है। सवाल यह कि जिस प्रकार देश में एक मजबूत सरकार जरूरी है, उसी तरह मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। पिछले दो चुनावों से कांग्रेस विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पा रही है। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जार्ज फर्नान्डीस, सोमनाथ चटर्जी, सुषमा स्वराज और जसवंत सिंह सरीखे दिग्गज नेताओं की कमी भी साफ झलकने लगी है, जो सरकार को मुद्दों पर घेर सकें।

बात सिक्के के दूसरे पहलू की भी जरूरी है। सन् 2004 में लोकसभा चुनाव की तरह अगर इस बार एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरते हैं तो देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आना तय है। उस हालात में आत्मावलोकन भाजपा को करना होगा कि आखिर जनता उससे नाराज क्यों है? क्या राम मंदिर और अनुच्छेद 370 से भी बड़े ऐसे मुद्दे है, जिन्हें भाजपा समझ नहीं पाई। ऐसी स्थिति आई तो न सिर्फ एनडीए के समीकरण बदलेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन भी नए स्वरूप में सामने आने वाला है।

आज नतीजे भले ही कुछ भी आएं लेकिन इतना तय है कि ये देश की राजनीति में बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम साबित होंगे।

कमल खिलावन POLI नोक-झोंक *पंजा सिंह*

नतीजे आज, क्या आप तैयार हैं !

(4 जून। ऐतिहासिक दिन। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबसे बड़े चुनाव। महापर्व। बड़बोले टीवी एंकर्स एग्जिट पोल पर चिल्ला चिल्लाकर पहले ही गला खराब कर चुके। पंजा सिंह उन डिबेट्स में गए नहीं। कमल खिलावन एक ऐसी जगह जिसके दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर।)

पंजा सिंह: *कैमरे के साथ तपस्या हो गई हो तो बाहर आ जाओ..।*

कमल खिलावन: *तुम राजघाट पर आंसू बहाने पीढ़ियों से जाते रहे हो, तो क्या वहां बिना कैमरे के जाते थे ?*

पंजा सिंह: *भाई.. हमारी पीढ़ियों ने स्वर्णिम काल देखा है। पहले चुनाव में 364 सीट जीतीं। 1984 में हमने रेकॉर्ड बनाया, 414 सीट्स के साथ।*

कमल खिलावन: *और 2019 में ?*

पंजा सिंह: *52 पर सिमट गए।*

कमल खिलावन: *ताश के पत्ते।*

पंजा सिंह: *पर हम तब भी खुश थे।*

कमल खिलावन: *क्यों ?*

पंजा सिंह: *2014 से तो ज्यादा थे। 2014 में हमें 44 मिली थीं, 2019 में 52, कितना बड़ा अचीवमेंट था हमारा।*

कमल खिलावन: *इस बार 52 से नीचे कि 44 के नीचे या दोनों के बीच में?*

पंजा सिंह: *आज पता चल जाएगा।*

कमल खिलावन: *एग्जिट पोल क्या कहते हैं ?*

पंजा सिंह: *वो एग्जिट पोल नहीं, कमल पोल हैं। तुम्हारे चैनल, तुम्हारे एंकर।*

कमल खिलावन: *चलो छोड़ो, ये बताओ दो दिन क्या किया? हम तो 100 दिन की कार्य योजना की मीटिंग में व्यस्त रहे।*

पंजा सिंह: *हमने 100 बार कॉल करके अपने सभी सहयोगियों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। किसी की जेल विदाई पर आंसू पोंछे, किसी के नखरे उठाए। फिर झोला उठा कर चुनाव आयोग चल दिए।*

कमल खिलावन: *ऑब्जेक्शन.. झोला वापस रखो, वो हमारा है।*

पंजा सिंह: *माफ करना.. झोला और जुमला तो सच में तुम्हारा ही पेटेंट है।*

कमल खिलावन: *झोला दे दो, जुमले की बात न करो। आज देखो रिजल्ट आते ही फिर नए जुमले.. मेरा मतलब नई इबारत लिखेंगे...*

पंजा सिंह: *उलटा हो गया तो.. फिर रंग फीके पड़ जाएंगे।*

कमल खिलावन: *चचा गालिब कह गए हैं- मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे।*

पंजा सिंह: *बशीर बद्र को भी पढ़ो- शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है।*

कमल खिलावन: *आज डाल टूटेगी नहीं, तोड़ी जाएगी। (कमल खिलावन बाजू के पेड़ की डाल तोड़कर पंजा सिंह के धर देता है। जवाब में पंजा सिंह भी एक डाल तोड़कर कमल खिलावन के सटीक देता है। आसपास के लोग उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। झगड़ा रोकने नहीं, हरे पेड़ की डाल तोड़ने पर सबक सिखाने.. दोनों सरपट.. अपने अपने मुख्यालयों की ओर.. एक लड्डू खाने, एक सुनसान कार्यालय का ताला खोलने।)* **- सुप्रिया शर्मा**

आपकी बात

कौशल विकास को प्राथमिकता

विकसित भारत का निर्माण करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार सृजन और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

-संजय माकोड़े, बैतूल, मध्यप्रदेश

आज का सवाल

ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जनता को कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'विकसित भारत का निर्माण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?' ऑनलाइन भी देखें।
rb.gy/dxthg1
इसे स्कैन करें

चिंतन

जनादेश का सभी दल करें सम्मान

आज चुनाव परिणाम आने वाला है। 18वीं लोकसभा के लिए आज जो भी परिणाम आए, लोकतंत्र नया रिकार्ड बनाएगा। जैसा अधिकांश एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है, अगर उसी अनुरूप नतीजे आए तो केंद्र में भाजपा नीत राजग की सरकार बनेगी। भाजपा को तीसरी बार अकेले पूर्ण बहुमत मिलेगा, राजग नया इतिहास रचेगा। मोदी 3:0 शुरू होगा। अगर एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित होते हैं और केंद्र में कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार बनती है, तो भी नया कीर्तिमान होगा। वर्ष 2014 की तरह दस वर्ष बाद सत्ता बदल जाएगी। कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी की नेता के तौर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी। माना जाएगा कि कांग्रेस के वादे और राहुल गांधी की दो पदयात्रा का लाभ जनादेश के रूप में इंडी गठबंधन को मिला है। नतीजे जो भी हो, लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले जिस तरह भारतीय शेयर बाजार झूमा है, सेंसेक्स तीन प्रतिशत बढ़त के साथ 2500 अंक चढ़ा है, निफ्टी में 733 अंक का उछाल आया है, उससे लगता है कि बाजार को एग्जिट पोल्स के अनुमान पर भरोसा है और बाजार मानकर चल रहा है कि चुनाव में सफलता भाजपा को ही मिलेगी। केंद्र में बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी। सेंसेक्स और निफ्टी में एक फरवरी, 2021 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। उस समय बजट पेश करने के बाद दोनों सूचकांक करीब पांच प्रतिशत मजबूत हुए थे। यह दिलचस्प है कि 20 मई, 2019 को 'एग्जिट पोल' के बाद भी सेंसेक्स और निफ्टी तीन प्रतिशत से अधिक मजबूत हुए थे। उस 'एग्जिट पोल' में भी आम चुनाव में भाजपा नीत राजग सरकार की बड़ी जीत का अनुमान जताया गया था। शनिवार को आये एग्जिट पोल के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभाल सकते हैं। भाजपा नीत राजग सरकार के भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का अनुमान है। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार एक बार फिर बनने की उम्मीदों से शेयर बाजार में सोमवार को निवेशकों की संपत्ति में एक ही कारोबारी सत्र में 13.78 लाख करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सफल आयोजन के लिए नागरिकों का आभार जताया है। आयोग ने सबक भी लिया है कि इस बार चुनाव कराने का इतना लंबा शेडयूल रखना ठीक नहीं था। अत्यधिक गर्मी के चलते मतदान में कमी दर्ज की गई, तो कई मतदान कर्मियों की जान चली गई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वादा किया है कि अगला आम चुनाव अप्रैल तक करा लिया जाएगा। आयोग ने कांग्रेस की डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम से पहले करा लेने की मांग भी मानकर चुनाव को अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया है। विपक्ष की मांग मानने से आयोग पर सवाल नहीं उठेंगे। इस चुनाव में अगर नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। यदि वर्ष 2004 की तरह ही कुछ ऐसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे, जिसकी उम्मीद विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन कर रहा है, तो मोदी नेहरू के रिकार्ड की बराबरी करने से चूक जाएंगे। राष्ट्रीय क्षितिज पर कमजोर होते जा रहे विपक्ष के लिए इस चुनाव में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस एक दल के रूप में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करेगी, नेता के तौर पर राहुल गांधी के दिन और कठिन होंगे। सबसे चिंता की बात है कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान धर्म व जाति के आधार पर ध्रुवीकरण देखने को मिला है, प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। धर्म व जाति विभाजनकारी तत्व हैं। इस वर्ष का चुनाव 'सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाले चुनावों में एक' है। आज चुनाव नतीजे जो भी आए, सभी दल उसका सम्मान करें, मतदाताओं का अपमान न करें।

चुनाव परिणाम

प्रो. नीलम महाजन सिंह

आज नया कीर्तिमान रचेगा लोकतंत्र

वर्ष 2014 में भाजपा को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। भाजपा नीत राजग बेशक एक गठबंधन है, लेकिन भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत मिल रही है। वर्ष 2019 में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ वर्ष 2014 से अधिक सीटें मिलीं। अब वर्ष 2024 में भी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब तक आए एग्जिट पोल्स के मुताबिक, भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रही है। राजग को 2019 से अधिक सीटें मिलेंगी। इस तरह देखें तो भारतीय राजनीति में तीन खास परिवर्तन हुए हैं। पहला, अब फिर से पूर्ण बहुमत का दौर शुरू हुआ है। बेशक सरकार का मुखौटा गठबंधन का हो। दूसरा, चुनाव दर चुनाव सत्ताधारी भाजपा की सीटें बढ़ी हैं, जबकि माना जाता है कि सत्ताधारी दल को एंटीइन्कम्बेंसी के चलते सीटें घटने का खतरा रहता है। भाजपा ने इस स्थापित मिथ को तोड़ा है। इसका कारण है कि भाजपा ने मास राजनीति के सभी रूपक को मजबूत किया है, कास्ट की बजाय क्लास की राजनीति को प्रमुखता दी है, नया लाभार्थी क्लास गढ़ा है। संस्कृति, सोशल ट्रांसफार्मेशन से लेकर विकास तक का विनिंग कॉकटेल तैयार किया है। तीसरा, नरेन्द्र मोदी ऐसा भारतीय राजनेता बनकर उभरे हैं, जिनकी चुनाव दर चुनाव लोकप्रियता बढ़ी है। वे भाजपा के जिताऊ चेहरा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद वर्ष 2004 में वापसी नहीं कर पाए थे, जबकि उन्होंने पोखरण 2.0 भी किया था और उनके कार्यकाल में कारगिल विजय हुई थी। मोदी ने भाजपा को नई धार दी है, मोदी की भाजपा वाजपेयी की भाजपा से अलग है। भाजपा की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत के साथ भारतीय राजनीति में बहुमत के दौर की फिर से वापसी हो गई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के नतीजे भी पूर्ण बहुमत के आए हैं। पूर्व के कई विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत मिला है। केंद्रीय राजनीति में पूर्ण बहुमत के दौर की वापसी सियासत में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन को परिलक्षित करती है। लोकतंत्र

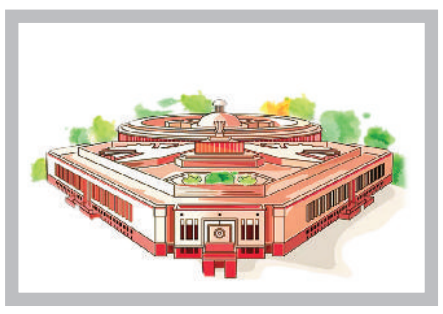

परिपक्व हो रहा है, मतदाता सजग हो रहे हैं।

सभी एग्ज़िट पोल का विश्लेषण करें तो 18वीं लोकसभा के लिए भविष्यवाणी साफ है कि भाजपा को दो तिहाई बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में एक विशेष क्षण होगा। भाजपा व एनडीए को बढ़त का मुख्य कारक यह है कि कोई भी ठोस विपक्षी दल नहीं है। जो विपक्षी गठबंधन है, उसके पास कोई मुद्दा या एजेंडा भी नहीं है। यह चुनावी मौसम के गठबंधन हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के पूर्वानुमानों पर राजनीतिक विश्लेषण अलग-अलग हैं, लेकिन इस आम चुनाव में 543 में से 343 से अधिक सीटें भाजपा को मिलेंगी। भाजपा नीत राजग सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जनता विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. की तुलना में, बीजेपी-एनडीए पर अधिक भरोसा कर रही है, क्योंकि इंडिया आम आदमी के लिए एक व्यवहार्य वैकल्पिक नेता, नीतियाँ व एजेंडा प्रदान करने में विफल रहा। आज 4 जून को जब आम चुनाव के नतीजे आएंगे, हम तथ्यात्मक रूप से यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाजपा- एनडीए की वापसी होगी। भाजपा को न तो कोई खास असंतोष का सामना करना पड़ रहा है और न ही विकल्प की कोई मज़बूत मांग है। चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी इसी तरह का आंकलन किया है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों द्वारा किए गए हमले व्यक्ति केंद्रित रहे। जन से जुड़े वास्तविक मुद्दे विपक्ष के वादों से गायब थे।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि नरेन्द्र मोदी ने नफ़रत भरे शब्दों से प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। डॉ. मनमोहन सिंह का, केवल मोदी के लिए, ऐसा कहना एक व्यक्तिपरक बयान है। दरअसल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और लालू यादव द्वारा, कांग्रेस के लिए किया गया अभियान भी उतना ही नफ़रत भरा था। नरेंद्र मोदी पर विपक्षी पार्टियों के समूह ने जमकर हमला किया था। सच तो यह है कि सार्वजनिक चर्चा काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है, इसलिए यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता। भाजपा का 'अबकी बार 400 पार का नारा' एक चतुर सियासी चाल है। पार्टी ने मतदाताओं में उत्साह पैदा करने के लिए 400+ का नारा दिया। पार्टी को पता है कि उसे इससे कम सीटें मिलेंगी, तो भी उसकी सरकार बन जाएगी, पर 400 पार का नारा देकर विपक्ष को अपने इस नैरेटिव में उलझा दिया। भाजपा ने विमर्श को इस बात पर मोड़ दिया कि भाजपा 400 पार करेगी या नहीं।

नई सरकार को किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ? मोदी सरकार 3:0 में किसानों से बातचीत करनी होगी। कृषि क्षेत्र, रोज़गार सृजन, एफडीआई में तेजी लाने, स्वास्थ्य सेवा, पाक व चीन से सीमा विवाद का हल, विदेश नीति में और धार, समावेशी विकास के लिए आर्थिक , वैश्वीकरण में भारत की मजबूत भूमिका, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, नया परिसीमन, जनगणना, डिजिटल इकोनॉमी, हरित विकास, ग्रीन एनर्जी और महिलाओं की सुरक्षा आदि ऐसे अहम क्षेत्र हैं जिन पर नई सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। समान नागरिक संहिता पर आवाम का ध्यान होगा। भाजपा के ये कोर मुद्दे हैं, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हट चुके हैं, 35 ए को खत्म कर दिया गया है। इस चुनाव में भाजपा हिंदुत्व की बहस को सनातन से विस्तार दिया है। न संविधान को खतरा है, न आरक्षण व न लोकतंत्र को। भारत की वैश्विक शांति में भूमिका बढ़ेगी। विश्व में जितनी अधिक शांति होगी, विकास उतना अधिक होगा। मोदी सरकर को सर्व-धर्म प्रभुता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज परिणाम जो भी हो, नया इतिहास बनेगा।

(लेखक वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

समत्वं योग उच्यते

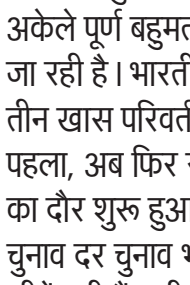

संकलित

दर्शन

जिस मनुष्य का जीवन योगयुक्त है, उसे जीवन चलाने के कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं होते। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कमल ही रहता है। युक्त और अयुक्त का अर्थ योगयुक्त और योगअयुक्त से है अर्थात योग है समत्व बुद्धि। 'समत्वं योग उच्यते'। समत्व बुद्धि से तात्पर्य सोच-विचार कर किए गए कर्म को योगयुक्त कर्म कहते हैं। समत्व बुद्धि से अर्थ सुख-दुख, विजय-पराजय, हर्ष-शोक, मान-अपमान इत्यादि द्वंद्वों में विचलित हुए बिना एक समान शांत चित्त रहे- वही कर्मयोगी कहलाता है। स्थितप्रज्ञ : जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ, जैसे जहाज को चलाने वाले के पास ठीक दिशा बताने वाला कम्पास या यंत्र होना चाहिए, उसी तरह श्रेष्ठ जीवन जीने के तथा मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति के पास 'योग' होना चाहिए। योग नहीं तो जीवन दिशाहीन है। यही बात कृष्ण ने गीता में स्थितप्रज्ञ के विषय में कही है। बुद्धि को निर्मल और तीव्र करने के लिए योग ही एक मात्र साधन है। योग स्थित व्यक्ति साधारण मनुष्यों से विलक्षण देखने लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर जीवन में सत्य की किरणें फैल जाती हैं, सत्य का सूर्य जगता है और जिसकी आंतरिक चेतना जागृति को, पूर्ण जागृति को उपलब्ध हो जाती है, उसका जीवन स्पांटेनियस हो जाता है, सहज हो जाता है, सहज-स्फूर्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी ढांचे को खोजना मुश्किल है। उसके जीवन में कोई बंधी-बंधाई रेखाएं नहीं होतीं।

जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे?

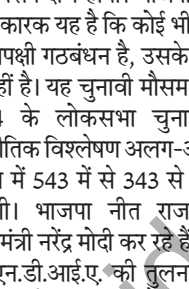

संकलित

प्रेरणा

एक मछलीमार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा... कहीं ऐसा तो नहीं कि मैने कांटा गलत जगह डाला है, यहां कोई मछली ही न हो! उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत-सी मछलियाँथीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं! एक राहगीर ने जब यह नजारा देखा तो उससे कहाः लगता है भैया, यहां पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो! अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसती। मछलीमार ने हैरत से पूछाः क्यों, ऐसा क्या है यहां? राहगीर बोलाः पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होने यहां मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनतीं। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यहीं होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इन्द्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो.. इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें बाकी सब इन्द्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए।

फैसला आज

प्रभात झा

बहुमत का नया रिकार्ड बनाएंगे नरेन्द्र भाई मोदी

भारतीय राजनीति में आजादी के बाद सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू रहे। वे लगभग साढ़े सत्तरह साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी पंद्रह साल तीन सौ पचास दिन प्रधानमंत्री रहीं। भारतीय जनसंघ की स्थापना से भाजपा के अब तक के इतिहास में प्रधानमंत्री के पद पर पहले तेरह दिन, दूसरी बार तेरह महीने और तीसरी बार साढ़े चार वर्ष के करीब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। अपने जीवन में जब वे कानपुर में स्नातकोत्तर और लॉ की पढ़ाई करने गए, तो उसके बाद वे संडीला जो उत्तरप्रदेश में एक स्थान है, वहां कुछ समय के लिए प्रचारक के रूप में रहे। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अटल जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक एवं कुछ समय प्रचारक रहे, ऐसे राजनेता भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में बात इतनी सी रही कि वे पूर्ण बहुमत वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं रहे। नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीति में पच्चीस वर्ष बाद ऐसे प्रधानमंत्री बने जो अपनी पार्टी भाजपा के पूर्ण बहुमत के आधार पर पहले प्रधानमंत्री बने। साथ ही उन्हें एनडीए का समर्थन था।

4 जून 2024 को आम चुनाव 2024 का परिणाम आएगा। 18वीं लोकसभा का गठन होगा। अब तक आए सभी चैनलों के चुनाव पूर्व अनुमान यह साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और नरेन्द्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर गणित लगाएंगे तो वे जनसंघ से भाजपा में रहे प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल से तो काफी आगे सन 2014 और 2019 के साथ-साथ अब सन 2024 में भी रहेंगे। अटल जी और नरेन्द्र भाई मोदी में जो समानता है कि अटल जी भी संघ के स्वयं सेवक और कुछ समय तक प्रचारक रहे। वहीं नरेन्द्र भाई मोदी तो वार्षों तक संघ के प्रचारक रहे और प्रचारक के नाते भाजपा के संगठन महामंत्री भी रहे। नरेन्द्र भाई मोदी के मुख्यमंत्री काल को जोड़ लिया जाए तो भारतीय राजनीति में तेरह वर्ष मुख्यमंत्री और दस वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के पहले राजनीतिज्ञ मोदी ही हैं। साथ ही जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कह रहे हैं, कि सन 2029 में भी नरेन्द्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो यहां यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वे भारतीय राजनीति के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो भारत में प्रधानमंत्री पद पर रहने के सारे रिकार्ड तोड़ देंगे। जैसे क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने इतना बड़ा रिकार्ड बना दिया कि अभी तक विश्व में उसे कोई तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही विश्व के लोकतांत्रिक देश के इतिहास में 4 जून 2024 को तो इतिहास रच ही जाएगा। साथ ही वर्ष 2029 में भाजपा और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं मान्यता और स्वीकार्यता प्राप्त व्यक्तित्व नरेन्द्र भाई मोदी हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार बहुमत से अधिक संख्या और हर बार संख्या में बढ़ोत्तरी कर न केवल भाजपा की साख बढ़ी है, बल्कि नरेन्द्र भाई मोदी ने यह सिद्ध किया है कि राजनीति भी एक साधना है, तपस्या है और यदि उन्होंने तपस्वी बनकर प्रधानसेवक की भूमिका निभाते हुए कहा कि मेरे लिए सिर्फ ग्यान (जीवाईएएन) अर्थात 'जी' से गरीब 'वाई' से यूथ 'ए' से अन्नदाता और 'एन' से नारी शक्ति ही सब कुछ है। न में जाति में विश्वास करता हूं और इन चारों के विकास के लिए और विश्व में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अपना जीवन का एक-एक पल लगा रहा हूं। सच भी है कि अगर वे चुनाव के समय ध्यान में भी गए तो भारत 'ग्यान' के विकास को और मजबूती के साथ ही भारत विश्व में नम्बर एक कैसे बने, इसलिए गए थे। उनकी कल्पना और दूरदृष्टि का भारत ही नहीं, विश्व भी कायल है। यही कारण है कि नरेन्द्र भाई मोदी विरोधियों की चिंता किए बगैर भारत माता को वैभव पर पहुंचाने में रात-दिन लगे रहते हैं।

(लेखक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

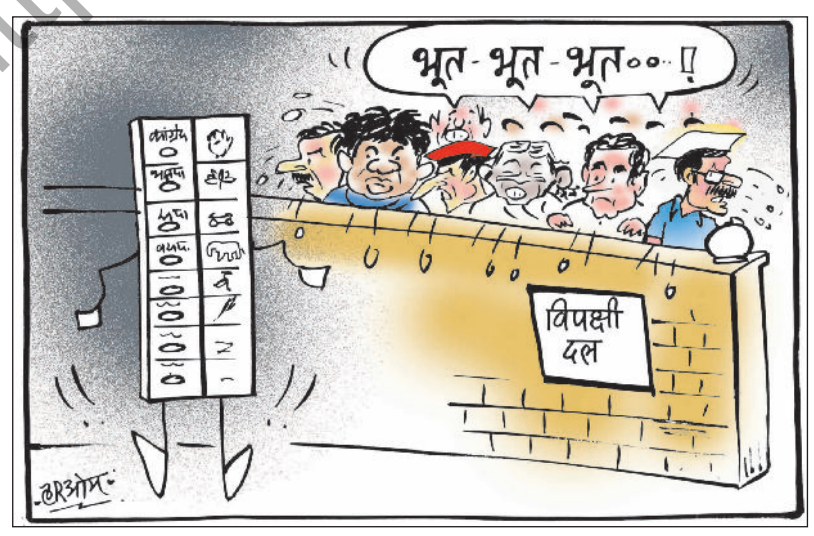

आज की पाती

दुग्ध क्षेत्र में सुधार की जरूरत

एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2001 में विश्व दुग्ध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध डेयरियों को नई पहचान देना और दूध कैसे लाभकारी है, इसके प्रति जागरूकता फैलाना भी है। इस दिवस को दुनिया के बहुत से देशों में मनाया जाता है। डेयरी स्वरोजगार का साधन भी माना जा सकता है। मौजूदा समय में हमारे देश में भी इससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी चल रही है। सरकारें भी इसके लिए विशेष योजनाएं अमल में ला रही हैं। हमारे देश में बहुत सी दुग्ध कंपनियां या डेयरियां हैं जो गांवों में दुधारू पशुपालकों के लिए वरदान हैं। इसके बावजूद डेयरी क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। - रंजन गुप्ता, राजिम

ट्रेंड

अच्छा संकेत

मैं अपने सामने सिविल सेवा में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देखता हूं। एक समय हमारे समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्ग जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वह आपने साकार कर दिखाया है। ये अच्छा संकेत है।

-जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

विकास के काम

मैं करुणानिधि जी को 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने तमिल लोगों के विकास के लिए काम किया। उनके विद्वतापूर्ण स्वभाव के कारण उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जनमत को धोखा

विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे धपला करने की गुंजाइश बन सके। पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था बस चैनलों ने चलाया आज है। ये जनमत को धोखा दिया जा रहा है।

-अखिलेश यादव, सपा नेता

बड़ी उपलब्धि

स्टारलिंक ने कल ही 28 एमएस का एक नया आंतरिक औसत विलंबता रिकॉर्ड हासिल किया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। समूह की इंजीनियरिंग और संचालन टीमों द्वारा बढ़िया काम। किसी भी संस्थान की कामयाबी में उसकी टीम का अहम योगदान होता है। -एलन मस्क, उद्योगपति

करंट अफेयर

ट्रंप 'टिकटॉक' से जुड़े, कुछ घंटों में 11 लाख फॉलोअर

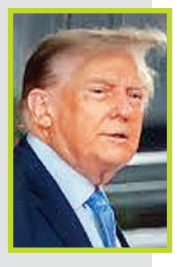

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे डोनाल्ड ट्रंप लोकप्रिय वीडियो एप 'टिकटॉक' से जुड़ गए है जिस पर उन्होंने व्हाइट हाउस में रहने के दौरान प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। वह टिकटॉक से ऐसे समय में जुड़े हैं जब उन्हें अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त तरीके से धन देने के मामले में रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 आरोपों के तहत दोषी पाया गया है। इसी के साथ वह किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप ने टिकटॉक पर एक वीडियो में कहा, ''यह एक सम्मान है।'' इस वीडियो में उन्हें शनिवार रात को न्यूजर्सी में 'अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप' मुकाबले में प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए और सेल्फी खिंचवाते हुए देखा गया। रविवार सुबह तक ट्रंप ने इस सोशल मीडिया मंच पर 11 लाख से अधिक 'फॉलोअर' जुटा लिए और उनके पोस्ट को 10 लाख से अधिक लोगों ने पसंद किया और 2.4 करोड़ लोगों ने उसे देखा। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन च्युंग ने उनके टिकटॉक से जुड़ने के बारे में एक बयान में कहा, 'हम किसी भी मोर्चे पर अपनी उपस्थिति नहीं छोड़ेंगे और यह ट्रंप समर्थक और बाइडन रोधी सामग्री देखने वाले युवा दर्शकों तक लगातार पहुंचने का प्रयास है।'

ऑफ बीट

तेजी से खत्म हो चुके हैं जीवाश्म ईंधन

ऊर्जा के कार्बन मुक्त स्रोतों ने तेजी से जीवाश्म ईंधन की जगह ले ली है, लेकिन अभी तक सभी लोग इनके इस्तेमाल पर सहमत नहीं हैं। पिछले साल दिसंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी-28) के अंत में अपनाए गए प्रस्ताव को जीवाश्म ईंधन युग के लिए 'अंत की शुरुआत' बताया गया था। हालांकि, इस तरह की घोषणा को बहुत निराशा की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन शायद यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पिछले छह महीनों में इस बात के और भी सबूत मिले हैं कि 'डिकार्बनाइजेशन' (कार्बन-मुक्तिकरण) की नई तकनीकों : पवन, सौर, बैटरी और विद्युत चालित वाहनों के आने से जीवाश्म ईंधन का उपयोग तेजी से कम हो रहा है। ये अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उद्यम, सरकारें और समुदाय इस बात को सीख रहे हैं कि शहरों और अन्य क्षेत्रों में इन्हें कैसे लागू किया जाए। सभी जीवाश्म ईंधन या तो स्थिर हो रहे हैं या नकारात्मक वृद्धि दिखा रहे हैं। कोयला, तेल और गैस के अत्यधिक इस्तेमाल से पता चलता है कि उनके इस्तेमाल में गिरावट कितनी तेजी से होगी। जीवाश्म ईंधन 'लॉबी' की प्रतिक्रियाएं मुख्यत : उपहासपूर्ण रही हैं और यह दिखाने के बजाय कि उनमें गिरावट हो रही है और उन्हें इन नई तकनीकों में विविधता लानी चाहिए, उन्होंने और भी बड़े विकास लक्ष्य चुने हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://www.epapr.in